



# SPECETION OF THE PROPERTY OF T

(मार्च 2022 – मार्च 2023)



Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi Drishti IAS, 21
Pusa Road, Karol Bagh
New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh Drishti IAS, Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, Website: www.drishtiias.com Contact: 011430665089, 7669806814, 8010440440

# अनुक्रम

>	आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23	4	>	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना	51
$\triangleright$	केंद्रीय बजट 2023-24	9	>	शक्ति (SHAKTI) नीति	52
$\triangleright$	नई कर व्यवस्था	20	>	पश्मीना शॉल	52
$\triangleright$	भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य	22	>	भारत का चाय उद्योग	53
$\triangleright$	विनिवेश की स्थिति और प्राप्ति	23	>	IIPDF योजना	55
$\triangleright$	भारत ऊर्जा सप्ताह	24	>	ग्रीनवॉशिंग	56
$\triangleright$	हरित ऊर्जा और रोज़गार	25	>	भारत का पहला जल में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर	57
$\triangleright$	स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम	25	>	कालानमक चावल	58
$\triangleright$	भारत का कृषि निर्यात	26	>	GM सरसों की व्यावसायिक खेती	59
$\triangleright$	प्रयोगशाला निर्मित हीरे	28	>	भारतीय मुद्रा डिजाइन तंत्र	60
$\triangleright$	वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: IMF	28	>	बिग टेक पर आरबीआई की रिपोर्ट	61
$\triangleright$	चीनी निर्यात	29	>	PM किसान सम्मान सम्मेलन	61
$\triangleright$	ओपन मार्केट सेल स्कीम	30	>	जैविक उर्वरक	62
$\triangleright$	सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट: द इंडिया स्टोरी	30	>	बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता	63
$\triangleright$	चलन में मौजूद मुद्रा	31	>	धन शोधन निवारण अधिनियम	65
$\triangleright$	निगम कर	32	>	चलनिधि समायोजन सुविधा	66
$\triangleright$	शहद मिशन और मीठी क्रांति	32	>	स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS)	66
$\triangleright$	बासमती चावल के लिये FSSAI मानक	33	>	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन)	67
$\triangleright$	अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष	34	>	भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव	68
$\triangleright$	डीप टेक स्टार्टअप्स	35	>	यूनेस्को की 50 प्रतिष्ठित वस्त्र शिल्पों की सूची	69
$\triangleright$	केरल के पाँच कृषि उत्पादों को जीआई दर्जा	35	>	वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2022	71
$\triangleright$	समर्थ योजना	36	>	दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना	72
$\triangleright$	ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स	36	>	भारत में कार्ड का टोकनाइज़ेशन	72
$\triangleright$	जीएनपीए अनुपात	37	>	विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट	73
$\triangleright$	मंदी और यील्ड वक्र	38	>	भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक	74
$\triangleright$	पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली	39	>	अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022	76
$\triangleright$	सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति	40	>	सार्वजानिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 16 स्टेशनों के लि	ये बोली
$\triangleright$	बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम	40		लगाएगा रेलवे	76
$\triangleright$	रबी की फसलें	41	>	इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022	78
$\triangleright$	GDP और GVA	41	>	चौथा हेली-इंडिया शिखर सम्मेलन, 2022	79
$\triangleright$	उर्वरक सिब्सिडी	42	>	पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना	80
$\triangleright$	RBI और खुदरा डिजिटल रुपया	43	>	लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें	81
$\triangleright$	विझिंजम बंदरगाह परियोजना	44	>	राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)	81
$\triangleright$	पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाई गई	45	>	ग्रीन फिन्स हब	83
$\triangleright$	मार्ग (MAARG) पोर्टल	46	>	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	84
>	कोयले की बढ़ती मांग	46	>	पीएम प्रणाम (PM PRANAM) योजना	84
>	भारत में रूसी बैंको के वोस्ट्रो खाते	47	>	IBBI विनियमों में संशोधन	85
>	राष्ट्रीय दुग्ध दिवस	48	>	AIBD की 47वीं वार्षिक सभा	86
>	फ्रेंडशोरिंग	49	>	राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022	87
	भारत में बेरोजगारी	50	<i>\sigma</i>	द्रथेरियम विलय	88

>	त्वरित सुधारात्मक कारवाई फ्रेमवर्क	89	>	वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो	136
$\triangleright$	स्टार्टअप की मदद के लिये स्थापित कोष	90	>	राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021	137
>	मेक इन इंडिया के आठ वर्ष	91	>	उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास विधेयक	138
>	REC को महारत्न का दर्जा	92	>	अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस	139
>	सेमीकंडक्टर चिप निर्माण हेतु संशोधित प्रोत्साहन योजना	95	>	पार्टिसिपेटरी नोट्स	140
$\triangleright$	मोटे अनाजों को बढ़ावा	96	>	भुगतान विज्ञन 2025: आरबीआई	141
>	शहरी रोजगार गारंटी	97	>	सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना	142
$\triangleright$	प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट	97	>	PACS का डिजिटलीकरण	143
$\triangleright$	विंडफॉल टैक्स	99	>	सहकारी बैंक	143
$\triangleright$	भारत बना विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था	100	۶	जमानती बॉण्ड	144
$\triangleright$	यूएस स्टार्ट-अप सेतु	101	۶	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21	145
>	सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी	101	>	विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2022	146
>	विदेशों में निवेश करने हेतु नए मानदंड	102	>	क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ना	147
>	ऑनलाइन मार्केटप्लेस एक्वा बाजार	103		ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स	147
>	तिलपिया जलीय कृषि परियोजना: मत्स्यपालन	104			
$\triangleright$	तिलिपया	104	>	वस्तु और सेवा कर परिषद रबर उद्योग	150
>	भारत में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म	105	>		151
>	विकसित देश का लक्ष्य	107	>	PFMS का एकल नोडल एजेंसी (SNA) डैशबोर्ड	152
>	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार	108	>	न्यूनतम् समर्थन मूल्य	153
>	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	109	>	स्टैगफ्लेशन	155
>	यूरिया में आत्मनिर्भरता	110	>	कोर सेक्टर आउटपुट	156
>	प्रधानमंत्री जन धन योजना के आठ वर्ष	111	>	बैड बैंक	156
>	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	112	$\triangleright$	नियोबैंक	158
>	वित्तीय समावेशन सूचकांक: आरबीआई	113	>	लिक्विड नैनो यूरिया	159
>	उद्यम पोर्टल	114	>	महाराष्ट्र पुनः शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य	160
>	भारत में गन्ना और चीनी उद्योग हेतु एफआरपी	115	>	भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र	160
>	इथेनॉल संयंत्र	116	>	वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट: ILO	162
>	जाली नोटों में गिरावट	117	>	बहिर्वाह प्रेषण प्रवृत्ति	163
>	गिफ्ट सिटी और बुलियन एक्सचेंज	118	>	NDB की 7वीं वार्षिक बैठक	164
>	निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)	119	>	क्रिप्टोकरेंसी के कारण 'डॉलरीकरण'	164
>	जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह	120	>	विशेष आहरण अधिकार	165
>	भारतः शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता	121	>	भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)	166
>	निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण मॉडल	121	>	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	167
>	आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की	122	>	विश्व दुग्ध दिवस	168
	संकटग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये एक शब्दावली	125	>	पहला लैवेंडर महोत्सव	168
>	यूरो-डॉलर समानता	126	>	विश्व मधुमक्खी दिवस	169
<b>&gt;</b>	भारत नवाचार सूचकांक २०२१: नीति आयोग	126	<u> </u>	इथेनॉल सम्मिश्रण	170
>	एमआईएसटी पनडुब्बी केबल प्रणाली	127	۶	भारतीय रुपए का अवमूल्यन	171
>	डिजिटल बैंक	127	>	क्रय प्रबंधक सूचकांक	171
	जैव अर्थव्यवस्था	129	>	कृषि, फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक	17 1
<b>&gt;</b>	पूर्वोत्तर क्षेत्र को कृषि निर्यात हब के रूप में बढ़ावा	129		याझेदारी के लिये समझौता ज्ञापन	170
	पूर्वारार क्षेत्र की कृति निवास हुँब के रूप में बढ़ाया देने की रणनीति	121			172
_	दन का रणनात ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम	131	>	UPI123Pay और डिजिसाथी	174
<b>&gt;</b>		131	>	बाजार अवसंरचना संस्थान	174
<b>&gt;</b>	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस	132	>	रिजर्व बैंक इनोवेशन हब	175
<b>&gt;</b>	RBI ने रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दी	133	>	MSMEs के लिये RAMP योजना	176
<b>&gt;</b>	भारत का रक्षा निर्यात	134	>	फिनक्लुवेशन	177
<b>&gt;</b>	लघु बचत योजनाएँ	135	>	सीवीड की खेती	177
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी	135	>	उबला चावल	178

# आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

#### चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त वर्ष 2022-23 के लिये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महामारी से भारत की अर्थव्यवस्था बाहर निकल चुकी है और आने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था के 6% से 6.8% के मध्य बढने की उम्मीद है।

#### आर्थिक सर्वेक्षणः

- भारत का 'आर्थिक सर्वेक्षण' वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज़ है। इसे प्राय: संसद में केंद्रीय बजट पेश किये जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।
- इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
- यह पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है और चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है. जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (GDP), मुद्रास्फीति, रोजगार और व्यापार पर डेटा शामिल है।
- भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था।
- वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। इसके बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया है।

#### वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति:

- प्रदर्शन:
  - 💠 भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलने वाला देश है जिसने 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन की ख़ुराक उपयोग किया।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार ने उन्हें ऋण आपूर्ति बढ़ाने में सक्षम बनाया है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small, and Medium Enterprises- MSME) हेतु ऋण में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
- वर्तमान चुनौतियाँ:
  - 💠 भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें रुपए में गिरावट और यूएस फेड की ब्याज दरों में और बढोतरी की संभावना शामिल है।

- चालू खाता घाटा (Current Account Deficit-CAD) भी बढ़ना जारी रह सकता है क्योंकि वैश्विक पण्य कीमतें ऊँची बनी हुई हैं।
- आउटलुक 2023-24:
  - वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व निजी संस्थाओं और पूंजी निर्माण उद्योगों द्वारा हो रहा है, जिससे रोज़गार का सृजन हो रहा है।
    - प्र आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (Emergency Credit Linked Guarantee Scheme- ECGS) द्वारा MSME से ऋण की प्राप्ति सरलता से हो रही है. जिससे उनकी ऋण संबंधी समस्याओं में कमी आई है।
  - 💠 वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में गिरावट का अनुमान है, किंतु वित्त वर्ष 2024 में भारत में सशक्त क्रेडिट वितरण और पूंजी निवेश चक्र के साथ तेज वृद्धि होने की संभावना है।
  - सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तार और पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति तथा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं जैसे उपायों से आर्थिक विकास का समर्थन होगा एवं विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

## भारत का मध्यम अवधि विकास परिदृश्य:

- संदर्भ:
  - वर्तमान दशक वर्ष 1998-2002 के समान है, जहाँ परिवर्तनकारी सुधारों की वजह से अस्थायी झटकों के कारण विकास प्रतिफल प्राप्त करने में देरी हुई थी लेकिन संरचनात्मक सुधारों का प्रतिफल बाद में विकास लाभांश के रूप प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2014-2022 की अवधि:
  - 💠 वर्ष 2014-2022 भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण अवधि है जिनमें विभिन्न सुधारों का उद्देश्य जीवन को सरल और व्यवसाय को आसान बनाना है।
  - 💠 ये सुधार सार्वजनिक उत्पाद बनाने, विश्वसनीय शासन, निजी क्षेत्र के साथ सह-भागीदारी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर आधारित थे।
  - हालाँकि बैलेंस शीट संबंधी तनाव और वैश्विक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक घटक (Variables) नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए।
- परिदृश्य 2023-2030:
  - महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में विकास का परिदृश्य बेहतर है और भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में अपनी क्षमता से बढ़ने हेतु तैयार है।

# राजस्व से संबंधित प्रमुख राजकोषीय विकासः

- 🕽 संदर्भः
  - प्रत्यक्ष करों और वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) राजस्व में वृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण वित्तीय वर्ष 2023 में लचीलापन देखा गया।
- 🗅 राजस्व वृद्धि और प्रदर्शन:
  - अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5% की साल-दर-साल वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करों और GST दोनों की मजबूत वृद्धि से प्रेरित थी।
  - GST ने खुद को केंद्र और राज्य सरकारों के लिये राजस्व के एक महत्त्वपूर्ण स्नोत के रूप में स्थापित किया है, जैसा कि अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 24.8% की सालाना वृद्धि से प्रदर्शित होता है।
  - पिछले कुछ वर्षों में केंद्र का पूंजीगत व्यय GDP (वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2020) के 1.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 अनंतिम वास्तविक (Provisional Actual) में 2.5% हो गया है।
    - प्रंजीगत व्यय पर खर्च को प्राथिमकता देने हेतु केंद्र ने ब्याज मुक्त ऋण और उधार सीमा में वृद्धि के माध्यम से राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया।
    - विशेष रूप से सड़क और राजमार्ग, रेलवे, आवास तथा शहरी मामलों जैसे बुनियादी ढाँचे एवं गहन क्षेत्रों में बढ़े हुए पूंजीगत व्यय का मध्यम अविध के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पडता है।
- ⊃ सतत् ऋण-से-जीडीपी अनुपात की ओर:
  - पूंजीगत व्यय आधारित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की रणनीति से वृद्धि-ब्याज दर अंतर सकारात्मक रहेगा, जिसके परिणामस्वरूप मध्यम अविध में एक स्थायी ऋण-जीडीपी अनुपात प्राप्त होगा।

#### मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता की स्थिति:

- संदर्भ:
  - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2022 में अपना सख्त मौद्रिक चक्र शुरू िकया और तब से उन्होंने रेपो दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि की है।
    - इससे अधिशेष तरलता में कमी आई है और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट में सुधार हुआ है जिससे उनके लिये पैसा उधार देना आसान हो गया है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि क्रेडिट वृद्धि में विस्तार का समर्थन जारी रखेगी, जिससे एक सकारात्मक निवेश चक्र शुरू होगा।

#### 🔾 प्रदर्शन और वृद्धिः

- ♦ SCB (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA) अनुपात 5.0 के रूप में 7 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है, और पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) 16.0 पर बना हुआ है।
- वित्त वर्ष 2022 में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (IBC) के माध्यम से रिकवरी दर अन्य माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक थी, जो SCB के प्रति सकारात्मक रुझान दर्शाती है।

## वर्ष 2022-23 में कीमतों और मुद्रास्फीति नियंत्रित:

- 🗅 संदर्भ
  - वर्ष 2022 में भारत ने उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के तीन चरणों का सामना किया। पहले चरण के दौरान जनवरी से अप्रैल तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तथा देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव के कारण फसल उत्पादकता में कमी की वजह से मुद्रास्फीति 7.8% पर पहुँच गई।
    - हालाँकि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित कार्रवाई ने दिसंबर तक 5.7% की गिरावट के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने में मदद की।

#### ⊃ बाधाएँ:

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच का अंतर और अधिक बढ़ गया, साथ ही कोर मुद्रास्फीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

#### विनियामक उपाय:

- सरकार ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें शामिल थे- पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क को कम करना, प्रमुख आदानों पर आयात शुल्क को शून्य पर लाना, गेहूँ उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध व चावल पर निर्यात शुल्क लगाना, कच्चे और परिष्कृत पाम तेल पर मूल शुल्क (Basic Duty) को कम करना।
- कम आवास ऋण ब्याज दरों के साथ-साथ आवास क्षेत्र में सरकार के समय पर नीतिगत हस्तक्षेप ने किफायती आवास खंड की मांग में वृद्धि की तथा वित्त वर्ष 2023 में अधिक खरीदारों को आकर्षित किया।

#### RBI का पूर्वानुमान:

- RBI ने निकट भविष्य में अनाज, मसालों और दूध के लिये उच्च घरेलू कीमतों का अनुमान लगाया है, मुख्य रूप से आपूर्ति की कमी और बढ़ती फीड लागत के कारण।
  - बदलती जलवायु भी विश्व भर में उच्च खाद्य कीमतों के जोखिम को बढ़ा रही है।

## वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में सामाजिक बुनियादी ढाँचे और रोजगार की स्थिति:

- संदर्भ:
  - 💠 सरकार ने सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया। मानव पूंजी निर्माण हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जुड़वाँ स्तंभों को मजबूत किया जा रहा है।
    - 💢 कुल मिलाकर सरकार का सामाजिक क्षेत्र का खर्च वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 21.3 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- सामाजिक अवसंरचनाः
  - ♦ शिक्षा:
    - 🗷 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देश के वृद्धि और विकास की संभावनाओं के समृद्ध होने की उम्मीद है।
    - 🗷 सरकार के प्रयासों से स्कूलों में नामांकन अनुपात और लैंगिक समानता में सुधार हुआ है।
  - स्वास्थ्य देखभाल:
    - 🙎 वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का बजट खर्च GDP का 2.1% था, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था।
    - 🛘 ४ जनवरी, 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किये गए हैं।
  - गरीबी उन्मूलन:
    - 🗷 वर्ष 2030 तक गरीबी को कम करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रगति इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2005-06 और 2019-21 के बीच 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं।
  - आधार और को-विन:
    - प्र आधार ने को-विन (Co-WIN) प्लेटफॉर्म को विकसित करने और 2 बिलियन से अधिक वैक्सीन ख़ुराक देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम:
    - 🗷 आकांक्षी जिला कार्यक्रम को खासकर दूर-दराज के इलाकों में सुशासन के एक मॉडल के रूप में देखा जाता है।
- रोजगार:
  - 💠 श्रम बल की भागीदारी: श्रम बाजार कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुके हैं, साथ ही बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 में 5.8% से गिरकर 2020-21 में 4.2% हो गई है।

- ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हो गई है, जो एक सकारात्मक विकास है।
- ♦ ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रिमकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिये ई-श्रम पोर्टल बनाया गया था और 31 दिसंबर, 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया था।
- जैम ट्रिनिटी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: जैम (JAM) ट्रिनिटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) के साथ संयुक्त रूप से हाशिये पर पडे लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाया गया है।

## जलवाय परिवर्तन और पर्यावरण में भारत का आर्थिक प्रदर्शन:

- संदर्भ:
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने 'जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण' पर एक अध्याय प्रस्तुत किया जिसमें भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में परिवर्तन, वर्ष 2070 तक "शुद्ध-शुन्य" उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिये उठाए गए कदम शामिल हैं।
- प्रदर्शन और लक्ष्य:
  - भारत अब वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने करने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्यत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
    - भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से स्थापित क्षमता 500GW से अधिक होने की संभावना है।
    - इससे वर्ष 2029-30 तक (2014-15 की तुलना में) औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की गिरावट आएगी।
  - ♦ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) के अवसर पर ग्लासगो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लोगों को व्यक्तिगत रूप से शामिल करने के लिये "LiFE (पर्यावरण हेतु जीवनशैली)" अभियान का शुभारंभ किया गया।

- नवंबर 2022 में भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SGrBs) फ्रेमवर्क जारी किया गया था। RBI ने 4000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड फ्रेमवर्क की दो किस्तों की नीलामी की।
- सर्वेक्षण में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर वर्ष 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की भारत की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।
- सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत पिछले 7 वर्षों में 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के लिये एक पसंदीदा स्थान बना हुआ है।
  - अक्तूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक प्रमुख मीट्रिक, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 61.6 GW थी।

## कृषि और खाद्य प्रबंधन में भारत का आर्थिक प्रदर्शन:

- 🗅 संदर्भः
  - भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। इसने कृषि को देश के समग्र प्रगति, विकास और खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया है।
- 🗅 प्रदर्शन:
  - हाल के वर्षों में भारत कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में उभरा है और वर्ष 2021-22 में निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा है।
  - सरकार द्वारा किये गए निम्निलिखित उपायों के कारण कृषि क्षेत्र
     में तेज़ी देखी गई:
    - 🗷 फसल और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि।
    - सभी अनिवार्य फसलों के लिये MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना पर तय किया जाना।
    - 🗷 फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना।
    - मशीनीकरण एवं बागवानी तथा जैविक खेती को बढ़ावा
       देना।
- वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। कृषि क्षेत्र के लिये संस्थागत ऋण वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई और यह वर्ष
   2021-22 में 315.7 मिलियन टन रहा।
  - वर्ष 2022-23 (केवल खरीफ) के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.9 मिलियन टन अनुमानित है जो पिछले पाँच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है।

- साथ ही भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिये NFSA 2013 के तहत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना ने किसानों को उनकी उपज (1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को कवर करते हुए) के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु एक ऑनलाइन, प्रतिस्पर्द्धी, पारदर्शी बोली प्रणाली स्थापित की है।
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (IYM) घोषित किये जाने के बाद भारत पोषक अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी है।

## औद्योगिक क्षेत्र में भारत का आर्थिक प्रदर्शन:

- संदर्भ:
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र (वित्त वर्ष 22-23 की पहली छमाही के लिये) द्वारा सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में 3.7% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक की पहली छमाही में हासिल 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है।
- 🕽 प्रदर्शन:
  - निजी अंतिम उपभोग व्यय में मज़बूत वृद्धि, वर्ष की पहली छमाही के दौरान निर्यात प्रोत्साहन, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निवेश मांग में वृद्धि और मज़बूत बैंक तथा कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ने औद्योगिक विकास के लिये मांग प्रोत्साहन प्रदान किया है।
    - माँग प्रोत्साहन हेतु उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत
       रही है।
  - जुलाई 2021 से क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) दोनों में प्रक्षेपित रूप से वृद्धि हो रही है।
- MSMEs और बड़े उद्योगों दोनों के ऋण में दो अंकों की वृद्धि देखने को मिली है (जनवरी 2022 से MSMEs में 30% की वृद्धि)।
- वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग तीन गुना बढ़ गया है, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बडा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।
- फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह चार गुना बढ़ गया है, अत: यह वित्त वर्ष 2019 के 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

- भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में शामिल करने के लिये अगले पाँच वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित कैपेक्स (Capex) के साथ 14 श्रेणियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ (पीएलआई) भी शुरू की गई है।
- कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके जनवरी 2023 तक 39,000 से अधिक प्रावधानों को कम तथा 3500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
- वैश्विक मुल्य शृंखला में भारत के एकीकरण को और बढावा देने के लिये 'मेक इन इंडिया 2.0' अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र एवं 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं।

#### सेवा क्षेत्र में भारत का आर्थिक प्रदर्शन:

- संदर्भ:
  - ♦ भारत में सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2022 में 8.4% (YoY) की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 9.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
- प्रदर्शन:
  - ♦ जुलाई 2022 से क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) सेवाओं में सर्वाधिक विस्तार देखा गया है।
  - विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 4% की हिस्सेदारी के साथ भारत वर्ष 2021 में शीर्ष दस सेवा निर्यातक देशों में शामिल था।
  - डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण की उच्च मांग के कारण भारत का सेवा क्षेत्र कोविड-19 महामारी के दौरान तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण लचीला रहा है।
  - रियल-एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे वर्ष 2021 और 2022 के बीच 50% की वृद्धि के साथ महामारी-पूर्व आवास बिक्री के स्तर में वृद्धि देखने को मिली है।
  - पर्यटन क्षेत्र में होटल अधिभोग दर अप्रैल 2021 में 30-32% के सुधार के साथ नवंबर 2022 में 68-70% हो गई है, जिससे वित्त वर्ष 2023 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के साथ पुनरुद्धार के संकेत देखने को मिल रहे है।
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव ला रहे हैं; भारत का ई-कॉमर्स बाजार वर्ष 2025 तक सालाना 18% के दर से बढ़ने का अनुमान है।

#### बाह्य क्षेत्रक में भारत का प्रदर्शन

- संदर्भ:
  - हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण, भारत के बाह्य क्षेत्रक वैश्विक रूप से अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है।

 तथापि भारत ने अपने बाजारों में विविधता लाने कार्य किया है और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा सऊदी अरब को किये जाने वाले अपने निर्यात में वृद्धि की है।

#### प्रदर्शन:

- ♦ वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही (Q2) में भारत के चालू खाता शेष (CAB) में 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 4.4%) का घाटा दर्ज किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 1.3%) का घाटा था।
  - 🗷 इसका प्रमुख कारण 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च व्यापारिक व्यापार घाटा और शुद्ध निवेश आय में वृद्धि था।
- अपने बाजार का आकार बढ़ाने और बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2022 में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA और ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA पर हस्ताक्षर किये।
- वर्ष 2022 में भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने के साथ विश्व में प्रेषण का सबसे बडा प्राप्तकर्त्ता बना।
  - 😕 सेवा निर्यात के बाद प्रेषण बाह्य वित्तपोषण का दूसरा सबसे बडा स्रोत है।
- ♦ दिसंबर 2022 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.3 महीनों के आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (यह वित्तीय वर्ष 21-22 में आयात के 13 महीनों की तुलना में कम है)।
  - 🗷 इसके बावजूद भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था।

## डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारत का आर्थिक प्रदर्शन

- संदर्भ:
  - भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत की संभावित GDP विकास दर में लगभग 60-100 आधार अंक (BPS) जोड सकता है।
  - निकट भविष्य में. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) जैसे प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों हेतु ई-कॉमर्स बाजार तक पहुँच और क्रेडिट उपलब्धता के मार्ग खोलेंगे तथा अपेक्षित आर्थिक विकास को मज़बूती प्रदान करेंगे।

#### 🗅 प्रदर्शन:

- ♦ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI):
  - प्रPI-आधारित लेनदेन ने वर्ष 2019-22 के बीच मूल्य (121%) एवं मात्रा (115%) दोनों ही दृष्टि से वृद्धि की, जिसके चलते इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- टेलीफोन तथा रेडियो- डिजिटल सशक्तीकरण के लिये
  - प्रामीण भारत में 44.3% उपभोक्ताओं के साथ, भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117.8 करोड़ (सितंबर 2022 तक) है।
- कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 98% से अधिक वायरलेस
   रूप से जुड़े हुए हैं।
- मार्च 2022 तक भारत में कुल टेलीडेंसिटी (प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या) 84.8% थी।
- आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ दूरसंचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
  - इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2022 टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को तीव्र और आसान बना देगा, जिससे 5G का विस्तार तीव्र गति से हो सकेगा।
- प्रसार भारती, भारत का स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक, को 479 स्टेशनों से 23 भाषाओं और 179 बोलियों में प्रसारित किया जाता है और भारत के कुल क्षेत्रफल के 92% तथा प्रसारण कुल आबादी के 99.1% को कवर करता है।
- 🗅 डिजिटल सार्वजनिक गुड्स:
  - माईस्कीम, TrEDS, GEM, ई-नाम, उमंग जैसी योजनाओं ने भारत के बाज़ार स्थान को बदल दिया है और नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं तक पहुँच हेतु सक्षम बनाया है।
  - ओपन क्रेडिट एनैबलमेंट नेटवर्क का उद्देश्य एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों की अनुमित देते हुए ऋण परिचालन का लोकतंत्रीकरण करना है।
  - राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल ने 1520 लेख, 262 वीडियो और 120 सरकारी पहल प्रकाशित किये हैं, भाषायी बाधा को दूर करने के लिये इसे एक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।
  - ई-रूपी, ई-वे बिल आदि जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पादों ने उत्पादकों के लिये अनुपालन बोझ को कम करते हुए उपभोक्ताओं हेतु मुद्रा के वास्तविक मूल्य को सुनिश्चित किया है।

# केंद्रीय बजट 2023-24

#### चर्चा में क्यों?

भारत के वित्त मंत्री ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट (2023-24 के लिये) प्रस्तुत किया।

बजट और संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है।
  - यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है)।
- समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
  - 💠 राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
  - 💠 राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
  - 💠 व्यय अनुमान।
  - पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण।
  - आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात् कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं/पिरयोजनाओं की शुरुआत।
- संसद में बजट छह चरणों से गुज़रता है:
  - 💠 बजट की प्रस्तृति।
  - 💠 आम चर्चा।
  - 💠 विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
  - 💠 अनुदान मांगों पर मतदान।
  - विनियोग विधेयक पारित करना।
  - वित्त विधेयक पारित करना।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का 'बजट प्रभाग' बजट तैयार करने हेतु जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है।
- 🗅 स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

## बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है जो विशेष रूप से सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, जिसमें शामिल हैं:
  - ♦ किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes-OBC), दिव्यांगजन (PwD) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS)।

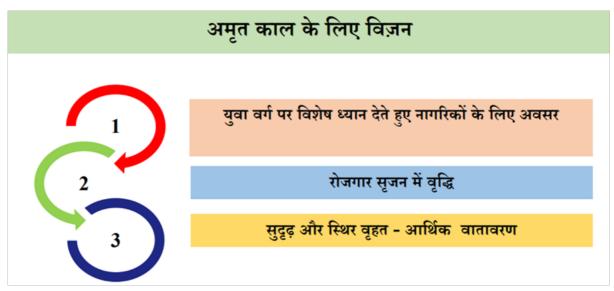
- वंचितों को समग्र प्राथमिकता (वंचितों को वरीयता)।
- ♦ जम्म्-कश्मीर और लद्दाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast Region- NER) के केंद्रशासित प्रदेशों पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्वि-आयामी विकास रणनीति की तर्ज पर है:
  - निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजित करना और विकास को आगे बढ़ाना।
  - 💠 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'; पूंजीगत परिव्यय (Capex) बढ़ाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना।
- बजट की मुख्य उपलब्धियाँ:
  - 💠 नई आयकर व्यवस्था में बदलाव (छूट की सीमा में और टैक्स स्लैब में)।
  - 💠 पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया

- है, इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए (पिछले एक दशक में सबसे अधिक) किया गया है।
- सीमा शुल्क में परिवर्तन; मोबाइल फोन निर्माण, झींगा हेतु खाद्य आदि के लिये कुछ निविष्टियों के आयात में कमी और सिगरेट, सोने की वस्तुओं, यौगिक रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की गई है।
- 💠 रेलवे के लिये पुंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड रुपए किया गया है।

#### भाग-А

## अमृत काल के लिये बजट का विज़न

- अमृत काल:
  - 💠 भारत के वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल में पहला बजट कहा। अमृत काल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मज़बूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित है।



- बजट में इंडिया@100 तक पहुँचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है:
  - स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
  - पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (PM विकास)
  - मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा
  - हरित विकास

## बजट 2023-24 की प्राथमिकताएँ:



#### प्राथमिकता- 1: समावेशी विकास:



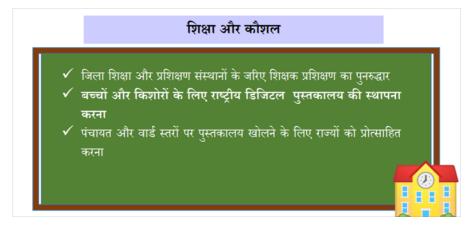
## ⊃ कृषिः

- 💠 डिजिटल सार्वजिनक अवसंरचना: ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक बेनिफिट के तौर पर कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिसके निम्नलिखित परिणाम होंगे:
  - समावेशी किसान-केंद्रित समाधान

- 🗷 फसल योजना/स्वास्थ्य के लिये प्रासंगिक सूचना सेवाएँ
- 🗷 कृषि इनपूट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहँच
- 🗷 कृषि-प्रौद्योगिकी उद्योग और स्टार्ट-अप्स का विकास-
- कृषि-स्टार्टअप के लिये वित्तपोषण: ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
- 💠 कृषि-ऋण: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
  - 😕 मछुआरों, मछली विक्रेताओं और MSME के लिये 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी।

- बागवानी: आत्मिनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल हेतु रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।
- कदन्न: भारत को 'श्री अन्न' (पोषक अनाज/कदन्न) हेत् एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिये 'भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद' को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को साझा करने हेत् उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।
- ♦ कृषि सहकारी सिमितियाँ: "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये सरकार अगले 5 वर्षों में विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने और कवर न किये गए गाँवों में कई सहकारी सिमतियों की स्थापना करने की योजना बना रही है।

#### शिक्षा और कौशल:



#### स्वास्थ्य:

- 💠 वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- ♦ वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें शामिल होगा:
  - 🗷 जागरूकता बढाना
  - प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड लोगों (0-40 वर्ष की आय्) की युनिवर्सल स्क्रीनिंग
  - 🗷 केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श



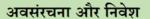
## प्राथमिकता- 2: अंतिम छोर तक पहुँचना

- नया 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम':
  - आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी
     ब्लॉक कार्यक्रम हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए
     शुरू किया गया था।
  - इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे जैसे कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है।
- प्रधानमंत्री कमज़ोर जनजातीय समृह (PVTG) विकास मिशन:
  - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
  - इससे PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
  - अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्ययोजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिये 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
  - केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिये 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भी भर्ती करेगा।
- स्रुखाग्रस्त क्षेत्र के लिये जल:
  - कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिये भूमिगत वाटर टैंकों को भरने हेतु 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
- 🗅 अन्य पहल:
  - प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर
     79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है
  - पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में 'भारत साझा शिलालेख (भारत श्री)' स्थापित किया जाएगा।

#### प्राथमिकता- 3: अवसंरचना और निवेश

- 🔾 अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धिः
  - पूंजी निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है जो 33%

- बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है।
- 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए है जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है।
- पूंजीगत निवेश हेतु राज्य सरकारों को सहायता:
  - सरकार ने अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों के लिये प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिये जारी रखने का फैसला किया है।
  - 💠 इसके लिये बढ़ा हुआ परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपए है।
- 🗅 रेलवे:
  - रेलवे के लिये 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, यह अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है जो वर्ष 2013-14 में किये गए परिव्यय का लगभग 9 गुना अधिक है।
- 🕽 विमानन:
  - क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एयरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्विकसित किया जाएगा।
- 🔾 अन्य परिवहन परियोजनाएँ:
  - निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सिहत 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिये अंतिम छोर तक पहुँच हेतु 100 महत्त्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।
  - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिये ऋण की उपलब्धता हेतु एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund- UIDF) की स्थापना की जाएगी।
    - पIDAF का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये सार्वजिनक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा।
    - इस उद्देश्य के लिये वार्षिक आधार पर 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।



अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन



विकास और रोजगार में



पुंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर  $\Box 10$  लाख करोड़ करना



अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना



रेलवे के लिए  $\square 2.4$  लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय



पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं



यूआईडीएफ\*\* की स्थापना द्वारा श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन

#### प्राथमिकता- 4: क्षमता को उजागर करना:

- अनुपालन को कम करना और जन विश्वास विधेयक:
  - 💠 कंपनी अधिनियम 2013 में किये गए संशोधनों के तहत व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिये 39,000 से अधिक अनुपालन कम किये गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है।
  - 💠 विश्वास पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिये जन विश्वास विधेयक पेश किया।
- AI के लिये उत्कृष्टता केंद्र:
  - ♦ "मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया" के विज्ञन को साकार करने के लिये शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
  - ♦ कृषि, स्वास्थ्य और स्थायी शहरों में अनुसंधान, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और बेहतर समाधान पेश करने में अग्रणी उद्योग के अभिकर्त्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- राष्ट्रीय डेटा शासन नीति:
  - स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान की सुविधा के लिये एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी, जो अज्ञात डेटा तक पहुँच को सक्षम करेगी।

- डेटा शेयरिंग के लिये डिजीलॉकर:
  - विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के सा, जब भी आवश्यक हो दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने और साझा करने के लिये MSME, बडे व्यवसाय तथा धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिये एक डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा।
- विवादों का समाधान:
  - विवाद से विश्वास: MSME के लिये कम कठोर अनुबंध निष्पादन (कोविड अवधि के दौरान प्रभावित MSME को राहत के रूप में प्रदान किया जा रहा है)।
    - सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों के तेज़ी से निपटान को सक्षम करने वाली आसान और मानकीकृत निपटान योजना।
  - ♦ ई-न्यायालय: न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिये ई-न्यायालय का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा।
- 5G प्रौद्योगिकी:
  - इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिये 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोज़गार की संभावनाओं की एक नई शृंखला को साकार किया जा सके।
  - प्रयोगशालाओं में स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर एप जैसे एप्लीकेशन की सुविधा होगी।

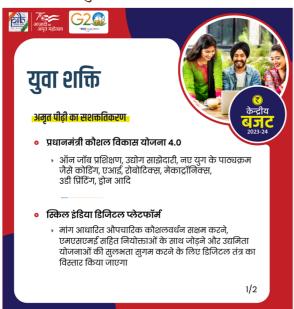
#### प्राथमिकता- 5: हरित विकास:



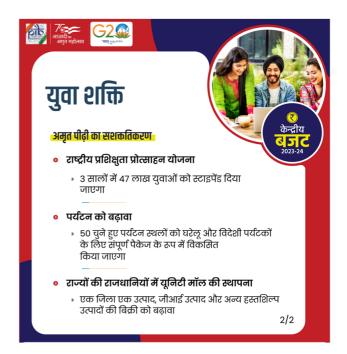
- 🗅 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:
  - राष्ट्रीय हिरत हाइड्रोजन मिशन के लिये 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिये तैयार किया जा सके।
  - लक्ष्यः वर्ष 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुँचने का लक्ष्य है।
- 🗅 गोबरधन योजना:
  - चक्रीय अर्थव्यवथा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 हजार करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए 'अपशिष्ट से आमदनी' संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
  - प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिये 5 प्रतिशत का कम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।

- भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र:
  - सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करेगी। इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक एवं कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
- ⊃ हरित ऊर्जा में अन्य निवेश:
  - ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिये 35,000 करोड़ रुपए।
  - 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों
     को व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ समर्थित किया
     जाएगा।
  - लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिये 20,700 करोड़ रुपए (केंद्रीय सहायता- 8,300 करोड़ रुपए)।

#### प्राथमिकता- 6: युवा शक्तिः



- MSME के लिये क्रेडिट गारंटी:
  - वर्ष 2022 में MSME के लिये क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया था और यह 1 अप्रैल, 2023 से 9,000 करोड रुपए की राशि के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी।
    - 🗷 इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड रुपए के संपार्श्विक (collateral) मुक्त गारंटीकृत ऋण की अनुमित मिलेगी।
    - 🛕 क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी।
    - 🗷 इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण प्रदान किया जा सकेगा।
    - 🙎 क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी।
- वित्तीय सूचना रजिस्ट्री:
  - वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिये एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी।
  - 💠 यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, जो वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढावा देगा।



- एक नया विधायी ढाँचा, जिसे RBI के परामर्श से तैयार किया गया है, इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को नियंत्रित करेगा।
- लघ् बचत योजनाएँ:
  - आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु एक बार नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, को मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।
    - प्र यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ महिलाओं या लडिकयों (7.5% की निश्चित ब्याज दर) के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा।
  - 💠 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिये अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढाकर 30 लाख रुपए की जाएगी।
  - मासिक आय खाता योजना के लिये अधिकतम जमा सीमा 4.5 लाख रुपए से बढाकर 9 लाख रुपए (एकल खाते के लिये) और 9 लाख रुपए से बढाकर 15 लाख रुपए (संयुक्त खाते के लिये) की जाएगी।

# वित्तीय क्षेत्र

#### राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना

ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा

#### केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना

कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी।

#### एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम

2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार

#### महिला सम्मान बचत पत्र

महिलाओं के लिए  $\Box 2$  लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अविध के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना

#### वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ

विरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमाराशि को  $\Box 15$  लाख से बढ़ाकर  $\Box 30$  लाख कर दिया गया है

#### अन्य पहलें

- जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहलें
- प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण-पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना

#### राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति:

- पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग:
  - वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को वर्ष 2023-24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के लिये अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिये।
  - इसमें से अधिकांश राज्यों के विवेक पर निर्भर होगा, हालाँकि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये नामित राज्यों हेतु एक हिस्सा सशर्त होगा. जैसे:
    - 🗷 पुराने सरकारी वाहनों को बदलना।
    - 🗷 शहरी नियोजन में सुधार।
    - शहरी स्थानीय निकायों को नगरपालिका बॉण्ड प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना।
    - 🗷 पुलिस अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण।
    - 💢 एकीकृत मॉल का निर्माण।
    - बच्चों और किशोरों हेतु पुस्तकालयों तथा डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
    - 🗷 केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में योगदान करना।
- 🗅 राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति:
  - राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का

3.5% घाटा रखने की अनुमित है, इस राशि का 0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिये निर्धारित है।

- संशोधित अनुमान 2022-23:
  - 💠 कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर): 24.3 लाख करोड़ रुपए।
    - 🗷 शुद्ध कर प्राप्ति: 20.9 लाख करोड़ रुपए।
  - 💠 कुल व्यय: 41.9 लाख करोड़ रुपए।
    - 🗷 पूंजीगत व्ययः ७.३ लाख करोड़ रुपए।
  - 💠 राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 6.4%।
- 🗅 बजट अनुमान २०२३-२४:
  - बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमश: 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।
    - □ निवल कर प्राप्तियाँ 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
  - ♦ राजकोषीय घाटा GDP के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
    - वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिये दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियाँ 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
    - सकल बाजार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ रुपए है।

साथ ही सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने के लिये इस योजना पर अडिग रहने हेतू प्रतिबद्ध है।

#### भाग- B



### प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार:

- व्यक्तिगत आयकरः
  - व्यक्तिगत आयकर से संबंधित पाँच प्रमुख घोषणाएँ हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है।
    - 🗷 इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था में ७ लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
  - नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढाँचे में स्लैब की संख्या को घटाकर पाँच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।
- अन्य कर सुधार:
  - मानक कटौती:
    - म नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों हेतू मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन के लिये कटौती को 15,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - MSMEs:
    - 🗷 सुक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिये प्रकल्पित कराधान की सीमा बढ़ा दी गई है, जब तक कि नकद में प्राप्त राशि कुल सकल प्राप्तियों/कारोबार के 5% से अधिक न हो।
    - अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान वास्तव में भुगतान की समय पर प्राप्ति (Timely Receipt) में सहयोग करने के लिये किया गया हो।

#### सहकारिता:

- 🛘 31 मार्च, 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर 15% कम होगी।
- 💢 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नकद जमा तथा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है।
- 💢 सहकारी समितियों की नकद निकासी पर स्रोत पर की गई टैक्स (कर) कटौती को बढाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया

#### ♦ स्टार्टअप:

म स्टार्टअप्स को आयकर लाभ प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिये हानियों को अग्रेषित करने की अवधि को निगमन के 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।

#### अॉनलाइन गेमिंगः

प्र ऑनलाइन गेमिंग पर करदेयता को TDS के साथ और निकासी के समय अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में जीती गई कुल राशि पर करदेयता के साथ स्पष्ट किया जाएगा।

#### ♦ सोनाः

🗷 सोने के इलेक्ट्रोनिक गोल्ड रिसीप्ट में परिवर्तन और इसके विपरीत (Vice Versa) को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।

#### ♦ आयकर से छूट:

- 🗷 आयकर प्राधिकरण बोर्ड और आयोग जिसकी स्थापना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आवास. शहर. कस्बे और गाँव के विकास लिये नियामक एवं विकास गतिविधियों या कार्यों हेतु की गई हो उन्हें आयकर से बाहर रखने का
- अग्निवीर निधि को EEE स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किये गए भूगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव।
- अग्निवीरों की कुल आय में की गई कटौती राशि को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो कि उन्होंने योगदान दिया है या केंद्र सरकार ने उनकी सेवा के लिये उनके खाते में हस्तांतरित किया है।

#### कॉमन IT रिटर्न फॉर्म:

करदाताओं की सेवाओं में सुधार के लिये सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत करने की योजना के साथ-साथ करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म के लिये एक प्रस्ताव पेश किया।

#### वर्तमान और प्रस्तावित कर दरें:

कर की दर	वर्तमान आय स्लैब	प्रस्तावित आय स्लैब
शून्य	2.5 लाख रूपए तक	3 लाख रूपए तक
5%	2.5 लाख से 5 लाख रूपए तक	3 लाख से 6 लाख रूपए तक
10%	5 लाख से 7.5 लाख रूपए तक	6 लाख से 9 लाख रूपए तक
15%	7.5 लाख से 10 लाख रूपए तक	9 लाख से 12 लाख रूपए तक
20%	10 लाख से 12 लाख रूपए तक	12 लाख से 15 लाख रूपए तक
25%	12 लाख से 15 लाख रूपए तक	-
30%	15 लाख रूपए से अधिक	15 लाख रूपए से अधिक

#### अप्रत्यक्ष कराधान हेत् प्रस्तावित सुधारः

- सीमा शुल्कः
  - 💠 वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य सामानों हेतू मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।
  - ♦ निर्दिष्ट सिगरेट्स पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingent Duty-NCCD) में लगभग 16% की वृद्धि की गई है।
  - शुल्क में वृद्धि:
    - 💢 सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुएँ
    - 🗷 चाँदी की डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क
  - शुल्क से छूट:
    - 🗷 मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में निहित संपीड़ित
    - परीक्षण एजेंसियाँ जो परीक्षण और/या प्रमाणन उद्देश्यों हेत् वाहनों, ऑटोमोबाइल उपकरण/घटकों, उप-प्रणालियों तथा टायरों का आयात करती हैं।
    - 🗷 साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी हेतु लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिये निर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क की समयसीमा को बढाकर 31.03.2024 कर दिया गया है।
    - 🗷 रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त विकृत एथिल अल्कोहल।

- सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन:
  - ♦ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को संशोधित किया जा रहा है ताकि आवेदन दायर होने के बाद समाधान हेत् अंतिम निर्णय लेने के लिये नौ महीने की समयसीमा निर्धारित की जा सके।
  - ♦ एंटी डंपिंग इयटी (ADD), काउंटरवेलिंग इयटी (CVD) और सेफगार्ड उपायों के उद्देश्य एवं दायरे को स्पष्ट करने के लिये सीमा शुल्क अधिनियम को संशोधित किया जाएगा।
  - केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में भी किये जाएँगे बदलावः
    - □ GST के तहत अभियोजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशि 1 करोड रुपए से बढाकर 2 करोड रुपए की जाएगी।
    - 🗷 कर के लिये चक्रवृद्धि राशि को कर राशि के 50-150% से घटाकर 25-100% कर दिया जाएगा।
    - 🙎 कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।
    - 🗷 रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल करने की अवधि नियत तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित होगी।
    - अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कंपोजिशन करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECO) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।





#### प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

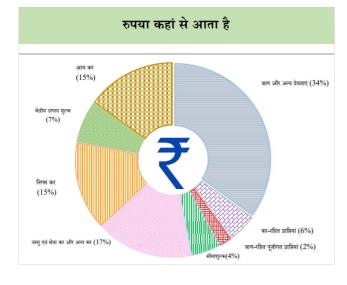
- - सूक्ष्म उद्यमों और पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमाओं को क्रमश: **₹3 करोड** और ₹75 लाख तक बढाया जाएगा

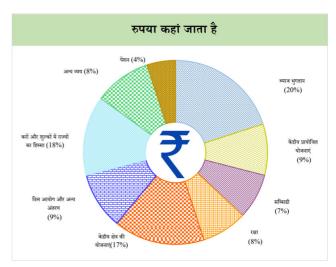


- विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% **की कम कॉरपोरेट** कर का लाभ
- सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर ₹3 करोड की उच्चतम सीमा
- स्टार्ट-अप:
  - स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए तारीख बढाकर **31 मार्च 2024** किया गया
- आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा ₹10 करोड़ हुई
- अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान में टैक्स से छूट



#### रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है ?





# नर्ड कर व्यवस्था

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 के भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब और छूट की सीमा में बदलाव की घोषणा की।

प्रस्तावित 2023 वित्त विधेयक के अनुसार, "एंजेल टैक्स", जो कभी केवल भारतीय निवासियों द्वारा जुटाए गए निवेशों पर लागू होता था, अब विदेशी निवेशकों को शेयर बेचने वाले व्यवसायों पर भी लगाया जा सकता है।

#### प्रस्तावित बदलावः

- कर छूट की सीमा बढ़ाई गई:
  - 💠 इस सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से कम है. उसे छूट का दावा करने के लिये कुछ भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गए निवेश की मात्रा के बावजूद पूरी आय कर-मुक्त होगी।
    - म नतीजतन, मध्यम आय वर्ग के पास अधिक क्रय शक्ति होगी क्योंकि वे छूट का लाभ लेने के लिये निवेश योजनाओं के बारे में बहुत अधिक चिंता किये बिना आय की पूरी राशि खर्च करने में सक्षम होंगे।

- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव:
  - नई व्यवस्था के तहत आय श्रेणियों की संख्या छह से घटाकर पाँच करने और कर छूट की सीमा बढाकर तीन लाख रुपए करने की योजना बनाई गई थी।
- ♦ कर निर्धारक अभी भी पूर्व व्यवस्था से चयन करने में सक्षम होंगे।
  - वेतनभोगी और पेंशनभोगी: नई प्रणाली में 15.5 लाख रुपए से अधिक कर योग्य आय के लिये मानक कटौती 52,500 रुपए है।

FY'23	Tax rate	FY'24	Taxrate	Cumulative benefit
Rs 2.5 lakh	Nil	Up to 3 lakh	Nil	■ ₹2,500
Rs 2.5-5 lakh	5%	₹3-6 lakh	5%	₹7,500
Rs 5-7.5 lakh	10%	₹6-9 lakh	10%	₹15,000
Rs 7.5 to 10 lakh	15%	₹9-12 lakh	15%	₹25,000
Rs 10-12.5 lakh	20%	₹12-15 lakh	20%	₹37,500
Rs 12.5-15 lakh	25%	NA	NA	N.A
Above Rs 15 lakh	30%	Above ₹ 15 lakh	30%	₹37,500

- पेंशनभोगी के लिये:
  - वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ देने की
    - 🗷 15.5 लाख रुपए या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपए का लाभ होगा।
- अधिभार के साथ अधिकतम कर:
  - नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अधिकतम कर की दर घटकर 39% हो जाएगी।
    - 🛘 भारत में उच्चतम कर दर 42.74% है। यह विश्व में सबसे अधिक है।
  - नई कर व्यवस्था के तहत कर की दरें कम कर दी गई हैं तथा अधिकतम सीमांत दर 42.74% से घटकर 39% हो गई है।
- वित्त विधेयक, 2023:
  - वित्त विधेयक, 2023 भी पेश किया गया जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 56(2)VIIB में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
    - प्रावधान में कहा गया है कि जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी, जैसे कि स्टार्टअप अपने निर्धारित मूल्य से अधिक शेयर जारी करने के लिये इक्विटी निवेश प्राप्त करती है, तो इसे स्टार्टअप के लिये आय माना जाएगा तथा "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आयकर के अधीन होगा।
    - आयकर अधिनियम की धारा 56(2)VIIB जिसे आम बोलचाल की भाषा में 'एंजेल टैक्स' के रूप में जाना जाता

- है, पहली बार वर्ष 2012 में पेश किया गया था ताकि किसी कंपनी के शेयर धारकों के माध्यम से बेहिसाब धन के उत्पादन और उपयोग को रोका जा सके।
- इसमें विदेशी निवेशकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसका मतलब है कि जब कोई स्टार्टअप किसी विदेशी निवेशक से धन प्राप्त करता है, तो उसे अब आय और कर योग्य माना जाएगा।

## स्टार्टअप के समक्ष चुनौतियाँ:

- विदेशी निवेशक स्टार्टअप के लिये वित्तपोषण का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, जो उनकी बढ़ी हुई कीमत में योगदान करते हैं, अत: प्रस्तावित संशोधनों का निवेश की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है।
  - ♦ PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत के स्टार्टअप हेतु वित्तपोषण 33% घटकर 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- भारत में एंजेल निवेशकों पर कर की पुन: शुरुआत से स्टार्टअप विदेश में स्थानांतरित हो सकते हैं, क्योंकि विदेशी निवेशक स्टार्टअप में अपने निवेश से जुड़े अतिरिक्त करों का भुगतान नहीं करना चाहते हैं।

#### अंकित मुल्यः

- अंकित मूल्य की परिभाषा के अनुसार, जारी करने के समय यह किसी भी स्टॉक (या किसी वित्तीय साधन) का डॉलर मूल्य है। इसे नाममात्र मूल्य या डॉलर मूल्य भी कहा जाता है।
- अंकित मृल्य = इक्विटी शेयर पुंजी/बकाया शेयरों की संख्या।

# भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य

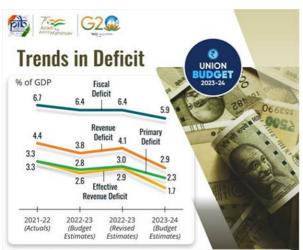
#### चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने सापेक्ष राजकोषीय विवेक को अपनाने की घोषणा की और वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5.9% तक की गिरावट का अनुमान लगाया, जो वित्त वर्ष 2023 में 6.4% था।

सरकार ने राजकोषीय समेकन के व्यापक पथ का अनुसरण जारी रखने और वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने की योजना बनाई है।

#### बजट में घाटे की प्रवृत्तियाँ:

- राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2022-23 के 4.1 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 2.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
- यदि ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है जिसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है, तो यह वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 3% था।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राथमिक घाटा, जो पिछले ब्याज भुगतान देनदारियों से रहित चालू राजकोषीय रुख को दर्शाता है, GDP का 2.3% अनुमानित है।



## राजकोषीय समेकन की दिशा में सरकार के प्रमुख कदम:

- कम सब्सिडी:
  - सरकार ने भोजन, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी हेतु आवंटित राशि को कम कर दिया है।
    - 🗷 वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) में खाद्य सब्सिडी 2,87,194 करोड़ रुपए थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 1,97,350 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

- इसी प्रकार वित्त वर्ष 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी 2,25,220 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में घटाकर 1,75,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- 🗷 वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोलियम सब्सिडी 9,171 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) थी जिसे वित्त वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान) में घटाकर 2,257 करोड़ रुपए किया गया है।
- ♦ विगत वर्ष की तुलना में सब्सिडी में कमी उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन यह अब भी वर्ष 2025-26 तक 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुँचने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- पूंजीगत व्यय:
  - 💠 वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% तक बढाने की योजना बनाई गई है और सरकार ने विकास को बढावा देने के लिये राज्यों को 50 वर्षों के लिये 1.3 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है।
- ऋण प्रबंधन:
  - अधिकांश राजकोषीय घाटे को आंतरिक बाजार ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है और एक छोटा हिस्सा बचत, भविष्य निधि तथा बाहरी ऋण के बदले प्रतिभृतियों से आता है।
    - 🙎 वर्ष 2023 के केंद्रीय बजट में भारत का बाहरी ऋण कुल राजकोषीय घाटे का केवल 1% है, यह अनुमानत: 22,118 करोड़ रुपए है।
  - ♦ राज्य अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3.5% के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के लिये स्वतंत्र हैं, जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिये है।

## उभरती अर्थव्यवस्था के लिये राजकोषीय समेकन का महत्त्वः

- राजकोषीय समेकन से तात्पर्य राजकोषीय घाटे को कम करने के तरीकों और साधनों से है। एक सरकार आमतौर पर घाटे को कम करने के लिये कर्ज़ लेती है। इसके बाद उसे कर्ज चुकाने के लिये अपनी कमाई का एक हिस्सा आवंटित करना होता है।
- कर्ज़ बढ़ने के साथ ब्याज का बोझ बढ़ता है। वित्त वर्ष 2022 के बजट में 34.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल सरकारी व्यय में से 8.09 लाख करोड़ रुपए (लगभग 20%) से अधिक ब्याज के भुगतान में खर्च हो गया।

#### राजकोषीय घाटाः

- परिचय:
  - 💠 राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है।

- यह एक संकेतक है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्तपोषित करने के लिये किस सीमा तक उधार लेना चाहिये और इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- ऋण स्तर में वृद्धि, मुद्रा का मूल्यहास और मुद्रास्फीति कर्ज के बोझ में वृद्धि का कारण बन सकता है।
  - जबिक कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय प्रबंधन और सुचारू अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत हैं।
- राजकोषीय घाटे के सकारात्मक पहलु:
  - सरकारी खर्च में वृद्धि: राजकोषीय घाटा सरकार को सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढाँचे और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने में सक्षम बनाता है जो आर्थिक विकास के लिये काफी सहायक हो सकते हैं।
  - सार्वजनिक वित्त निवेश: सरकार राजकोषीय घाटे के माध्यम से बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं जैसे दीर्घकालिक निवेशों को वित्तपोषित कर सकती है।
  - रोजगार सृजन: सरकारी व्यय में वृद्धि से रोजगार सृजन हो सकता है, जो बेरोजगारी को कम करने और जीवन स्तर को ऊँचा करने में मदद कर सकता है।
- राजकोषीय घाटे के नकारात्मक पहलू:
  - बढे हुए कर्ज़ का बोझ: लगातार उच्च राजकोषीय घाटा सरकारी ऋण में वृद्धि को दर्शाता है, जो भिवष्य की पीढ़ियों पर कर्ज़ चुकाने का दबाव डालता है।
  - मुद्रास्फीति का दबाव: बड़े राजकोषीय घाटे से धन की आपूर्ति में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है।
  - निजी निवेश में कमी: सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये भारी उधार लेना पड़ सकता है, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है और निजी क्षेत्र के लिये ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, इस प्रकार निजी निवेश बाहर हो सकता है।
  - भुगतान संतुलन की समस्याः यदि कोई देश बड़े राजकोषीय घाटे की स्थिति से गुजर रहा है, तो उसे विदेशी स्रोतों से उधार लेना पड़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है और भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ सकता है।

#### भारत में अन्य प्रकार के घाटे:

- राजस्व घाटा: यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है।
  - 💠 राजस्व घाटा = राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ

- प्राथिमिक घाटा: प्राथिमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे के समान होता है। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं और इसकी प्राप्तियों के मध्य अंतर को इंगित करता है तथा पिछले वर्षों के दौरान लिये गए ऋणों पर ब्याज भुगतान हेतु किये गए व्यय को ध्यान में नहीं रखता है।
  - 💠 प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान
- प्रभावी राजस्व घाटा: यह पूंजीगत पिरसंपित्तयों के निर्माण के लिये राजस्व घाटे और अनुदान के मध्य का अंतर है।
  - सार्वजिनक व्यय संबंधी रंगराजन सिमिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का सुझाव दिया गया है।

# विनिवेश की स्थिति और प्राप्ति

#### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 21% कम है और संशोधित अनुमान से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। यह सात वर्षों में सबसे कम विनिवेश लक्ष्य भी है।

#### विनिवेश ( Disinvestment ):

- 그 परिचय:
  - विनिवेश प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयरों की बिक्री के माध्यम से किया जाता।
  - विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग विभिन्न सामाजिक और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये एवं सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु किया जाता है।
- ⊃ विधि:
  - अल्पांश विनिवेश (Minority Disinvestment): इसमें सरकार कंपनी में बहुमत रखती है, आमतौर पर 51% से अधिक शेयर अपने पास रखती है तािक प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
  - बहुमत विनिवेश (Majority Divestment): सरकार अधिग्रहण करने वाली इकाई को नियंत्रण सौंपती है लेकिन कुछ हिस्सेदारी बरकरार रखती है।
  - पूर्ण निजीकरण: कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को दिया जाता है।
- 🗅 प्रक्रियाः
  - भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (Department of Invest-

ment and Public Asset Management-DIPAM) द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

- DIPAM का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार के निवेश का प्रबंधन करना और इन उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश की देख-रेख करना है।
- सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष (National Investment Fund- NIF) का गठन किया था जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को चैनलाइज़ किया जाना था।

#### विनिवेश की आवश्यकताः

- राजकोषीय दबाव में कमी: सरकार राजकोषीय दबाव को कम करने या उस वर्ष हेतु राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये विनिवेश कर सकती है।
  - वह विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने. अर्थव्यवस्था और विकास या सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में निवेश करने एवं सरकारी ऋण चुकाने हेत् करती है।
- निजी अभिकर्त्ता को प्रोत्साहन: विनिवेश संपत्ति निजी स्वामित्त्व और खुले बाजार में व्यापार को भी प्रोत्साहित करती है।
  - अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, यह सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने हेतु संकेत देता है।
  - इसके सफल होने पर अब सरकार को घाटे में चल रही इकाई के घाटे को निधि देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- कार्यकुशलता में सुधार: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से हटकर सरकार इन उद्यमों की दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार कर सकती है, क्योंकि निजी क्षेत्र का स्वामित्त्व और प्रबंधन नए विचारों एवं अधिक बाजारोन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकता है।
- संसाधनों का बेहतर आवंटन: सरकार विनिवेश के माध्यम से मुक्त संसाधनों को सामाजिक और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसी अन्य प्राथमिकताओं हेतु पुनः आवंटित कर सकती है।
- पारदर्शिता: विनिवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कामकाज़ में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ा सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के स्वामित्त्व तथा प्रबंधन के तहत वित्तीय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्टिंग अधिक सख्त हो सकती है।

# भारत ऊर्जा सप्ताह

#### चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी, 2023 को कर्नाटक के बंगलूरू में भारत ऊर्जा सप्ताह (India Energy Week- IEW) 2023 का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन भी लॉन्च किया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा आयोजित हरित गतिशीलता रैली को हरी झंडी दिखाई।

## E20 इथेनॉल फ्यूल और हरित गतिशीलता रैली:

- E20 इथेनॉल फ्यूल:
  - परिचय:
    - 🗷 ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम सरकार का एक प्रमुख केंद्रित क्षेत्र रहा
    - का लक्ष्य वर्ष 2025 तक इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को पूर्ण रूप से हासिल करना है और HPCL तथा अन्य तेल विपणन कंपनियों द्वारा 2G-3G इथेनॉल संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं जो प्रगति को सुगम बनाएगी।
  - उपलिब्धयाँ:
    - म सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 से इथेनॉल उत्पादन क्षमता में छह गुना वृद्धि हुई है।
    - 🗷 इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और जैव ईंधन कार्यक्रम के तहत हासिल उपलब्धियों ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढाया है बल्कि इसके परिणामस्वरूप 318 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी एवं लगभग 54,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत सहित कई अन्य लाभ भी प्राप्त हुए हैं।
- हरित गतिशीलता रैली:
  - 💠 हरित गतिशीलता रैली का उद्देश्य हरित ईंधन हेतु जन जागरूकता बढ़ाना है।
    - प्र इसमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों जैसे E20, E85, फ्लेक्स फ्यूल, हाइडोजन, इलेक्ट्रिक आदि के उपयोग से चलने वाले 57 वाहनों की भागीदारी शामिल है।
  - 💠 हरित गतिशीलता कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने हेत् पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ परिवहन विकल्पों के उपयोग को संदर्भित करती है।

- उचित नीति समर्थन, औद्योगिक कार्रवाई, बाजार निर्माण, निवेशकों की बढ़ती रुचि और स्वीकृति के साथ, भारत हरित गतिशीलता के क्षेत्र में कम लागत, शून्य-कार्बन विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी मजबूत स्थिति सुनिश्चित कर सकता है, साथ ही आर्थिक विकास, रोजगार सृजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है।
- अन्य पहलें:
  - → प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल की 'अनबॉटल्ड' ('Unbottled') पहल के तहत वर्दी भी लॉन्च की। यह वर्दी पुनर्नवीनीकरण PET बोतलों से बनी हैं।
  - प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन-कुकटॉप मॉडल को भी समर्पित किया तथा इसके व्यावसायिक रोल-आउट को हरी झंडी दिखाई।

# हरित ऊर्जा और रोज़गार

#### चर्चा में क्यों?

एक अध्ययन के अनुसार, भारत के सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों ने 52,700 नए श्रमिकों के लिये रोजगार सृजित किया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से आठ गुना अधिक है।

यह अध्ययन ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW), प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद भारत (एनआरडीसी इंडिया) तथा स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (SCGJ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

## अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ ?

- ⊃ आँकड़े:
  - लगभग 99% नए कार्यबल (52,100 कर्मचारी) सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत थे, जिसमें पवन ऊर्जा क्षेत्र में बहुत कम वृद्धि (600 नए कर्मचारी) दर्ज की गई थी।
  - भारत के सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से वित्तीय वर्ष 2022 में 1,64,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है, जो वित्तीय वर्ष 2021 से 47% की वृद्धि को दर्शाता है। इस कार्यबल का 84% सौर ऊर्जा क्षेत्र में है।
  - हालाँिक पॉलीसिलिकॉन, इनगट, वेफर्स और सेल बनाने जैसे अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चिरंग सेगमेंट में प्रशिक्षित श्रिमिकों की "भारी कमी" रही है। वर्तमान में रोजगार का एक बड़ा हिस्सा सोलर मॉड्यूल्स को असेंबल करने में लगा हुआ है।
    - प्र यह सेगमेंट हाल ही में लॉन्च की गई 19,500 करोड़ रुपए (2.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' (Production-Linked Incentive- PLI scheme) योजना पर केंद्रित है, जो 65 GW घरेलू विनिर्माण क्षमता को लक्षित करता है।

#### ्र संभावनाः

- यदि ये रुझान नए ऑन-ग्रिड सौर (238 GW) और पवन (101 GW) क्षमता जारी रखते हैं, तो संभावित रूप से लगभग 3.4 मिलियन अस्थायी और स्थायी रोजगार सृजित किये जा सकते हैं।
- 🗅 अनुशंसाएँ:
  - स्किलिंग प्रोग्राम को सौर मॉड्यूल और बैटरी निर्माण तथा हाइब्रिड परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली नई आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिये।

## भारत में हरित ऊर्जा की क्षमता और चुनौतियाँ क्या हैं?

- 🔾 संभावनाः
  - भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें सौर, पवन, पनिबजली और बायोमास शामिल हैं, जिनका नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिये उपयोग किया जा सकता है।
  - इसके अलावा भारत की तेज़ी से बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था ऊर्जा की भारी मांग पैदा करती है, जिसे हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है।
- 🗅 संभावित लाभ:
  - उत्सर्जन में कमी: हिरत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग वातावरण में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा को काफी कम कर सकता है, जिससे जलवायु पिरवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।
  - ऊर्जा सुरक्षा: भारत आयातित तेल और प्राकृतिक गैस पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसे कीमतों में आई गिरावट एवं आपूर्ति में व्यवधान के प्रति संवेदनशील बनाता है। हरित ऊर्जा स्रोत इस निर्भरता को कम कर सकते हैं तथा ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा सकते हैं।
  - ग्रामीण विद्युतीकरण: भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बिजली नहीं है और विकेंद्रीकृत हरित ऊर्जा स्रोतों, जैसे कि सौर पैनल एवं छोटे पैमाने की पवन टर्बाइनों द्वारा प्रदान की जा सकती है।
  - रोजागार: हरित ऊर्जा क्षेत्र में भारत में लाखों नए रोजागार विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और ग्रिड एकीकरण जैसे क्षेत्रों में मुजित किये जाने की क्षमता है।

# स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) के तहत 477.25 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत एक प्रमुख योजना है। सीड फंडिंग (Seed Funding) एक स्टार्टअप या नए व्यवसाय में निवेश का एक प्रारंभिक चरण है। सीड फंडिंग का लक्ष्य कंपनी को एक ऐसे बिंदु तक पहुँचाने में मदद करना है जहाँ यह अतिरिक्त वित्तपोषण को सुरक्षित कर सकता है या आत्मनिर्भर बनने के लिये राजस्व उत्पन्न कर सकता है।

#### स्टार्टअप इंडिया पहल:

- स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढावा देने और उभरते उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिये देश में एक मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिको तंत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- इस पहल के तहत जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा 19 कार्य बिंदुओं की एक कार्ययोजना का अनावरण किया गया था।
  - 💠 इस कार्ययोजना ने भारत में स्टार्टअप के लिये एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु रोडमैप निर्धारित किया।
- स्टार्टअप इंडिया पहल फ्लैगशिप योजनाओं जैसे- स्टार्टअप्स हेत् फंड ऑफ फंड्स (FFS), SISFS और स्टार्टअप्स के लिये क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS) को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती है।

#### स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ( SISFS ):

- परिचय:
  - 💠 इस योजना की घोषणा 16 जनवरी, 2021 को स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में की गई थी।
  - ♦ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले 4 वर्षों की अवधि हेतु 945 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंज़्री दी है ताकि स्टार्टअप को विचार अथवा सिद्धांत के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण हेत् वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
- निष्पादन और निगरानी:
  - DPIIT द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) का गठन किया गया है, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिये जिम्मेदार होगा।
  - EAC बीज निधियों के आवंटन के लिये इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करेगी, प्रगति की निगरानी करेगी तथा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में निधियों के कुशल उपयोग हेत् सभी आवश्यक उपाय करेगी।
- पात्रता:
  - DPIIT (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसा स्टार्टअप जो आवेदन के समय से 2 वर्ष से अधिक पहले शामिल नहीं किया गया हो।

- स्टार्टअप ने केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता प्राप्त नहीं की हो।
- 💠 सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, गतिशीलता, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस. वस्त्र आदि जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधान प्रदान करने वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुदान और समर्थन:
  - यह अगले 4 वर्षों में 300 इनक्यूबेटरों के माध्यम से अनुमानत: 3.600 उद्यमियों को समर्थन देगा।
  - ♦ सिमिति द्वारा चयिनत पात्र इनक्युबेटरों को 5 करोड रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  - चयनित इनक्युबेटर स्टार्टअप विचार अथवा सिद्धांत के प्रमाण या प्रोटोटाइप विकास या उत्पाद परीक्षणों के सत्यापन के लिये 20 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त करेंगे।
  - परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण से जुडी प्रतिभृतियों के माध्यम से व्यवसायों को बाजार में प्रवेश, व्यावसायीकरण अथवा स्केलिंग के लिये 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।

# भारत का कृषि निर्यात

## चर्चा में क्यों?

पिछले दो वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास हुआ है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत का कृषि क्षेत्र निर्यात एक नई ऊँचाई पर पहुँच सकता है। परंतु साथ ही आयात में भी उतनी ही वृद्धि हुई है जिससे कुल कृषि व्यापार अधिशेष में गिरावट आई है।

## INDIA'S AGRICULTURAL TRADE IN MILLION US DOLLARS

YEAR	EXPORTS	IMPORTS	TRADE SURPLUS
2012-13	41726.33	18978.33	22748.00
2013-14	43251.66	15528.94	27722.72
2014-15	39080.43	21151.77	17928.66
2015-16	32808.64	22578.60	10230.04
2016-17	33696.83	25643.40	8053.43
2017-18	38897.21	24890.90	14006.31
2018-19	39203.53	20920.34	18283.19
2019-20	35600.47	21859.99	13740.48
2020-21	41895.68	21652.05	20243.63
2021-22	50240.21	32422.30	17817.91
Apr-Dec 21	36155.42	24071.55	12083.87
Apr-Dec 22	38997.92	27770.64	11227.28

#### कृषि-आँकड़े:

- अप्रैल-दिसंबर 2022 में कृषि निर्यात मूल्य अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 7.9% अधिक (39 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा।
- हालाँकि अप्रैल-दिसंबर 2021 के 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2022 में आयात 15.4% (27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) बढा है।
- नतीजतन, कृषि व्यापार अधिशेष में और कमी आई है।
- चावल और चीनी भारत के कृषि-निर्यात विकास में दो बड़े योगदानकर्त्ता हैं।
  - चावल: भारत ने वर्ष 2021-2022 में 9.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का 21.21 मिलियन टन चावल का रिकॉर्ड निर्यात किया।
    - 🙎 इसमें 172.6 लाख टन गैर-बासमती और 39.5 लाख टन बासमती चावल शामिल है।
  - ♦ चीनी: पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में चीनी निर्यात 4.60 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहँच गया।
    - 🗷 इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल-दिसंबर 2021 के 2.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अप्रैल-दिसंबर 2022 में 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में 43.6% की वृद्धि देखी गई है।
- हालाँकि मसाले, गेहूँ, भैंस का मांस आदि जैसी कुछ वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई है।

#### आयात के बारे में:

- वनस्पति तेल:
  - सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, भारत का कुल खाद्य तेल आयात वर्ष 2020-21 के 13.13 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 (नवंबर-अक्तूबर) में 14.03 मिलियन टन हो गया तथा नवंबर-दिसंबर 2021 में 2.36 मिलियन टन से 30.9% बढकर नवंबर-दिसंबर 2022 में 3.08 मिलियन टन हो गया।

#### कपास:

- 💠 भारत कपास के शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक बन गया है।
- अप्रैल-दिसंबर 2022 में निर्यात घटकर 51.204 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया (अप्रैल-दिसंबर 2021 के 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर से) तथा आयात भी इसी अवधि में 41.459 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

#### काजु:

💠 अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान आयात 64.6 प्रतिशत बढ़कर 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो अप्रैल-दिसंबर 2021 में 996.49 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबिक इसी अवधि के लिये काजू उत्पादों का निर्यात 344.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 259.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

## भारत का कृषि प्रदर्शन तथा अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में संबंध:

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का खाद्य मूल्य सूचकांक- जिसका आधार मूल्य वर्ष वर्ष 2014-16 की अविध के लिये 100 अंक है, वर्ष 2012-13 में औसतन 122.5 अंक और वर्ष 2013-14 में 119.1 अंक था।
  - 💠 ये ऐसे वर्ष थे जब भारत का कृषि निर्यात 42-43 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- वित्त वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में सेंसेक्स में 90-95 अंकों की गिरावट के कारण निर्यात 33-34 अरब डॉलर तक कम हो गया।



- युक्रेन पर रूसी आक्रमण के ठीक पश्चात् मार्च 2022 में FAO सूचकांक 159.7 अंक पर पहुँच गया। तब से यह हर माह कम ही हो रहा है, जनवरी 2023 के लिये 131.2 अंकों की नवीनतम रीडिंग सितंबर 2021 के 129.2 अंकों के बाद सबसे कम है।
  - ♦ निर्यात में सामान्य मंदी से अधिक, आयात में वृद्धि चिंता का विषय होना चाहिये।
- पूर्व सहसंबंध के अनुसार, जब सूचकांक उच्च था, तब निर्यात अधिक था और जब यह कम था, तो निर्यात भी कम था। वर्तमान में सूचकांक गिर रहा है, जिससे भारत के कृषि निर्यात में मंदी एवं आयात में वृद्धि हो सकती है।
- इस स्थिति में नीति निर्माताओं का ध्यान भी उपभोक्ता समर्थक (निर्यात पर प्रतिबंध लगाने/प्रतिबंधित करने की सीमा तक) से उत्पादक समर्थक (बेलगाम आयात के खिलाफ टैरिफ सुरक्षा प्रदान करना) की तरफ स्थानांतरित करना पड़ सकता है।

# प्रयोगशाला निर्मित हीरे

#### चर्चा में क्यों ?

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में प्रयोगशाला निर्मित हीरों (LGD) पर विशेष ध्यान दिया है।

न्यूयॉर्क में एक जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को वर्ष 1954 में दुनिया के पहले प्रयोगशाला निर्मित हीरे के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।

## प्रयोगशाला निर्मित हीरे:

- परिचय:
  - ♦ LGD प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के विपरीत प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं। हालाँकि दोनों की रासायनिक संरचना और अन्य भौतिक एवं ऑप्टिकल गुण समान होते हैं।
  - प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं; वे तब बनते हैं जब पृथ्वी के भीतर दफन कार्बन अत्यधिक गर्मी और दबाव के संपर्क में आता है।
- उत्पादन:
  - वे ज्यादातर दो प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं, उच्च दबाव, उच्च तापमान (HPHT) विधि या रासायनिक वाष्प जमाव (CVD) विधि।
  - HPHT और CVD दोनों तरीकों से कृत्रिम रूप से निर्मित हीरे में एक बीज, दूसरे हीरे के टुकड़े का उपयोग होता है।
    - HPHT प्रक्रिया में शुद्ध ग्रेफाइट कार्बन के साथ बीज को लगभग 1,500 डिग्री सेल्सियस के उच्च दबाव और तापमान के संपर्क में लाया जाता है।
    - 🙎 कार्बन से भरपूर गैस से भरे सीलबंद कक्ष के अंदर CVD तकनीक का उपयोग करके बीज को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गैस के बीज से जुड़ने के साथ-साथ हीरा धीरे-धीरे बनता जाता है।

#### अनुप्रयोग:

- औद्योगिक उपयोगिता के कारण इन्हें मशीनरी और उपकरणों में उपयोग किया जाता है तथा उनकी मज़बूती एवं कठोरता उन्हें कटर के रूप में उपयोगी बनाती है।
- उच्च शक्ति वाले लेजर डायोड, लेजर सरणियाँ और उच्च क्षमता वाले ट्रांजिस्टर के लिये हीट स्प्रेडर के रूप में शुद्ध सिंथेटिक हीरे का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है।
- महत्त्व:
  - ♦ प्रयोगशाला निर्मित हीरे का पर्यावरणीय फुटप्रिंट (Environmental Footprint) प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे की तुलना में बहुत कम होता है।

- ♦ पर्यावरण के प्रति सचेत LGD निर्माता, डायमंड फाउंड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार, विकसित किये जाने वाले हीरे की तुलना में प्राकृतिक हीरा प्राप्त करने में दस गुना अधिक ऊर्जा लगती
- ओपन-पिट खनन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरों के खनन के सबसे आम तरीकों में से एक है, जिसमें इन कीमती पत्थरों को निकालने हेतु मृदा और चट्टान में खनन शामिल है।

#### भारत के हीरा उद्योग का परिदृश्य:

- भारत हीरों के लिये दुनिया का सबसे बडा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र है, जो वैश्विक स्तर पर पॉलिश किये गए हीरों के निर्माण का 90% से अधिक हिस्सा है। इसके लिये उच्च कुशल श्रम की आसान उपलब्धता, अत्याधुनिक तकनीक एवं कम लागत जैसे कारक आवश्यक है।
  - 💠 गुजरात राज्य का सूरत, हीरा निर्माण का वैश्विक केंद्र है।
  - 💠 इन कटे और पॉलिश किये गए हीरों हेतु अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें चीन दूसरे नंबर पर है।
- दुनिया के कुल हीरे के निर्यात में भारत 19% का योगदान करता है। 0
- संयुक्त अरब अमीरात भारतीय सोने के आभूषणों का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है, जो दक्षिण एशियाई देश के आभूषण निर्यात के 75% से अधिक है।
- नवंबर 2022 में भारत का रत्न और आभूषण का कुल निर्यात 2.43 0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि एक वर्ष पहले की इसी अवधि की तुलना में 2.05% अधिक है।

# वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: IMF

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) रिपोर्ट जारी की है, जिसने वर्ष 2023 के लिये वैश्विक विकास के पूर्वानुमान को अद्यतन किया है।

## प्रमुख बिंदु

- वैश्विक विकास में कमी:
  - वैश्विक विकास जो वर्ष 2022 में 3.4% अनुमानित था, अब वर्ष 2023 में 2.9% तक गिरावट के बाद वर्ष 2024 में 3.1% तक बढ़ने का अनुमान है।
  - ♦ हालाँकि IMF प्रभावी रूप से वैश्विक मंदी की संभवना को नकारता है।
  - ♦ वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) या प्रति व्यक्ति वैश्विक सकल घरेल

- उत्पाद में नकारात्मक वृद्धि अपेक्षित नहीं है जो अक्सर वैश्विक मंदी होने पर देखी जाती है।
- 💠 हालाँकि यह वर्ष 2024 में गति पकडने से पहले वर्ष 2023 में वैश्विक विकास की उम्मीद करता है।
- मुद्रास्फीति में कमी:
  - मुद्रास्फीति-विस्फीति:
    - 🗷 वर्ष 2022 में मुद्रास्फीति चरम पर थी, जबिक अवस्फीति धीमी होगी और यह वर्ष 2023 और 2024 तक रहेगी।
  - हेडलाइन मुद्रास्फीतिः
    - 🗷 लगभग 84% देशों में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में हेडलाइन (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है।
  - वैश्विक मुद्रास्फीतिः
    - 🛘 वैश्विक मुद्रास्फीति वर्ष 2022 के 8.8% (वार्षिक औसत) से गिरकर वर्ष 2023 में 6.6% और वर्ष 2024 में 4.3% रहने की संभावना है, जो महामारी पूर्व (2017-19) लगभग 3.5% के स्तर से ऊपर थी।
  - मूल्य वृद्धि में कमी:
    - मृल्य वृद्धि दो मुख्य कारणों से धीमी हो रही है,
    - प्र पहला, विश्व भर में मौद्रिक सख्ती- उच्च ब्याज दरें वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मांग को कम करती हैं और बदले में मुद्रास्फीति को धीमा कर देती हैं।
  - 💠 दूसरा, लड़खड़ाती मांग के मद्देनज़र विभिन्न वस्तुओं- ईंधन और गैर-ईंधन दोनों की कीमतें अपने हालिया उच्च स्तर से नीचे आ गई हैं।
  - 💠 वर्ष 2023 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 4.6% रहने की संभावना है, जबिक उभरती अर्थव्यवस्थाओं को 8.1% की मुद्रास्फीति का सामना करना पडेगा।
- भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा:
  - 💠 वर्ष 2023 और 2024 में भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा।
  - भारत में विकास दर वर्ष 2022 के 6.8% से घटकर वर्ष 2023 में 6.1% हो जाएगी, जो बाहरी चुनौतियों के बावजूद लचीली घरेलू मांग के साथ वर्ष 2024 में 6.8% तक बढ़ेगी।

## चीनी निर्यात

#### चर्चा में क्यों ?

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के अनुसार, भारत में चीनी मिलों ने 55 लाख टन चीनी के निर्यात हेतु अनुबंध किया है।

सरकार ने चीनी मिलों को विपणन वर्ष 2022-23 (अक्तूबर-सितंबर) में मई तक 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी है।

#### भारत में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति:

- परिचय:
  - 💠 चीनी उद्योग एक महत्त्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है।
  - ♦ वर्ष 2021-22 (अक्तूबर-सितंबर) में भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता तथा विश्व के दूसरे सबसे बडे निर्यातक के रूप में उभरा है।
- गन्ने की वृद्धि के लिये भौगोलिक स्थितियाँ:
  - ♦ तापमान: गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 °C के मध्य।
  - वर्षा: लगभग 75-100 सेमी.।
  - 💠 मृदा का प्रकार: गहरी समृद्ध दोमट मृदा।
  - 💠 शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र> उत्तर प्रदेश> कर्नाटक।
- चीनी उद्योग के लिये विकास उत्प्रेरक:
  - ♦ प्रभावोत्पादक चीनी अविध (सितंबर-अक्तूबर): इस अविध के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद. गन्ने के बकाये का भुगतान और इथेनॉल उत्पादन सभी के रिकॉर्ड बने थे।
  - उच्च निर्यात: बिना किसी वित्तीय सहायता के निर्यात लगभग 109.8 LMT था तथा वर्ष 2021-22 में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की।
  - भारत सरकार की नीतिगत पहल: पिछले 5 वर्षों में उचित समय पर की गई सरकारी पहलों ने उन्हें वर्ष 2018-19 में वित्तीय संकट से निकालकर वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहँचा दिया है।
    - 🗷 इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करना: सरकार ने चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने एवं अतिरिक्त चीनी का निर्यात करने के लिये चीनी मिलों को प्रोत्साहित किया है ताकि मिलों के संचालन को जारी रखने के लिये उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति हो।
    - पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण (Ethanol Blending with Petrol) कार्यक्रमः जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, वर्ष 2025 तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत 20% इथेनॉल मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करती है।

- - प्र यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है।

# ओपन मार्केट सेल स्कीम

#### चर्चा में क्यों ?

भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India-FCI) ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत विभिन्न मार्गों से सेंट्रल पुल स्टॉक से 30 LMT गेहूँ को बाजार में उतारेगा।

 ई-नीलामी के बिना राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी योजनाओं के लिये भी गेहूँ की पेशकश की जाएगी।

## ओपन मार्केट सेल स्कीम ( OMSS ):

- FCI खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने हेतु समय-समय पर खुले बाजार में ई-नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूँ और चावल के अधिशेष स्टॉक को बेचता है।
- OMSS का उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा धारित गेहूँ और चावल के अधिशेष स्टॉक का निपटान करना तथा खुले बाजार में गेहूँ के मूल्य को विनियमित करना है।
- FCI गेहूँ की ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) के प्लेटफॉर्म पर साप्ताहिक नीलामी आयोजित करता है।
  - NCDEX भारत में एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न कृषि और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिये मंच प्रदान करता है।

#### भारतीय खाद्य निगमः

- FCI एक सरकारी स्वामित्त्व वाला निगम है जो भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत पूरे देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।
- FCI खाद्य संबंधी कमी या संकट के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को भी बनाए रखता है।

- FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पूरे देश में खाद्यान्न वितरण हेत् उत्तरदायी है।
- ⇒ FCI ई-नीलामी भी आयोजित करता है जो कि अधिशेष खाद्यान्न से निपटने के तरीकों में से एक है।

# सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट: द इंडिया स्टोरी

#### चर्चा में क्यों?

ऑक्सफैम की रिपोर्ट "सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी" के अनुसार, भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबिक एक-साथ वर्ष 2012 और 2021 के दौरान नीचे की आधी आबादी की संपत्ति में हिस्सेदारी मात्र 3% रही।

- ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने दाबोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन भारत के संदर्भ में अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट भी जारी की।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शीर्ष 10 सबसे धनी व्यक्तियों पर 5% कर लगाने से बच्चों को स्कूल में पुन: नामांकित करने के लिये पर्याप्त धन मिल सकता है।

#### प्रमुख बिंदु

- लेंगिक असमानताः
  - रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि पुरुष श्रमिकों द्वारा अर्जित प्रति 1 रुपए के मामले में महिला श्रमिकों को केवल 63 पैसे मिलते हैं।
  - सामाजिक-आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति वाले लोगों की तुलना में वर्ष 2018 और 2019 में अनुसूचित जाति और ग्रामीण मजदूरों की हिस्सेदारी क्रमश: 55% और 50% ही रही।
- 🕽 🛮 सामाजिक असमानता:
  - ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार, सिर्फ सबसे अमीर लोगों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण देश में हाशिये पर रहने वाले समुदाय जैसे- दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएँ और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक पीडित हैं।
  - भारत में अमीरों की तुलना में गरीब असमान रूप से उच्च करों का भुगतान कर रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं।
- असमानता कम करने के लिये सुझाए गए उपाय:
  - असमानता को कम करने और सामाजिक कार्यक्रमों के लिये राजस्व की व्यवस्था करने के लिये विरासत, संपत्ति और भूमि करों के साथ-साथ शुद्ध संपत्ति पर करों का लागू किया जाना।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिकल्पित वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र के बजटीय आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक करना।
- शिक्षा के लिये बजटीय आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 6%
   के वैश्विक बेंचमार्क/मानदंड तक बढ़ाना।
- ऑक्सफैम ने इन मुद्दों के हल के रूप में अमीरों पर करों में वृद्धि करने का तर्क दिया, एकमुश्त कर के कार्यान्वयन की व्यवस्था हो और एक न्युनतम कर दर का निर्धारण भी हो।
- ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने उन खाद्य कंपिनयों का आह्वान किया है जो मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण अधिक मुनाफा कमा रही हैं, उन्हें अप्रत्याशित करों (विंडफॉल टैक्स) का सामना करना पडेगा।
  - इसके पीछे विचार यह है कि इन कंपनियों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से लाभ हुआ है तथा उन्हें गरीबी और असमानता को दूर करने में मदद के लिये उचित योगदान देना चाहिये।
  - यह उपाय गरीबी और असमानता को कम करने में मदद करने वाले सामाजिक कार्यक्रमों का समर्थन करने हेतु सरकारों के लिये राजस्व उत्पन्न कर सकता है।
  - पुर्तगाल ने सुपरमार्केट तथा हाइपरमार्केट शृंखला सिहत ऊर्जा कंपनियों एवं प्रमुख खाद्य खुदरा विक्रेताओं दोनों पर अप्रत्याशित कर पेश किये।

#### विंडफॉल टैक्स:

- विंडफॉल टैक्स/अप्रत्याशित कर अप्रत्याशित या असाधारण लाभ पर लगाए गए कर हैं, जो कि आर्थिक संकट, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय प्राप्त किये गए हैं।
- सरकारें आमतौर पर ऐसे लाभ पर कर की सामान्य दरों के अलावा पूर्वव्यापी रूप से एक बार कर लगाती हैं, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।
- एक क्षेत्र जहाँ इस तरह के करों पर नियमित रूप से चर्चा की गई है, वह तेल बाजार है, जहाँ मूल्यों में उतार-चढ़ाव उद्योग को अस्थिर या अनियमित मुनाफे की ओर ले जाता है।

## ऑक्सफैम इंटरनेशनल:

- ऑक्सफैम इंटरनेशनल 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक संघ है जो 90 से अधिक देशों में भागीदारों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- इस मिशन का उद्देश्य गरीबी उत्पन्न करने वाले अन्याय को समाप्त करना है।
- ऑक्सफैम लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और विकसित बनाने के लिये व्यावहारिक एवं अभिनव माध्यमों से कार्य करता है।

- संकट आने पर वे जीवन का बचाव और आजीविका के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं।
- वे अभियान चलाते हैं तािक गरीबों की आवाज उनस्थानीय और वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करे जो उन्हें प्रभावित करते हैं।

# चलन में मौजूद मुद्रा

#### चर्चा में क्यों

वर्ष 2016 में सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा के लगभग छह वर्ष और दो महीने बाद चलन में मौजूद मुद्रा एक नई ऊँचाई (विमुद्रीकरण की घोषणा से पहले के दिनों की तुलना में 74% की वृद्धि) पर है।

- चलन में मौजूद मुद्रा की कुल राशि में से बैंक नकदी घटाने के बाद जनता के पास मुद्रा की मात्रा निर्धारित की जाती है।
- भले ही सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने "कैशलेस सोसाइटी" के लिये अभियान चलाया, डिजीटल भुगतान एवं विभिन्न लेन-देन में नकदी के उपयोग पर सीमाएँ भी निर्धारित कीं परंतु नकदी की मात्रा में वृद्धि हो ही रही है।

## चलन में मुद्राः

- चलन में मौजूद मुद्रा से तात्पर्य एक देश के भीतर उस नकदी या मुद्रा से है जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच लेन-देन करने के लिये भौतिक रूप से उपयोग की जाती है।
- चलन में मौजूद मुद्रा देश की मुद्रा आपूर्ति का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- केंद्रीय बैंकों के मौद्रिक प्राधिकरण चलन में भौतिक मुद्रा (physical currency) की मात्रा पर नज़र रखते हैं क्योंकि यह सबसे अधिक तरल संपत्तियों में से एक का प्रतिनिधित्त्व करती है।
- चलन में मौजूद मुद्रा के अंतर्गत नोट, रुपए के सिक्के और छोटे सिक्के शामिल हैं।
- करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। सिक्कों को जारी करने का प्राधिकार भारत सरकार के पास है और मांग के आधार पर यह रिज़र्व बैंक को सिक्कों की आपूर्ति करती है।

## मुद्रा आपूर्तिः

- यह ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा का कुल स्टॉक मुद्रा की कुल आपूर्ति से भिन्न होता है।
  - मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा के कुल भंडार का केवल वह भाग है जो किसी समय विशेष पर जनता के पास होती है।
- चलन में जो धन शामिल होता है उसमें मुद्रित नोट, जमा खातों में धन और अन्य तरल संपत्तियाँ होती हैं।

- आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के चार वैकल्पिक उपायों के लिये आँकड़े
   प्रकाशित करता है, अर्थात् M1, M2, M3 और M4।
  - $\rightarrow$  M1 = CU + DD
  - ♦ M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा
  - ♦ M3 = M1 + वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध साविध जमा
  - M4 = M3 + डाकघर में कुल जमा (सावधि जमा+आवर्ती जमा) (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोडकर)
- CU जनता द्वारा धारित मुद्रा (नोट+सिक्के) है और DD वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा है।
- 'नेट' शब्द का तात्पर्य है कि बैंकों द्वारा रखी गई जनता की जमा राशि
   को ही मुद्रा आपूर्ति मं। शामिल किया जाना है।
  - जब एक वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों में इंटरबैंक डिपॉजिट रखता है, तो इसे मुद्रा की आपूर्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है।
- M1 और M2 को संकुचित मनी (नैरो मनी) कहा जाता है। M3 और M4 को विस्तृत मनी (ब्रॉड मनी) के रूप में जाना जाता है।
- ये श्रेणियाँ तरलता के घटते क्रम में हैं।
  - ♦ M1 लेन-देन के लिये सबसे अधिक तरल और आसान है, जबिक M4 सबसे कम तरल है।
  - M3 पैसे की आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। इसे कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है।

## निगम कर

#### चर्चा में क्यों?

वर्ष 2021-22 में दो वर्ष के अंतराल के बाद निगम कर (Corporate Tax) संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% से अधिक रहा।

- यह वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि से प्रेरित भारतीय उद्योग जगत की लाभप्रदता में समग्र सुधार को दर्शाता है।
- हालाँकि निगम कर संग्रह अभी भी वर्ष 2018-19 में दर्ज GDP के 3.51% के अपने पाँच वर्ष के उच्च स्तर से कम है।

#### निगम कर:

- निगम कर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा देय है।
- निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या कंपनी के संचालन से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है।

यह कर किसी निगम के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है, जिसकी गणना उक्त निगम के कुल राजस्व से बेचे गए उत्पादों की लागत, परिचालन व्यय और मूल्यहास जैसे स्वीकार्य खर्चों को घटाकर की जाती है।

#### निगम कर का महत्त्व:

- निगम कर किसी भी सरकार के लिये राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं जैसे-स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों तथा रक्षा क्षेत्र के वित्तपोषण में मदद मिलती है।
- निगम कर धन के पुनर्वितरण और आय असमानता को दूर करने में भी भूमिका निभाता है, क्योंकि यह अधिक लाभकारी निगमों पर अधिक कर लगाता है।
- इसके अलावा, निगम कर के अन्य आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये एक उच्च निगम कर दर कम कर दरों वाले क्षत्रों की तुलना में किसी देश या क्षेत्र को निवेश के संदर्भ कम आकर्षक बना सकती है, जो उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धा को प्रभावित कर सकती है।
- निगम कर का फर्मों के स्थान और प्रकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है जो एक अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि निगम कर के आधार पर एक विशिष्ट क्षेत्र में निवेश करने की अधिक या कम संभावना हो सकती है।

# शहद मिशन और मीठी क्रांति

## चर्चा में क्यों ?

शहद मिशन के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा देश भर में 17,500 लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देने के बाद से अब तक 1,75000 मधुमक्खी पेटियों का वितरण किया जा चुका है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हिरयाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक 2021-22 में शीर्ष दस शहद उत्पादक राज्य थे।

#### शहद मिशन:

- 🗅 इसे वर्ष 2017 में 'मीठी क्रांति' के अनुरूप लॉन्च किया गया था।
- मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत
   KVIC किसानों या मधुमक्खी पालकों को प्रदान करता है:
  - मधुमक्खी कालोनियों की निगरानी के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण।

- सभी मौसमों में मधुमक्खी कालोनियों के प्रबंधन के साथ-साथ मधुमक्खी के शत्रुओं और रोगों की पहचान और प्रबंधन।
- 💠 मधुमक्खी पालन उपकरण से परिचित कराना।
- शहद निष्कर्षण एवं मोम शोधन।

#### मीठी क्रांति

- परिचय:
  - यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसे 'मधुमक्खी पालन' के नाम से जाना जाता है।
    - 🗷 मीठी क्रांति बुस्टर शॉट प्रदान करने के लिये सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना) को आत्मनिर्भर भारत योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया।

#### उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तेज़ी लाना है।
  - 🗷 अच्छी गुणवत्ता वाले शहद की मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक उत्पाद माना जाता है।
  - 🗷 अन्य मधुमक्खी पालन उत्पादों जैसे- रॉयल जेली, मोम, पराग, आदि का भी विभिन्न क्षेत्रों जैसे- फार्मास्यूटिकल्स, भोजन, पेय, सौंदर्य और अन्य में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

#### महत्त्व:

- इस मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित करेगा, बीमारियों को रोकेगा या मधुमक्खी कालोनियों के नुकसान को रोकेगा तथा मधुमक्खी पालन उत्पादों की गुणवत्ता के साथ अधिक मात्रा प्रदान करेगा।
  - 🗷 खेती के तरीकों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिये बेहतर गुणवत्ता वाला शहद व अन्य उत्पाद प्राप्त होंगे।
- मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है, जो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एक बड़े कारक के रूप में उभरा है।
  - मधुमक्खी पालन को बढ़ाने से किसानों की आय दोगुनी होगी, रोजगार पैदा होगा, खाद्य सुरक्षा और मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित होगा तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी।

#### खादी और ग्रामोद्योग आयोगः

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 'खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956' के तहत एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये योजनाएँ बनाना, उनका प्रचार-प्रसार करना तथा सुविधाएँ एवं सहायता प्रदान करना है।
- यह भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) के अंतर्गत आने वाली एक मुख्य संस्था है।

## बासमती चावल के लिये FSSAI मानक

#### चर्चा में क्यों?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) ने देश में पहली बार बासमती चावल की पहचान के लिये व्यापक मानक निर्दिष्ट किये हैं, जो 1 अगस्त, 2023 से लागू होंगे।

#### बासमती चावल की विशेषताएँ:

- बासमती की उत्पत्ति भारत (और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों) से हुई है: यह भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय की तलहटी में उगाई जाने वाली चावल की एक प्रीमियम किस्म है।
  - सार्वभौमिक रूप से इसे अपने लंबे एवं उभरे हुए दानों और अनुठी अंतर्निहित सुगंध एवं स्वाद के लिये जाना जाता है।
- इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है।
  - 💠 बासमती चावल उगाए जाने वाले विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की कृषि-जलवाय परिस्थितियों के साथ ही चावल की कटाई. प्रसंस्करण और परिपक्वता अवधि बासमती चावल की विशिष्टता में योगदान देते हैं।
- अपनी अनूठी गुणवत्तापूर्ण विशेषताओं के कारण बासमती चावल का घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से उपभोग किया जाता है और इसकी कुल आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी दो- तिहाई है।
  - ♦ प्रीमियम गुणवत्ता वाला चावल होने तथा गैर-बासमती किस्मों की तुलना में इसकी अधिक कीमत होने के कारण बासमती चावल में आर्थिक लाभ के लिये विभिन्न प्रकार की मिलावट की जाती है, जिसमें चावल की अन्य गैर-बासमती किस्मों का अघोषित मिश्रण शामिल हो सकता है।

#### बासमती चावल हेतु विनिर्दिष्ट मानकः

- मानकों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) प्रथम संशोधन विनियम, 2023 के तहत अधिसूचित किया गया है।
  - 💠 इसका उद्देश्य बासमती चावल के व्यापार में उचित कार्यप्रणाली को स्थापित करना और घरेलू एवं विश्व स्तर पर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है।
- मानक:
  - बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध की विशेषता:
    - 🗷 बासमती चावल में 2-एसिटाइल-1-पाइरोलाइन नामक रसायन की उपस्थिति के कारण एक अनुठी सुगंध और स्वाद होता है।
  - यह कृत्रिम रंग, चमक बढ़ाने वाले कारकों (पोलिशिंग एजेंट्स) और कृत्रिम सुगंध से मुक्त होना चाहिये।
  - इसके अलावा ये मानक बासमती चावल के पकने के बाद उसके औसत आकार और वृद्धि अनुपात, नमी की अधिकतम सीमा, एमाइलोज तत्त्व, यूरिक एसिड, क्षतिग्रस्त अनाज तथा अन्य गैर-बासमती चावल की आकस्मिक उपस्थिति आदि को भी निर्दिष्ट करते हैं।

# अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष

## चर्चा में क्यों?

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को 'जन आंदोलन' बनाने के साथ-साथ भारत को 'वैश्विक पोषक अनाज हब (Global Hub for Millets)' के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण को साझा किया है।

## अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष:

- परिचय:
  - 💠 वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष (International Year of Millets- IYM) मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है।
  - 💠 इसे संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया और इसका नेतृत्व भारत ने किया तथा 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया।
- उद्देश्य:
  - खाद्य सुरक्षा और पोषण में पोषक अनाज/बाजरा/मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।

- 💠 पोषक अनाज के टिकाऊ उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार के लिये हितधारकों को प्रेरित करना।
- उपर्युक्त दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अनुसंधान और विकास एवं विस्तार सेवाओं में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना।

#### पोषक अनाज/बाजरा/मोटे अनाज:

- परिचय:
  - पोषक अनाज एक सामूहिक शब्द है जो कई छोटे-बीज वाले फसलों को संदर्भित करता है, जिसकी खेती खाद्य फसल के रूप में मुख्य रूप से समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों व शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर की जाती
  - भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य फसलों में बाजरा रागी (फिंगर मिलेट), ज्वार (सोरघम), समा (छोटा बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा) और वरिगा (प्रोसो मिलेट) शामिल हैं।
    - 🗷 इन अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए और ये भोजन के लिये उगाए गए पहले पौधों में से थे।
  - लगभग 131 देशों में इसकी खेती की जाती है, यह एशिया और अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिये पारंपरिक भोजन है।
  - भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है।
    - 🗷 यह वैश्विक उत्पादन का 20% और एशिया के उत्पादन का 80% हिस्सा है।
- वैश्विक वितरण:
  - भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में बाजरा के सबसे बडे उत्पादक हैं, जिनका वैश्विक उत्पादन में 55% से अधिक की हिस्सेदारी है।
  - कई वर्षों तक भारत बाजरा का एक प्रमुख उत्पादक था। हालाँकि हाल के वर्षों में अफ्रीका में बाजरे के उत्पादन में प्रभावशाली रूप से वृद्धि हुई है।

#### महत्त्व:

- उच्च पोषण से युक्तः
  - 🗷 बाजरा अपने उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और लौह तत्त्व जैसे खनिजों के कारण गेहूँ एवं चावल की तुलना में कम खर्चीला तथा पौष्टिक रूप से बेहतर है।
  - 🗷 बाजरा कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। उदाहरण के लिये रागी को सभी अनाजों में सबसे अधिक कैल्शियम स्रोत के रूप में जाना जाता है।
  - बाजरा पोषण सुरक्षा प्रदान करता है और विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं के बीच पोषण की कमी के खिलाफ

ढाल के रूप में कार्य करता है। इसमें उपस्थित उच्च लौह तत्त्व भारत में महिलाओं की प्रजनन अवस्था के दौरान तथा शिशुओं में एनीमिया के उच्च प्रसार को रोकने में सक्षम हैं।

- ग्लुटेन मुक्त तथा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स
  - 🗷 बाजरा जीवनशैली की समस्याओं जैसे कि मोटापा और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद करता है क्योंकि वे ग्लूटेन मुक्त होते हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है (खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की एक सापेक्ष रैंकिंग इस आधार पर होती है कि वे रक्त में शर्करा के स्तर को किस प्रकार प्रभावित करती हैं)।
- उन्नत उपज वाली फसल:
  - 🗷 बाजरा प्रकाश-संवेदी होता है (फूलों के लिये विशिष्ट प्रकाश काल की आवश्यकता नहीं होती) तथा जलवायू परिवर्तन के लिये सवेदनशील भी है। बाजरा बहुत कम या बिना किसी बाहरी रखरखाव के खराब मिट्टी में भी बढ़ सकता है।
  - 🙎 बाजरा पानी की कम खपत करता है तथा सूखे की स्थिति में असिंचित परिस्थितियों में बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बढने में सक्षम होता है।
  - 🙎 बाजरा में कम कार्बन और वाटर फुटप्रिंट होते हैं (चावल के पौधों को उगाने के लिये बाजरे की तुलना में कम-से-कम 3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है)।

#### सरकार द्वारा की गई संबंधित पहलें:

- पोषण सुरक्षा के लिये गहन बाजरा संवर्द्धन (INSIMP) के माध्यम से पहल:
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धिः सरकार ने बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जो किसानों के लिये एक बड़े मूल्य प्रोत्साहन के रूप में है।
  - इसके अलावा उपज के लिये स्थिर बाजार प्रदान करने हेत् सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मोटे अनाज को शामिल किया है।
  - इनपुट सहायता: सरकार ने किसानों की सहायता हेतु बीज किट का प्रावधान शुरू किया है तथा किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से मुल्य शृंखला का निर्माण किया है और बाजरा की बिक्री का समर्थन किया है।

# डीप टेक स्टार्टअप्स

#### चर्चा में क्यों ?

सरकार डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करेगी।

#### डीप टेक:

- परिचय:
  - 💠 डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप व्यवसायों के एक वर्ग को संदर्भित करता है जो मूर्त इंजीनियरिंग नवाचार या वैज्ञानिक खोजों और अग्रिमों के आधार पर नवाचार को बढावा देता है।
  - सामान्यतः ऐसे स्टार्टअप कृषि, लाइफ साइंस, रसायन विज्ञान, एयरोस्पेस और हरित ऊर्जा पर काम करते हैं. हालाँकि इन तक ही सीमित नहीं हैं।
- डीप टेक की विशेषताएँ:
  - 💠 प्रभाव: डीप टेक नवाचार बहुत मौलिक हैं और मौजूदा बाजार को बाधित करते हैं या एक नया विकास करते हैं। डीप टेक पर आधारित नवाचार अक्सर जीवन. अर्थव्यवस्था और समाज में व्यापक परिवर्तन लाते हैं।
  - समयावधि और स्तर: प्रौद्योगिकी को विकसित करने और बाजार में उपलब्धता के लिये डीप टेक की आवश्यक समयावधि सतही प्रौद्योगिकी विकास (जैसे मोबाइल एप एवं वेबसाइट) से कहीं अधिक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित होने में दशकों लग गए और यह अभी भी पूर्ण नहीं है।
  - पूंजी: डीप टेक को अक्सर अनुसंधान और विकास, प्रोटोटाइप, परिकल्पना को मान्य करने एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिये प्रारंभिक चरणों में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

# केरल के पाँच कृषि उत्पादों को जीआई दर्जा

## चर्चा में क्यों ?

केरल के पाँच कृषि उत्पादों- अट्टापडी अट्ट्कोम्बु अवारा, अट्टापडी थुवारा, ओनाटुकारा एलु, कंथल्लूर-वट्टावदा वेलुथुल्ली और कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी को भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा प्रदान किया गया है।

असम के गमोसा (पारंपरिक कपडा), महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज, लद्दाख के रक्तसे कारपो खुबानी और तेलंगाना के तंद्र रेडग्राम को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है।

## नवीनतम GI के बारे में मुख्य बिंदु:

- अट्टापडी अट्ट्कोम्बु अवारा (बीन्स):
  - ♦ जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है, यह बकरी के सींग की तरह घुमावदार होती है।
  - ♦ अन्य डोलिचोस बीन्स की तुलना में इसकी उच्च एंथोसायिनन सामग्री तने और फलों में बैंगनी रंग प्रदान करती है।

- 🗷 एंथोसायनिन अपने एंटीडायबिटिक गुणों के साथ हृदय रोगों के खिलाफ मददगार है।
- अट्टापडी अट्कोम्ब् अवारा की उच्च फेनोलिक सामग्री कीट और रोगों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे फसल जैविक खेती के लिये उपयुक्त हो जाती है।
- अट्टापडी थुवारा (लाल चना):
  - इसके बीज सफेद आवरण वाले होते हैं।
  - 💠 अन्य लाल चने की तुलना में अट्टापडी थुवारा के बीज बड़े होते हैं और बीज का वजन अधिक होता है।
- ओनाटुकारा एलु (तिल):
  - ओनाटुकारा एलु और इसका तेल अपने अनोखे स्वास्थ्य लाभों के लिये प्रसिद्ध है।
  - ओनाटुकारा एलु में अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री मुक्त मूलकों से लड़ने में मदद करती है, जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं।
  - ♦ साथ ही असंतृप्त वसा की उच्च सामग्री इसे हृदय रोगियों के लिये फायदेमंद बनाती है।
- कंथलूर-वट्टवडा वेलुथुल्ली (लहसुन):
  - अन्य क्षेत्रों में उत्पादित लहसुन की तुलना में इस लहसुन में सल्फाइड, फ्लेवोनोइड्स, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह आवश्यक तेल से भी भरपुर होता है।
  - यह एलिसिन से भरपूर होता है, जो माइक्रोबियल संक्रमण, ब्लड शुगर, कैंसर आदि के खिलाफ प्रभावी है।
- कोडुंगलूर पोट्टुवेलारी (स्नैपमेलन):
  - ♦ गर्मियों में काटे जाने वाले इस स्नैप तरबुज में विटामिन C की उच्च मात्रा होती है।
  - अन्य कुकुरबिट्स की तुलना में कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलारी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा की मात्रा जैसे पोषक तत्त्व भी अधिक होते हैं।

# समर्थ योजना

#### चर्चा में क्यों ?

वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के तहत विगत तीन वर्षों में 13,235 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है।

#### समर्थ योजनाः

- परिचय:
  - समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना (FYP) के लिये एकीकृत कौशल विकास योजना, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की निरंतरता में अनुमोदित किया गया है।

 विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प) का कार्यालय राष्ट्रीय हस्तिशिल्प विकास कार्यक्रम (NHDP) के घटक 'हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास' के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये समर्थ (SAMARTH) का कार्यान्वयन कर रहा है।

#### उद्देश्य:

- 💠 वस्त्र मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों/संगठनों के माध्यम से पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये संगठित वस्त्र एवं संबंधित क्षेत्रों में रोज़गार सुजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु मांग-आधारित रोजगार -उन्मख कौशल प्रदान करना।
- 💠 देश में समाज के सभी वर्गों को आजीविका प्रदान करना।

# ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

#### चर्चा में क्यों?

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) उन प्लेटफार्मों पर "कम शुल्क" अधिरोपित करेगा जो नेटवर्क के "रखरखाव और विकास" में योगदान देंगे।

यह नेटवर्क देश में दो सबसे बड़ी ई-कॉमर्स फर्मों यूएस-आधारित अमेज़न और घरेलू फ्लिपकार्ट जैसे निजी ई-कॉमर्स द्वारा नेटवर्क पर विक्रेताओं एवं लॉजिस्टिक्स भागीदारों से लिये जाने वाले अनिवार्य कमीशन को कम करने का प्रयास करेगा।

#### ONDC:

- परिचय:
  - यह वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department of Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा स्थापित एक ओपन ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल है।
  - ONDC के तहत यह परिकल्पना की गई है कि एक भागीदार ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये-अमेजन) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है।
  - वर्तमान में एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले लेन-देन के लिये खरीदारों और विक्रेताओं को एक ही एप पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिये किसी खरीदार को अमेजन (Amazon) पर किसी विक्रेता से उत्पाद खरीदने के लिये अमेजन के ही एप या वेबसाइट पर जाना होगा।

- ⊃ उद्देश्य:
  - ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण और विकेंद्रीकरण।
  - विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के साथ-साथ स्थानीय व्यवसायों के लिये समावेशिता और पहुँच।
  - 💠 उपभोक्ताओं के लिये विकल्पों और निर्भरता में वृद्धि।

#### ONDC के फायदेः

- सबके लिये एकसमान अवसर: ONDC सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिये एकसमान अवसर प्रदान करने और देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) तथा छोटे व्यापारियों के लिये डिजिटल बाज़ार तक पहुँच के विस्तार का इच्छुक है।
- प्रतिस्पर्द्धी और नवोन्मेषी पारितंत्रः ONDC रिटेल, फूड और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने तथा व्यवसायों को रूपांतरित करने के लिये दिग्गज प्लेटफॉर्मों के एकाधिकार को तोड़कर आपूर्तिकर्त्ताओं व उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा।
- उपभोक्ताओं के लिये चयन की स्वतंत्रता: उपभोक्ता संभावित रूप से किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा को एक साझा मंच पर खोज सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिये चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि होती है।
- तटस्थ और विनियमित प्लेटफॉर्म: ONDC ओपन-सोर्स कार्यप्रणाली पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने, खुले विनिर्देशों एवं नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करने तथा किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र रहने पर लक्षित है।
  - यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे ओपन सोर्स-आधार पर कैटलॉगिंग, वेंडर मैच और प्राइस डिस्कवरी के लिये प्रोटोकॉल तय करेगा।

# जीएनपीए अनुपात

## चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात, जो सितंबर 2022 में कम होकर सात वर्ष के निचले स्तर 5.0% पर आ गया, के सितंबर 2023 तक 4.9% तक सुधरने की उम्मीद है।

э हालाँकि यदि व्यापक आर्थिक वातावरण एक मध्यम या गंभीर तनाव परिदृश्य में बदलता है तो GNPA अनुपात क्रमश: 5.8% और 7.8% तक बढ सकता है।

## प्रमुख शब्दावली:

 GNPA: ये संपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जिन्होंने वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया था लेकिन ऋण नही चुकाया है।

- समिष्ट पर्यावरण (Macro-environment): यह संदर्भित करता है कि मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियाँ जिसमें कोई कंपनी या क्षेत्र संचालित होता है, किस प्रकार इनके प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं।
  - समिष्ट अर्थशास्त्र (मैक्रोइकोनॉमिक्स) निजी उद्योगों और बाजारों के विपरीत एक अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, खर्च और मूल्य स्तर से संबंधित होता है।
- NNPA: यह वह प्रावधान राशि है जो गैर-निष्पादित संपत्तियों से घटाने के बाद वसल की जाती है
- CRAR: पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR), जिसे CRAR के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और विश्व भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।
  - CAR बैंक द्वारा व्यक्त की गई उपलब्ध पूंजी का एक मापन है जो कि बैंक के जोखिम भारित क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है।
- CET1: इसमें इक्विटी इंस्ट्र्मेंट्स शामिल हैं और इसलिये शेयर की कीमतों का प्रदर्शन बैंकों के प्रदर्शन से संबंधित होता हैं। इनकी कोई परिपक्वता अविध नहीं होती है।
  - बेसल-III मानकों के अनुसार, बैंकों की नियामक पूंजी को टियर 1 और टियर 2 में बाँटा गया है, जबिक टियर 1 को कॉमन इिक्वटी टियर-1 (CET-1) और अतिरिक्त टियर-1 (Additional Tier1- AT-1) पूंजी में विभाजित किया गया है।

## गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ:

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट रुप में हैं अथवा मूलधन या ब्याज़ के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।
- किसी परिसंपत्ति के अनर्जक/गैर-निष्पादित रहने की अविध और बकाया ऋण एकत्र करने की क्षमता के आधार पर बैंकों को गैर-निष्पादित संपत्तियों को निम्निलिखित तीन समूहों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है:
  - सब-स्टैंडर्ड पिरसंपित्तयाँ: वह पिरसंपित्त जिसे 12 महीने से कम या उसके बराबर की अविध के लिये NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - संदिग्ध परिसंपत्तियाँ: वह परिसंपत्ति जो 12 महीने से अधिक की अविध के लिये गैर-निष्पादक रही है।
  - नुकसान वाली पिरसंपित्तयाँ: ये पिरसंपित्तयाँ बैंक, लेखा परीक्षक या निरीक्षक द्वारा पहचाने गए घाटे वाले ऋण हैं जिन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिये।

# मंदी और यील्ड वक्र

#### चर्चा में क्यों?

जैसे-जैसे नए साल के आगमन का समय नज़दीक आ रहा है दुनिया की कई प्रमुख शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ, विशेष रूप से सबसे बडी और प्रभावशाली संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यस्था मंदी का सामना कर रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेज़री यील्ड (अर्थव्यस्था के संदर्भ में उत्पादन के घटकों के आपूर्तिकर्ताओं को वापस मिलने वाला धन यील्ड/लब्धि/प्रतिफल कहलाता है।) का कम होना एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है कि अमेरिका मंदी की ओर बढ रहा है।

#### मंदी:

- मंदी में सामान्यत: रोजगार और समग्र मांग में कमी के साथ कम-से-कम दो लगातार तिमाहियों के लिये अनुबंधित अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन शामिल होता है।
- युएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च (NBER) अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, प्रसार और अवधि के आकलन के आधार पर यह निर्धारित करता है कि अर्थव्यवस्था मंदी में है या नहीं।
  - कभी-कभी अवधि दीर्घकालिक नहीं हो सकती है लेकिन गिरावट बहुत गंभीर हो सकती है क्योंकि ऐसा कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र हुआ है।
  - इसकी गंभीरता एवं प्रसार अपेक्षाकृत कम हो सकता है लेकिन मंदी लंबे समय तक रह सकती है जैसा कि आर्थिक संकट के मद्देनजर यूनाइटेड किंगडम में अपेक्षित है।

## संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्रेज़री:

- किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे सुरक्षित ऋण वे होते हैं जो सरकारों को दिये जाते हैं, ऐसी संस्थाएँ जो हमेशा बनी रहेंगी और जो सामान्यतः अपने ऋण पर चूक नहीं करती हैं।
- सरकारों को धन उधार लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि अक्सर उनका कर राजस्व उनके सभी खर्चों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता है।
- जिस साधन द्वारा सरकार बाजार से उधार लेती है उसे सरकारी बॉण्ड कहा जाता है।
- भारत में उन्हें जी-सेक कहा जाता है, ब्रिटेन में उन्हें गिल्ट कहा जाता है और अमेरिका में उन्हें ट्रेज़री कहा जाता है।

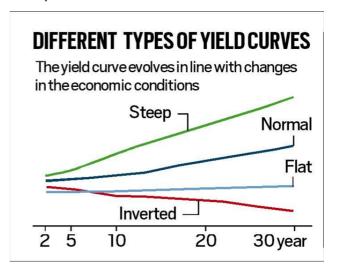
## राजकोष की लब्धि/यील्डः

बैंक ऋण जिसकी एक परिवर्तनीय ब्याज दर होती है, के विपरीत एक सरकारी बॉण्ड में एक निश्चित "कूपन" भुगतान होता है।

- नतीजतन, अमेरिकी सरकार 100 अमेरिकी डॉलर के अंकित मूल्य और 5 अमेरिकी डॉलर के कूपन भुगतान के साथ 10 साल के बॉण्ड को "फ्लोट" कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस बॉण्ड को खरीदते हैं और अमेरिकी सरकार को 100 अमेरिकी डॉलर उधार देते हैं, तो आपको अगले दस वर्षों के लिये प्रतिवर्ष 5 अमेरिकी डॉलर, साथ ही दस वर्षों के अंत में 100 अमेरिकी डॉलर की पूरी राशि प्राप्त होगी।
- लेकिन यदि किसी कारण से किसी ने इस बॉण्ड को किसी अन्य निवेशक को बेच दिया, तो जिस कीमत पर बॉण्ड बेचा जाता है, उसके आधार पर यील्ड बदल जाएगी। यदि कीमत में वृद्धि होती है और बॉण्ड को USD 110 में बेचा जाता है, तो यील्ड कम हो जाएगा क्योंकि वार्षिक रिटर्न (USD5) समान रहता है और यदि कीमत गिरती है, तो यील्ड बढ जाएगा।

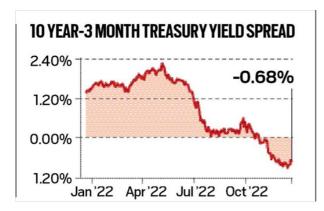
#### योल्ड वक्रः

- सरकारें 1 महीने से 30 वर्ष तक की अवधि के लिये उधार लेती हैं।
- आमतौर पर लंबी अवधि के लिये यील्ड अधिक होता है क्योंकि इसमें धन लंबे समय तक के लिये उधार दिया जाता है।
- यदि बॉण्ड के अलग-अलग कार्यकाल के लिये यील्ड को मापा जाता है, तो यह ऊपर की ओर ढाल वाला वक्र प्रदान करेगा।
- बाजार में उपलब्ध धन और अपेक्षित समग्र आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वक्र सपाट या सीधा हो सकता है। जब निवेशक अर्थव्यवस्था के बारे में उत्साहित महसूस करते हैं, तो वे दीर्घकालिक बॉण्ड से पैसा निकालते हैं और इसे शेयर बाजारों जैसे अल्पकालिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। जैसे-जैसे दीर्घकालिक बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं, उनका यील्ड बढता है और यील्ड वक्र बढ़ता जाता है।



## यील्ड व्युत्क्रमण (Yield inversion):

- यील्ड व्युत्क्रम तब होता है जब कम अवधि के बॉण्ड के लिये यील्ड लंबी अवधि के बॉण्ड पर यील्ड की तुलना में अधिक होता है। यदि निवेशकों को संदेह है कि अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ रही है, तो वे अल्पकालिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों (जैसे शेयर बाजार) से पैसा निकालेंगे और इसे दीर्घकालिक बॉण्ड में निवेश करेंगे। इससे दीर्घकालिक बॉण्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं और उनका यील्ड घट जाता है। यह प्रक्रिया पहले सपाट और अंतत: यील्ड व्युत्क्रमण की स्थिति होती है।
- यील्ड व्युत्क्रम लंबे समय से अमेरिका में मंदी का एक विश्वसनीय अनुमान प्रदान कर रहा है तथा अमेरिकी कोष में पिछले कुछ समय से यील्ड व्युत्क्रमण देखा जा रहा है।
- 10 वर्ष और 3 महीने के ट्रेज़री की यील्ड्स का प्रसार नकारात्मक देखा जा रहा है।



## भारत के लिये इसका महत्त्व:

- ब्याज दरें बढ़ने से रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर और भी मज़बूत हो सकता है। परिणामस्वरूप भारतीय आयात महँगा हो जाएगा तथा यह घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है।
- अमेरिका के उच्च यील्ड से भारत में आने वाले निवेशों से आयात-निर्यात में कुछ पुनर्संतुलन की स्थिति देखी जा सकती है।
- कमज़ोर रुपए के कारण भारतीय निर्यात को लाभ हो सकता है लेकिन मंदी भारतीय निर्यात की मांग को कम कर देगी।

# पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली- स्पर्श (System for Pension Administration Raksha-SPARSH), के हितधारकों से इसे उपयोगकर्त्ताओं हेत् और अधिक अनुकूल बनाने का आग्रह किया है।

वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना भी सेवा की समान अवधि (भले ही सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो) के लिये समान रैंक के सैन्य अधिकारियों को समान पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान करती है।

### स्पर्श (SPARSH) योजना

#### परिचय:

- 💠 यह रक्षा पेंशन की स्वीकृति एवं संवितरण के स्वचालन हेतु एक एकोकृत प्रणाली है।
- यह वेब-आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाह्य मध्यस्थ पर भरोसा किये बिना सीधे रक्षा पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन जमा करती है।
- पेंशनरों के लिये उनकी पेंशन संबंधी जानकारी को देखने. सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने और शिकायत दर्ज करने (यदि कोई हो) के लिये एक पेंशनभोगी पोर्टल उपलब्ध है।

#### उद्देश्य:

- ♦ स्पर्श (SPARSH) सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना करता है ताकि उन पेंशनभोगियों को अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके जो स्पर्श पोर्टल तक सीधे पहुँचने में असमर्थ हो सकते हैं।
- स्पर्श को रक्षा पेंशनरों को केंद्र में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पेंशन खाते के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी जानकारी प्रदान की जाएगी।
- इसका उद्देश्य पेंशन स्वीकृति और संवितरण प्रक्रिया में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना है जैसे कि-
  - साइलो (silos) में मौज़ूद विकेंद्रीकृत समाधान।
  - प्रसंस्करण में मैनुअल हस्तक्षेप।
  - पेंशनरों के प्रश्नों आदि के समाधान के लिये केंद्रीकृत सूचना का अभाव।

#### 0 लाभ:

- यह पेंशनरों को उनके अनुरोधों के त्विरत कार्यवाही और घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने के लिये सक्षम सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करता है, जिससे उनका अनुभव वास्तव में कागज रहित और परेशानी मुक्त हो जाता है।
- यह पेंशन शुरू होने की तारीख से अंतिम पात्र लाभार्थी को देय पेंशन की समाप्ति की तारीख तक पेंशनभोगी की घटनाओं और हकदारियों का पूरा इतिहास रखता है।

# सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने अब तक लगभग 39,000 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाओं के विकास को मंज़री दी है, लेकिन वास्तव में अभी तक केवल 25% ही अधिकृत हो सकी है।

इन सौर परियोजनाओं को 'सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु योजना' के तहत मंज़्री दी गई थी।

## सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेत् योजनाः

- परिचय:
  - यह योजना वर्ष 2014 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
  - इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के भीतर 20.000 मेगावाट क्षमता से अधिक सौर ऊर्जा की स्थापना को लक्षित करते हुए कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव था।
    - 🗷 योजना की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दी गई। इन पार्कों को वर्ष 2021-22 तक स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- क्रियान्वयन एजेंसी:
  - इसकी कार्यान्वयन एजेंसी सोलर पावर पार्क डेवलपर (Solar Power Park Developer- SPPD) है।
- विशेषताएँ:
  - 💠 योजना में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये आवश्यक बनियादी ढाँचा तैयार करने की दुष्टि से देश में विभिन्न स्थानों पर सौर पार्क स्थापित करने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करने की परिकल्पना की गई है।
  - सौर पार्क राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्यमियों के सहयोग से विकसित किये गए हैं।

## संबंधित पहलें:

- सौर पार्क योजनाः
  - ♦ सौर पार्क योजना कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट (MW) क्षमता वाले कई सोलर पार्क बनाने की योजना है।
- रूफटॉप सौर योजनाः
  - रूफटॉप सौर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना है।

- अटल ज्योति योजना (AJY):
  - अटल ज्योति योजना सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (SSL) प्रणाली की स्थापना के लिये शुरू की गई थी, जहाँ 50% से कम घरों में ग्रिड आधारित बिजली का उपयोग शामिल है (2011 की जनगणना के अनुसार)।
- राष्ट्रीय सौर मिशन:
  - यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है।
- सुष्टि योजनाः
  - भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये सोलर ट्रांसिफगरेशन ऑफ इंडिया (सिष्ट) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भारत और फ्राँस द्वारा सह-स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वितरण में वृद्धि के लिये एक सिक्रय तथा सदस्य-संचालित एवं सहयोगी मंच है।

# बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Horticulture Cluster Development Programme- CDP) के लिये एक बैठक आयोजित की गई थी।

- CDP के कार्यान्वयन की मदद से देश में बागवानी के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- बागवानी पौधे कृषि की वह शाखा है जो बगीचे की फसलों, सामान्यतः फलों. सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है।

#### बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रमः

- परिचय:
  - 💠 यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पहचान किये गए बागवानी क्लस्टर को विकसित करना है ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके।
  - 💠 बागवानी क्लस्टर लक्षित बागवानी फसलों का क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेंद्रण है।
- कार्यान्वयनः
  - ♦ इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

- अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों को भी 55 क्लस्टरों की सूची में शामिल किया जाएगा, जिनकी पहचान उनके फोकस/मुख्य फसलों के साथ की जाएगी।
  - इससे पहले पायलट चरण में इसे 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 12 क्लस्टरों में लागू किया गया था।

#### 🗅 उद्देश्य:

- CDP का उद्देश्य लिक्षत फसलों के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि करना और क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिये क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।
- भारतीय बागवानी क्षेत्र से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना जिसमें पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, रसद, विपणन और ब्रांडिंग शामिल हैं।
- भौगोलिक विशेषज्ञता (Geographical Specialisation) का लाभ उठाकर बागवानी क्लस्टरों के एकीकृत तथा बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देना।
- सरकार की अन्य पहलों जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष
   (AIF) के साथ अभिसरण करना।
- ♦ CDP के माध्यम से बागवानी क्षेत्र में निवेश बढाना।

#### महत्त्व:

क्लस्टर विकास कार्यक्रम में बागवानी उपज के कुशल और समय पर निकासी तथा परिवहन के लिये मल्टीमॉडल परिवहन के उपयोग के साथ अंतिम-मील कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) बनाकर संपूर्ण बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की एक बडी क्षमता है।

# रबी की फसलें

## चर्चा में क्यों ?

उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ की असामान्य कमी के कारण रबी की फसल खतरे में है।

 इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा और नमी की कमी है, जो सर्दियों के मौसम में गेहूँ उगाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

#### अन्य कारकः

- कई सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण अक्तूबर, 2022 के पहले दो हफ्तों में इस क्षेत्र में लगातार बारिश ने इस विरोधाभास को जन्म दिया।
- इसमें भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में जारी ला नीना और गर्म आर्कटिक क्षेत्र के संभावित प्रभावों ने भी योगदान दिया है।

- अक्तूबर की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ से अत्यधिक वर्षा होती है- इसके अतिरिक्त उष्णकिटबंधीय तूफान जो आर्किटक, भूमध्यसागरीय और पश्चिम एशियाई क्षेत्रों से नमी लाकर उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सर्दियों में वर्षा करवाते हैं।
- नवंबर, 2022 में पश्चिमी विक्षोभ की कमी और दिसंबर, 2022 में उनकी पूर्ण अनुपस्थिति के कारण अक्तूबर, 2022 की शुरुआत में कम वर्षा हुई।
- इन फसलों को लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान(अक्तूबर) बोया जाता है, जिन्हें रबी या सर्दियों की फसल कहा जाता है।
- इन फसलों की कटाई सामान्यत: गर्मी के मौसम में अप्रैल और मई के दौरान होती है।
- 🗅 इन फसलों पर वर्षा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 🗅 रबी की प्रमुख फसलें गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि हैं।
- बीजों के अंकुरण के लिये गर्म जलवायु और फसलों के विकास हेतु
   ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है।

#### भारत में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार:

🔾 खरीफ की फसलें :

रबी की फसल

- दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाने वाली फसलें खरीफ या मानसून की फसलें कहलाती हैं।
- ये फसलें मौसम की शुरुआत में मई के अंत से लेकर जून की शुरुआत तक बोई जाती हैं और अक्तूबर से शुरू होने वाली मानसुनी बारिश के बाद काटी जाती हैं।
- ये फसलें वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करती हैं।
- चावल, मक्का, दालें जैसे उड़द, मूंग दाल और बाजरा प्रमुख खरीफ फसलों में से हैं।
- इन्हें बढ़ने के लिये अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।
- 🗅 जायद फसलें:
  - बुवाई और कटाई: मार्च-जुलाई (रबी और खरीफ के बीच)
  - जायद की महत्त्वपूर्ण फसलों में मौसमी फल, सिब्जियाँ, चारा फसलें आदि शामिल हैं।

# GDP और GVA

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (2022-23 या वित्त वर्ष 2023) के लिये भारत के आर्थिक विकास के आँकड़े जारी किये।

- भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दूसरी तिमाही में 6.3% बढ़ा और इसी दौरान सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.6% वृद्धि हुई।
- विशेष रूप से भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा क्योंकि चीन ने जुलाई-सितंबर, 2022 में 3.9% की ही आर्थिक वृद्धि दर्ज की।
- GDP और GVA देश के आर्थिक प्रदर्शन का पता लगाने के दो मुख्य तरीके हैं।

#### GDP और GVA:

- GDP:
  - सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आम तौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है।
  - चार प्रमुख "GDP विकास के इंजन":
    - 🗷 भारतीयों द्वारा अपने निजी उपभोग (अर्थात् निजी अंतिम उपभोग व्यय या PFCE) के लिये खर्च किया गया सारा पैसा ।
    - 🗷 सरकार द्वारा अपने वर्तमान उपभोग पर खर्च किया गया सारा पैसा, जैसे कि वेतन [सरकारी अंतिम उपभोग व्यय या GFCE]
    - 🗷 अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देने के लिये निवेश किया गया सारा पैसा। इसमें फैक्टरियों में निवेश करने वाली व्यावसायिक फर्म या सडकों और पुलों का निर्माण करने वाली सरकारें शामिल हैं [सकल स्थायी पूंजीगत व्यय]।
    - 🗷 निर्यात का शुद्ध प्रभाव (विदेशियों ने हमारी वस्तुओं पर जो खर्च किया) और आयात (भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं पर जो खर्च किया) [शृद्ध निर्यात या NX]।
  - GDP की गणनाः
    - निवेश + सरकार द्वारा खर्च + (आयात-निर्यात)
- सकल मृल्य वर्द्धन (Gross Value Added- GVA):
  - ♦ GVA आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना करता है।
  - 💠 यह विभिन्न क्षेत्रों के सभी मूल्य वर्द्धन का योग करता है।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, किसी क्षेत्र के GVA को आउटपुट के मुल्य में से मध्यवर्ती इनपुट के मुल्य को घटा कर प्राप्त मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- यह "मूल्य वर्द्धन " उत्पादन, श्रम और पूंजी के प्राथमिक कारकों के बीच साझा किया जाता है।
- GVA वृद्धि को देखकर यह समझना आसान है कि अर्थव्यवस्था के कौन- से क्षेत्र मज़बूत है और कौन- क्षेत्र संघर्षशील है।

#### GDP और GVA में संबंध:

- GDP का मुख्य आधार GVA डेटा होता है।
- GDP और GVA निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित हैं: GDP = (GVA) + (RATA) + (RATAद्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी) ।
- जैसे, अगर सरकार द्वारा अर्जित कर उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से अधिक है, तो सकल घरेलू उत्पाद GVA से अधिक होगा।
- सकल घरेलू उत्पाद डेटा वार्षिक आर्थिक विकास का आकलन करने और देश के आर्थिक विकास की तुलना बीते समय अथवा किसी अन्य देश की आर्थिक विकास से करने काफी सहायक होता

# उर्वरक सब्सिडी

## चर्चा में क्यों ?

उच्च सरकारी सब्सिडी के कारण दो उर्वरकों - यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) का अत्यधिक उपयोग हो रहा है।

## उर्वरक सब्सिडी

- उर्वरक:
  - 💠 उर्वरक एक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ होता है जिसमें नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटेशियम (K) रासायनिक तत्त्व होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करते
  - भारत में 3 मुख्य उर्वरक हैं यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।
- उर्वरक सब्सिडी के बारे में:
  - 💠 सरकार उर्वरक उत्पादकों को सब्सिडी का भुगतान करती है ताकि किसानों को बाजार दर से कम मूल्य पर उर्वरक खरीदने की अनुमति मिल सके।
  - उर्वरक के उत्पादन/आयात की लागत और किसानों द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि के बीच का अंतर सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सब्सिडी का हिस्सा होता है।

- 🗅 यूरिया पर सिब्सिडी:
  - भारत में, यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, आयातित, खपत और भौतिक रूप से विनियमित उर्वरक है। यह केवल कृषि उपयोगों के लिये अनुदानित है।
  - केंद्र प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सिब्सिडी का भुगतान करता है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक बेचती है।
    - म्यूरिया की MRP फिलहाल 5,628 रुपये प्रति टन तय की गई है।
- ⊃ गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी:
  - गैर-यूरिया उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य कंपिनयों द्वारा नियंत्रित या तय नहीं की जाती है।
  - लेकिन सरकार ने हाल ही में और विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उर्वरकों के वैश्विक मूल्य में वृद्धि आने के के बाद से उर्वरकों को सरकारी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर दिया है।
  - सभी गैर-यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्त्व आधारित सिब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है।
  - ♦ गैर-यूरिया उर्वरकों के उदाहरण DAP और MOP।

## उर्वरकों हेतु पहलें:

- नीम कोटेड यूरिया':
  - उर्वरक विभाग (DoF) ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिये शत-प्रतिशत यूरिया का उत्पादन 'नीम कोटेड यूरिया' (NCU) के रूप में करना अनिवार्य कर दिया है।
- 🗅 नई यूरिया नीति 2015:
  - इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
    - 🗷 स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना।
    - 🗷 यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
    - 🗷 भारत सरकार पर सिंब्सिडी के भार को युक्तिसंगत बनाना।
- सिटी कम्पोस्ट के प्रोत्साहन हेतु नीति:
  - भारत सरकार ने सिटी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिये 1500 रुपए की बाजार विकास सहायता (Market Development Assistance) प्रदान करने हेतु वर्ष 2016 में उर्वरक विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी।

- बिक्री में वृद्धि करने के लिये, शहर के खाद को बेचने के इच्छुक खाद निर्माताओं को सीधे किसानों को खाद थोक में बेचने की अनुमति दी गई।
- शहरी खाद का विपणन करने वाली उर्वरक कंपनियाँ को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- 🔾 उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग:
  - उर्वरक विभाग ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और परमाणु खनिज निदेशालय (AMD) के सहयोग से इसरो के तहत राष्ट्रीय्र रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा "रॉक फॉस्फेट का रिफ्लेक्सेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करके संसाधन मानचित्रण" पर तीन साल का पायलट अध्ययन शुरू किया।

# RBI और खुदरा डिजिटल रुपया

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पहले पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है जिसे केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है।

सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिये, RBI ने 01 नवंबर, 2022 को थोक बाजार हेतु डिजिटल रुपए की शुरुआत की थी।

## इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रमुख बिंदुः

- इस पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभिक चरण कुछ विशिष्ट स्थानों और बैंकों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापार मालिकों से बने एक सीमित उपयोगकर्त्ता समूह ( closed user group - CUG) में होंगे।
- यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे शहरों को कवर करेगा, जहाँ ग्राहक और व्यापारी डिजिटल रुपए (ई-आर) या ई-रुपए का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- केंद्रीय बैंक के मुताबिक, यह पायलट प्रोजेक्ट वास्तविक समय (रियलटाइम) में डिजिटल रुपए के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा।

## ई-रुपया (e-rupee):

- 🗅 परिभाषाः
  - RBI, CBDC को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किये गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में पिरभाषित करता है। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार यह केंद्रीय बैंक (इस मामले में, RBI) द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है।

#### लीगल टेंडर:

- ♦ एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद CBDC को तीनों पक्षों - नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।
- RBI ई-रुपए पर ब्याज के पक्ष में नहीं है क्योंकि लोग बैंकों से पैसे निकालकर इसे डिजिटल रुपए में बदल सकते हैं, जिससे बैंक विफल हो सकते हैं।

#### क्रिप्टोकरेंसी से भिन्नताः

 क्रिप्टोकरेंसी (डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर) की अंतर्निहित तकनीक डिजिटल रुपया प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन RBI ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। हालाँकि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी प्रकृति में 'निजी' हैं। दूसरी ओर डिजिटल रुपए को RBI द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाएगा।

#### वैश्विक परिदृश्य:

♦ जुलाई 2022 तक करीब 105 देश CBDC पर विचार कर रहे थे। दस देशों ने CBDC की शुरुआत कर दी है जिनमें सबसे पहला है वर्ष 2020 में बहामियन सैंड डॉलर तथा सबसे नवीनतम है जमैका का JAM-DEX।

## ई-रुपया के प्रकार:

- डिजिटल रुपए द्वारा किये गए उपयोग और कार्यों के आधार पर तथा पहुँच के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए, RBI ने डिजिटल रुपए को दो व्यापक श्रेणियों - खुदरा और थोक में सीमांकित किया है।
  - खुदरा ई-रुपया नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेनदेन के लिये है। यह संभावित रूप से सभी - निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिये उपलब्ध होगा और भुगतान तथा निपटान के लिये सुरक्षित धन तक पहुँच प्रदान कर सकता है क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता है
- थोक CBDC को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच के लिये डिजाइन किया गया है। इसमें सरकारी प्रतिभृतियों (G-sec) और पूँजी बाजार में बैंकों द्वारा किये गए वित्तीय लेनदेन के लिये निपटान प्रणालियों को परिचालन लागत, संपार्श्विक तथा तरलता प्रबंधन के उपयोग के मामले में अधिक कुशल एवं सुरक्षित बनाने की क्षमता है।

#### खुदरा डिजिटल रुपया:

- e₹-R एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कागज़ी मुद्रा और सिक्कों के समान मृल्यवर्ग में जारी किया जाएगा और मध्यस्थों यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- RBI के अनुसार, उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किये 0 गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e□-R के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे और मोबाइल फोन तथा उपकरणों पर संग्रहीत होंगे।
- लेनदेन व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) दोनों हो सकते हैं।
  - व्यापारियों को भुगतान स्थानों पर प्रदर्शित क्युआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है।
  - ♦ e□-R में ट्रस्ट, सुरक्षा और निपटान को अंतिम रूप देने जैसी भौतिक नकदी की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
  - नकदी के मामले में, यह कोई ब्याज अर्जित नहीं करेगा और इसे बैंकों के साथ धन के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है।

## ई-रुपए के फायदेः

- भौतिक नकद प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना।
- जनता को ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो कोई भी निजी आभासी मुद्राएँ जोखिमों के बिना प्रदान कर सकती हैं।

# विझिंजम बंदरगाह परियोजना

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अडानी समूह ने केरल उच्च न्यायालय में विझिंजम में बंदरगाह निर्माण स्थल पर सुरक्षा बलों को भेजने के लिये याचिका दायर की, जो हिंसक मछुआरों के विरोध से बाधित हो रहा है।

## विझिंजम बंदरगाह परियोजना

- परिचय:
  - ♦ यह 7,525 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना है, जिसे केरल के तिरुवनंतपुरम के पास विझिंजम में अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत बनाया जा रहा है।
  - इसके निर्माण की समय सीमा दिसंबर 2015 निर्धारित की गई थी और तब से इसके पूरा होने की समय सीमा से समाप्त हो गई है।

बंदरगाह में 30 बर्थ हैं, जो विशाल "मेगामैक्स" कंटेनर जहाजों
 को संभालने में सक्षम होंगे।

#### महत्त्व:

- ऐसा माना जाता है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के करीब स्थित अल्ट्रामॉडर्न पोर्ट, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ इस स्थान का सामरिक महत्त्व भी है।
- ट्रांस-शिपमेंट ट्रैफिक के संदर्भ में यह बंदरगाह कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम है।
- बंदरगाह के लाभों में तट के एक समुद्री मील के भीतर 20-मीटर समोच्च होना, तट के किनारे कोई बहाव नहीं होना, रखरखाव के लिये कम आवश्यकता, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रेल तथा सड़क नेटवर्क से कनेक्शन एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से निकटता शामिल है।

## मछुआरों के विरोध का कारण:

- मछुआरे पिछले चार महीनों से इस पिरयोजना का विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इसके निर्माण से बड़े पैमाने पर समुद्री कटाव हो रहा है, जिससे उनकी आजीविका और आवास का ह्रास हो रहा है।
- उनकी मांग हैं कि एक प्रभावी अध्ययन किया जाए और अध्ययन रिपोर्ट आने तक परियोजना को निलंबित रखा जाए।
- मछुआरा समुदाय ने छह अन्य मांगें भी रखी हैं:
  - तटीय क्षरण में अपना घर गँवाने वाले परिवारों का पुनर्वास
  - 💠 तटीय क्षरण को कम करने के लिये प्रभावी कदम
  - मौसम की चेतावनी जारी किये जाने वाले दिनों में मछुआरों को वित्तीय सहायता
  - मत्स्यन की दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के पिरवारों को मुआवजा
  - 💠 सब्सिडी युक्त केरोसिन
  - तिरुवनंतपुरम जिले के अंचुथेंगु में मुथलप्पोझी बंदरगाह को साफ करने हेतु एक तंत्र की स्थापना।
  - केरोसिन सिब्सिडी की मांग यह कहकर की गई है कि इस परियोजना के कारण मछुआरों को मत्स्यन के लिये गहरे समुद्र में जाना पड़ता है, जिससे ईंधन लागत का बोझ बढ़ जाता है।

# पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाई गर्ड

## चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की अवधि को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाया गया है।

#### विस्तारित योजना के लिये प्रावधान:

- 🔾 दिसंबर २०२४ तक ऋण अवधि का विस्तार।
- ⇒ क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा ₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत।
- देश भर में पीएम स्विनिध योजना के सभी लाभार्थियों के लिये
   'स्विनिध से समृद्धि' घटक का विस्तार।
  - स्विनिधि से समृद्धि' को जनवरी, 2021 में 'पीएम स्विनिधि' लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को चिह्नित करने हेतु लॉन्च किया गया था।

### पीएम स्वनिधि योजनाः

- 🗅 परिचय:
  - प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मिनर्भर निधि (पीएम स्विनिधि) को आत्मिनर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
  - इसे 1 जून, 2020 से लागू िकया गया था, तािक उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीिवका को फिर से शुरू करने के लिये िकफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान िकया जा सके, जो कोिवड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
    - अब तक कुल 13,403 वेंडिंग जोन की पहचान की जा चुकी है।
    - प्र दिसंबर, 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है।

#### 🗅 वित्तपोषण:

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - 🗷 कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
  - 🗷 नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा
  - डिजिटल लेनदेन हेतु पुरस्कृत करना

#### 🕽 महत्त्व:

- यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिये आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगी।
- पात्रताः
  - राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
    - यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।

- 💠 हालाँकि मेघालय के लाभार्थी जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकता है।
- स्टीट वेंडर्स:
  - यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्टीट वेंडर्स (पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं) के लिये उपलब्ध है।
    - 💢 इससे पहले यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्टीट वेंडर्स के लिये उपलब्ध थी।

# मार्ग ( MAARG ) पोर्टल

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) ने नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप, सलाहकार, सहायता, लचीलापन और विकास पोर्टल (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience and Growth-MAARG) या मार्ग पोर्टल पर पंजीकरण के लिये स्टार्टअप आवेदनों हेतु कॉल सेवा शुरू की है।

## मार्ग ( MAARG ) पोर्टल:

- परिचय:
  - ♦ MAARG पोर्टल स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरिशप प्लेटफॉर्म है।
  - 💠 यह विविध क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप्स के लिये मेंटरशिप की सुविधा हेतु वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।



- मुख्य विशेषताएँ:
  - पारिस्थितिकी तंत्र सक्षमकर्त्ताओं हेतु मेंटरशिप कार्यक्रम
  - मोबाइल के अनुकूल यूजर इंटरफेस
  - मेंटर्स के योगदान की मान्यता
  - वीडियो और ऑडियो कॉल विकल्प
- चरणः MAARG पोर्टल तीन चरणों में संचालित किया जा रहा है:
  - पहला चरण: मेंटर ऑनबोर्डिंग

- सफलतापूर्वक लॉन्च तथा निष्पादित किया गया, 400 से अधिक विशेषज्ञ संरक्षक सभी सेक्टरों में शामिल हैं।
- दुसरा चरण 2: स्टार्टअप ऑनबोर्डिंग
  - □ DPIIT 14 नवंबर, 2022 से मार्ग (MAARG) पोर्टल पर स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग लॉन्च कर रहा है।
- तीसरा चरण: मार्ग पोर्टल लॉन्च एवं मेंटर मैचमेकिंग
  - अंतिम लॉन्च जहाँ संरक्षकों को स्टार्टअप्स के साथ मैच किया जाएगा। DPIIT ने दूसरे चरण के तहत स्टार्टअप्स की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आरंभ की है।

#### महत्त्व:

स्टार्टअप अब विकास और रणनीति संबंधी व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मैचमेकिंग के माध्यम से शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, सफल संस्थापकों, अनुभवी निवेशकों और विश्व के अन्य विशेषज्ञों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं।

## स्टार्टअप इंडियाः

- यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप कल्चर को उत्प्रेरित करना और भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिये एक मज़बूत व समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
  - 💠 स्टार्टअप एक उद्यम है जो अपने संस्थापकों द्वारा एक विचार या एक समस्या के समाधान के रूप में शुरू किया जाता है जिसमें महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर की संभावना होती है।
- 2016 में शुरुआत के बाद से, स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमियों का समर्थन करने और भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरियाँ सृजित करने वालों का देश बनाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किये हैं।
- भारतीय स्टार्टअप जो कि वर्तमान में विश्व में तीसरे स्थान पर है तथा भारत अभी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र को और बढावा देने के लिये व स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने तथा भारत में नवाचार एवं उद्यमिता के लिये एक मबूत, समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

# कोयले की बढ़ती मांग

## चर्चा में क्यों?

नवीकरणीय ऊर्जा के महत्त्व के बावजूद कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना रहेगा।

#### कोयलाः

- 🗅 परिचय:
  - यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है और इसे अक्सर 'ब्लैक गोल्ड' के रूप में जाना जाता है।
  - यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिये किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को 'थर्मल पावर' कहते हैं।

#### भारत में कोयले का वितरण::

- गोंडवाना कोयला क्षेत्र (250 मिलियन वर्ष पुराना):
  - भारत के लगभग 98% कोयला भंडार और कुल कोयला उत्पादन का 99% गोंडवाना क्षेत्रों से प्राप्त होता है।
  - भारत के धातुकर्म ग्रेड के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है।
  - यह दामोदर (झारखंड-पश्चिम बंगाल), महानदी (छत्तीसगढ़-ओडिशा), गोदावरी (महाराष्ट्र) और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है।
- 🗅 टर्शियरी कोयला क्षेत्र (15-60 मिलियन वर्ष पुराना):
  - इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम लेकिन नमी और सल्फर की मात्रा भरपुर होती है।
  - टर्शियरी कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्रों तक ही सीमित है।
  - महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में असम, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय की तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं।

#### 🗅 वर्गीकरण:

- एन्थ्रेसाइट (80-95% कार्बन सामग्री) जम्मू-कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है।
- बिटुमिनस (60-80% कार्बन सामग्री) झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
- लिग्नाइट (४०-५५% कार्बन सामग्री, उच्च नमी सामग्री)
   राजस्थान, लखीमपुर (असम) एवं तमिलनाडु में पाया जाता है।
- पीट [इसमें 40% से कम कार्बन सामग्री और कार्बनिक पदार्थ (लकड़ी) से कोयले में परिवर्तन के पहले चरण में प्राप्त होता है]।

# भारत में रूसी बैंको के वोस्ट्रो खाते

#### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत और रूस के बीच व्यापार हेतु रुपए में भुगतान करने के लिये दो भारतीय बैंकों (यूको बैंक और इंडसइंड बैंक) में नौ विशेष वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी है।

- रूस के दो सबसे बड़े बैंक- 'Sberbank' और 'VTB' बैंक ऐसे पहले विदेशी ऋणदाता हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक लेन-देन करने की मंज़री मिली है।
- वोस्ट्रो खाता नोस्ट्रो खाता का एक अन्य नाम है। यह एक बैंक द्वारा नियोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।

## पृष्ठभूमि:

- जुलाई 2022 में RBI ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिये रुपए में अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिये एक क्रियाविधि का अनावरण किया था, जिसमें भारत द्वारा निर्यात पर जोर दिया गया था, साथ ही रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पहचान दिलाने के लिये किया गया था।
- इसके माध्यम से रूस जैसे प्रतिबंध-प्रभावित देशों के साथ व्यापार को सक्षम करने की भी आशा है।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय क्रियाविधि के अनुसार, भागीदार देशों के बैंक विशेष रुपया वास्ट्रो खाता खोलने के लिये भारत में अधिकृत बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। तब अधिकृत बैंक को ऐसी व्यवस्था के विवरण के साथ केंद्रीय बैंक से अनुमोदन लेना होगा।

## नोस्ट्रो खाता (Nostro Accounts)

- नोस्ट्रो खाता का तात्पर्य एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में खोले गए खाता से है। इससे ग्राहकों को किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की सुविधा मिलती है। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती है। नोस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ " हमारा (ours) " होता है।
  - मान लीजिये कि बैंक "A" की रूस में कोई शाखा नहीं है लेकिन बैंक "B" की शाखा रूस में है। रूस में अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिये बैंक "A" बैंक "B" में नोस्ट्रो खाता खोलेगा।
  - अब यदि रूस में कोई ग्राहक "A" को पैसा भेजना चाहता है तो
     वह इसे "B" बैंक में खुले "A" के खाते में जमा कर सकता
     है। "B" बैंक इस पैसे को "A" के खाते में स्थानांतरित कर
     देगा।
- जमा खाते और नोस्ट्रो खाते के बीच मुख्य अंतर यह है कि जमा खाते व्यक्तिगत जमाकर्त्ताओं के पास होता है, जबिक विदेशी संस्थानों के पास नोस्ट्रो खाता होता है।

## वोस्ट्रो खाता (Vostro Accounts):

- इस शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ- तुम्हारा (yours) होता है।
- खाता खोलने वाले बैंक के लिये नोस्ट्रो खाता, एक वोस्ट्रो खाता होता है।
  - ♦ उपर्युक्त उदाहरण में बैंक "B" में खुले खाते को इस बैंक के लिये वोस्ट्रो खाता कहा जाएगा। वोस्ट्रो खाता में खाताधारक के बैंक की ओर से भुगतान स्वीकार किया जाता है।
- यदि कोई व्यक्ति वोस्ट्रो खाते में पैसा जमा करता है तो यह खाताधारक के बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
- नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते, विदेशी मूल्यवर्ग में खोले जाते हैं।
- वोस्ट्रो खाते के माध्यम से घरेलू बैंक, वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- वोस्टो खाता सेवाओं में वायर टांसफर निष्पादित करना, विदेशी विनिमय करना, जमा और निकासी करना व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेज़ी लाना शामिल है।

## रुपया भुगतान तंत्रः

- परिचय:
  - 💠 भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी गई है (एक खाता जो एक अधिकृत बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है)।
    - इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक भारतीय रुपए में भुगतान करेंगे, इसमें विदेशी विक्रेता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिये चालान भागीदार देश के अधिकृत बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा।
    - प्र तंत्र का उपयोग करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के अधिकृत बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा शेष राशि से निर्यात का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाएगा।
  - भारतीय निर्यातक उपर्युक्त रुपए भुगतान तंत्र के माध्यम से विदेशी आयातकों से भारतीय रुपए में निर्यात के लिये अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
    - 🗷 निर्यात के लिये अग्रिम भुगतान की ऐसी किसी भी प्राप्ति की अनुमति देने से पहले भारतीय बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन खातों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग पहले से ही निष्पादित निर्यात आदेशों/ पाइपलाइन में निर्यात भुगतान से उत्पन्न भुगतान दायित्वों के लिये किया जाता है।

- विशेष वोस्ट्रो अकाउंट में शेष राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जा सकता है: परियोजनाओं और निवेशों के लिये भुगतान, निर्यात/आयात अग्रिम प्रवाह प्रबंधन, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश आदि।
- मौजूदा तंत्र:
  - यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है, तो लेन-देन (नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर) हमेशा एक विदेशी मुद्रा में होता है।
  - इसलिये आयात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है (मुख्य रूप से डॉलर में और इसमें पाउंड, यूरो, येन आदि मुद्राएँ भी शामिल हो सकती हैं)।
  - निर्यात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भगतान किया जाता है और कंपनी उस विदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित कर देती है क्योंकि उसे ज़्यादातर मामलों में अपनी ज़रूरतों के लिये रुपए की आवश्यकता होती है।

# राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

#### चर्चा में क्यों ?

पशुपालन विभाग 26 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रहा

- है।
- 0 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, 2022 समारोह के दौरान प्रदान किया गया।
- पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का भी उद्घाटन किया गया है। 0
- प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 0

## राष्ट्रीय दुग्ध दिवसः

- यह दिवस एक व्यक्ति के जीवन में दूध के महत्त्व को रेखांकित करता है और इसका उद्देश्य दुग्ध से संबंधित लाभों को बढ़ावा देना तथा दूध एवं दुग्ध उत्पादों के महत्त्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
- 26 नवंबर, 2022 को "भारत में खेत क्रांति के जनक" डॉ. वर्गीज 0 कुरियन की 101वीं जयंती मनाई जा रही है।
- 'डॉ. वर्गीज़ कुरियन (1921-2012):
  - उन्हें 'भारत में खेत क्रांति के जनक' के रूप में जाना जाता है।
  - वह अपने 'ऑपरेशन फ्लड' के लिये काफी प्रसिद्ध हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।
  - ♦ उन्होंने विभिन्न किसानों और श्रमिकों द्वारा चलाए जा रहे 30 संस्थानों की स्थापना की।
  - 💠 उन्होंने 'अमूल ब्रांड' की स्थापना और सफलता में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- उन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत वर्ष 1998 में अमेरिका
   को पीछे छोड़ते हुए दूध का सबसे बडा उत्पादक बन गया था।
- उन्होंने 'दिल्ली दूध योजना' के प्रबंधन में भी मदद की और कीमतों में सुधार किया। उन्होंने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद की।
- उन्हें 'रेमन मैग्सेसे पुरस्कार' (1963), 'कृषि रत्न' (1986)
   और 'विश्व खाद्य पुरस्कार' (1989) सिहत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- वह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार- पद्मश्री (1965),
   पद्मभूषण (1966) और पद्मिवभूषण (1999) के प्राप्तकर्त्ता भी हैं।



#### भारत की श्वेत क्रांति:

- परिचय:
  - ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी, 1970 को लॉन्च किया गया था।
     यह विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था।
  - 30 वर्षों के भीतर ऑपरेशन फ्लड ने भारत में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन को दोगुना करने में मदद की, जिससे डेयरी फार्मिंग भारत का सबसे बड़ा आत्मिनर्भर ग्रामीण रोज्जगार उत्पन्न करने वाला क्षेत्र बन गया।
  - ऑपरेशन फ्लड ने किसानों को उनके द्वारा उत्पन्न संसाधनों पर सीधा नियंत्रण प्रदान किया, जिससे उन्हें अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद मिली। इससे न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, बल्कि इसे अब 'श्वेत क्रांति' (White Revolution) के रूप में भी जाना जाता है।
- चरण:
  - चरण I (1970-1980): इस चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किये गए बटर आयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री से प्राप्त धन से वित्तपोषित किया गया था।
  - चरण II (1981 से 1985): इस चरण के दौरान दुग्धशालाओं
     की संख्या 18 से बढ़कर 136 हो गई, दुध की दुकानों का

- विस्तार लगभग 290 शहरी बाजारों में किया गया, एक आत्मनिर्भर प्रणाली स्थापित की गई जिसमें 43,000 ग्राम सहकारी समितियों के 42,50,000 दूध उत्पादक शामिल थे।
- चरण III (1985-1996): इस चरण में डेयरी सहकारी सिमितियों का विस्तार कर उन्हें सक्षम बनाया गया और कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इसने दूध की बढ़ती मात्रा की खरीद और बाजार के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे को भी मजबूत किया।
- ⊃ उद्देश्य:
  - 💠 दूध उत्पादन को बढ़ाना।
  - 💠 ग्रामीण आय में वृद्धि।
  - 💠 उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य।
- 🗅 महत्त्व:
  - इसने डेयरी किसानों को स्वयं के विकास के लिये निर्देशित करने में मदद की, उनके संसाधनों पर उन्हें नियंत्रण प्रदान किया।
  - इसने भारत को वर्ष 2016-17 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की है।
  - वर्तमान में भारत 22% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है।
- 🔾 संबंधित पहल:
  - पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund-AHIDF)
  - 💠 राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
  - राष्ट्रीय गोकुल मिशन
  - 💠 राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम
  - राष्ट्रीय पशुधन मिशन

# फ्रेंडशोरिंग

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी ट्रेज़री सिचव ने भू-राजनीतिक जोखिम वाले देशों से परे व्यापार में विविधता लाने के लिये "फ्रेंडशोरिंग" पर ज़ोर दिया है।

## फ्रेंडशोरिंग:

फ्रेंडशोरिंग एक रणनीति है जहाँ एक देश कच्चे माल, घटकों और यहाँ तक कि निर्मित वस्तुओं को उन देशों से प्राप्त करता है जो इसके मूल्यों को साझा करते हैं। इसमें आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता के लिये "खतरा" माने जाने वाले देशों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो जाती है।

- इसे "एलीशोरिंग" भी कहा जाता है।
  - अमेरिका के लिये रूस ने लंबे समय से खुद को एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है लेकिन यूक्रेन युद्ध में, उसने यूरोप के लोगों के खिलाफ गैस को हथियार बनाया है।
    - यह एक उदाहरण है कि कैसे सभी भागीदार देश दुर्भावना के चलते अपने स्वयं के लाभ के लिये भू-राजनीतिक लाभ उठाने या व्यापार को बाधित करने की कोशिश में अपने बाजार की स्थिति का उपयोग कर सकते हैं।
- फ्रेंड-शोरिंग या एली-शोरिंग अमेरिका के लिये फर्मों को अपने सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को उन फ्रेंडली तटों पर ले जाने के लिये प्रभावित करने का एक साधन बन गया है जो अमेरिका से संबंधित हैं।
- फ्रेंडशोरिंग का लक्ष्य कम संगत देशों से आपूर्ति शृंखलाओं की रक्षा करना है, जैसे अमेरिका के मामले में चीन।

## फ्रेंडशोरिंग के निहितार्थ क्या हो सकते हैं?

- फ्रेंडशोरिंग विश्व के देशों को व्यापार के लिये अलग-थलग कर सकता है और इससे वैश्वीकरण के लाभों की प्रकृति बिलकुल ही विपरीत हो जाएगी। यह "डीग्लोबलाइजेशन" प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
- कोविड-19 के वर्षों के लॉकडाउन से वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बाद किसी भी प्रकार का संरक्षणवाद पहले से ही अस्थिर वैश्विक आपूर्ति शृंखला को और बाधित करेगा।
- संरक्षणवाद का यह नया रूप वैश्विक आपूर्ति शृंखला और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हुए वैश्वीकरण के अनुकूल नहीं होगा और लंबी अवधि में इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। यदि कोई कंपनी बैटरी हेत् लिथियम या कंप्यूटर चिप्स जैसे कीमती धात् के लिये किसी देश पर निर्भर करती है, वह ऐसे में स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकता है।
- इसके अलावा जैसा कि यह एक प्रवृत्ति बन जाती है, दुनिया धीरे-धीरे अलग हो जाएगी और देशों के लिये मानवता की भलाई हेतु एक साथ काम करना मुश्किल होगा।

# भारत में बेरोजगारी

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) ने आविधक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey- PLFS) जारी किया है।

15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी दर जुलाई-सितंबर 2021 में 9.8% से घटकर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2% हो गई।

#### आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण:

- अधिक नियत समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की शुरुआत की।
- PLFS के मुख्य उद्देश्य हैं:
  - ♦ 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना।
  - प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थित तथा CWS दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

#### बेरोजगारी:

- ♦ किसी व्यक्ति द्वारा सिक्रयता से रोजगार की तलाश किये जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था बेरोज़गारी कहलाती है।
  - बेरोजगारी का प्रयोग प्राय: अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापक के रूप में किया जाता है।
- बेरोजगारी को सामान्यत: बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है. जिसे श्रमबल में शामिल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या को भाग देकर प्राप्त किया जाता है।
- ♦ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) किसी व्यक्ति की निम्नलिखित स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है:
  - कार्यरत (आर्थिक गतिविधि में संलग्न) यानी 'रोजगार'।
  - काम की तलाश में या काम के लिये उपलब्ध यानी 'बेरोजगार' ।
  - न तो काम की तलाश में है और न ही उपलब्ध।
  - पहले दो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल का प्रतिशत है जो बिना काम के है।
  - च बेरोजगारी दर = (बेरोजगार श्रमिक/कुल श्रम शक्ति) × 100
- बेरोजगारी के प्रकार:
  - प्रच्छन्न बेरोजगारी:
    - प्र यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है।
    - 🗷 यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है।

- मौसमी बेरोजगारी:
  - यह एक प्रकार की बेरोजगारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
  - भारत में खेतिहर मज़दूरों के पास वर्ष भर काफी कम काम होता है।
- संरचनात्मक बेरोजगारी:
  - यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रिमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है।
  - भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।

#### चक्रीय बेरोजगारी:

- यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
- भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आँकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है।

#### तकनीकी बेरोजगारी:

- यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है।
- वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आँकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकिरयों का अनुपात साल-दर-साल 69% है।

#### घर्षण बेरोजगारी:

- घर्षण बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति से है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकिरयों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो यह नौकिरयों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है।
- दूसरे शब्दों में, एक कर्मचारी को एक नई नौकरी खोजने या एक नई नौकरी में स्थानांतिरत करने के लिये समय की आवश्यकता होती है, यह अपिरहार्य समय की देरी घर्षण बेरोजगारी का कारण बनती है।
- इसे अक्सर स्वैच्छिक बेरोजगारी के रूप में माना जाता है क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होता है, बल्कि वास्तव में बेहतर अवसरों की तलाश में श्रमिक स्वयं अपनी नौकरी छोड देते हैं।

#### स्भेद्य रोजगारः

इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिये कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है।

- इन व्यक्तियों को 'बेरोजगार' माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी भी बनाया नहीं जाता हैं।
- यह भारत में बेरोज़गारी के मुख्य प्रकारों में से एक है।

# प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

#### चर्चा में क्यों?

अधिकांश अर्थशास्त्री सभी कृषि सिब्सिडी को प्रत्यक्ष आय सहायता अर्थात् किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में बदलने की वकालत करते हैं।

#### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( DBT ) योजनाः

- उद्देश्य: इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- कार्यान्वयन: इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।
  - महालेखाकार कार्यालय की सार्वजिनक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के पुराने संस्करण यानी 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटिरंग सिस्टम' को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।
- ⊃ DBT के घटक: प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजिनक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।
- DBT के तहत योजनाएँ: DBT के तहत 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएँ हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ हैं:
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
     प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान, स्वच्छ भारत
     मिशन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
- आधार अनिवार्य नहीं: DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूँिक आधार विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

#### DBT के लाभ:

सेवाओं के कवरेज का विस्तार: एक मिशन-मोड दृष्टिकोण में, इसने सभी परिवारों के लिये बैंक खाते खोलने, सभी के लिये आधार का विस्तार करने और बैंकिंग तथा दूरसंचार सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया।

- तत्काल और आसान मनी ट्रांसफर: इसने आधार पेमेंट ब्रिज बनाया ताकि सरकार से लोगों के बैंक खातों में तत्काल धन हस्तांतरण किया जा सके।
  - इस दृष्टिकोण ने न केवल सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी प्राप्त करने के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत विशिष्ट रूप से जोड़ने की अनुमति दी, बल्कि आसानी से धन भी हस्तांतरित किया।
- वित्तीय सहायता: ग्रामीण भारत में. DBT ने सरकार को कम लेन-देन लागत वाले किसानों को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी है।
- वित्त का हस्तांतरण और सामाजिक सुरक्षा: शहरी भारत में, PM आवास योजना और LPG पहल योजना पात्र लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने के लिये DBT का सफलतापूर्वक उपयोग करती है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये DBT आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं।
- नए अवसरों का द्वार: मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिये स्वरोजगार योजना (Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers- SRMS) जैसे पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत DBT नए अवसर प्रदान करता है जो समाज के सभी वर्गों की सामाजिक गतिशीलता को सक्षम बनाता है।

# शक्ति (SHAKTI) नीति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन योजना/Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India/SHAKTI) नीति के B(v) के तहत वित्त, स्वामित्त्व और संचालन (Finance, Own and Operate- FOO) के आधार पर पाँच साल के लिये प्रतिस्पर्द्धी आधार पर 4500 मेगावाट की कुल विद्युत की खरीद हेतु एक योजना शुरू की है।

## प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत PFC कंसिल्टंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिये बोलियाँ आमंत्रित की हैं।
  - ♦ PFC कंसिल्टंग लिमिटेड (PFC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- कोयला मंत्रालय से इसके लिये लगभग 27 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) आवंटित करने का अनुरोध किया है।

इस योजना से विद्युत की कमी का सामना कर रहे राज्यों को मदद मिलने की उम्मीद है और इससे उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढाने में भी मदद मिलेगी।

#### शक्ति नीतिः

- परिचय:
  - विद्युत मंत्रालय (MoP) ने 2017 में कोल नीति को मंजूरी दी, जिसे शक्ति (भारत में कोयला का दोहन और आवंटन पारदर्शी रूप से दोहन और आवंटन करने की योजना) के रूप में जाना जाता है।
  - इस नीति में उन विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान किये गए हैं जिनके पास कोयला नीलामी के माध्यम से ईंधन आपूत करारों (FSA) की कमी है।

#### उद्देश्य:

- शक्ति योजना का उद्देश्य भारत में सभी थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण हो।
- यह योजना न केवल बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के लिये, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु भी फायदेमंद मानी जाती है, जिनके पास विद्युत कंपनियों द्वारा भारी ऋण चुकाया नहीं गया
- इस योजना का उद्देश्य आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना भी है।

# पश्मीना शॉल

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कस्टम अधिकारियों ने कई निर्यातित वस्तुओं की खेपों में पश्मीना शॉल में 'शहतुश' गार्ड हेयर की उपस्थित के विषय में शिकायत की जो विशेषकर लुप्तप्राय तिब्बती मृगों से प्राप्त किया जाता है।

#### पश्मीनाः

- परिचय:
  - पश्मीना एक भौगोलिक संकेतक (GI) प्रमाणित ऊन है जिसकी उत्पत्ति भारत के कश्मीर क्षेत्र में हुई।
    - मूल रूप से कश्मीरी लोग सर्दियों के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिये पश्मीना शॉल का इस्तेमाल करते थे।
  - 'पश्मीना' शब्द फारसी शब्द "पश्म" से लिया गया है जिसका अर्थ है बुनाई योग्य फाइबर जो मुख्य रूप से ऊन है।
  - पश्मीना शॉल ऊन की अच्छी गुणवत्ता और शॉल बनाने में लगने वाली कड़ी मेहनत के कारण बहुत महँगे होते हैं।

पश्मीना शॉल बुनने में काफी समय लगता है और यह काम के प्रकार पर निर्भर करता है। एक शॉल को पूरा करने में आमतौर पर लगभग 72 घंटे या उससे अधिक समय लगता

#### स्रोत:

- 💠 पश्मीना शॉल की बुनाई में उपयोग किया जाने वाला ऊन लद्दाख में पाए जाने वाले पालतू चांगथांगी बकरियों (Capra hircus) से प्राप्त किया जाता है।
- फाइबर प्रसंस्करण:
  - 💠 कच्चे पश्म को लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली चांगथांगी बकरियों से प्राप्त किया जाता है।
    - 🗷 चांगपा अर्द्ध-खानाबदोश समुदाय से हैं जो चांगथांग ( लद्दाख और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फैले हुए हैं) या लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं।
    - 🙎 वर्ष 2001 तक भारत सरकार के आरक्षण कार्यक्रम के तहत चांगपा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - कश्मीरी बुनकरों द्वारा कच्चा पश्म को मध्यस्थों के माध्यम से खरीदा जाता है, जो चांगपा जनजाति और कश्मीरियों के बीच एकमात्र संपर्क कडी है, इसके बाद कच्चे पश्म फाइबर को ठीक से साफ किया जाता है।
    - 🗷 बाद में वे इस फाइबर को सुलझाते हैं और उसकी गुणवत्ता के आधार पर इसे अच्छी तरह से अलग करते हैं।
    - प्र फिर इसे हाथ से काता जाता है और ताने (Warps) में स्थापित किया जाता है एवं हथकरघा पर रखा जाता है।
    - 🗷 इसके बाद यार्न को हाथ से बुना जाता है और खूबसूरती से शानदार पश्मीना शॉल का निर्माण किया जाता है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
    - पश्मीना शॉल बुनाई की यह कला कश्मीर में एक परंपरा के रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चली आ रही है।

#### महत्त्व:

- पश्मीना शॉल दुनिया में बेहतरीन और उच्चतम गुणवत्ता वाले ऊन से बने होते हैं।
- पश्मीना शॉल ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और यह पूरी दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले शॉल में से एक बन गई है।
- 💠 इसकी उच्च मांग ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया।

#### चिंताएँ:

सीमित उपलब्धता और उच्च कीमतों के कारण निर्माताओं द्वारा पश्मीना में भेड के ऊन/अल्ट्रा-फाइन मेरिनो ऊन की मिलावट करना आम बात है।

- वर्ष 2019 में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने पश्मीना उत्पादों की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिये उनकी पहचान, अंकन और लेबलिंग हेत् भारतीय मानक निर्धारित किया।
- पश्मीना हेतु GI प्रमाणन मानदंड:
  - शॉल 100% शुद्ध पश्म से बनी होनी चाहिये।
  - रेशों की सुक्ष्मता 16 माइक्रोन तक होनी चाहिये।
  - शॉल को कश्मीर के स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथ से बुना जाना
  - धागे को केवल हाथ से काता जाना चाहिये।

#### शहतूश:

- शहतूश तिब्बती मृग से प्राप्त महीन अस्तर (Undercoat) फाइबर है, जिसे स्थानीय रूप से 'चिरू' के रूप में जाना जाता है, यह मुख्य रूप से तिब्बत में चांगथांग पठार के उत्तरी भागों में रहने वाली प्रजाति है।
  - इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड लिस्ट में,चिरू को 'निकट संकट (Near Threatened)' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- चुँकि यह शॉल बहुत गर्मी प्रदान करती है और मुलायम होती है, इसलिये शहतूश शॉल अत्यधिक महँगी वस्तु बन गई है।
- दुर्भाग्यवश इस जानवर के वाणिज्यिक शिकार के कारण इनकी आबादी में नाटकीय रूप से गिरावट आई है।
  - ♦ तिब्बती मृग वर्ष 1979 में जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में इंटरनेशनल युनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (CITES) के तहत शामिल था, जिससे शहतूश शॉल और स्कार्फ की बिक्री एवं व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

# भारत का चाय उद्योग

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने भारतीय चाय संघ (ITA) के अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय उत्पादक सम्मेलन को संबोधित किया।

वर्ष 1881 में स्थापित भारतीय चाय संघ (ITA) भारत में चाय उत्पादकों का प्रमुख और सबसे पुराना संगठन है। इसने नीतियाँ बनाने और उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लिये कार्रवाई शुरू करने की दिशा में एक बहुआयामी भूमिका निभाई है।

#### भारतीय चाय उद्योग की स्थिति:

- 0 उत्पादन:
  - 💠 भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है।

- भारत का उत्तरी भाग 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है।
  - 🗷 असम घाटी और कछार असम के दो चाय उत्पादक क्षेत्र
  - 🗷 पश्चिम बंगाल में डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग तीन प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं।
  - 🗷 भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं।
  - 🗷 वित्त वर्ष 2020-21 के लिये भारत का कुल चाय उत्पादन 1.283 मिलियन किलोग्राम था।

#### खपत:

- 🗷 भारत दुनिया के शीर्ष चाय खपत करने वाले देशों में से एक है, जहाँ देश में उत्पादित चाय का 80% घरेलू आबादी द्वारा उपभोग किया जाता है।
- भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है, जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं।
- ♦ वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कुल चाय उत्पादन 1,283 मिलियन किलोग्राम था।
- निर्यात:
  - 🗷 भारत दुनिया के शीर्ष 5 चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल निर्यात का लगभग 10% निर्यात करता है।
  - 🗷 वर्ष 2021 में भारत से चाय निर्यात का कुल मूल्य लगभग9 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत दुनिया भर के 25 से अधिक देशों में चाय का निर्यात करता है।
  - 🗷 रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे देश भारत से चाय के सबसे बड़े आयातकों में से हैं।
- वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल चाय निर्यात मात्रा में 201 मिलियन किलोग्राम था।
- भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय है जो कुल निर्यात का लगभग 96% है।
  - 🗷 भारत के माध्यम से निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार हैं: काली चाय, नियमित चाय, हरी चाय, हर्बल चाय, मसाला चाय और नींबू चाय।
- इनमें से काली चाय, नियमित चाय और हरी चाय भारत से निर्यात की जाने वाली कुल चाय का लगभग 80%, 16% और5% है।

- 😕 भारत की असम, दार्जिलिंग और नीलगिरि चाय को दुनिया में बेहतरीन चाय में से एक माना जाता है।
- मज़बृत भौगोलिक संकेतों, चाय प्रसंस्करण इकाइयों में भारी निवेश, निरंतर नवाचार, संवर्द्धित उत्पाद मिश्रण और रणनीतिक बाजार विस्तार के परिणामस्वरूप भारतीय चाय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।
- भौगोलिक संकेत (GI) टैग:
  - दार्जिलिंग चाय जिसे "चाय की शैंपेन" के रूप में भी जाना जाता है, इसकी आकर्षक खुशबू के कारण दुनिया भर में पहला GI टैग उत्पाद था।
  - 💠 दार्जिलिंग चाय के अन्य दो प्रकार यानी ग्रीन और व्हाइट टी (सफ़ेद चाय) में भी GI टैग है।
- उद्योग का विनियमनः
  - भारतीय चाय बोर्ड भारत में चाय उद्योग के विकास और संवर्द्धन का प्रभारी है।

#### भारतीय चाय बोर्ड:

- परिचय:
  - यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसे 1953 में भारत में चाय उद्योग के विकास के लिये स्थापित किया गया था। इसने 1954 में काम करना शुरू किया।
- दृष्टिकोण:
  - 💠 इसका दृष्टिकोण और मिशन देश को दुनिया भर में चाय का एक प्रमुख उत्पाद बनाना है जिसके लिये इसने कई कार्यक्रम और योजनाएं स्थापित की हैं।
- सदस्य:
  - बोर्ड का गठन संसद सदस्यों, चाय उत्पादकों, चाय व्यापारियों, चाय दलालों, उपभोक्ताओं और प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों तथा ट्रेड यूनियनों के 31 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) से किया जाता है।
  - 💠 बोर्ड का हर तीन साल में पुनर्गठन किया जाता है।
- भारत में कार्यालय:
  - 💠 बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और पूरे भारत में 17 अन्य कार्यालय हैं।
- विदेश कार्यालय:
  - वर्तमान में चाय बोर्ड के दुबई और मॉस्को में स्थित दो विदेशी कार्यालय हैं।

#### चाय:

- परिचय:
  - 💠 चाय कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे से बना एक पेय है। पानी के बाद यह दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है।
- उत्पत्ति:
  - 💠 ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर-पूर्वी भारत, उत्तरी म्याँमार और दक्षिण-पश्चिम चीन में हुई थी, लेकिन यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि इनमें से वास्तव में यह पहली बार कहाँ पाई गई थी। इस बात के प्रमाण हैं कि 5,000 साल पहले चीन में चाय का सेवन किया जाता था।
- विकास की आवश्यक दशाएँ:
  - जलवाय: चाय एक उष्णकिटबंधीय और उपोष्णकिटबंधीय पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में इसकी पैदावार अच्छी होती है।
  - ♦ तापमान: इसकी वृद्धि हेतु आदर्श तापमान 20-30°C होता है तथा 35°C से ऊपर और 10°C से नीचे का तापमान इसके लिये हानिकारक होता है।
  - 💠 वर्षा: इसके लिये पूरे वर्ष समान रूप से वितरित 150-300 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
  - 💠 मिट्टी: चाय की खेती के लिये सबसे उपयुक्त छिद्रयुक्त अम्लीय मृदा (कैल्शियम के बिना) होती है, जिसमें जल आसानी से प्रवेश कर सके।

#### महत्त्व:

- चाय उद्योग सबसे महत्त्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है, जो कुछ सबसे गरीब देशों के लिये आय और निर्यात राजस्व का एक मुख्य स्रोत है तथा श्रम प्रधान क्षेत्र के रूप में, विशेष रूप से दूरस्थ एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है।
  - 🗷 चाय उत्पादन और प्रसंस्करण सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में योगदान देता है जिसमें अत्यधिक गरीबी को कम करना (लक्ष्य 1), भूख के खिलाफ लड़ाई (लक्ष्य 2), महिलाओं का सशक्तीकरण (लक्ष्य 5) और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सतत् उपयोग (लक्ष्य 15) शामिल
- 💠 कई समाजों में इसका सांस्कृतिक महत्त्व भी है।
- स्वास्थ्य लाभ:
  - उत्तेजक विरोधी, एंटीऑक्सिडेंट और वजन घटाने के प्रभावों के कारण चाय का सेवन स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है।

- 0 अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस:
  - 💠 यह दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किये जाने के बाद से प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है।

#### भारतीय चाय उद्योग के विकास को प्रोत्साहनः

- एक ज़िला और एक उत्पाद (ODOP) योजना भारतीय चाय की प्रतिष्ठा फैलाने में मदद कर सकती है।
- चाय क्षेत्र को लाभदायक, व्यवहार्य और टिकाऊ बनाने के लिये चाय की 'सुगंध' (AROMA) को बढ़ाया जाना चाहिये:
  - 💠 समर्थन: स्थिरता के साथ गुणवत्ता में सुधार के लिये छोटे उत्पादकों का समर्थन करना, घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पुरा करने के लिये उत्पादन बढ़ाना।
  - पुन: सिक्रयता: निर्यात बढाने के लिये बुनियादी ढाँचा तैयार करना और यूरोपीय संघ, कनाडा, दक्षिण अमेरिका तथा मध्यपूर्व जैसे उच्च मूल्य वाले बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - जैविक: बॉण्ड प्रचार और विपणन के माध्यम से जैविक और जीआई चाय का प्रचार करना।
  - ♦ आधुनिकीकरण: चाय किसानों को आत्मिनिर्भर बनने और स्थानीय आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करने में सक्षम बनाना।
  - अनुकूलनशीलता: एक जोखिम मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र के महत्त्व यानी चाय बागानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिये स्थायी समाधान की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना।

# IIPDF योजना

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिये वित्तीय सहायता हेतु भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना (IIPDF योजना) को अधिसूचित किया।

## भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि योजना ( IIPDF योजना ):

- परिचय:
  - IIPDF योजना की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी।
  - ♦ यह वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक तीन साल की अवधि के लिये 150 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - यह परियोजना विकास लागत को पूरा करने के लिये PPP परियोजनाओं के प्रायोजक प्राधिकरणों के लिये उपलब्ध है।

- PPP परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने और बड़े नीति एवं नियामक मुद्दों को संबोधित करने के लिये PPP सेल का निर्माण तथा उन्हें सशक्त बनाने हेत् प्रायोजक प्राधिकरण के लिये यह आवश्यक होगा।
- उद्देश्य: 0
  - इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण परियोजना विकास गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- महत्त्व:
  - प्रायोजक प्राधिकरण, PPP लेन-देन लागत के एक हिस्से को कवर करने के लिये वित्तपोषण के स्रोत के रूप में सक्षम होगा. जिससे उनके बजट पर खरीद से संबंधित लागतों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।
- वित्तीय परिव्ययः
  - IIPDF परियोजना विकास खर्च का 75% तक प्रायोजक प्राधिकरण को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में योगदान देगा। शेष 25% प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सह-वित्तपोषित किया जाएगा।
  - बोली प्रक्रिया के सफल समापन पर सफल बोलीदाता से परियोजना विकास व्यय की वसूली की जाएगी।
  - हालाँकि बोली की विफलता के मामले में ऋण को अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा।
  - यदि प्रायोजक प्राधिकरण किसी कारण से बोली प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो योगदान की गई पूरी राशि IIPDF को वापस कर दी जाएगी।

## सार्वजनिक-निजी भागीदारी ( PPP ) मॉडल के प्रकार:

- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT): यह एक पारंपरिक PPP मॉडल है जिसमें निजी भागीदार डिजाइन, निर्माण, संचालन (अनुबंधित अवधि के दौरान) और सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र में वापस स्थानांतरित करने के लिये जिम्मेदार होते हैं।
  - निजी क्षेत्र के भागीदार को किसी परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था करनी होती है और इसके निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होती है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के भागीदारों को उपयोगकर्ताओं से राजस्व एकत्र करने की अनुमित देगा। PPP मोड के तहत NHAI द्वारा अनुबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ BOT मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण है।
- बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO): इस मॉडल में नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी पार्टी के पास रहेगा।
  - पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदार परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की 'खरीद' करने पर सहमति बनाई जाती है।

- बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT): इसके अंतर्गत समय पर बातचीत के बाद परियोजना को सरकार या निजी ऑपरेटर को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
  - ♦ BOOT मॉडल का उपयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिये किया जाता है।
- बिल्ड-ऑपरेट-लीज़-ट्रांसफर (BOLT): इस मॉडल में सरकार निजी साझेदार को सुविधाओं के निर्माण, डिजाइन, स्वामित्त्व और लीज़ का अधिकार देती है तथा लीज़ अवधि के अंत में सुविधा का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित किया जाता है।
- डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट (DBFO): इस मॉडल में अनुबंधित अवधि के लिये परियोजना के डिजाइन, उसके विनिर्माण, वित्त और परिचालन का उत्तरदायित्त्व निजी साझीदार पर होता है।
- लीज-डेवलप-ऑपरेट (LDO): इस प्रकार के निवेश मॉडल में 0 या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधा का स्वामित्व बरकरार रहता है और निजी प्रमोटर के साथ लीज समझौते के रूप में भुगतान प्राप्त किया जाता है।
  - इसका पालन अधिकतर एयरपोर्ट सुविधाओं के विकास में किया जाता है।
  - इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल: इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग कार्य के लिये बोलियाँ आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम तथा इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के प्रावधान तक सीमित होती है। इस मॉडल की एक समस्या यह है कि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढता है।
- हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM): भारत में नया HAM, BOT-एन्युइटी और EPC मॉडल का मिश्रण है। डिजाइन के अनुसार, सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों में परियोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष भुगतान सृजित परिसंपत्तियों एवं विकासकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

# ग्रीनवाशिग

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने निजी निगमों को ग्रीनवॉशिंग की प्रथा को बंद करने और एक साल के भीतर अपने तरीकों में सुधार करने की चेतावनी दी है।

महासचिव ने पूरी तरह से इससे संबंधित अभ्यास की निगरानी हेत् एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का भी निर्देश दिया है।

#### ग्रीनवॉशिंग:

- 🗅 परिचय:
  - ग्रीनवॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1986 में एक अमेरिकी पर्यावरणविद् और शोधकर्त्ता जे वेस्टरवेल्ड द्वारा किया गया था।
  - ग्रीनवॉशिंग कंपिनयों और सरकारों की गितिविधियों की एक विस्तृत शृंखला को पर्यावरण के अनुकूल के रूप में चित्रित करने का एक अभ्यास है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन से बचा या इसे कम किया जा सकता है।
    - 🗷 इनमें से कई दावे असत्यापित, भ्रामक या संदिग्ध होते हैं।
    - हालाँकि यह संस्था की छिव को बेहतर करने में मदद करता है, लेकिन वे जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में किसी प्रकार का विशेष सहयोग नहीं करता है।
    - शेल और BP जैसे तेल दिग्गजों तथा कोका कोला सिंहत कई बहुराष्ट्रीय निगमों को ग्रीनवॉशिंग के आरोपों का सामना करना पडा है।
  - पर्यावरणीय गतिविधियों की एक पूरी शृंखला में ग्रीनवॉशिंग सामान्य बात है।
    - अक्सर विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में वित्तीय प्रवाह के जलवायु सह-लाभों का सहारा लिया जाता है, जो कि कभी-कभी बहुत कम तर्कसंगत होते है, इन विकसित देशों के इस प्रकार के व्यवसाय निवेशों पर ग्रीनवॉशिंग का आरोप लगता रहता है।
- ग्रीनवॉशिंग का प्रभाव:
  - ग्रीनवॉशिंग जलवायु पिरवर्तन से निपटने के संदर्भ में प्रगित और विकास के गलत आँकड़े पेश करता है जो विश्व को आपदा की ओर अग्रसर करते हैं। इसी के साथ यह गैर-जिम्मेदार व्यवहार के लिये विभिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत भी करता है।

# भारत का पहला जल में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में 'निवेशक दीदी' पहल के तहत 'महिलाओं के लिये, महिलाओं के द्वारा' की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिये भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया।

## निवेशक दीदी पहल:

- ⊃ विषय:
  - 💠 यह महिलाओं के लिये महिलाओं की विचारधारा पर आधारित

है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अपने प्रश्नों को एक महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज महसूस करती हैं।

- 🗅 🏻 कार्यान्वयन एजेंसी:
  - इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तत्त्वाधान में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) के सहयोग से IPPB द्वारा लॉन्च किया गया है।
- पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर:
  - इस सत्र में बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों, विनियमित संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं में शामिल होने के महत्त्व एवं निवेश से जुड़े विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के उपायों से सुरक्षा जैसे विषय शामिल थे।

#### वित्तीय साक्षरता के लिये भारत की अन्य पहलें:

- ⊃ प्रधानमंत्री जन-धन योजना:
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन हेतु
     राष्ट्रीय मिशन है।
- यह किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारिशला रही है। चाहे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम-किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर हो, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को बैंक खाता प्रदान करना है, जिसे PMJDY लगभग पूरा कर चुका है।
- ⊃ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:
  - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रवासियों एवं श्रमिकों को क्रमश: जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा प्रदान करती है।
- 🗅 प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना:
  - PMKMDY की शुरुआत सभी छोटे और सीमांत किसानों (जिन किसानों की भूमि दो हेक्टेयर से कम है) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।
  - 💠 यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है।
  - िकसानों को पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड से किया जाएगा।
  - ♦ किसानों को पेंशन फंड में 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह के बीच की राशि का योगदान करना होगा. जब तक कि वे

सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाते।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः
  - PMMY गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिये वर्ष 2015 में शुरू की गई एक योजना है।
  - इन ऋणों को PMMY के तहत MUDRA ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, RRB, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, MFI और NBFC द्वारा दिये जाते हैं।

## इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ( IPPB ):

- परिचय:
  - यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है।
- उद्देश्य: 0
  - बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिये सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है।
- IPPB का मूल उद्देश्य बैंक सुविधाओं रहित लोगों के लिये बाधाओं को दूर करना है और 160,000 डाकघरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 145,000) एवं 400,000 डाक कर्मचारियों वाले नेटवर्क का लाभ अंतिम मील तक पहुँचाना है।
- IPPB की पहुँच और इसका ऑपरेटिंग मॉडल इंडिया स्टैक के प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है - CBS-एकीकृत स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ग्राहकों के दरवाज़े पर पेपरलेस, कैशलेस एवं उपस्थिति-रहित बैंकिंग को सरल व सुरक्षित तरीके से सक्षम करना।
- आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिये प्रतिबद्ध है।

#### कालानमक चावल

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने उत्तर प्रदेश में कालानमक चावल की दो नई बौनी किस्मों, पूसा नरेंद्र कालानमक 1638 और पूसा नरेंद्र कालानमक 1652 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो दोगुनी उपज देती हैं।

यह पारंपरिक किस्म में कम उपज की समस्या का समाधान करेगा।



# KALADAMAK RICE

#### कालानमक चावल:

- परिचय:
  - कालानमक धान की एक पारंपरिक किस्म है जिसमें काली भूसी और तेज सुगंध होती है।
  - इसे श्रावस्ती के लोगों के लिये 'भगवान बुद्ध का उपहार' माना जाता है जब उन्होंने ज्ञान के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था।
    - ¤ इसे 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) योजना के तहत सिद्धार्थनगर के ओडीओपी उत्पाद के रूप में सम्मानित किया गया है जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित एक आकाँक्षी जिला है।।
  - 💠 यह उत्तरपूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 11 जिलों और नेपाल में उगाया जाता है।
  - यह भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रणाली के तहत संरक्षित है।
- कालानमक चावल से किसानों को लाभ:
  - प्राकृतिक खेती: कालानमक चावल मुख्य रूप से उर्वरक या कीटनाशक अवशेषों का उपयोग किये बिना उगाया जाता है जो इसे फसल उत्पादन के लिये एकदम सही बनाता है।
  - लागत प्रभावी कारक: चूँकि कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिये इसकी लागत कम है और उत्पादकों को पैसे की बचत होती है।
- कालानमक चावल के स्वास्थ्य लाभ:
  - कालानमक चावल एंथोसायनिन की तरह एक एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है, जो हृदय रोग की रोकथाम और त्वचा की देखभाल में सहायता करता है।
  - कालानमक चावल में जिंक और आयरन जैसे बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्त्व शामिल होते हैं। नतीजतन, इस चावल को खाने से जिंक और आयरन की कमी से होने वाली बीमारी से भी बचाव होता है।
  - ♦ ऐसा दावा किया जाता है कि नियमित रूप से कालानामक चावल खाने से अल्जाइमर रोग की रोकथाम में मदद मिल सकती है।

कालानमक चावल शरीर को मजबूत बनाने और गैल्वनाइज करने में मदद कर सकता है, साथ ही रक्तचाप, मधुमेह एवं त्वचा की क्षिति को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।

# GM सरसों की व्यावसायिक खेती

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों के व्यावसायिक रिलीज से पहले बीज उत्पादन को मंज़्री दी है।

## आनुवंशिक रूप से संशोधित ( GM ) फसलें:

- परिचय:
  - GM फसलों के जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किये जाते हैं,
     आमतौर इसमें किसी अन्य फसल से आनुवंशिक गुणों जैसे उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सिहष्णुता, रोग या सूखे से
     प्रतिरोध, या बेहतर पोषण मूल्य का समामेलन किया जा सके।
  - ♦ GM चावल की सबसे प्रसिद्ध किस्म गोल्डन राइस है।
    - गोल्डन राइस के एक पौधे में डैफोडील्स और मक्का के जीन का उपयोग किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इसमें विटामिन A की मात्रा समृद्ध हो जाती है।
  - इससे पहले, भारत ने केवल एक GM फसल, BT कपास की व्यावसायिक खेती को मंज़ूरी दी थी, लेकिन GEAC ने व्यावसायिक उपयोग के लिये GM सरसों की सिफारिश की है।

#### लाभ:

- बढ़ती उपज: आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज पौधे की उपज में वृद्धि देखी गई है। इसका मतलब है कि उतनी भूमि के साथ ही किसान अब काफी अधिक फसल पैदा कर सकता है।
- ♦ विशिष्ट जलवायु में लाभकारी: विशिष्ट परिस्थितियों या जलवायु के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का उत्पादन भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, सूखा प्रतिरोधी बीजों का उपयोग कम पानी वाले स्थानों पर किया जा सकता है ताकि फसल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

#### GM सरसों:

- परिचय:
  - धारा सरसों हाइब्रिड (DMH-11) एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) सरसों का आनुवंशिक तौर पर संशोधित रूप है।

- इसमें दो एलियन जीन ('बार्नेज' और 'बारस्टार') होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियन्स नामक मिट्टी के जीवाणु से आइसोलेट होते हैं जो उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है।
- इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (CGMCP) द्वारा विकसित किया गया है।
- 2017 में GEAC ने HT सरसों की फसल के वाणिज्यिक अनुमोदन की सिफारिश की थी। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार से इस संदर्भ में जनता की राय लेने को कहा।
- महत्त्व: भारत प्रतिवर्ष केवल 8.5-9 मिलियन टन (mt) खाद्य तेल का उत्पादन करता है जबिक यह 14-14.5 मिलियन टन आयात करता है जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 18.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा व्यय किया गया। इसके अलावा जीएम सरसों भारत को तेल उत्पादन में आत्मिनिर्भर बनाने और विदेशी मुद्रा बचाने में सहायक होगी।
  - भारत में सरसों की किस्मों का आनुवंशिक आधार संकीर्ण है। 'बार्नेज'-बारस्टार प्रणाली पूर्वी यूरोपीय मूल की सरसों जैसे 'हीरा' और 'डोंस्काजा' सिहत सरसों की किस्मों की एक विस्तृत शृंखला का मार्ग प्रशस्त करती है।

#### भारत में अन्य GM फसलों की स्थिति:

- ) BT कपास:
  - अतीत में कपास की फसलों को तबाह करने वाले बॉलवर्म के हमले से निपटने के लिये BT कपास की शुरुआत की गई थी, जिसे महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी (महिको) और अमेरिकी बीज कंपनी मोनसेंटो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
  - 2002 में GEAC ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तिमलनाडु जैसे 6 राज्यों में व्यावसायिक खेती के लिये BT कपास को मंज़ूरी दी। यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि BT कपास जीईएसी द्वारा अनुमोदित पहली और एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है।
- DT बैंगन:
  - माहिको ने धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और तिमलनाडु
     कृषि विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से BT बैंगन विकसित
     किया।
  - भले ही GEAC ने वर्ष 2007 में BT बैंगन की व्यावसायिक रिलीज की सिफारिश की थी, लेकिन वर्ष 2010 में इस पहल को रोक दिया गया था।

## जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ( GEAC ):

- यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुन: संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिये जिम्मेदार है।
- समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और उत्पादों के निर्गमन से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिये भी जिम्मेदार है।
- GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC के विशेष सचिव/ अतिरिक्त सचिव करते हैं और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है।

# भारतीय मुद्रा डिज़ाइन तंत्र

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक राजनीतिक दल के प्रमुख ने देश में "समृद्धि" लाने के लिये केंद्र सरकार से नोटों (मुद्रा) पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के चित्र छापने का अनुरोध किया।

## भारतीय बैंक नोटों एवं सिक्कों के डिज़ाइन व जारी करने में कौन-कौन शामिल होता है?

- विषय:
  - ♦ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार बैंक नोटों एवं सिक्कों के डिज़ाइन तथा स्वरूप में बदलाव का फैसला करते हैं।
  - 💠 करेंसी नोट के डिजाइन में किसी भी बदलाव को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।
    - 🗷 सिक्कों के डिज़ाइन में बदलाव करना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है।
- नोट जारी करने में RBI की भूमिका:
  - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22. RBI को भारत में बैंक नोट जारी करने का "एकमात्र अधिकार" प्रदान करती है।
    - 🗷 केंद्रीय बैंक आंतरिक रूप से डिजाइन तैयार करता है, जिसे RBI के केंद्रीय बोर्ड के सामने रखा जाता है।
  - धारा 25 में कहा गया है कि "बैंक नोटों का डिज़ाइन, स्वरूप और सामग्री ऐसी होनी चाहिये जैसा कि RBI के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो"।
  - RBI के मुद्रा प्रबंधन विभाग के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में मुद्रा प्रबंधन के कार्य को प्रशासित करने की जिम्मेदारी है।

- यदि किसी करेंसी नोट का डिजाइन बदलना है, तो विभाग डिज़ाइन पर काम करता है और इसे RBI को प्रस्तुत करता है, जो केंद्र सरकार को इसकी अनुशंसा करता है। सरकार अंतिम मंज़री देती है।
- सिक्कों की ढलाई में केंद्र सरकार की भूमिका:
  - ♦ सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार, विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों की रूपरेखा तैयार करने (डिज़ाइनिंग) तथा ढलाई की ज़िम्मेदारी भारत सरकार की है।
    - 🗷 भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सिक्कों के वितरण करने तक सीमित है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक से वार्षिक आधार पर प्राप्त होने वाले मांगपत्र (इंडेंट) के आधार पर ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा का निर्धारण भारत सरकार करती है।
  - सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के स्वामित्व वाली चार टकसालों में की जाती है। ये टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा में स्थित हैं।

## भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रा प्रबंधन प्रणाली:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार तथा अन्य साझेदारों के परामर्श से एक वर्ष में मृल्यवर्ग वार संभावित आवश्यक बैंक नोटों की मात्रा का आकलन किया जाता है और बैंक नोटों की आपूर्ति हेतू विभिन्न करेंसी प्रिंटिंग प्रेसों को मांगपत्र (इंडेंट) सौंपता है।
  - भारत सरकार की दो प्रिंटिंग प्रेस नासिक (पश्चिमी भारत) तथा देवास (मध्य भारत) में स्थित हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड (BRBNML) की दो अन्य प्रेस मैस्र (दक्षिण भारत) तथा सालबोनी (पूर्वी भारत) में स्थित हैं।
- संचलन से वापस लिये गए बैंक नोटों की जाँच की जाती है तथा जो संचलन के योग्य हैं उन्हें पुन: जारी किया जाता है, जबकि अन्य (गंदे तथा कटे-फटे) को नष्ट कर दिया जाता है ताकि संचलन में बैंक नोटों की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।
  - अब तक जारी नोटों के प्रकार:
  - अशोक स्तंभ वाले बैंक नोट: स्वतंत्र भारत में पहला बैंक नोट वर्ष 1949 में जारी किया गया जो कि 1 रुपए का नोट था। मौज़ुदा डिज़ाइन को जारी रखते हुए नए बैंक नोटों में किंग जॉर्ज के चित्र की बजाय वॉटरमार्क वाले स्थान में सारनाथ के अशोक स्तंभ की लायन कैपिटल के प्रतीक का उपयोग किया गया।
- महात्मा गांधी (एमजी) शृंखला वाले नोट, 1996: इस शृंखला के सभी बैंक नोटों पर अशोक स्तंभ की लायन कैपिटल के प्रतीक के स्थान पर आगे की तरफ महात्मा गांधी का चित्र है. जिसे वॉटरमार्क वाले स्थान के बाईं ओर रखा गया था। इन बैंक नोटों में महात्मा गांधी वॉटरमार्क के साथ-साथ महात्मा गांधी का चित्र भी है।

- ⇒ महात्मा गांधी शृंखला वाले नोट, 2005: "MG सीरीज 2005" के तहत 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट जारी किये गए थे। इन नोटों में 1996 की MG सीरीज की तुलना में कुछ अतिरिक्त/नई सुरक्षा संबंधी विशेषताएँ हैं। इस शृंखला के 500 और 1,000 रुपए के नोटों को 8 नवंबर, 2016 की मध्यरात्रि के बाद वापस ले लिया गया था।
- महात्मा गांधी (नई) शृंखला वाले नोट, 2016: "MGNS" नोट देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करते हैं। छोटे आकार के होने के कारण ये नोट वॉलेट के लिये अधिक अनुकूल हैं, इनके खराब होने की संभावना भी कम होती है। इन नोटों का रंग साफ़ और स्पष्ट है।

# बिग टेक पर आरबीआई की रिपोर्ट

#### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी गैर-वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियाँ जिन्हें "बड़ी प्रौद्योगिकियाँ (बिग टेक)" कहा जाता है, उनके तकनीकी लाभ, बड़े उपयोगकर्ता समुदाय, वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाने और नेटवर्क प्रभावों के कारण वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिम पैदा करती हैं।

#### बिग टेक

- 🗅 विषय:
  - बिग टेक के अंतर्गत अलीबाबा, अमेजन, फेसबुक, गूगल और टेनसेंट जैसी कंपनियाँ शामिल हैं।
  - ये आमतौर पर स्वामित्त्व नियंत्रण और क्षेत्राधिकार नियामक लाभ के विभिन्न स्तरों के साथ सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के माध्यम से सेवा लाइसेंस रखते हैं।
- बिग टेक की बढ़ती भूमिका:
  - तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं के रूप में व्यापक रूप से अपनाए जाने को देखते हुए, बड़ी प्रौद्योगिकियाँ आम तौर पर अंतर्निहित मंच बन जाती हैं, जिसके माध्यम से कई सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
    - बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के कारण, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ अब आसानी से क्रॉस-फंक्शनल डेटाबेस प्राप्त कर सकती हैं जिनका उपयोग अत्याधुनिक उत्पाद प्रस्तुत करने के लिये किया जा सकता है।
  - बिग टेक की व्यापकता उन्हें एक बड़ा ग्राहक आधार प्रदान करती है जो ग्राहकों के डेटा के कई पहलुओं तक पहुँच के साथ अपने प्लेटफार्मों उत्पादों का उपयोग करने में उलझे हुए हैं, जिससे मजबूत नेटवर्क का प्रभाव उत्पन्न होता है।

- वित्त में बड़ी तकनीक का प्रवेश वित्तीय सेवाओं और उनकी मुख्य गैर-वित्तीय सेवाओं के बीच मजबूत पूरकता को भी दर्शाता है।
- तकनीकी लाभों के अलावा, बिग टेक के पास सामान्यत: प्रतिस्पर्धी दबावों का सामना करने के लिये वित्तीय ताकत भी होती है।
- 🗅 भारत द्वारा उठाए गए संबंधित कदम:
  - भारत में भुगतान डेटा के स्थानीय भंडारण और महत्त्वपूर्ण भुगतान मध्यस्थों को औपचारिक ढाँचे में लाने के प्रयास किये गए हैं।
  - भुगतान स्वीकृति के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और डेटा संरक्षण कानून बनाने के लिये भी पहल की जा रही है।

# PM किसान सम्मान सम्मेलन

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।

#### PM किसान सम्मान सम्मेलन

- प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान/ PM-KISAN) फंड की 12वीं किस्त जारी की। योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 16,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गए।
- प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 'प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्रों' (PMKSK) का भी उद्घाटन किया। इस योजना के तहत देश में 3 लाख से अधिक खुदरा उर्वरक दुकानों को चरणबद्ध तरीके से PMKSK में परिवर्तित किया जाएगा।
- ये केंद्र कई किसान जरूरतों को पूरा करेंगे जैसे कृषि-आगतें (उर्वरक, बीज, उपकरण) प्रदान करना; मृदा, बीज, उर्वरक के लिये परीक्षण सुविधाएँ, किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और ब्लॉक/जिला स्तर के आउटलेट पर खुदरा विक्रेताओं की नियमित क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।
- प्रधानमंत्री ने 'प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना' एक राष्ट्र,
   एक उर्वरक भी लॉन्च किया।
- इस योजना के तहत 'भारत यूरिया बैग' लॉन्च किये गए हैं। ये कंपनियों को एकल ब्रॉण्ड नाम "भारत" के तहत उर्वरकों के विपणन में मदद करेंगे।

प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक पर एक ई-पत्रिका 'इंडियन एज्र' का भी शुभारंभ किया गया। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक परिदृश्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें हालिया विकास, मूल्य रुझान विश्लेषण, उपलब्धता और खपत, किसानों की सफलता की कहानियाँ आदि शामिल हैं।

#### PM किसानः

- परिचय:
  - भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 1 नवंबर, 2018 को पीएम-किसान शुरू किया गया था।
- वित्तीय लाभ:
  - ♦ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।
- योजना का दायरा:
  - ♦ यह योजना शुरू में उन छोटे एवं सीमांत किसानों (SMFs) के लिये थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को कवर हेतु बढ़ा दिया गया।
- वित्तपोषण और कार्यान्वयन:
  - यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्रक
  - 💠 इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- उद्देश्य:
  - 💠 इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है।
  - इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाना तथा खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- PM-KISAN मोबाइल एप: इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है।
- बहिष्करण मापदंड: उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ योजना के तहत लाभ के लिये पात्र नहीं होंगी।
  - सभी संस्थागत भूमि धारक।
- वे किसान परिवार जो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक श्रेणियों से संबंधित हैं:
- पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों के धारक

- पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, ज़िला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी. साथ ही केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और सरकार के तहत जुड़े कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारी को छोडकर)।
- उपरोक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपए या अधिक है (मल्टी-टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोडकर)।
- विगत मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
- ऐसे पेशेवर जो निकायों के साथ पंजीकृत हैं और सिक्रय रूप से अपने व्यवसायों का अभ्यास कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट।

# जैविक उर्वरक

### चर्चा में क्यों ?

आर्थिक सुधारों के पथ पर भारत की विकास गाथा ने देश को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है। सही नीतिगत हस्तक्षेप से भारत 'जैविक उर्वरक' उत्पादन का केंद्र बन सकता

## जैविक उर्वरकः

- परिचय:
  - 💠 जैविक उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें जैविक खाद, पशु खाद, मुर्गी पालन और घरेल सीवेज शामिल हैं।
  - सरकारी नियमों के अनुसार, जैविक खाद को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: जैव उर्वरक और जैविक खाद।
- जैव उर्वरक:
  - ♦ यह ठोस या तरल वाहकों से जुड़े जीवित सूक्ष्मजीवों से निर्मित हैं और कृषि योग्य भूमि के लिये उपयोगी होते हैं। ये सूक्ष्मजीव मृदा और/या फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
    - 🗷 उदाहरण: राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, एजोटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल (BGA), माइकोराइजा, एजोला।

- 🗅 जैविक खाद:
  - 'जैविक खाद' का तात्पर्य आंशिक रूप से विघटित कार्बिनक पदार्थ जैसे बायोगैस संयंत्र, खाद और वर्मीकम्पोस्ट से है। ये मृदा / फसलों को पोषक तत्त्व प्रदान करते हैं तथा उपज में सुधार करते हैं।

### भारत में जैविक उर्वरकों की क्षमता:

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग:
  - ♦ भारत 150,000 टन से अधिक नगरपालिका ठोस अपिशष्ट (MSW) का उत्पादन करता है।
  - 80% की संग्रह क्षमता और MSW के जैविक भाग को 50% शामिल करते हुए भारत में उत्पन्न होने वाला कुल जैविक कचरा लगभग 65,000 टन प्रतिदिन है।
  - यहाँ तक कि इसका आधा हिस्सा बायोगैस उद्योग में लगा दिया जाए, सरकार जीवाश्मों और उर्वरकों के आयात में कमी करके इसका लाभ उठा सकती है।
- बायोगैस अपशिष्टों का उपयोग करना:
  - जैविक उर्वरक का महत्त्वपूर्ण है जिसे डाइजेस्टेट भी कहा जाता
     है, जो कि बायोगैस संयंत्र का अपशिष्ट है।
  - बायोगैस का उपयोग हीटिंग, बिजली और यहाँ तक कि वाहनों (उन्नयन के बाद) में किया जा सकता है, जबिक डाइजेस्ट दूसरी हरित क्रांति के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद कर सकता है।
- ⊃ 🏻 मृदा की उर्वरता बढ़ाना:
  - डाइजेस्ट अपने मानक पोषण मूल्य के अलावा लगातार घटती मृदा को कार्बनिक के लिये कार्बन प्रदान कर सकता है।
  - भारत में वर्तमान में जैव-उर्वरक का उत्पादन सिर्फ 110,000 टन (वाहक आधारित 79,000 टन और तरल-आधारित 30,000 टन) तथा 34 मिलियन टन जैविक खाद है, जो कि शहरीय अपशिष्ट और वर्मीकम्पोस्ट से बना है।
- जैविक खेती की लोकप्रियता:
  - हाल के वर्षों में घरेलू बाजार में जैविक खेती की लोकप्रियता बढ़ी है।
    - भारतीय जैविक पैकेज्ड फूड का बाजार आकार 17% की दर से बढ़ने और वर्ष 2021 तक 871 मिलियन रुपए के आँकड़े को पार करने की उम्मीद है।
  - इस क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि मृदा पर सिंथेटिक उर्वरक के हानिकारक प्रभावों के बारे में बढ़ती जागरूकता, बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं, शहरी जनसंख्या आधार का विस्तार और खाद्य वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय में वृद्धि से जुड़ी है।

#### संबंधित पहल:

- सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SA-TAT) योजना।
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- ⊃ कृषि वानिकी पर उप-मिशन
- 🗅 सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
- ⊃ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

# बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता

#### चर्चा में क्यों?

बेहतर पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (EASE) सुधारों के एक हिस्से के रूप में सरकार नए खंडों को जोड़कर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का लाभ उठाने की योजना बना रही है।

## प्रमुख बिंदुः

- पहल तथा लक्ष्य केंद्र द्वारा किये जा रहे EASE सुधार कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।
- ग्रामीण बैंकों को फसल ऋण के अलावा ट्रैक्टर, छोटे उद्यमों, शिक्षा और आवास के लिये ऋण देने के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों के लिये ऋण प्रदान करने के लिये कहा जाएगा।
- केंद्र सरकार शिक्षा ऋण के लिये गारंटी सीमा 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक शिक्षा क्षेत्र को ऋण की सुविधा देना फिर से शुरू करें।
- सरकार की योजना RRB की लाभप्रदता में सुधार जारी रखने की है।
  - कोविड-19 महामारी की अविध के दौरान लगातार दो वर्षों के नुकसान के बाद RRB ने वित्त वर्ष 2011 में 1,682 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जिसमें से 43 RRBs में से 30 ने शुद्ध लाभ दर्ज किया।

#### महत्त्व:

- यह RRBs को अपने वृहत ग्रामीण नेटवर्क और स्थानीय समझ का लाभ उठाकर व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगा तथा शिक्षा, आवास एवं सूक्ष्म व्यवसायों जैसे उद्देश्यों के लिये ग्रामीण उपभोक्ताओं तक ऋण की पहुँच में भी वृद्धि करेगा।
- RRB को छोटे उद्यमों, आवास और शिक्षा के लिये ऋण प्रदान करने हेतु निर्देश से इन क्षेत्रों के लिये ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

- RRB को अधिक प्रतिस्पर्द्धी और व्यवसाय के अनुकूल बनने की दिशा में निर्देशित किया जाएगा यानि उन्हें ग्राहक अनुकूल बनाने का एजेंडा सबसे प्राथमिक है।
- RRB के लिये EASE कार्यक्रम परिचालनों को डिजिटल बनाने और RRB को एक-दूसरे से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

## EASE सुधार क्या है?

- इसे सरकार और PSB द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
- यह इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से बोस्टन कंसिल्टंग ग्रुप द्वारा तैयार किया गया।
- इसका उद्देश्य लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और डिजिटल क्षमताओं में सुधार के लिये PSB में नए युग के सुधारों को बढावा देना है।
- EASE सुधार एजेंडा के तहत विभिन्न चरण:
  - EASE 1.0: EASE 1.0 रिपोर्ट ने पारदर्शी रूप से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के समाधान में PSB के प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार दिखाया।
  - EASE 2.0: EASE 2.0 को EASE 1.0 की नींव पर बनाया गया था और सुधार प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय बनाने, प्रणालियों को मजबूत करने तथा परिणामों को प्रभावित करने के लिये छह विषयों में नए सुधार कार्य बिंदु पेश किये गए, ये छह विषय हैं:
    - जिम्मेदार बैंकिंग
    - ग्राहक प्रतिक्रिया
    - क्रेडिट ऑफ-टेक
    - उद्यमी मित्र के रूप में PSB (MSME के क्रेडिट प्रबंधन के लिये SIDBI पोर्टल)
    - वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण
    - 🙎 शासन और मानव संसाधन (HR)
  - EASE 3.0: यह तकनीक का उपयोग करते हुए सभी ग्राहकों के लिये बैंकिंग को आसान बनाने का प्रयास करता है।

    - फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ साझेदारी,
    - क्रेडिट@क्लिक करें.
    - तकनीक-सक्षम कृषि ऋण,
    - EASE बैंकिंग आउटलेट आदि।
  - EASE 4.0: यह ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढाने के लिये PSB को तकनीक-सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग के लिये प्रतिबद्ध करता है।

- इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख विषय प्रस्तावित किये गए:
- 24×7 बैंकिंग
- उत्तर-पूर्वी राज्यों पर फोकस
- बैड बैंक
- बैंकिंग क्षेत्र के बाह्य क्षेत्रों से धन का सजन:
- फिनटेक क्षेत्र का लाभ उठाना

#### EASE 5.0:

- 🗷 बदलती उपभोक्ता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रतिस्पर्द्धी गतिशीलता और तकनीकी वातावरण को बदलने के लिये PSB अत्याधुनिक क्षमताओं में निवेश करते रहेंगे और जारी सुधारों को तेज करेंगे।
- यह छोटे व्यवसायों और कृषि का समर्थन करने पर जोर देने के साथ डिजिटल ग्राहक अनुभव एवं एकीकृत तथा समावेशी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ये पहलें विविध विषयों पर केंद्रित होंगी जैसे- व्यवसाय वृद्धि, लाभप्रदता, जोखिम, ग्राहक सेवा, संचालन व क्षमता निर्माण।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( RRBs ):

- परिचय:
  - ♦ RRBs वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975) की सिफारिशों के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के विनियमन के बाद की गई थी।
  - ♦ पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक "प्रथम ग्रामीण बैंक" 2 अक्तूबर, 1975 को स्थापित किया गया था।
  - RRBs को अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक है।

#### हितधारक:

💠 एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के पास 50:15:35 के अनुपात में होती है।

#### उद्देश्य:

- 💠 ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मज़दूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जमाओं के बहिर्वाह को रोकना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करना।

# धन शोधन निवारण अधिनियम

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले एक राजनेता की याचिका को खारिज कर दिया है।

#### धन शोधनः

- विषय:
  - ♦ मनी लॉन्डिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।
    - 🗷 अवैध हथियारों की बिक्री, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति, गुप्त व्यापार, रिश्वतखोरी और कंप्यूटर धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतिविधियों में बड़ा मुनाफा होता है।
  - ऐसा करने से यह मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त व्यक्ति को मनी लॉन्डिंग के माध्यम से अपने अवैध लाभ को "वैध" करने के लिये एक प्रोत्साहन देता है।
  - ♦ इससे उत्पन्न धन को 'डर्टी मनी' कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग "डर्टी मनी" को 'वैध' धन के रूप में प्रकट करने के लिये रूपांतरण की प्रक्रिया है।

#### चरण:

- प्लेसमेंट: यह मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है, इसके तहत अपराध से संबंधित धन का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है।
- लेयरिंग: दूसरे चरण में मनी लॉन्डिंग में प्रवेश कराए गए पैसे की 'लेयरिंग' की जाती है और उस पैसे के अवैध उद्गम स्रोत को छिपाने के लिये विभिन्न लेन-देन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है।
- 💠 एकीकरण: तीसरे और अंतिम चरण में धन को वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि इसके अपराध के साथ मूल जुड़ाव को समाप्त कर धन को अपराधी द्वारा पुन: वैध तरीके से उपयोग किया जा सके।

## धन शोधन निवारण अधिनियम ( PMLA ), 2002:

- पृष्ठभूमि:
  - धन शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में PMLA

अधिनियमित किया गया था। इसमे शामिल है:

- 🗷 नारकोटिक इग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988
- सिद्धांतों का बेसल वक्तव्य, 1989
- मनी लॉन्डिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सिफारिशें, 1990
- 🗷 वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम।

#### परिचय:

- 💠 यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्डिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- ♦ इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

#### PMLA में हाल के संशोधन:

- अपराध से अर्जित आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण: अपराध से अर्जित आय (Proceeds of crime) में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि किसी भी आपराधिक गतिविधि से संबंधित या अनुसूचित अपराध के समान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होकर प्राप्त की गई कोई अन्य संपत्ति भी शामिल होगी।
- मनी लॉन्डिंग की परिभाषा में परिवर्तन: इससे पूर्व मनी लॉन्डिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराध पर निर्भर था, जिसे विधेय अपराध या अनुसचित अपराध (Predicate offence or Scheduled offence) के रूप में जाना जाता है।
- 💠 संशोधन ने मनी लॉन्ड्रिंग को स्वयं में विशिष्ट अपराध मानने का प्रयास किया है।
- PMLA की धारा 3 के तहत उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्जित आय से संलग्न है।
  - आय छिपाना
  - स्वामित्व
  - अधिग्रहण
  - बेदाग संपत्ति के रूप में उपयोग करना या पेश करना
  - बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना

अपराध की निरंतर प्रकृति: इस संशोधन में आगे उल्लेख किया गया है कि उस व्यक्ति को मनी लॉन्डिंग के अपराध में उस स्तर तक शामिल माना जाएगा जहाँ तक उस व्यक्ति को मनी लॉन्डिंग से संबंधित गतिविधियों का फल मिल रहा है क्योंकि यह अपराध निरंतर प्रकृति का है।

# चलनिधि समायोजन सुविधा

#### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अक्तूबर 2022 में बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ावा देने के लिये 72,860.7 करोड़ रुपए का निवेश किया। त्योहारी सीज़न के दौरान क्रेडिट की अधिक मांग के चलते तरलता की स्थिति सख्त होने के बाद यह अप्रैल 2019 के बाद से सबसे अधिक है।

रुपए की अस्थिरता को कम करने के लिये यह विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप है।

#### तरलताः

- बैंकिंग प्रणाली में तरलता आसानी से उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है जिससे बैंक अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को परा करते हैं।
- किसी निश्चित दिन पर यदि बैंकिंग प्रणाली तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत RBI से एक शुद्ध उधारकर्त्ता है, तो इसे तरलता के घाटे की स्थिति कहा जाता है और यदि बैंकिंग प्रणाली RBI के लिये एक शुद्ध ऋणदाता है तो इसे तरलता अधिशेष कहा जाता है।

## तरलता समायोजन सुविधा ( LAF ):

- LAF भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों, रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण प्राप्त करने या रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से RBI को ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है।
- इसे वर्ष 1998 के बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिंहम समिति के परिणाम के एक भाग के रूप मंग पेश किया गया था।
- तरलता समायोजन सुविधा के दो घटक रेपो (पुनर्खरीद समझौता) और रिवर्स रेपो हैं। जब बैंकों को अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये तरलता की आवश्यकता होती है, तो वे रेपो के माध्यम से RBI से उधार लेते हैं। जब बैंकों के पास धन की अधिकता होती है, तो वे रिवर्स रेपो प्रणाली के माध्यम से रिवर्स रेपो दर पर RBI को उधार देते हैं।
- इससे मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर व घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन किया जा सकता है।

- LAF का उपयोग बैंकों को आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान या उनके नियंत्रण से परे होने वाले उतार-चढाव की स्थिति में अल्पकालिक नकदी की कमी को पूरा करने के लिये किया जाता
- विभिन्न बैंक रेपो समझौते के माध्यम से पात्र प्रतिभृतियों को बंधक  $\supset$ के रूप में उपयोग करते हैं और अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये धन का उपयोग करते हैं, इस प्रकार इनकी स्थिरता बनी रहती है।
- इस सुविधा को दिन-प्रतिदिन के आधार पर लागू किया जाता है क्योंकि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास ओवरनाइट बाज़ार में पर्याप्त पूंजी है।
- चलनिधि समायोजन सुविधाओं का लेन-देन नीलामी के माध्यम से दिन के एक निर्धारित समय पर होता है।

## मौद्रिक नीतिः

- मौद्रिक नीति का तात्पर्य निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये केंद्रीय बैंक द्वारा अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों का उपयोग करना है।
- 0 RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य, विकास को ध्यान में रखते हुए मुल्य स्थिरता बनाए रखना है।
  - 💠 सतत् विकास के लिये मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
- संशोधित RBI अधिनियम, 1934 में हर पाँच साल में एक बार रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% + -2%) रखने का भी प्रावधान है।
- मौद्रिक नीति के उपकरण:
  - ♦ नकद आरक्षित अनुपात (CRR)।
  - वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)।
  - बैंक दर।
  - ♦ स्थायी जमा सुविधा (SDF)।
  - ♦ सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)।
  - ♦ नकद आरक्षित अनुपात (CRR)।

# स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS)

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित किया है।

## स्टार्टअप के लिये क्रेडिट गारंटी योजना ( CGSS ):

- 🗅 परिचय:
  - यह योजना पात्र स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के क्रम में सदस्य संस्थानों (MIs) द्वारा दिये गए ऋण को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
    - MIs में वित्तीय मध्यस्थ (बैंक, वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) शामिल हैं। ये संस्थान ऋण देने/ निवेश करने के साथ योजना के तहत अनुमोदित पात्रता मानदंड के अनुरूप होते हैं।
  - यह योजना स्टार्ट-अप्स को बंधक -मुक्त आवश्यक ऋण निधि
     प्रदान करने में मदद करेगी।
  - इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर, लेन-देन आधारित और अम्ब्रेला आधारित होगा।
  - अलग-अलग मामलों में एक्सपोज़र की सीमा 10 करोड़ रुपए प्रति मामला या वास्तविक बकाया क्रेडिट राशि (जो भी कम हो) मान्य होगी।
  - लेन-देन आधारित गारंटी कवर के संबंध में गारंटी कवर सदस्य संस्थानों (MI) द्वारा एकल पात्र उधाकर्त्ता आधार पर प्राप्त किया जाता है।
    - म लेन-देन आधारित गारंटी से बैंकों/NBFCs द्वारा पात्र स्टार्टअप को ऋण देने को बढावा मिलेगा।
  - अम्ब्रेला धारित गारंटी कवर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) नियमों के तहत पंजीकृत वेंचर डेट फंड (VDF) को गारंटी प्रदान करेगा।

#### लक्ष्यः

इसका लक्ष्य उन स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना है जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं एवं अब बढ़ती ब्याज दर परिदृश्य के कारण उनके और अधिक प्रभावित होने की संभावना है तथा नए उद्यमियों को आसानी से तरलता उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

#### भारत में स्टार्टअप्प की स्थिति:

- परिचय:
  - अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
     स्टार्टअप्स इकोसिस्टम बन गया है।
    - 🛚 भारत में 75,000 स्टार्टअप्स हैं।
    - 🙎 49% स्टार्टअप्स टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं।
  - वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 44 की शुरुआत वर्ष 2021 में और 19 की वर्ष 2022 में हुई।

- IT, कृषि, विमानन, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स उभर रहे हैं।
- संबंधित पहलें:
  - नवाचारों के विकास और दोहन हेतु राष्ट्रीय पहल (NIDHI/ निधि)
  - ♦ स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान (SIAP)
  - पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (RSSSE)
  - ♦ स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS)

# पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन/PM-DevINE) को मंज़्री दी।

 पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) में विकास अंतराल को दूर करने के लिये केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।

#### पीएम-डिवाइन योजनाः

- 그 परिचय:
  - यह 100% केंद्रीय वित्तपोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना
     है।
  - पीएम-डिवाइन योजना में वर्ष 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अविध के शेष वर्षों) तक चार साल की अविध में 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा।
  - पीएम-डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त है। यह मौजूदा केंद्र और राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं होगी।
- 🗅 कार्यान्वयन:
  - यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों/ एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी।
- ⊃ उद्देश्य:
  - पीएम गित शक्ति में सिम्मिलित रूप से बुनियादी ढाँचे को निधि
     देना;
  - एनईआर द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना;
  - युवाओं और महिलाओं के लिये आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना:
  - विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को कम करना।

## भारत के लिये पूर्वीत्तर का महत्त्व:

- सामरिक महत्त्व: पूर्वोत्तर भारत दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे का प्रवेश द्वार है। यह म्याँमार के लिये भारत का भूमि-पुल है।
  - भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के पूर्व की ओर संलग्नता की क्षेत्रीय अग्रिम पंक्ति पर रखती है।
- सांस्कृतिक महत्त्व: पूर्वोत्तर भारत दुनिया के सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है। यह 200 से अधिक जनजातियों का घर है। लोकप्रिय त्योहारों में नगालैंड का हॉर्निबल महोत्सव, सिक्किम का पांग ल्हाबसोल आदि शामिल हैं।
  - पूर्वोत्तर भारत दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से मुक्त क्षेत्र है।
  - पूर्वोत्तर की संस्कृतियों की समृद्धता कपड़ों पर बनी चित्रकारी और इसके अत्यधिक विकसित लोक नृत्य रूपों जैसे बिह् (असम) में परिलक्षित होती है।
  - ♦ मिणपुर में पिवत्र उपवनों में प्रकृति की पूजा करने की परंपरा है, जिसे उमंगलाई कहा जाता है।
- आर्थिक महत्त्व: आर्थिक रूप से यह क्षेत्र चाय, तेल और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है।
  - 💠 यहाँ 50000 मेगावाट की जलविद्युत शक्ति और जीवाश्म ईंधन के प्रचुर भंडार के साथ एक स्थापित विद्युतगृह है।
- पारिस्थितिक महत्त्व: पूर्वोत्तर भारत-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों और पादपों की जैवविविधता में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।

## पूर्वोत्तर भारत से संबंधित वर्तमान चुनौतियाँ:

- शेष भारत से अलगाव: भौगोलिक कारणों और शेष भारत के साथ अविकसित परिवहन ढाँचे के कारण इस क्षेत्र तक पहुँच हमेशा कमज़ोर रही है।
- कुशल बुनियादी ढाँचे का अभाव: बुनियादी ढाँचे यानी भौतिक (जैसे सड़क मार्ग, जलमार्ग, ऊर्जा आदि) के साथ-साथ सामाजिक बुनियादी ढाँचा (उदाहरण के लिये शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएँ) किसी भी क्षेत्र के मानव विकास और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।।
  - पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की खराब स्थिति है।
- औद्योगिक विकास की धीमी गति: औद्योगिक विकास के मामले में पूर्वोत्तर ऐतिहासिक रूप से अविकसित रहा है।
- प्रादेशिक संघर्ष: पूर्वोत्तर के भीतर मौजूदा अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघर्ष रहे हैं, जो अक्सर ऐतिहासिक सीमा विवादों एवं भिन्न जातीय, आदिवासी या सांस्कृतिक समानता पर आधारित होते हैं। उदाहरण: असम-मिज़ोरम सीमा विवाद।

- विद्रोह और राजनीतिक मुद्देः उग्रवाद या आतंकवाद एक राजनीतिक हथियार है और अक्सर राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से जन्म लेता है।
  - पूर्वोत्तर राज्यों ने अन्य भारतीय राज्यों से शोषण और अलगाव की भावना के साथ विद्रोही गतिविधियों एवं क्षेत्रीय आंदोलनों का उदय देखा है।

# पूर्वोत्तर में प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:

- रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी:
  - 4,000 किमी. सडकें, 2,011 किमी. की 20 रेलवे परियोजनाएँ और 15 हवाई कनेक्टिविटी परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं।
- जलमार्ग कनेक्टिविटी:
  - 💠 गंगा, ब्रह्मपुत्र व बराक निदयों के राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा पर NW-1, ब्रह्मपुत्र पर NW-2 और बराक पर NW-16) बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये विकास के चरण में हैं।
- ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड:
  - 💠 यह 5,000 किमी. नौगम्य जलमार्ग प्रदान करके पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोडेगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (NERPSIP):
  - ♦ NERPSIP इंट्रा-स्टेट ट्रांसिमशन एंड डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम को मजबूत करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की दिशा में एक बडा कदम है।
  - सरकार विद्युत पारेषण और वितरण, मोबाइल नेटवर्क, 4जी तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं पर भी जोर दे रही है।

# भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गाँव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया।

## भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव:

- मोढेरा गाँव: मोढेरा अपने सूर्य मंदिर, संरक्षित प्राचीन स्थल के लिये प्रसिद्ध है, जो पुष्पावती नदी पर स्थित है। इसे चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने 1026-27 इस्वी में बनवाया था।
- मंदिर में 3-डी प्रोजेक्शन सुविधा मिलेगी जो पर्यटकों को मोढेरा के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

- सौर ऊर्जा उत्पादन: सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा गाँव आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि यह गाँव के घरों पर लगाए गए 1000 सौर पैनलों का उपयोग करेगा. जिससे ग्रामीणों के लिये चौबीसों घंटे बिजली पैदा होगी।
  - इसे ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और आवासीय एवं सरकारी भवनों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से विकसित किया गया है, जो सभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के साथ एकीकृत हैं।
    - □ BESS एक प्रकार की ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो बिजली के रूप में ऊर्जा को स्टोर और वितरित करने के लिये बैटरी का उपयोग करती है।

#### लाभ:

- यह परियोजना प्रदर्शित करेगी कि कैसे भारत की अक्षय ऊर्जा कौशल जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बना सकती है।
  - 🗷 गाँव के लोग बिजली के लिये भुगतान नहीं करेंगे, बल्कि वे इसे बेचना शुरू कर सकते हैं और सौर पैनल द्वारा उत्पादित ऊर्जा को सरकारी ग्रिड को बेचकर धन कमा सकते हैं।
  - यह परियोजना ग्रामीण स्तर पर रोज़गार पैदा करेगी और अंतत: जीवन स्तर में सुधार होगा।
- इससे क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं के सतत् कार्यान्वयन को बढावा मिलेगा।
  - 🗷 क्षेत्र के निवासी अपने बिजली बिलों का 60-100% बचा सकेंगे।
- इससे उन ग्रामीण महिलाओं और लडिकयों के कठिन परिश्रम में कमी आएगी जो लंबी दूरी से ईंधन की लकड़ी के संग्रह करने और रसोई में खाना पकाने में लगी हुई हैं।
  - प्र यह फेफडों और आँखों की बीमारियों के जोखिम को भी कम करेगा।

## भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति:

- परिचय: पिछले 8 वर्षों में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 19.3 गुना वृद्धि हुई है और यह 56.6 GW है।
  - 💠 इसके अलावा भारत ने वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट (GW) अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अक्षय ऊर्जा के लिये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है।
  - भारत नई सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में एशिया में दुसरा और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यह पहली बार जर्मनी (59.2 GW) को पछाडते हुए कुल स्थापित क्षमता (60.4 GW) के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है।

- 💠 जून 2022 तक राजस्थान और गुजरात बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले शीर्ष राज्य थे, जिनकी स्थापित क्षमता क्रमश: 53% एवं 14% थी, इसके बाद महाराष्ट्र (9%) का स्थान है।
- संबंधित पहलें:
  - सौर पार्क योजना: सौर पार्क योजना कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट (MW) क्षमता वाले कई सोलर पार्क बनाने की योजना है।
  - ♦ रूफटॉप सौर योजना: रूफटॉप सौर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना है।
  - अटल ज्योति योजना (अजय): अजय योजना सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (SSL) प्रणाली की स्थापना के लिये शुरू की गई थी, जहाँ 50% से कम घरों में ग्रिड आधारित बिजली का उपयोग शामिल है (2011 की जनगणना के अनुसार)।
  - ♦ राष्ट्रीय सौर मिशन: यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढावा देने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है।
  - 💠 सृष्टि योजना: भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये सोलर ट्रांसिफगरेशन ऑफ इंडिया (सृष्टि) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

# यूनेस्को की 50 प्रतिष्ठित वस्त्र शिल्पों की सूची

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है।

दक्षिण एशिया में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये  $\supset$ प्रमुख चुनौतियों में से एक उचित सूची और प्रलेखन की कमी है।

## कुछ महत्त्वपूर्ण सूचीबद्ध वस्त्र शिल्पः

- तमिलनाडु की टोडा कढ़ाई और सुंगुडी  $\mathsf{C}$
- हैदराबाद की हिमरू बुनाई D
- ओडिशा के संबलपुर की बंधा टाई और डाई बुनाई 0
- गोवा की कुनबी बुनाई 0
- 0 गुजरात की मशरू बुनाई और पटोला
- महाराष्ट्र की हिमरू 0
- पश्चिम बंगाल की गरद-कोरियल

- कर्नाटक की इलकल और लंबाडी या बंजारा कढ़ाई
- तमिलनाडु की सिकलनायकनपेट कलमकारी
- हरियाणा की खेस
- हिमाचल प्रदेश के चंबा के रुमाल
- लद्दाख के थिग्मा या ऊन की टाई और डाई
- वाराणसी की अवध जामदानी

# यूनेस्को

- परिचय:
  - इसकी स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति के साधन के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी। यह पेरिस, फ्राँस में स्थित है।
- यूनेस्को की प्रमुख पहलें:
  - मानव व जीवमंडल कार्यक्रम
  - विश्व विरासत कार्यक्रम
  - यनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क
  - यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क
  - 💠 एटलस ऑफ द वल्ड्र्स लैंग्वेजेज़ इन डेंजर

## अमूर्त सांस्कृतिक विरासत:

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वे प्रथाएँ, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान और कौशल हैं जिन्हें समुदाय, समूह तथा कभी-कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं।
  - इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है, इसे आमतौर पर निम्नलिखित रूपों में से एक में व्यक्त किया जाता है:
  - मौखिक परंपराएँ
  - कला प्रदर्शन
  - सामाजिक प्रथाएँ
  - अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम
  - प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं अभ्यास
  - पारंपरिक शिल्प कौशल
- मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शमिल हैं।

यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें				
1.	वैदिक जप की परंपरा, 2008	8.	लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, 2012	

2.	रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, 2008	9.	मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोलक बजाना और नृत्य करना, 2013
3.	कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर, 2008	10.	जंडियाला गुरु, पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्प, 2014
4.	रम्माण, गढ़वाल हिमालय (भारत) के धार्मिक उत्सव और परंपरा का मंचन, 2009	11.	योग, 2016
5.	मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक, 2010	12.	नवरोज, 2016
6.	कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत और नृत्य, 2010	13.	कुंभ मेला, 2017
7.	छऊ नृत्य, 2010	14.	दुर्गा पूजा, 2021

## भारत के वस्त्र क्षेत्र की स्थिति:

- परिचय:
  - वस्त्र एवं परिधान उद्योग एक श्रम-प्रधान क्षेत्र है, जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और रोजगार के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा प्रमुख क्षेत्र है।
  - वस्त्र क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, विरासत एवं संस्कृति का निधान और वाहक है।
  - इसे दो खंडों में विभाजित किया जा सकता है:
    - असंगठित क्षेत्र छोटे पैमाने पर है और पारंपिरक उपकरणों एवं विधियों का उपयोग करता है। इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प तथा रेशम उत्पादन (रेशम का उत्पादन) शामिल हैं।
    - 🗷 संगठित क्षेत्र आधुनिक मशीनरी और तकनीकों का उपयोग करता है एवं इसमें कताई, परिधान और वस्त्र शामिल हैं।
- वस्त्र उद्योग का महत्त्व:
  - ♦ यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत की निर्यात आय में 12% और कुल रोज़गार में 21% से अधिक का योगदान देता है।
  - भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों (Technical Textile) का छठा (विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक) बड़ा उत्पादक देश है।

- तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं।
- भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है जिसकी विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़े के मामले में 95% हिस्सेदारी है।

# वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2022

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII), 2022 रैंकिंग में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर है।

🗅 भारत २०२१ में ४६वें और २०१५ में ८१वें स्थान पर था।

## रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- देशों की रैंकिंग:
  - सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था:
    - वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है- लगातार 12वें वर्ष- इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम व नीदरलैंड का स्थान है।
    - चीन शीर्ष 10 के करीब है, जबिक तुर्की और भारत पहली बार शीर्ष 40 में शामिल हुए हैं।
  - भारत का प्रदर्शन:
    - 🗷 भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में नवोन्मेषी नेतृत्त्वकर्ता है।
    - यह ICT सेवाओं के निर्यात में दुनिया के नेतृत्वकर्ता के साथ अन्य संकेतकों में शीर्ष रैंकिंग में शामिल है, जिसमें उद्यम पूँजी प्राप्ति मूल्य, स्टार्टअप और स्केलअप के लिये वित्त, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक, श्रम उत्पादकता वृद्धि तथा घरेलू उद्योग विविधीकरण शामिल हैं।
- ⊃ अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धिः
  - शीर्ष वैश्विक कॉर्पोरेट R&D पर खर्च करने वालों ने अपने R&D खर्च को वर्ष 2021 में लगभग 10% बढ़ाकर 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कर दिया है जो महामारी से पहले वर्ष 2019 की तुलना में अधिक है।
- 🔾 वेंचर कैपिटल (VC) ग्रोथ:
  - वर्ष 2021 में 46% के साथ इसमें बेहतरीन वृद्धि हुई है, वर्ष 1990 के दशक के बाद से यह रिकॉर्ड स्तर रहा है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन तथा अफ्रीकी क्षेत्रों में VC की सबसे अधिक वृद्धि देखी जा रही है।

## वैश्विक नवाचार सूचकांक ( GII ):

- 🗅 परिचय:
  - 'वैश्विक नवाचार सूचकांक'(GII) देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक है।
  - बड़ी संख्या में देश GII का उपयोग अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन और सुधार करने के लिये करते हैं तथा GII को आर्थिक योजनाओं एवं/या नीतियों में संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं।
  - सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के संबंध में नवाचार को मापने के लिये GII को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिये नवाचार पर 2019 के संकल्प में एक आधिकारिक बेंचमार्क के रूप में मान्यता दी गई है।
- 🔾 सूचकांक के संकेतक:
  - सूचकांक की गणना के मानकों में 'संस्थान', 'मानव पूंजी और अनुसंधान', 'आधारभूत ढाँचे', बाजार' संरचना', 'व्यापार संरचना', 'ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आउटपुट' शामिल हैं।
- 🗅 2022 की थीम: "नवाचार-संचालित विकास का भविष्य क्या है ?"
- दो नवीन नवाचारों का प्रभाव: GII 2022 दो नवीन नवाचार के सकारात्मक प्रभावों को भी रेखांकित करता है, हालाँकि यह इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के प्रभावों को महसूस होने में कुछ समय लगेगा:
  - सुपरकंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर निर्मित डिजिटल युग नवाचार।
  - प्रभाव: वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादकता प्रभाव बनाना।
  - जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, नई सामग्री, और अन्य प्रौद्योगिकी सफलताओं पर निर्मित एक गहन विज्ञान नवाचार।
  - स्वास्थ्य, भोजन, पर्यावरण और गतिशीलता में क्रांतिकारी नवाचार (समाज के लिये महत्त्वपूर्ण चार क्षेत्र)।

## विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ( WIPO ):

- WIPO बौद्धिक संपदा (IP) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिये वैश्विक मंच है।
- यह 193 सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है।
- इसका उद्देश्य संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय IP प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिये नवाचार एवं रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।

इसका जनादेश, शासी निकाय और प्रक्रियाएँ WIPO कन्वेंशन में निर्धारित की गई हैं, जिसने वर्ष 1967 में WIPO की स्थापना की थी।

# दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (TTDF) योजना की शुरुआत की।

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत ग्रामीण एवं दरस्थ डिजिटल कनेक्टिविटी के वित्तपोषण हेतु एक निकाय है।
- केंद्र ने दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे में कहा है कि 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत बनाए गए USOF को "दुरसंचार विकास कोष" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

### दुरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष ( TTDF ) योजना:

- TTDF का उद्देश्य ग्रामीण-विशेष संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्तपोषित करना, दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण तथा विकास के लिये अकादिमक, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच तालमेल स्थापित करना है।
- इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्वामित्व और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सह-नवाचार की संस्कृति बनाना, आयात को कम करना, निर्यात के अवसरों को बढावा देना तथा बौद्धिक संपदा का निर्माण करना है।
- इस योजना के तहत USOF देशव्यापी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मानकों को विकसित करने और अनुसंधान, डिजाइन, प्रोटोटाइप, उपयोग के मामलों, पायलटों और परीक्षण के प्रमाण के लिये पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण को भी लक्षित कर रहा है।
- यह योजना घरेलु ज़रूरतों को पूरा करने के लिये स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन और उन्हें शामिल करने के लिये भारतीय संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराने पर जो र देती है।

## भारत के दुरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- भारत में दूरसंचार उद्योग वर्ष 2022 तक 1.17 बिलियन ग्राहकों के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारत की कुल टेलीडेंसिटी (एक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक सौ व्यक्तियों के लिये टेलीफोन कनेक्शन की संख्या) 85.11 प्रतिशत है।
- ि पिछले कुछ वर्षों में उद्योग की घातीय वृद्धि मुख्य रूप से किफायती टैरिफ, व्यापक उपलब्धता, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP)

- के रोलआउट, 3G और 4G कवरेज का विस्तार एवं ग्राहकों के उपभोग प्रतिरूप को विकसित करने की वजह से प्रेरित है।
- FDI प्रवाह के मामले में दुरसंचार क्षेत्र तीसरा सबसे बडा क्षेत्र है. जो कुल FDI प्रवाह में 6.44% योगदान देता है और प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन रोजगार एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन रोजगार प्रदान करता है।
- वर्ष 2014 से 2021 के बीच दूरसंचार क्षेत्र में FDI प्रवाह 150% बढकर 20.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो वर्ष 2002-2014 के दौरान 8.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- टेलीकॉम सेक्टर में अब ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष 0 विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दे दी गई है।
- भारत वर्ष 2025 तक लगभग 1 बिलियन स्थापित उपकरणों के साथ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनने की राह पर है और वर्ष 2025 तक 920 मिलियन मोबाइल ग्राहक होने की उम्मीद है जिसमें 88 मिलियन 5G कनेक्शन शामिल होंगे।

# भारत में कार्ड का टोकनाइज़ेशन

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-एप लेनदेन में उपयोग किये जाने वाले सभी क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के लिये टोकनाइजेशन अनिवार्य कर दिया है।

उपभोक्ता को टोकनाइज़ेशन सेवा के बदले कोई भी शुल्क नहीं देना पडेगा।

## टोकनाइज़ेशन:

यह वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड में बदलने को संदर्भित करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता (वह इकाई जो कार्ड के टोकनाइजेशन के लिये ग्राहक का अनुरोध स्वीकार करता है और संबंधित टोकन जारी करने के लिये इसे कार्ड नेटवर्क पर भेजता है) तथा डिवाइस के संयोजन के लिये विशिष्ट होगा।

## टोकनाइजेशन की आवश्यकताः

- संवेदनशील जानकारियों की सुभेद्यता: अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट आदि जैसे ई-कॉमर्स दिग्गज अपने साथ कार्ड के संवेदनशील विवरण जैसे कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी इन कंपनियों के डेटाबेस में संग्रहीत कर लेते हैं।
  - लेकिन यदि डेटाबेस हैक कर लिया जाता है तो कार्ड के डेटा के चोरी या गलत उपयोग के कारण समस्या पैदा हो जाती है।

- डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धिः COVID-19 महामारी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव किया है। उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों की बढती संख्या को देखते हुए इस दिशा में सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।
  - प्रत्येक माह औसतन 6 अरब लेन-देन होने के साथ, यदि ध्यान नहीं दिया गया तो धोखाधड़ी भी आनुपातिक रूप से बढ़ सकती है।
  - यह धोखाधड़ी पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था के लिये बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। वर्ष 2019 से वर्ष 2020 तक, कार्ड धोखाधड़ी 14% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है, जबिक पिछले तीन वर्षों में इसमें 34% की वृद्धि हुई है।
- अप्रचलित वर्तमान व्यवस्था: मौजूदा कार्ड-ऑन-फाइल सिस्टम (CoF) को आसानी से भंग किया जा सकता है और डेटा चोरी हो सकता है। इन्हीं सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखने के लिये आरबीआई टोकन प्रणाली लेकर आया है जो गारंटी देता है कि ग्राहकों के विवरण का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है तथा किसी के द्वारा उनका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।
  - CoF लेन-देन एक ऐसा लेन-देन है जहाँ कार्डधारक ने कार्डधारक के मास्टरकार्ड या वीजा भुगतान विवरण को संग्रहीत करने हेतु एक व्यापारी को अधिकृत किया है।

## टोकनाइज़ेशन सेवाओं की पेशकश:

- अधिकृत कार्ड नेटवर्क: टोकनाइजेशन केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा किया जा सकता है और मूल प्राथमिक खाता संख्या (पैन) तक पहुँच केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क के लिये संभव होनी चाहिये।
  - इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये कि पैन और अन्य संवेदनशील डेटा टोकन से कार्ड नेटवर्क को छोड़कर किसी अन्य के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि टोकन बनाने की प्रक्रिया की अखंडता हर समय सुनिश्चित की जानी चाहिये।

## टोकनाइज़ेशन के लाभ:

- एक टोकनयुक्त कार्ड लेन-देन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेन-देन के दौरान वास्तिवक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। वास्तिवक कार्ड डेटा, टोकन और अन्य प्रासंगिक जानकारी अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा सुरक्षित रूप से संग्रहीत की जाती है।
  - टोकन अनुरोधकर्त्ता प्राथिमक खाता संख्या (Primary Account Number-PAN), या कोई अन्य कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं कर सकता है। कार्ड नेटवर्क को सुरक्षा के

- लिये टोकन अनुरोधकर्त्ता को प्रमाणित करना भी अनिवार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं/विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप है।
- टोकनाइज्रेशन भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उन्नत नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह भुगतान के लिये आधारिशला बन गया है, चाहे वह इन-स्टोर हो, ऑनलाइन हो या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से।
- 🗅 यह ग्राहकों और व्यवसायों के मध्य विश्वास को मज़बूत करता है।
- ⊃ व्यवसायों के लिये लालफीताशाही के स्तर को कम करता है।
- इसमें शामिल सभी पक्षों के लिये आसान और सुरक्षित भुगतान अनुभव का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है।

# विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट

## चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, पिछले 13 महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है।

# विदेशी मुद्रा भंडारः

- पिरचयः विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभृतियाँ शामिल होती हैं।
  - 💠 अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित को शामिल किया जाता
   है:
  - विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ
  - स्वर्ण भंडार
  - ♦ विशेष आहरण अधिकार (SDR)
  - ♦ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास रिज़र्व ट्रेंच
- विदेशी मुद्रा भंडार का महत्त्व:
  - मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन हेतु निर्मित नीतियों के प्रति समर्थन व विश्वास बनाए रखना।
  - यह राष्ट्रीय या संघ की मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है।
  - संकट के समय या जब उधार लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो संकट के समाधान के लिये विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाहरी प्रभाव को सीमित करती है।

# विशेष आहरण अधिकार ( SDRs ):

विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा 1969 में अपने

सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।

- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। बल्कि यह IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- SDR के मूल्य की गणना 'बास्केट ऑफ करेंसी' में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड।
- SDRs या SDRi पर ब्याज दर सदस्यों को उनके SDR होल्डिंग्स पर दिया जाने वाला ब्याज है।

## भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण:

- वर्तमान परिदृश्य:
  - सितंबर 2021 के बाद से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है, जहाँ यह 642.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था।
    - यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारतीय रुपया एक स्वतंत्र रूप से फ्लोटिंग मुद्रा है और इसकी विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। RBI की कोई निश्चित विनिमय दर नहीं है।
  - 💠 इस भारी गिरावट के बावजूद भारत की स्थिति कई आरक्षित मुद्राओं, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और इसके एशियाई समकक्षों की तुलना में काफी बेहतर रहा है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण:
  - 💠 रुपए का समर्थन: वैश्विक विकास के कारण प्रमुख रूप से दबाव के मध्य केंद्रीय बैंक रुपए का समर्थन करने के लिये विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर का विक्रय कर रहा है।
    - 🗷 रुपए की मुक्त गिरावट को रोकने और बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिये हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  - अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की आक्रामक नीति:
    - प्रंजी बहिर्वाह: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (foreign portfolio investors-FPIs) द्वारा पूंजी बहिर्वाह के रूप में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने मौद्रिक नीति को सख्त करने और ब्याज दरों में वृद्धि की शुरूआत
  - FPIs ने भारतीय बाजारों से हटना शुरू कर दिया है। ये FPIs वित्तीय और आईटी सेवाओं के विक्रेता तथा दूरसंचार एवं पूंजीगत वस्तुओं के खरीदार थे।

- मूल्यांकन हानि: मूल्यांकन हानि, प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत में वृद्धि और सोने की कीमतों में गिरावट ने भी विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी में भूमिका निभाई।
- ♦ चालू वित्त वर्ष के दौरान भंडार में लगभग 67% गिरावट, अमेरिकी डॉलर की बढ़त और उच्च अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल से उत्पन्न मूल्यांकन परिवर्तनों के कारण थी।

#### विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले कारक:

मुद्रास्फीति दरः बाजार मुद्रास्फीति में परिवर्तन मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिये दूसरे देश की तुलना में कम मुद्रास्फीति दर वाले देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि देखी जाती है।

भुगतान संतुलन: इसमें निर्यात, आयात, ऋण आदि सहित कुल लेन-देन शामिल हैं।

उत्पादों के आयात पर अपने विदेशी मुद्रा कोअधिक खर्च करने के कारण चालू खाते में घाटा, निर्यात की बिक्री से होने वाली आय से मूल्यह्रास का कारण बनता है और यह किसी देश की घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में उतार-चढाव को बढावा देता है।

सरकारी ऋण: सरकारी ऋण केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला ऋण है। बड़े सरकारी कर्ज वाले देश में विदेशी पूंजी प्राप्त करने की संभावना कम होती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।

इस मामले में,विदेशी निवेशक अपने बॉण्ड की विक्री खुले बाजार में करेंगे, यदि बाजार किसी निश्चित देश के भीतर सरकारी ऋण का अनुमान लगाता है। परिणामत: इसकी विनिमय दर के मूल्य में कमी आएगी।

# भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी

# उत्पादक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत 5000 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक गन्ने के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक एवं उपभोक्ता और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है।

# चीनी के अच्छे उत्पादन के कारण:

- चीनी का शानदार सीजन (सितंबर-अक्तूबर): सीजन के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और इथेनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड बनाए गए।
- उच्च निर्यात: निर्यात बिना किसी वित्तीय सहायता के लगभग 109.8 LMT के साथ सबसे अधिक था और इसने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

- भारत सरकार की नीतिगत पहल: विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा समय पर की गई पहल के चलते गन्ना उत्पादन वर्ष 2018-19 के वित्तीय संकट से बाहर निकलकर वर्ष 2021-22 में आत्मिनर्भरता के स्तर पर पहुँचा दिया है।
- इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन: सरकार ने चीनी मिलों को चीनी को इथेनॉल में बदलने और अधिशेष चीनी का निर्यात करने के लिये प्रोत्साहित किया है ताकि मिलों के परिचालन जारी रखने के लिये उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति हो।
  - इसके अलावा तेज़ी से भुगतान, कम कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और मिलों में अतिरिक्त चीनी की कमी के कारण कम नकदी ब्लॉकेज के कारण चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, वर्ष 2025 तक EBP कार्यक्रम के तहत 20% इथेनॉल मिश्रण का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करती है।
- ⇒ उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and remunerative price-FRP): FRP वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को गन्ने की खरीद के लिये चुकानी पड़ती है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices-CACP) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है।
- राज्य की सलाह का महत्त्व: हालाँकि केंद्र सरकार FRP तय करती है, राज्य सरकारें एक राज्य सलाहकारी मूल्य भी निर्धारित कर सकती हैं जो चीनी मिल को किसानों को चुकानी पड़ती है।
- चीनी उद्योग के नियमन पर सिफारिशें देने के लिये रंगराजन सिमिति
   (2012) का गठन किया गया था।
- रंगराजन सिमिति की सिफारिशें:
  - चीनी के निर्यात और आयात पर मात्रात्मक नियंत्रण को समाप्त करने के लिये इन्हें उचित टैरिफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।
  - उप-उत्पादों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये और कीमतें बाजार निर्धारित होनी चाहिये।
  - मिलों को खोई से उत्पन्न विद्युत का उपयोग करने की अनुमित देने के लिये राज्यों को नीतिगत सुधार भी करने चाहिये।

### भारत में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति:

परिचय: चीनी उद्योग एक महत्त्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है।

- चीनी उद्योग कपास के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि
   आधारित उद्योग है।
- गन्ने की वृद्धि के लिये भौगोलिक स्थितियाँ:
  - ♦ तापमान: गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 °C के मध्य।
  - 💠 वर्षा: लगभग 75-100 सेमी।
  - 💠 मृदा का प्रकार: गहरी समृद्ध दोमट मृदा।
  - शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र> उत्तर प्रदेश> कर्नाटक।
- वितरण: चीनी उद्योग मोटे तौर पर उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों- उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तथा दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तिमलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में स्थापित हैं।
  - दक्षिण भारत में उष्णकिटबंधीय जलवायु है जो उत्तर भारत की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज देने के साथ उच्च सुक्रोज के लिये उपयुक्त है।

## 🔾 चुनौतियाँ:

- अनिश्चित उत्पादन निर्गत: गन्ने को कई अन्य खाद्य और नकदी फसलों, जैसे- कपास, तिलहन, चावल इत्यादि से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है। इससे मिलों को गन्ने की आपूर्ति प्रभावित होती है और चीनी का उत्पादन भी साल-दर-साल बदलता रहता है जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। कम कीमतों के कारण अतिरिक्त उत्पादन के समय में चीनी मिलों को नुकसान उठाना पड़ता है।
- गन्ने की कम उपज: दुनिया के कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर उपज बेहद कम है। उदाहरण के लिये जावा में 90 टन प्रति हेक्टेयर और हवाई में 121 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में भारत की उपज केवल 64.5 टन/ हेक्टेयर है।
- लघु पेराई अविध: चीनी उत्पादन एक मौसमी उद्योग है जिसमें एक वर्ष में सामान्य रूप से 4 से 7 महीने की छोटी पेराई अविध होती है।
- यह श्रिमिकों के वित्तीय नुकसान और मौसमी रोजगार के साथ चीनी मिलों के पूर्ण उपयोग न होने का कारण बनता है।
- चीनी की कम रिकवरी दर: भारत में गन्ने से चीनी की औसत रिकवरी दर 10% से कम है जो अन्य प्रमुख चीनी उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है।
- उत्पादन की उच्च लागत: गन्ने की उच्च लागत, अकुशल तकनीक, उत्पादन की अनौपचारिक प्रक्रिया और भारी उत्पाद शुल्क के कारण विनिर्माण की लागत बढ़ जाती है।
- भारत में अधिकांश चीनी मिलें छोटे आकार की हैं जिनकी पेराई क्षमता 1,000 से 1,500 टन प्रतिदिन है जिससे यह उचित लाभ उठाने में विफल रहती हैं।

# अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022

### चर्चा में क्यों ?

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने "बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिये" बेन एस. बर्नानके (Ben S. Bernanke), डगलस डब्ल्यू. डायमंड (Douglas W. Diamond) और फिलिप एच. डायबविग (Philip H. Dybvig) को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में वर्ष 2022 का स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।

- अर्थशास्त्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार कनाडा में जन्मे डेविड कार्ड (David Card) को और दूसरा आधा भाग संयुक्त रूप से इजरायल-अमेरिकी जोशुआ डी. एंग्रिस्ट (Joshua D. Angrist) तथा डच-अमेरिकी गुइडो डब्ल्यू. इम्बेन्स (Guido W. Imbens) को दिया गया था।
- वर्ष 2022 के लिये साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा और शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। नोट:

अन्य पुरस्कारों के विपरीत अर्थशास्त्र में पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वर्ष 1895 की वसीयत में नहीं, बल्कि उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा की गई थी, इसका पहला विजेता वर्ष 1969 में चुना गया था।

## बैंकिंग प्रणाली में इन पुरस्कार विजेताओं का योगदान:

- बेन एस. बर्नानके:
  - बेन बर्नानके ने 1930 के दशक की महामंदी का विश्लेषण किया, जो आधुनिक इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट था।
  - सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से बर्नानके ने दर्शाया कि किस प्रकार असफल बैंकों ने 1930 के दशक के वैश्विक अवसाद की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभाई।
    - 🗷 उन्होंने बताया कि कैसे बैंक सुविधाओं का जारी रहना इस गहरे और दीर्घकालिक संकट में एक निर्णायक कारक था।
    - 🗷 उन्होंने बैंक के सुचालित विनियमन के महत्त्व को समझाने में भी मदद की।
  - बर्नानके उस समय अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिज़र्व के प्रमुख थे, जब 2008 का संकट उत्पन्न हुआ था और उन्होंने "अनुसंधान से प्राप्त अपने ज्ञान से नीति निर्माण" में मदद की
- डगलस डब्ल्यू. डायमंड और फिलिप एच. डायबविग:
  - डायमंड और डायबविंग दोनों ने सैद्धांतिक मॉडल विकसित करने के लिये मिलकर काम किया ताकि यह समझ सकें कि

- बैंकों की उपस्थिति क्यों आवश्यक है, समाज में उनकी भूमिका उन्हें अपने आसन्न पतन के बारे में अफवाहों के प्रति किस प्रकार संवेदनशील बनाती है, और समाज इस भेद्यता को कैसे कम कर सकता है। ये अंतर्दृष्टियाँ आधुनिक बैंक विनियमन की नींव रखती हैं।
- उन्होंने सरकार की ओर से जमा बीमा के रूप में बैंक की भेद्यता का समाधान प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, जब जमाकर्त्ताओं को पता चलता है कि राज्य ने उनके पैसे की गारंटी दी है, तो उन्हें बैंक के बारे में अफवाहें शुरू होते ही बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है।
- डायमंड ने यह भी दिखाया कि कैसे बैंक सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में बैंक उधारकर्त्ताओं की साख का आकलन करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिये अनुकूल हैं कि ऋण का उपयोग अच्छे निवेश हेतु किया जाता है।

# सार्वजानिक-निजी भागीदारी के माध्यम से 16 स्टेशनों के लिये बोली लगाएगा रेलवे

### चर्चा में क्यों ?

रेल मंत्रालय सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership-PPP) मॉडल के तहत 16 स्टेशनों के लिये बोली लगाने की योजना बना रहा है। यात्रियों के लिये बेहतर बुनियादी सुविधाओं और पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये इन रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जाएगा।

यह उन 1253 रेलवे स्टेशनों के अतिरिक्त है, जिन्हें आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिये चिह्नित किया गया है।

## सार्वजनिक-निजी भागीदारी ( PPP ):

- परिचय:
  - यह सार्वजनिक संपत्ति और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिये सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी बडे पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं, जैसे सड़कों, पुलों, या अस्पतालों को निजी वित्तपोषण के साथ पूरा करने की अनुमित देती है।
  - ♦ इस प्रकार की साझेदारी में, निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिये निवेश किया जाता है।
  - चुँकि PPP मॉडल में सेवाएँ प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा जिम्मेदारी का पूर्ण प्रतिधारण शामिल है, यह निजीकरण की प्रक्रिया नहीं है।

- इसमें निजी और सार्वजनिक इकाई के मध्य जोखिम का एक सुव्यवस्थित तरीके से आवंटन होता है।
- निजी इकाई को खुली प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर चुना जाता है और वह प्रदर्शन आधारित भुगतान प्राप्त करती है।
- PPP मार्ग उन विकासशील देशों में एक विकल्प हो सकता है. जहाँ सरकारों को महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये ऋण लेने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पडता है।
- यह बडी परियोजनाओं की योजना बनाने या उन्हें क्रियान्वित करने में आवश्यक विशेषज्ञता भी प्रदान कर सकता है।

#### लाभ: $\supset$

- ♦ PPP मॉडल निवेश, परिचालन दक्षता और आधुनिक एवं स्वच्छ प्रौद्योगिको को शामिल करता है।
- PPP के तहत रेलवे रेल पटरियों के साझा उपयोग के लिये प्रदान करती हैं, जिससे राज्यों और निजी निवेशकों के लिये लाभ एवं राजस्व आधार (या कम लागत के आधार) को बढाया जा सकता है।
- PPP रेलवे परियोजनाएँ रेल पटरियों के साझा उपयोग के लिये प्रदान करती हैं, जो राज्यों और निजी निवेशकों के लिये दक्षता लाभ और बढ़े हुए राजस्व आधार (या कम लागत के आधार) हो सकते हैं।
- 💠 इसके अतिरिक्त इससे प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हो सकती है और रेलवे के बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण हो सकता है।

#### चुनौतियाँ:

- ♦ PPP परियोजनाएँ मौजूदा अनुबंधों में विवाद, पूंजी की अनुपलब्धता और भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियामक बाधाओं जैसे मुद्दों में उलझी हुई हैं।
- ♦ भिम अधिग्रहण में देरी होने के कारण PPP को व्यवहार में विनियमित करने में भारत सरकार का खराब रिकॉर्ड है।
- ऐसा माना जाता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के एक बड़े हिस्से में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये ऋण शामिल हैं।
- कई क्षेत्रों में PPP परियोजनाएँ क्रोनी कैपिटलिज्म के वाहक के रूप में तब्दील हो गई हैं।
- बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में कई PPP परियोजनाएँ "राजनीति से जुड़ी कंपानियों" द्वारा चलाई जाती हैं जिन्होंने अनुबंध हासिल करने के लिये राजनीतिक संपर्क का उपयोग किया होता है।
- PPP कंपनियाँ कम राजस्व या लागत में वृद्धि जैसे कारणों का हवाला देकर अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने के लिये हर अवसर का उपयोग करती हैं जो भारत में एक मानदंड बन गया है।

### सार्वजनिक-निजी भागीदारी ( PPP ) मॉडल के प्रकार:

- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT): यह एक पारंपरिक PPP मॉडल है जिसमें निजी भागीदार डिजाइन, निर्माण, संचालन (अनुबंधित अवधि के दौरान) और सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र में वापस स्थानांतरित करने के लिये जिम्मेदार होते है।
  - निजी क्षेत्र के भागीदार को किसी परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था करनी होती है और इसके निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होती है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के भागीदारों को उपयोगकर्ताओं से राजस्व एकत्र करने की अनुमति देगा। PPP मोड के तहत NHAI द्वारा अनुबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ BOT मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण है।
- बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO): इस मॉडल में नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी पार्टी के पास रहेगा।
  - पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदार परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की 'खरीद' करने पर सहमति बनाई जाती है।
- बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT): इसके अंतर्गत समय पर बातचीत के बाद परियोजना को सरकार या निजी ऑपरेटर को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
  - BOOT मॉडल का उपयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिये किया जाता है।
- बिल्ड-ऑपरेट-लीज़-ट्रांसफर (BOLT): इस मॉडल में सरकार निजी साझेदार को सुविधाओं के निर्माण, डिजाइन, स्वामित्त्व और लीज़ का अधिकार देती है तथा लीज अवधि के अंत में सविधा का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित किया जाता है।
- डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट(DBFO): इस मॉडल में अनुबंधित अवधि के लिये परियोजना के डिजाइन, उसके विनिर्माण, वित्त और परिचालन का उत्तरदायित्त्व निजी साझीदार पर होता है।
- लीज-डेवलप-ऑपरेट (LDO): इस प्रकार के निवेश मॉडल में  $\supset$ या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधा का स्वामित्व बरकरार रहता है और निजी प्रमोटर के साथ लीज समझौते के रूप में भुगतान प्राप्त किया जाता है।
  - 💠 इसका पालन अधिकतर एयरपोर्ट सुविधाओं के विकास में किया जाता है।
  - इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल: इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग कार्य के लिये बोलियाँ आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम और इंजीनियरिंग

- विशेषज्ञता के प्रावधान तक सीमित होती है। इस मॉडल की एक समस्या यह है कि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढता है।
- हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM): भारत में नया HAM, BOT-एन्युइटी और EPC मॉडल का मिश्रण है। डिजाइन के अनुसार, सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों में परियोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष भुगतान सुजित परिसंपत्तियों और विकासकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

#### आदर्श स्टेशन योजनाः

- विषय: रेल मंत्रालय की आदर्श स्टेशन योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के उपनगरीय स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों में अद्यतन करना है।
  - इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का चयन सुविधाओं के उन्नयन की पहचान की आवश्यकता पर आधारित है।
- प्रमुख बिंदु:
  - 💠 आदर्श स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसिज्जित और उन्नत किया जाएगा जैसे:
    - 🗷 स्टेशन भवन के अग्रभाग का सुधार।
    - यातायात संचालन को विधिवत सुव्यवस्थित करना
    - मंच की सतह में सुधार
    - 🗷 मौजूदा प्रतीक्षालय और विश्रामालयों में सुधार
    - 🗷 शौचालय की सुविधा
    - 🙎 फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान
    - 🗷 लिफ्ट और एस्केलेटर आदि की व्यवस्था।
  - उन्नयन प्रक्रिया की निगरानी भारत सरकार और भारतीय रेलवे द्वारा की जाएगी।

# इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पैटर्न पर इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई।

# रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुः

- वैश्विक परिदृश्य:
  - कोविड-19 संकट के कारण वर्ष 2020 में भारी कमी के बाद OECD देशों में स्थायी प्रवास के मामले में वर्ष 2021 में 22% की वृद्धि हुई है।

- ♦ वर्ष 2021 में पारिवारिक प्रवास में 40% की वृद्धि के साथ यह प्रवास की सबसे बड़ी श्रेणी बनी रही और कुल 10 स्थायी प्रवासियों में से चार से भी अधिक OECD में प्रवासित हुए।
- 💠 मुक्त गतिशीलता क्षेत्रों में प्रवासन महामारी से कम प्रभावित हुआ था, फिर भी वर्ष 2020 में 17% की गिरावट आई।
- ♦ वर्ष 2020 में OECD में 4.4 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी नामांकित थे, जो कुल टर्शियरी विद्यार्थियों (tertiary students) का 10% थे। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका (22%), यूनाइटेड किंगडम (13%) और ऑस्ट्रेलिया (10%) में हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2021 (83,4000) में स्थायी अप्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या देखी गई, यह वर्ष 2020 की तुलना में 43% अधिक और वर्ष 2019 की तुलना में 19% कम है। स्थायी प्रवास के मामले में यूरोपीय संघ (+15%) में वृद्धि की स्थिति कम स्पष्ट थी।

#### भारतीय परिदृश्य:

- OECD देशों में विदेशी छात्रों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन (22%) और भारत (10%) की है। 20-29 आयु वर्ग की दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी इन दोनों देशों में रहती है।
- वर्ष 2015 में शिक्षा परिमट प्राप्त करने वाले भारतीयों तथा चीनी छात्रों के ठहरने की दरों पर नज़र डालने से पता चलता है कि कनाडा, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जापान सहित लगभग हर OECD देश में भारतीयों की प्रतिधारण दर चीनियों की तुलना में काफी अधिक है।
- भारतीय छात्रों की निवास की दर समग्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या की तुलना में अधिक है।

## आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ( OECD ):

- परिचय: OECD एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।
- अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनका मानव विकास सूचकांक (HDI) बहुत अधिक है और उन्हें विकसित देश माना जाता है।
- स्थापनाः 1961 0
- मुख्यालयः पेरिस, फ्राँस
- कुल सदस्य: 38 0
- OECD में हाल ही में शामिल हुए देश हैं- कोलंबिया (अप्रैल 2020 में ) और कोस्टा रिका (मई 2021 में)।

- भारत इसका सदस्य नहीं है बिल्क एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।
  - ♦ OECD द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और सूचकांक:
  - सरकार,एक नज़र में
  - ♦ OECD बेहतर जीवन सूचकांक।

#### प्रवासन के प्रकार:

- आवागमन पैटर्न के आधार पर
  - क्रिमिक प्रवास: इसका तात्पर्य छोटी बस्ती और छोटे पैमाने से प्रवासन शुरू होकर आगे के वर्षों में बड़े पैमाने पर शहरी पदानुक्रम की ओर पलायन करना है। जैसे कि जंगली क्षेत्र से गाँव, फिर शहर और बाद में उपनगर (यदि उपलब्ध हो) तथा अंत में शहर की ओर जाना।
  - चक्रीय प्रवासन: कम-से-कम एक प्रवास और वापसी के साथ मूल व गंतव्य के बीच चक्रीय प्रवासन अनुभव।
    - मौसमी प्रवास, चक्रीय प्रवास का एक बहुत ही सामान्य रूप है, यह ज्यादातर कृषि क्षेत्र में जहाँ श्रम की मांग हो, मौसमी घटनाओं द्वारा संचालित है।
    - रिटर्न माइग्रेशन एक बार के उत्प्रवास को संदर्भित करता है तथा मेजबान क्षेत्र के बाहर विस्तारित प्रवास के बाद लौटता है।
    - शृंखला प्रवास: जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास, जो बाद में लोगों को उनके गृह स्थान से इस नए स्थान पर लाता है।
- ⊃ निर्णय लेने के दृष्टिकोण के आधार पर:
  - स्वैच्छिक प्रवासनः िकसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, पहल और बेहतर स्थान पर रहने एवं अन्य कारकों के बीच अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की इच्छा के आधार पर।
  - अनैच्छिक प्रवासन: कुछ प्रतिकूल पर्यावरणीय और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण किसी व्यक्ति को अपने गृह क्षेत्र से बाहर निकलने के लिये मज़बूर होने के आधार पर।
- 🔾 अवधि के आधार पर:
  - स्थायी प्रवासन: जब लोग लंबी अवधि के लिये रहने हेतु लंबी दूरी पर दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, तो इसे स्थायी प्रवास कहा जाता है। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति नौकरी के बेहतर अवसरों के लिये सतना (मध्य प्रदेश) से गुरुग्राम (हरियाणा) चला गया और उसने वहीं बसने की योजना बनाई। इस प्रकार के प्रवास को स्थायी प्रवास माना जाएगा।
  - अस्थायी प्रवासन: यह एक ऐसे देश में प्रवास है जिसमें स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं होता, इस तरह का प्रवास निर्दिष्ट और सीमित अविध के लिये आमतौर पर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिये किया जाता है।

# चौथा हेली-इंडिया शिखर सम्मेलन, 2022

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्री ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चौथे हेली-इंडिया शिखर सम्मेलन, 2022 का उद्घाटन किया।

- थीम: हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी (Helicopters for Last Mile Connectivity)। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उपलब्धियों की घोषणा करते हुए यह बताया गया कि देश में वर्ष 1947 से 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन पिछले सात वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 141 हो गई है।
- जम्मू में एक सिविल एन्क्लेव बनाने का प्रस्ताव है और श्रीनगर के वर्तमान टर्मिनल का तीन गुना विस्तार किया जाएगा।
- फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल और हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज (HEMS) नामक पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की घोषणा की गई है।
  - आंशिक स्वामित्व मॉडल: यह गैर-अनुसूचित कार्यों में सहायता करता है।
    - यह बहु-स्वामित्व द्वारा एकत्रित पूंजी के माध्यम से हेलीकाप्टरों और हवाई जहाज के अधिग्रहण में आने वाले अवरोधों को कम करेगा।
  - HEMS: इसे प्रोजेक्ट संजीवनी भी कहा जाता है; एम्स ऋषिकेश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा।
    - इसके तहत हेलीकॉप्टर 20 मिनट की समय अविध के भीतर अस्पताल में स्थित होगा और इसमें 150 किलोमीटर के दायरे को शामिल किया गया है।

## संबंधित पहलें:

- हेली-सेवा पोर्टल:
  - हेली-सेवा पोर्टल पूरी तरह से ऑनलाइन है और सभी ऑपरेटरों द्वारा हेलीपैड के लिये लैंडिंग अनुमित प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है, यह देश में हेलीपैड के डेटाबेस का भी निर्माण कर रहा है।
- 🗅 हेली-दिशा:
  - राज्य प्रशासन के लिये हेलीकॉप्टर संचालन पर मार्गदर्शन सामग्री, हेली-दिशा को 780 जिलों में वितरित किया गया है।
  - इसमें हेलीकॉप्टर के आकार, वजन, संचालन आदि से संबंधित सभी नियम शामिल हैं जिसे देश भर में जिला प्रशासन को इसके बारे में जागरूक करने के लिये वितरित किया जाएगा।

- हेलीकॉप्टर एक्सेलेरेटर सेल:
  - हेलीकॉप्टर एक्सेलेरेटर सेल हेलीकॉप्टर से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिये सिक्रय रूप से काम कर रहा है और व्यापार प्रतिनिधियों का सलाहकार समूह समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता कर रहा है।
- उडे देश का आम नागरिक:
  - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - यह क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने के लिये एक अभिनव योजना है।
- कृषि उडान 2.0 योजना:
  - 💠 यह कृषि-कटाई और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण एवं अनुकूलन के माध्यम से मूल्य में सुधार, विभिन्न एवं गतिशील परिस्थितियों में कृषि-मृल्य शृंखला को स्थिरता व लचीलापन प्रदान करने में सहायता करता है।

# पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिये पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना शुरू की है।

# पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजनाः

- परिचय:
  - 💠 इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - ♦ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये राज्यों को कुल 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  - 💠 इस योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधार सीमा से अधिक होगा और इसे उसी वित्तीय वर्ष में खर्च करना होगा।
- योजना हेतु पात्रः
  - 💠 नई परियोजनाओं या चल रही पूंजीगत परियोजनाओं में लंबित बिलों के निपटान के लिये।
  - राज्य अपनी वरीयता/प्राथमिकता दर्शाते हुए आवंटित निधि से अधिक मूल्य की परियोजनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

- योजना के विभिन्न भागः
  - 💠 पूंजीगत कार्यों के लिये (प्रधानमंत्री गित शक्ति मास्टर प्लान को प्राथमिकता मिलेगी): प्रधानमंत्री गति शक्ति से संबंधित खर्च: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; डिजिटलीकरण के लिये प्रोत्साहन: ऑप्टिकल फाइबर केबल: शहरी सुधार: विनिवेश और मुद्रीकरण।
- अयोग्यता: 5 करोड़ रुपए से कम (पूर्वोत्तर के लिये 2 करोड़) के पूंजीगत परिव्यय वाली परियोजनाएँ और पूंजीगत परिव्यय के बावजूद मरम्मत एवं खरखाव परियोजनाएँ पात्र नहीं हैं।

## पूंजीगत व्ययः

- अर्थः
  - पूंजीगत व्यय मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर सरकार द्वारा खर्च किया गया धन है।
  - इसमें सरकार द्वारा भूमि और निवेश जैसी अचल संपत्तियों के अधिग्रहण पर होने वाला खर्च भी शामिल है जो भविष्य में लाभ या लाभांश देता है।
  - 💠 संपत्ति के निर्माण के साथ-साथ ऋण का पुनर्भुगतान भी पूंजीगत व्यय है, क्योंकि यह देयता को कम करता है।
  - पूंजीगत व्यय निवेश या विकास संबंधी व्यय से जुड़ा होता है, जहाँ व्यय का लाभ भविष्य में वर्षों तक प्राप्त होता है।

#### महत्त्व:

- पूंजीगत व्यय प्रकृति में दीर्घकालिक है और उत्पादन हेत् सुविधाओं के संयोजन या सुधार एवं परिचालन दक्षता को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को कई वर्षों तक राजस्व उत्पन्न करने की अनुमति देता है।
- ♦ इससे श्रम भागीदारी को बढ़ावा मिलने के साथ भविष्य में अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन करने की क्षमता को बढावा मिलता है।
- राजस्व व्यय से अंतर:
  - पूंजीगत व्यय, जिससे भविष्य के लिये संपत्ति का निर्माण होता है, के विपरीत राजस्व व्यय से न तो संपत्ति का निर्माण होता और न ही इससे सरकार के किसी दायित्व में कमी आती है।
  - ♦ कर्मचारियों का वेतन, पिछले कर्ज पर ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन आदि राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं। यह प्रकृति में आवर्ती है।

# लघु बचत योजनाओं पर ब्याज़ दरें

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने अक्तूबर-दिसंबर 2022 के लिये कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की है।

2 वर्ष और 3 वर्ष की सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और किसान विकास पत्र के लिये दरों में मामूली वृद्धि की गई, जबिक अन्य योजनाओं की दरें अपरिवर्तित रहीं।

## लघु बचत योजनाएँ:

- परिचय:
  - 💠 लघु बचत योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित बचत साधनों का एक समृह है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ज्यादा उम्र के बावजूद नियमित रूप से बचत करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
    - वे लोकप्रिय हैं क्योंिक वे न केवल बैंक सावधि जमा से अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं बल्कि सॉवरेन गारंटी और कर लाभ भी प्रदान करते हैं।
  - विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत प्राप्त सभी जमाराशियों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष में जमा किया जाता है। फंड में जमा पैसा केंद्र सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये उपयोग किया जाता है।
- वर्गीकरण:
  - डाक जमा:
    - 🗷 बचत जमा, आवर्ती जमा तथा 1, 2, 3 और 5 साल की परिपक्वता के साथ टाइम डिपॉजिट एवं मासिक आय खाता।
  - बचत प्रमाण पत्र:
    - ¤ राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC):
  - अर्जित ब्याज को हर साल स्वचालित रूप से योजना में पुन: निवेश किया जाता है।
    - ¤ किसान विकास पत्र (KVP):
  - यह योजना सभी के लिये है जिसमे एक बार किये गए निवेश को 124 महीनों में दोगुना किया जाता है जो वार्षिक 6.9% दर के रिटर्न को दर्शाता है।
  - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:
    - ¤ लोक भविष्य निधि (PPF):
  - पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा पेश की जाने वाली एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसका उद्देश्य सभी को सेवानिवृत्ति पश्चात एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।

- 🗷 सुकन्या समृद्धि खाताः
- यह योजना वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत विशेष रूप से बालिकाओं के लिये लॉन्च की गई थी।
- ♦ इसके तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खाता खोला जा सकता है।
- यह योजना प्रतिवर्ष 7.6% की वापसी की गारंटी देती है और आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिये पात्र है।
  - वरिष्ठ नागरिक बचत योजना:
- ♦ 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ ले सकता है।
- दरों का निर्धारण:
  - ♦ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉण्डों के अनुरूप तिमाही आधार पर किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दरों की समीक्षा की जाती है।
  - 💠 लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ पैनल (वर्ष 2010) ने छोटी बचत योजनाओं के लिये बाजार-संबद्ध ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था।

# राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)

## चर्चा में क्यों ?

वस्त्र मंत्रालय ने हाल ही में फ्लैगशिप कार्यक्रम 'नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन' (NTTM) के अंतर्गत स्पेशियलिटी फाइबर्स, कम्पोजिटस, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, मोबिलटेक, स्पोर्टेक और जियोटेक क्षेत्रों में 60 करोड़ रुपए की 23 रणनीतिक परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।

### तकनीकी वस्त्र:

- तकनीकी वस्त्रों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य कार्यात्मक (Functionality) होता है। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग कृषि, वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा, सैन्य क्षेत्र, व्यक्तिगत सुरक्षा, उद्योग तथा खेलकृद के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर होता है।
  - तकनीकी वस्त्र उत्पाद किसी देश में विकास और औद्योगीकरण से अपनी मांग प्राप्त करते हैं।
- उपयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र हैं: एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डटेक, मोबिलटेक, क्लॉथटेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंड्रटेक और स्पोर्टेक।
  - उदाहरण के लिये 'मोबिलटेक' वाहनों के उत्पादों को संदर्भित करता है जैसे सीट बेल्ट और एयरबैग, हवाई जहाज की सीट;

जियोटेक जो संयोग से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला उप-क्षेत्र है, इसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता वापस लाने/बनाए रखने के लिये किया जाता है।

### राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ( NTTM ):

- परिचय:
  - इसे वर्ष 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय सिमिति (CCEA) द्वारा 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
  - कार्यान्वयन की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक चार वर्ष है।
- उद्देश्य:
  - मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक घरेलू बाजार का आकार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँचा कर तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक लीडर के रूप में भारत को स्थापित करना है।
  - 💠 यह संबंधित मशीनरी और उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने वाली 'मेक इन इंडिया' पहल का भी समर्थन करता है।

- पहला घटक: 1,000 करोड रुपए के परिव्यय वाले मिशन का पहला घटक अनुसंधान, नवाचार और विकास पर केंद्रित होगा।
  - 🗷 इस घटक के तहत (1) कार्बन, फाइबर, अरामिड फाइबर, नायलॉन फाइबर और कम्पोज़िट में अग्रणी तकनीकी उत्पादों के उद्देश्य से फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान भू-टेक्सटाइल, कृषि-टेक्सटाइल, चिकित्सा-टेक्सटाइल, मोबाइल-टेक्सटाइल और खेल-टेक्सटाइल के विकास पर आधारित अनुसंधान अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 💠 दूसरा घटक: यह तकनीकी वस्त्रों हेतु बाजार के प्रचार और विकास के लिये होगा।
  - 🗷 विकसित देशों में 30-70% के स्तर के मुकाबले भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर 5-10% के बीच काफी कम है।
  - 🗷 मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक औसतन 15-20% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर है।
- तीसरा घटक: इस घटक के तहत तकनीकी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 तक 20,000 करोड़ रुपए किये जाने का लक्ष्य है जो कि वर्तमान में लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। साथ ही वर्ष 2023-24 तक प्रतिवर्ष निर्यात में 10 प्रतिशत औसत वृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी।
  - 🗷 तकनीकी वस्त्रों के लिये एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी।

- 💠 चौथा घटक: यह शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित होगा।
  - 🗷 यह मिशन तकनीकी वस्त्रों और इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों से संबंधित उच्च इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा।

#### कपड़ा क्षेत्र का परिदृश्य:

- भारत में तकनीकी वस्त्रों के विकास ने पिछले पाँच वर्षों में गति पकड़ी है, जो वर्तमान में 8% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है।
  - 🗷 इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों के दौरान इस वृद्धि को 15-20% की श्रेणी में ले जाना है।
- भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जो कि 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार का लगभग 6% है।
  - 🗷 इस क्षेत्र में सबसे बड़े अभिकर्त्ता संयुक्त राज्य अमेरिका,पश्चिमी यूरोप,चीन और जापान (20-40% हिस्सेदारी) हैं।

#### कार्यान्वयन और शासनः

- ♦ मिशन को तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - म मिशन संचालन समृह: समृह को मिशन की योजनाओं, घटकों और कार्यक्रम के संबंध में सभी वित्तीय मानदंडों को मंजूरी देने के लिये अधिकृत किया जाएगा।
- ♦ मिशन के तहत सभी वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान परियोजनाओं को मंज़री देने की जिम्मेदारी भी इस समृह को सौंपी जाएगी।
  - 🗷 अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति: इस समिति का कार्य मिशन संचालन समूह द्वारा अनुमोदित विभिन्न कार्यक्रमों की वित्तीय सीमाओं के भीतर सभी परियोजनाओं (अनुसंधान परियोजनाओं को छोड़कर) को अनुमोदित करना होगा।
- ♦ सिमिति को मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की निगरानी की भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
  - 😕 अनुसंधान, विकास और नवाचार संबंधी तकनीकी वस्त्र समिति: यह समिति अनुमोदन के लिये मिशन संचालन समूह को अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान और सिफारिश करने हेतु जिम्मेदार होगी।
- 💠 ये परियोजनाएँ अंतरिक्ष, सुरक्षा, रक्षा, अर्द्धसैनिक और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित होंगी।

# ग्रीन फिन्स हब

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने यूके स्थित चैरिटी रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया।

ग्रीन फिन्स हब दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों के लिये वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

#### ग्रीन फिन्स

- परिचय:
  - ♦ ग्रीन फिन्स द रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन और UNEP द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित संरक्षण प्रबंधन दुष्टिकोण है जो समुद्री पर्यटन से जुड़े नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों में औसत दर्जे की कमी को प्रदर्शित करता है।
  - मूल रूप से वर्ष 2004 में थाईलैंड में स्थापित ग्रीन फिन्स दुष्टिकोण डाइविंग और स्नॉर्कलिंग पर्यटन उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये एक उपकरण है।

#### लक्ष्य:

- इसका उद्देश्य स्थायी डाइविंग और स्नॉर्किलिंग को बढ़ावा देने वाले पर्यावरण के अनुकूल दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्रवाल भित्तियों की रक्षा करना है।
- यह समुद्री पर्यटन के लिये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरण मानक प्रदान करता है और इसकी मज़बूत मूल्यांकन प्रणाली अनुपालन को मापती है।

#### ग्रीन फिन्स हब

- परिचय:
  - ग्रीन फिन्स हब अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है।
  - 💠 यह स्थायी समुद्री पर्यटन को 'बढ़ावा' देगा।
  - इसके 14 देशों के लगभग 700 ऑपरेटरों से दुनिया भर में संभावित 30,000 ऑपरेटरों तक पहुँचने की उम्मीद है।

#### महत्त्व:

- 💠 इसका उद्देश्य ग्रीन फिन्स सदस्यता के माध्यम से समुद्री पर्यटन क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में भुकंपीय बदलाव को उत्प्रेरित करना है।
- प्रवाल भित्तियाँ कम-से-कम 25% समुद्री जीवन का घर हैं, समुद्री-संबंधित पर्यटन के लिये मक्का है, कुछ द्वीप राष्ट्रों में सकल घरेलु उत्पाद में 40% या उससे अधिक का योगदान

करते हैं। हालाँकि वे सबसे कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र हैं, विशेष रूप से जलवाय परिवर्तन के लिये 1.5 या 200 C के वैश्विक तापमान वृद्धि के बीच प्रवाल भित्ति अस्तित्व में है।

- 🙎 ग्रीन फिन्स हब के माध्यम से सर्वोत्तम अभ्यास, ज्ञान और नागरिक विज्ञान की बढ़ती पहुँच प्रवाल भित्तियों तथा अन्य नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के भविष्य को सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर हो सकती है।
- प्लेटफॉर्म दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों द्वारा परीक्षण किये गए समाधानों का उपयोग करके अपनी दैनिक प्रथाओं में सरल. लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करेगा।
  - 🗷 यह उन्हें अपने वार्षिक सुधारों पर नज़र रखने और अपने समुदायों तथा ग्राहकों के साथ संवाद करने में भी मदद करेगा।

# सतत् तटीय और समुद्री पर्यटनः

- सतत् पर्यटन का तात्पर्य पर्यटन उद्योग की सतत् कार्यप्रणाली से है। यह मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर हरित पर्यटन क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करता है।
  - संयुक्त राज्य के अनुसार, सतत् पर्यटन में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिये:
    - पर्यावरणीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करें जो पर्यटन विकास में एक प्रमुख तत्त्व का गठन करते हैं, आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हैं और प्राकृतिक विरासत एवं जैवविविधता के संरक्षण में मदद करते हैं।
    - 🗷 मेजबान समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रामाणिकता का सम्मान करें, उनकी निर्मित और जीवित सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक मुल्यों का संरक्षण करें एवं अंतर-सांस्कृतिक समझ व सिहष्णुता में योगदान करें।
    - 🗷 व्यवहार्य, दीर्घकालिक आर्थिक संचालन सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों को सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करना जो उचित रूप से वितरित हो, जिसमें स्थिर रोजगार और आय-अर्जन के अवसर तथा समुदायों की मेज़बानी के लिये सामाजिक सेवाएँ व गरीबी उन्मूलन में योगदान करना शामिल है।
- तटीय और समुद्री पर्यटन (सीएमटी) कुल वैश्विक पर्यटन का कम-से-कम 50% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिकांश छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) और कई तटीय राज्यों के लिये सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है।
  - ♦ 5 फ़ीसदी की अनुमानित वैश्विक विकास दर से तटीय और समुद्री पर्यटन के वर्ष 2036 तक 26 फीसदी के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मूल्यवर्द्धित खंड बनने की उम्मीद है।

# वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council-FSDC) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।

# प्रमुख बिंदु

- परिषद ने अर्थव्यवस्था के लिये प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्तीय एवं क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार तथा व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर जोर दिया।
- यह नोट किया गया कि सरकार और नियामकों द्वारा वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों. वित्तीय स्थितियों तथा बाजार के विकास की निरंतर आधार पर निगरानी करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी भेद्यता को कम करने एवं वित्तीय स्थिरता को मज़बूत करने के लिये उचित और समय पर कार्रवाई की जा सके।
- परिषद ने वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उठाए जाने वाले वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में तैयारी पर ध्यान दिया।

# वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ( FSDC ):

- स्थापना:
  - 💠 यह वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक शीर्ष परिषद है तथा इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी।
  - FSDC की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति (2008) द्वारा किया गया था।.

#### संरचना:

- 💠 इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA और IRDA) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं।
  - 🗷 वर्ष 2018 में सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के जिम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष तथा राजस्व सचिव को शामिल करने के उद्देश्य से FSDC का पुनर्गठन किया।

- ♦ FSDC उप-सिमिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर द्वारा की जाती है।
- आवश्यकता पड़ने पर यह परिषद विशेषज्ञों को भी अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है।

#### कार्य:

- 💠 वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढावा देने के लिये प्रक्रिया को मज़बूत एवं संस्थागत बनाना।
- अर्थव्यवस्था के वृहद-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना। यह बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज का आकलन करती है।

# पीएम प्रणाम (PM PRANAM) योजना

## चर्चा में क्यों ?

रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये सरकार पीएम प्रणाम यानी कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्त्वों का संवर्द्धन (Promotion of Alternate Nutrients Agriculture Management Yojana-PM PRANAM) योजना शुरू करने की योजना बना रही है।

### योजना के बारे में:

- उद्देश्य:
  - जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- रासायनिक उर्वरकों पर सिब्सिडी के बोझ को कम करना, जो 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है – 2021 के 1.62 लाख करोड़ रुपए के आँकड़े से 39% अधिक है।
- प्रस्तावित योजना की विशेषताएँ:
  - इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत "मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत" के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
  - सब्सिडी बचत का 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा जो पैसा बचाता है।
    - योजना के तहत प्रदान किये गए अनुदान का 70% गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी अपनाने से संबंधित परिसंपत्ति सृजन के लिये उपयोग किया जा सकता है।

- 🗷 शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समृहों को पुरस्कृत करने तथा प्रोत्साहित करने के लिये किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग को कम करने व जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।
- 💠 एक वर्ष में यूरिया के रासायनिक उर्वरक उपयोग को कम करने की गणना की तुलना पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से की जाएगी।
  - 🗷 इस उद्देश्य के लिये, उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (Integrated Fertilizer Management System-IFMS) पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा।

#### योजना की आवश्यकताः

- सरकार पर सिंब्सडी का बोझ:
  - किसान अपनी सामान्य आपूर्ति-और-मांग-आधारित बाजार दरों या उनके उत्पादन/आयात की लागत से कम अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक खरीदते हैं।
    - 🗷 उदाहरण के लिये, नीम लेपित यूरिया की MRP सरकार द्वारा 5,922.22 रुपए प्रति टन तय की गई है, जबकि घरेल निर्माताओं और आयातकों को देय इसकी औसत लागत-प्लस कीमत क्रमशः लगभग 17,000 रुपए और 23,000 रुपए प्रति टन है।
  - 💠 शेष भाग, जो संयंत्र-वार उत्पादन लागत और आयात मूल्य के अनुसार भिन्न होता है, केंद्र द्वारा सब्सिडी के रूप में रखा जाता है, यह अंतत: कंपनियों को जाता है।
  - 💠 गैर-यूरिया उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय किया जाता है। हालांकि उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये केंद्र इन पोषक तत्त्वों पर एक समान प्रति टन सब्सिडी का भुगतान करता है।
    - विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के लिये प्रति टन सिब्सिडी 10.231 से 24.000 रूपए है। ।
  - केंद्र सरकार प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करती है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक बेचना आवश्यक है।

# IBBI विनियमों में संशोधन

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) ने

तनावग्रस्त कंपनियों के मुल्य को बढावा देने के लिये अपने नियमों में संशोधन किया है।

- IBBI (कॉरपोरेट्स के लिये दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन संकल्प में मुल्य को अधिकतम करने के लिये किया गया है।
- यह अन्य परिवर्तनों के अलावा दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुज़र रही इकाई की एक या अधिक संपत्तियों की बिक्री की अनुमति देगा।

#### संशोधित नियमः

- लेनदारों की समिति (Committee of Creditors-CoC) अब जाँच कर सकती है कि परिसमापन अवधि के दौरान कॉरपोरेट देनदार (CD) के लिये समझौता या व्यवस्था की जा सकती है या नहीं।
  - 💠 जून 2022 तक 1,703 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएँ (CIRPs) समाप्त हो गईं।
- नियामक ने समाधान पेशेवर और CoC को संबंधित कॉरपोरेट देनदार की एक या अधिक संपत्तियों की बिक्री की तलाश करने की अनुमति दी है, जहाँ पुरे व्यवसाय के लिये कोई समाधान योजना नहीं
- समाधान योजना जिसमें एक या एक से अधिक CD परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है, एक या एक से अधिक सफल समाधान आवेदकों को शेष संपत्तियों के उचित उपचार के साथ उपलब्ध कराई जाएगी।
- समाधान पेशेवर (Resolution Professional-RP) को संबंधित कंपनी के ज्ञात (खातों की पुस्तिका के आधार पर) लेनदारों से सिक्रय रूप से दावों की जानकारी प्राप्त करनी होगी जो ऋण उपलब्ध कराने में मदद करेंगे।
  - ♦ RPs को CIRP के शुरू होने के 75 दिनों के भीतर इस बारे में राय देनी होगी कि क्या कंपनी ऋण भुगतान लेनदेन के अधीन है।
  - RP को अब यह आकलन और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी कि क्या कंपनी ने दिवाला कार्यवाही से पहले धन की निकासी के लिये कोई लेन-देन किया है।
  - ♦ विनियमों में कहा गया है कि RP द्वारा की गई किसी भी नियुक्ति हेतु पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये।
  - अंतरण से बचने के लिये दायर किसी भी आवेदन का विवरण समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले आवेदकों को उपलब्ध कराया जाएगा और आवेदक उन्हें अपनी योजनाओं में संबोधित कर सकते हैं।

सूचना के ज्ञापन में भौतिक जानकारी का शामिल होना आवश्यक है जो चुनौती के रूप में उन्हें स्थिति का आकलन करने में मदद करेगा, न कि केवल संपत्ति की जानकारी के बारे में, जिससे बाज़ार की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित किया जा सकेगा।

### संशोधित विनियमों का महत्त्व:

- प्रावधान हितधारकों को खोए हुए मूल्य को वापस पाने की अनुमति देंगे और हितधारकों को इस तरह के लेन-देन करने से हतोत्साहित करेंगे।
- ये संशोधन बाज़ार में परिसंपत्ति को दीर्घ अवधि तक उपलब्ध रहने की अनुमति देते हैं।
- इन संशोधनों से दिवाला समाधान के लिये उचित बाजार आधारित समाधानों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह सुनिश्चित करेगा कि दिवालिया कंपनी और उसकी संपत्ति के बारे में बेहतर गुणवत्ता की जानकारी संभावित समाधान आवेदकों सहित बाजार के लिये समय पर उपलब्ध हो।

### भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड:

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना वर्ष 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता नियम, 2016 द्वारा की गई थी।
- यह इस नियम के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी परितंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। यह उद्यमिता को बढावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिये कॉरपोरेट्स, साझेदारी फर्मों तथा लोगों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानुनों को समयबद्ध तरीके से समेकित एवं संशोधित करता है ताकि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके।
- यह एक अद्वितीय नियामक है क्योंकि यह पेशे के साथ-साथ प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है।
- यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं का नियामक पर्यवेक्षण करता है।
- इसे देश में मुल्यांकनकर्ताओं के पेशे के विनियमन और विकास के लिये कंपनियाँ (पंजीकृत मृल्यकार और मृल्यांकन नियम), 2017 के तहत 'प्राधिकरण' के रूप में भी नामित किया गया है।

# AIBD की 47वीं वार्षिक सभा

# चर्चा में क्यों ?

प्रतिष्ठित एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) की भारत की अध्यक्षता को एक और वर्ष के लिये बढा दिया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित संस्थान की दो दिवसीय वार्षिक सभा में AIBD के सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मित से यह निर्णय लिया गया।

#### एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट ( AIBD ):

- परिचय:
  - एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) की स्थापना वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को/UNESCO) के तत्त्वावधान में हुई थी।
  - यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UN-ESCAP) के देशों की सेवा करने वाला अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
  - ♦ इसका सिचवालय कुआलालंपुर में स्थित है और इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार करती है।

#### C उद्देश्य:

♦ AIBD नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और संगठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण प्रदान करने के लिये अनिवार्य है।

#### संस्थापक सदस्य:

♦ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) तथा एशिया-प्रशांत प्रसारण संघ (ABU) संस्थान के संस्थापक संगठन हैं और वे आम सम्मेलन के गैर-मतदाता सदस्य है।

#### सदस्य: )

भारत सिहत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों के प्रसारणकर्त्ता संगठन के पूर्ण सदस्य हैं।

#### 47वीं AIBD वार्षिक सभा:

- 47वीं AIBD वार्षिक सभा/20वाँ AIBD आम सम्मेलन और संबद्ध बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गईं।
- इसमें विशेष रूप से "महामारी के बाद की अवधि में प्रसारण के क्षेत्र में एक मज़बूत भविष्य का निर्माण" विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई चर्चाओं, प्रस्तृतियों और विचारों का आदान-प्रदान किया गया।
- सहकारी गतिविधियों और विनिमय कार्यक्रमों के लिये एक पंचवर्षीय योजना को भी अंतिम रूप दिया गया।
- सभी भाग लेने वाले देशों और सदस्य प्रसारकों ने एक स्थायी प्रसारण वातावरण, नवीनतम प्रौद्योगिकी जानकारी, बेहतरीन सूचना सामग्री के लिये मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

### कोविड-19 महामारी युग में AIBD का महत्त्व:

- AIBD के नेतृत्व ने सदस्य देशों को कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन जोड़े रखा और इस बात पर भी निरंतर संवाद बनाए रखा कि मीडिया किस प्रकार महामारी के प्रभाव को कम कर सकता है।
- सदस्य देशों को चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम विकास, कोरोना योद्धाओं के सकारात्मक परिणामों और महामारी से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही फर्ज़ी खबरों का मुकाबला करने के बारे में जानकारी साझा किये जाने से अत्यधिक लाभ हुआ।
- AIBD ने लॉकडाउन के दौरान भी अपना प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखा। अकेले वर्ष 2021 में 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए थे और पारंपरिक मुद्दों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन, हरित प्रौद्योगिकियों, सतत् विकास, तेज रिपोर्टिंग, बच्चों के लिये प्रोग्रामिंग आदि जैसे उभरते मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- प्रसारण क्षेत्र में इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ साइबर सुरक्षा पत्रकारिता में पत्रकारों का प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है।
  - ♦ AIBD अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इसे शामिल करने वाला पहला समूह है।
- यह मीडिया ही है जिसने कठिन दौर में दुनिया को एक मंच प्रदान किया और एक वैश्विक परिवार की भावना को मज़बूत किया।

# राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy-NLP) 2022 शुरू की है, जिसका उद्देश्य 'अंतिम छोर तक त्वरित वितरण' करना है, साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना है।

### लॉजिस्टिक्स:

- लॉजिस्टिक्स में संसाधनों, लोगों, कच्चे माल, सूची, उपकरण आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात उत्पादन बिंदुओं से उपभोग, वितरण या अन्य उत्पादन बिंदुओं तक ले जाने के साथ नियोजन, समन्वय, भंडारण प्रक्रिया शामिल है।
- लॉजिस्टिक्स शब्द संसाधनों के अधिग्रहण, भंडारण और वितरण को उनके इच्छित स्थान पर नियंत्रित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करता है।
- इसमें संभावित वितरकों और आपूर्तिकर्त्ताओं का पता लगाना तथा ऐसी पार्टियों की व्यवहार्यता एवं पहुँच का मूल्यांकन करना शामिल है।

### राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति ( NLP ) 2022

- परिचय:
  - ♦ नीति प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और मल्टी-मोडल टांसपोर्ट पर केंद्रित है।
  - यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि उच्च लॉजिस्टिक्स लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू सामानों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करती है।
  - एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक है।

#### लक्ष्य:

- ♦ इस नीति की मदद से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का प्रयास किया जायेगा। इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 14-15 प्रतिशत है। जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8 प्रतिशत तक की कमी लाना है.
  - 🗷 अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत GDP अनुपात से कम है।
  - 😕 वर्तमान लागत सकल घरेलू उत्पाद का 16% है।
- दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में शीर्ष 10 में शामिल होना है। उसे दक्षिण कोरिया की विकास गति की बराबरी करनी होगी।
  - प्र भारत वर्ष 2018 में LPI में 44वें स्थान पर था।
- कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिये डेटा-संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support Systems-DSS) बनाना।
- नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक मुद्दों को कम-से-कम किया जाए, निर्यात कई गुना बढ़े और छोटे उद्योगों एवं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की विशेषताएँ:
  - ♦ डिजिटल एकीकरण प्रणाली: यह निर्बाध और तेज़ी से कार्य की गति को बढ़ाएग ताकि लॉजिस्टिक्स सेवाओं को कुशलता के साथ सुनिश्चित किया जा सके।
  - यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म: इसका उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं को एक ही पोर्टल पर लाया जाएगा, जिससे निर्माताओं एवं निर्यातकों को लंबी और बोझिल प्रक्रियाओं जैसी वर्तमान समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

- लॉजिस्टिक्स सेवाओं में आसानी: ई-लॉग्स, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, उद्योग को त्वरित समाधान के लिये सरकारी एजेंसियों के साथ परिचालन संबंधी मुद्दों को उठाने की अनुमति देगा।
- व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजनाः व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्ययोजना जिसमें इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम. भौतिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण, बेंचमार्किंग सेवा मानक, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास आदि शामिल है।

## इस नीति का महत्त्व क्या है?

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के शुभारंभ के साथ पीएम गति शक्ति को और बढ़ावा एवं पूरकता मिलेगी।
- यह नीति इस क्षेत्र को देश में एक एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला तथा सतत् लॉजिस्टिक परितंत्र बनाने में मदद करेगी क्योंकि यह नियमों को सुव्यवस्थित करने व आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ क्षेत्र के सभी बुनियादों को कवर करती है।
- यह नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है। लॉजिस्टिक से संबंधित पहलें:
- माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993  $\supset$
- पीएम गति शक्ति योजना
- मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क 0
- लीड्स (LEADS) रिपोर्ट
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
- सागरमाला प्रोजेक्ट्स
- भारतमाला परियोजना

# इथेरियम विलय

# चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एथेरियम ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से "प्रूफ-ऑफ वर्क' से 'प्रूफ-ऑफ-स्टेक' सर्वसम्मित तंत्र में परिवर्तित हो गया है और इस सुधार को विलय के रूप में जाना जाता है।

### वास्तविक परिवर्तन

- पुरानी पद्धति:
  - प्रफ-ऑफ वर्क: एक विकेंद्रीकृत मंच के रूप में एथेरियम के पास बैंक जैसे संस्थान नहीं हैं जो अपने नेटवर्क पर होने वाले लेन-देन को मंज़्री देते हैं, अनुमोदन पहले प्रूफ-ऑफ वर्क (PoW) सर्वसम्मित तंत्र के तहत हो रहे थे जो अनिवार्य रूप से खनिकों (Miners) द्वारा किया जाता था।

- इसके तहत खनिक अत्याधनिक कंप्यूटर हार्डवेयर के विशाल बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके जटिल गणितीय पहेली को हल करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा करेंगे और पहेली को हल करने वाले पहले व्यक्ति को सत्यापनकर्ता के रूप में चुना जाएगा।
- यह विधि लगभग पूरी तरह से क्रिप्टो फार्मों पर निर्भर थी, जो कंप्यूटर के बड़े पैमाने पर उपयोग कर समस्याओं को हल करेंगे।

#### ♦ मुद्देः

- उच्च ऊर्जा खपत: ये माइनिंग फार्म, ऊर्जा की खपत करते थे और वे कभी-कभी देशों की तुलना में अधिक ऊर्जा की खपत करते थे और इसलिये पर्यावरणीय स्थिरता के मामले में एक बड़ी चिंता थी।
- 🗷 क्रिप्टो की कुल वार्षिक ऊर्जा खपत फिनलैंड के बराबर है, जबिक इसका कार्बन फुट प्रिंट स्विट्जरलैंड के बराबर
- 💠 कुछ समय के लिये यूरोपीय देशों ने क्रिप्टो माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया, जबकि चीन ने वास्तव में क्रिप्टो खनिकों पर एक राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की जिससे उन्हें विदेशों से भागना पड़ा।

#### नई विधि:

- हिस्सेदारी का प्रमाण: यह उन क्रिप्टो खनिकों और विशाल माइनिंग फार्म की आवश्यकता को अलग कर देगा, जिन्होंने पहले ब्लॉकचेन को 'प्रफ-ऑफ-वर्क' (PoW) नामक एक तंत्र के तहत संचालित किया था।
  - 🗷 इसके बजाय यह अब 'प्रूफ-ऑफ-स्टेक' (PoS) तंत्र में स्थानांतरित हो गया है जो लेन-देन की मंज़्री देने के लिये यादुच्छिक रूप से 'सत्यापनकर्त्ता' प्रदान करता है।
- सत्यापनकर्ता वे लोग होते हैं जो पहले ब्लॉक से आखिरी तक लिंकेज की लगातार गणना करके ब्लॉकचैन की अखंडता को बनाए रखने के लिये कंप्यूटर को स्वेच्छा से रखते हैं।

#### लाभ:

- 💢 यह इथेरियम नेटवर्क पर खनिकों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा।
- प्र यह इथेरियम की ऊर्जा खपत को लगभग 99.95% कम
- 🗷 यह इथेरियम नेटवर्क पर लेन-देन को बेहद सुरक्षित बना देगा।

# इथेरियम:

इथेरियम डेवलपर्स द्वारा विकेंद्रीकृत एप (DAP), स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट

और यहाँ तक कि क्रिप्टो टोकन बनाने के लिये सबसे अधिक उपयोग किये जाने वाले प्लेटफार्मों में से एक है। प्लेटफार्म की मुद्रा, ईथर बाजार पूंजीकरण के मामले में बिटकॉइन के बाद दूसरे स्थान पर है।

 क्रिप्टोकरेंसी के कुछ सबसे लोकप्रिय एप्लीकेशन जैसे कि अपूरणीय टोकन/नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) और विकेंद्रीकृत वित्त (DFI) इथेरियम नेटवर्क पर आधारित हैं।

#### क्रिप्टोकरेंसी:

- क्रिप्टोकरेंसी, जिसे कभी-कभी क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक रूप है जो डिजिटल या वस्तुत: मौजूद होती है और यह लेन-देन को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है।
- क्रिप्टोकरेंसी में मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह लेन-देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिये विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है।
  - यह एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा संचालित होता
     है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।

#### ब्लॉकचेन तकनीकः

- ब्लॉकचेन तकनीक सुनिश्चित करती है कि क्रिप्टोकरेंसी में सभी लेन-देन एक सार्वजनिक वित्तीय लेन-देन डेटाबेस में दर्ज किये जाते हैं।
  - बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल क्रिप्टोकरेंसी के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
- ब्लॉकचेन का नाम डिजिटल डेटाबेस या लेजर से लिया गया है जहाँ जानकारी "ब्लॉक" के रूप में संग्रहीत की जाती है जो "चेन" बनाने के लिये एक साथ मिलती हैं।
  - यह स्पष्ट रिकॉर्ड-कीपिंग, रियल-टाइम लेन-देन पारदर्शिता और ऑडिटेबिलिटी का एक विलक्षण संयोजन प्रदान करता है।
  - ब्लॉकचेन की एक सटीक प्रति कई कंप्यूटरों या उपयोगकर्ता ओं में से प्रत्येक के लिये उपलब्ध है जो एक नेटवर्क में एक साथ जुड़े हुए हैं।
    - नए ब्लॉक के माध्यम से जोड़ी या बदली गई किसी भी नई जानकारी का कुल उपयोगकर्ता ओं के आधे से अधिक द्वारा जाँच और अनुमोदन किया जाना है।

# त्वरित सुधारात्मक कारवाई फ्रेमवर्क

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, CBI द्वारा न्यूनतम नियामक पूंजी और कुल गैर-

निष्पादित परिसंपत्तियों (NNPAs) सिंहत विभिन्न वित्तीय अनुपातों में सुधार दिखाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) को अपने त्विरत सुधारात्मक कारवाई फ्रेमवर्क (PCAF) से हटा दिया है।

RBI ने अपने उच्च कुल NPA और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) के कारण जून 2017 में सेंट्रल बैंक पर त्वरित सुधारात्मक कारवाई (PCA) मानदंड लागू किया था।

## त्वरित सुधारात्मक कारवाई फ्रेमवर्क ( PCAF ):

- 🗅 पृष्ठभूमि:
  - PCA एक फ्रेमवर्क रूपरेखा है जिसके तहत कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों की निगरानी RBI द्वारा की जाती है।
  - RBI ने वर्ष 2002 में PCA फ्रेमवर्क को बैंकों के लिये एक संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पेश किया, जो बुरी आस्तियों की गुणवत्ता के कारण अल्प पूंजीकृत हो जाते हैं अथवा लाभप्रदता के नुकसान के कारण कमजोर हो जाते हैं।
  - भारत में वित्तीय संस्थानों और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के लिये संकल्प व्यवस्था पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर इस रूपरेखा की समीक्षा वर्ष 2017 में की गई थी।
- 그 मानदंड:
  - RBI ने PCA फ्रेमवर्क के भाग के रूप में, तीन मापदंडों के संदर्भ में कुछ नियामक ट्रिगर बिंदु निर्दिष्ट किये हैं, यथा पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR), कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA)।
- 🗅 उद्देश्य:
  - PCA फ्रेमवर्क का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को लागू करना है और पर्यवेक्षित इकाई से यह अपेक्षित होता है कि वे समय-समय पर आवश्यक कदम उठायें तािक इसके वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके।
  - इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों
     (NPA) की समस्या की जाँच करना है।
  - इसका उद्देश्य नियामक के साथ-साथ निवेशकों और जमाकर्त्ताओं को सतर्क करने में सहायता करना है यदि कोई बैंक NPA की ओर बढ़ रहा है।
  - इसका उद्देश्य किसी संकट के अनुपात में वृद्धि होने से पहले ही समस्याओं का समाधान करना है।
- लेखा परीक्षा वार्षिक वित्तीय परिणाम:
  - एक बैंक को आम तौर पर लेखा परीक्षा वार्षिक वित्तीय परिणामों
     और RBI द्वारा किये गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर
     PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा जाएगा।

- हाल में हुए विकास कार्य:
  - ♦ वर्ष 2021 में, RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये PCA फ्रेमवर्क को संशोधित कर राउंड कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लीवरेज को प्रमुख क्षेत्र माना गया जबकि परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता इस ढाँचे के तहत निगरानी के प्रमुख क्षेत्र थे।

### गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ:

- यह एक ऋण अथवा अग्रिम भुगतान है जिसके लिये मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिये अतिदेय रहता है।
- बैंकों को NPA को घटिया, संदेहास्पद और हानि वाली संपत्तियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है।

## पूंजी पर्याप्तता अनुपातः

- पुँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) बैंक की उपलब्ध पूंजी बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोज़र को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने का एक उपाय है।
  - ♦ CAR वह माप अनुपात है जो बैंकों की घाटे को अवशोषित करने की क्षमता का आकलन करता है।
- पुंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसे पुंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा और विश्व भर में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।
  - परिसंपत्तियों पर रिटर्न/लाभ (Return on Assets-RoA):
- परिसंपत्तियों पर रिटर्न एक लाभप्रदता अनुपात है जो यह बताता है कि कंपनी अपनी संपत्ति से कितना लाभ उत्पन्न कर सकती है।
- RoA को प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है और संख्या जितनी अधिक होगी, कंपनी का प्रबंधन मुनाफा उत्पन्न करने के लिये अपनी बैलेंस शीट का प्रबंधन करने में उतना ही कुशल होगा।
- कम RoA वाली कंपनियों के पास आमतौर पर अधिक संपत्ति होती है जो लाभ पैदा करने में शामिल होती है, जबिक उच्च RoA वाली कंपनियों के पास कम संपत्ति होती है।
- समान कंपनियों की तुलना करते समय ROA सर्वोत्तम होता है, परिसंपत्ति-गहन कंपनी का निम्न RoA कम संपत्ति और समान लाभ के साथ एक असंबंधित कंपनी के उच्च RoA की तुलना में खतरनाक दिखाई दे सकता है।

# स्टार्टअप की मदद के लिये स्थापित कोष

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने 88 वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) के लिये 2016 में शुरू किये गए स्टार्टअप इंडिया निवेश के लिये फंड ऑफ फंड के तहत 7,385 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

बदले में AIF ने 720 स्टार्टअप में 11,206 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

## स्टार्टअप की मदद के लिये स्थापित कोष:

- विषय:
  - ♦ FSS के तहत भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) को सहायता दी जाती है, जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं।
  - ♦ FFS की घोषणा 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ की गई थी।.
    - 🗷 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्र (वित्त वर्ष 2016-2020 तथा वित्त वर्ष 2021-2025) में इस राशि का संग्रह किया जाना है।
  - ♦ FFS ने शुरुआती चरण, बीज चरण और विकास चरण में स्टार्टअप के लिये पूंजी उपलब्ध कराई है।
    - 🗷 इसने घरेलू पूंजी जुटाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम करने और घरेलु एवं नए उद्यम पुंजी कोष को प्रोत्साहित करने में भी भूमिका निभाई है।

#### प्रदर्शन: $\supset$

- ♦ FFS के अंतर्गत तय राशि योजना के शुभारंभ के बाद से 21% से अधिक की CAGR (यौगिक वार्षिक वृद्धि दर) दर से प्रतिवर्ष बढी है।
- 💠 इस योजना के संचालन के लिये उत्तरदायी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा हाल ही में सुधारों की एक शृंखला शुरू की है ताकि FFS के तहत सहायता प्राप्त वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) को त्वरित गिरावट प्राप्त करके अभीष्ट स्थिति प्राप्त करने के सक्षम बनाया जा सके।
  - 💢 इसके परिणामस्वरूप गिरावट की राशि में साल-दर-साल 100% की वृद्धि हुई है।
- ♦ FFS ने AIFs समर्थित 88 में से 67 AIF को एंकर करने में मदद की है।
  - 🗷 इनमें से 38 बिल्कुल नए निवेश प्रबंधक हैं जो FFS के भारतीय स्टार्टअप्स के लिये उद्यम पूंजी निवेश के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप हैं।
- ♦ FFS के माध्यम से समर्थित प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप मूल्यांकन में 10 गुना से अधिक की वृद्धि दर्शा रहे हैं, उनमें से कई ने यूनिकॉर्न स्थिति (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का मूल्यांकन) प्राप्त कर ली है।

### वैकल्पिक निवेश कोष:

- विषय:
  - वैकल्पिक निवेश कोष भारत में स्थापित या निगमित कोई भी कोष जो निजी रूप से एक जमा निवेश साधन है तथा अपने निवेशकों के लाभ के लिये एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु परिष्कृत निवेशकों, चाहे भारतीय हो या विदेशी, से धन एकत्र करता है।
  - भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (SEBI) विनियम (AIFs), 2012 के विनियम 2(1)b में AIFs की परिभाषा दी गई है।
  - ♦ एक कंपनी, या सीमित देयता भागीदारी (LLP) के माध्यम से, एक वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया जा सकता है।

# मेक इन इंडिया के आठ वर्ष

### चर्चा में क्यों ?

मेक इन इंडिया ने आठ वर्ष के पथ-प्रदर्शक सुधार कर लिये हैं और वर्ष 2022 में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

## मेक इन इंडिया कार्यक्रमः

- परिचय:
  - वर्ष 2014 में लॉन्च किये गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है।
  - 💠 यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला निमंत्रण है।
  - मेक इन इंडिया ने 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

#### उद्देश्य:

- नए औद्योगीकरण के लिये विदेशी निवेश को आकर्षित करना और चीन से आगे निकलने के लिये भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना।
- 💠 मध्याविध में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12-14% वार्षिक करने का लक्ष्य।
- 💠 देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना।
- 💠 वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सुजित करना।
- निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना।

#### परिणाम:

- FDI अंतर्वाह: 2014-2015 में भारत में FDI अंतर्वाह 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और तब से लगातार आठ वर्षों में रिकॉर्ड FDI प्रवाह तक पहुँच गया है।
  - म वर्ष 2021-22 में 83.6 अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक FDI दर्ज किया गया।
  - 🗷 हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों और ईज ऑफ ड्रइंग बिजानेस की वजह से भारत चालू वित्त वर्ष (2022-23) में FDI में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आकर्षित करने की राह पर है।
- ♦ वित्तीय वर्ष 2021-22 में खिलौनों का आयात 70% घटकर (877.8 करोड़ रुपए) हो गया है। भारत के खिलौनों के निर्यात में अप्रैल-अगस्त 2022 में 2013 की इसी अवधि की तुलना में 636% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है।
- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI): 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना 2020-21 में मेक इन इंडिया पहल को एक बड़े बढ़ावा के रूप में शुरू की गई थी।

## मेक इन इंडिया योजना में सहायक पहल:

- राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS):
  - ♦ राष्ट्रीय एकल खिड्की प्रणाली (NSWS) का सितंबर 2021 में शुभारंभ किया गया ताकि निवेशकों को अनुमोदन और मंज़्री के लिये एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके व्यापार करने में आसानी हो।
  - इस पोर्टल ने निवेशकों के अनुभव को बढाने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई मौजूदा निकासी प्रणालियों को एकीकृत किया है।

#### गति शक्तिः

- कनेक्टिविटी हेतु एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसे प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम कहा जाता है। यह कनेक्टिविटी में सुधार करने वाले बुनियादी ढाँचे के निर्माण के माध्यम से व्यावसायिक संचालन में ढुलाई-संबंधी दक्षता सुनिश्चित करेगा।
- एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP):
  - इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले को स्वदेशी उत्पादों के प्रचार और उत्पादन की सुविधा प्रदान करना तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के कारीगरों और निर्माताओं को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है. जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

- खिलौना निर्यात में सुधार और आयात को कम करना:
  - 💠 निम्न गुणवत्ता और खतरनाक खिलौनों के आयात को संबोधित करने तथा खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को बढावा देने के लिये सरकार द्वारा बुनियादी सीमा शुल्क को 20% से बढाकर 60% करने, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का कार्यान्वयन, आयातित खिलौनों का अनिवार्य नम्ना परीक्षण, घरेलु खिलौना निर्माताओं को 850 से अधिक बीआईएस लाइसेंस देने, खिलौना क्लस्टरों के विकास आदि जैसे कई रणनीतिक हस्तक्षेप किये गए हैं।
- अर्द्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेत् योजना:
  - विश्व अर्थव्यवस्था में अर्द्धचालकों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत में एक अर्द्धचालक, प्रदर्शन और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेत् 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन योजना शुरू की है।

# REC को महारत का दर्जा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) को 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) का दर्जा दिया गया है।

## REC और महारत्नः

- REC का परिचय:
  - ♦ REC एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है, जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
  - इसे निम्नलिखित के रूप में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिये एक नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है:
    - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)
    - च दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGIY)
    - प्राष्ट्रीय विद्युत कोष (NEF)
  - उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की निगरानी में REC विद्युत मंत्रालय की भी सहायता करती है।

- REC को महारत्न का दर्जा मिलने के लाभ:
  - 🙎 'महारत्न' CPSE का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिये इक्विटी निवेश कर सकता है एवं भारत और विदेशों में विलय और अधिग्रहण कर सकता है, जो संबंधित CPSE के कुल मुल्य के 15% की सीमा तक सीमित है। यह राशि एक प्रोजेक्ट के लिये ₹5,000 करोड रुपए है।
  - बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का संरचना कार्य तथा कार्यान्वयन भी कर सकता है।
  - □ REC अब प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठबंधनों में भी प्रवेश कर सकता है।
- महारत्न' का दर्जा:
  - 'महारत्न' व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से की गई
    - 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' (CPSEs) का आशय उन कंपनियों से है, जिनमें केंद्र सरकार या अन्य CPSE की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है।
  - 'महारत्न' का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है अथवा बीते तीन वर्षों के लिये उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था या फिर बीते तीन वर्षों के लिये उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है।
  - 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' के लिये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है।
  - सरकार ने CPSEs को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देने के लिये मानदंड निर्धारित किये हैं।

## CPSEs का वर्गीकरण

	श्रेणी		शुरुआत		मानदंड		उदाहरण
)	<b>श्रेणी</b> महारत्न	D C	शुरुआत  CPSEs के लिये महारत्न योजना  मई 2010 में शुरू की गई थी,  तािक मेगा CPSEs को अपने  संचालन का विस्तार करने और  वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने  के लिये सशक्त बनाया जा सके।		कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये।  कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Prescribed Public Shareholding) के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिये।  विगत तीन वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय (Average Annual Turnover) 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।  पछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य (Average Annual Net Worth) 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिये।  पछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक होना चाहिये।  पछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक होना चाहिये।	O .	अराहरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, आदि।
				n n			

⊃ नवरत्न	⇒ नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी ताकि उन CPSEs	⇒ मिनीरत्न श्रेणी - I और अनुसूची 'A' के तहत आने वाली	<ul><li>भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,</li><li>हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड,</li></ul>
	की पहचान की जा सके जो अपने	CPSEs, जिन्होंने पिछले पाँच	आदि।
	संबंधित क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ	वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन	
	प्राप्त करते हैं और वैश्विक	प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत	
	अभिकर्त्ता बनने के उनके अभियान	अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है और छह	
	में उनका समर्थन करते हैं।	प्रदर्शन मापदंडों में 60 या उससे	
		अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त किया हो। ये छह मापदंड हैं:	
		<ul> <li>शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ</li> </ul>	
		♦ उत्पादन की कुल लागत के	
		सापेक्ष मैनपॉवर पर आने वाली कुल लागत	
		कुल लागत	
		लाभ, वर्किंग कैपिटल पर लगा	
		टैक्स और ब्याज	
		और कुल बिक्री पर लगा कर	
		<ul><li>प्रति शेयर कमाई</li></ul>	
		<ul><li>अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन</li></ul>	
<ul><li>मिनीरत्न</li></ul>	<ul><li>मिनीरत्न योजना की शुरुआत वर्ष</li></ul>	· ·	<ul><li>श्रेणी-1: भारतीय विमानपत्तन</li></ul>
	1997 में सार्वजनिक क्षेत्र को	श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के	प्राधिकरण, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन
	। अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी	लिये आवश्यक है कि कंपनी ने	लिमिटेड, आदि।
	बनाने और लाभ कमाने वाले	पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ	
	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को	प्राप्त किया हो तथा तीन साल में	निगम (ALIMCO), भारत
	अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों का	एक बार कम से कम 30 करोड़	पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
	प्रत्यायोजन प्रदान करने के नीतिगत	रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया	(BPCL), आदि।
	उद्देश्य के अनुसरण में की गई थी।	हो।	
		⊃ मिनीरत्न श्रेणी- 2 : CPSE द्वारा	
		पिछले तीन साल से लगातार लाभ	
		अर्जित किया हो और उसकी	
		निवल संपत्ति सकारात्मक हो, वे	
		मिनीरत्न- II का दर्जा पाने के लिये	
		पात्र हैं।	

# सेमीकंडक्टर चिप निर्माण हेतु संशोधित प्रोत्साहन योजना

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु योजना में बदलाव को मंज़ूरी दी है ताकि भारत की 10 बिलियन डॉलर की चिप निर्माण पहल को निवेशकों के लिये अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

## भारत की चिप निर्माण योजना में स्वीकृत परिवर्तन:

- 🔾 पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 2021 में भारत ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिये लगभग \$ 10 बिलियन डॉलर की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की घोषणा की।
  - साथ ही डिजाइन सॉफ्टवेयर, आईपी अधिकारों आदि से संबंधित वैश्विक और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिये एक डिजाइन-लिंक्ड इनिशिएटिव (DLI) योजना की घोषणा की गई।

#### परिवर्तनः

- एक समान 50% वित्तीय सहायता: योजना के पिछले संस्करण में केंद्र सरकार 45nm से 65nm चिप उत्पादन के लिये परियोजना लागत का 30%, 28nm से 45nm के लिये 40% और 28nm या उससे कम के लिये 50% या आधी लागत की सहायता करती थी। संशोधित योजना सभी नोड्स के लिये एक समान 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- वेदांता और ताइवान की चिपमेकर फॉक्सकॉन ने गुजरात में
   1,54,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिये
   समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
- दो अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है:
  - इंटरनेशनल कंसोर्टियम आईएसएमसी द्वारा कर्नाटक में 3 बिलियन डॉलर का प्लांट।
- आईएसएमसी अबू धाबी स्थित नेक्स्ट ऑबिंट वेंचर्स और इज्ञरायल के टॉवर सेमीकंडक्टर का संयुक्त उद्यम है।
  - सिंगापुर के आईजीएसएस वेंचर्स द्वारा तिमलनाडु में 3.5 बिलियन डॉलर का प्लांट।
  - 45nm चिप का उत्पादन: संशोधित योजना ने 45nm चिप के उत्पादन पर भी जोर दिया, जो उत्पादन के मामले में काफी कम समय लेने वाला और किफायती है।
  - इन चिप्स की उच्च मांग है, जो मुख्य रूप से ऑटोमोटिव, पावर और दूरसंचार अनुप्रयोगों द्वारा संचालित है।

#### ) महत्त्व:

- इन परिवर्तनों से अर्द्धचालकों के सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिये सरकारी प्रोत्साहनों में सामंजस्य स्थापित होगा।
- यह भारत में एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये
   चिप के सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा।
- PLI और DLI योजनाओं ने भारत में अर्द्धचालक निर्माण संयंत्र (fabs) स्थापित करने के लिये कई वैश्विक अर्द्धचालक अभिकर्त्ताओं को आकर्षित किया था एवं संशोधित कार्यक्रम इन निवेशों को और तेज करने के साथ ही अधिक आवेदकों को आमंत्रित करेगा।

#### 🕽 चिंताएँ:

- हालाँकि यह योजना एक उत्साहजनक कदम है, चिप उत्पादन एक संसाधन-गहन और महँगी प्रक्रिया है। नई योजना प्रक्रिया के सभी चरणों के लिये समान वित्तपोषण प्रदान करती है। तथापि, इस योजना का परिव्यय 10 अरब डॉलर है।
- केवल एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिये 3 से 7
   बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होती है।

### सेमीकंडक्टर चिप्स:

#### 🗅 विषय:

- सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री है जिसमें चालकता सुचालक और कचालक के बीच होती है।
- ये शुद्ध धातु, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम या कोइ यौगिक,
   गैलियम, आर्सेनाइड या कैडिमियम सेलेनाइड हो सकते हैं।
- सेमीकंडक्टर चिप का मूल घटक सिलिकॉन का एक टुकड़ा होता है, जिसे अरबों सूक्ष्म ट्रांजिस्टर के साथ उकेरा जाता है और विशिष्ट खिनजों एवं गैसों के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, जो विभिन्न संगणकीय निर्देशों का पालन करते हुए विद्युत् धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिये प्रतिरूप बनाते हैं।
- आज के समय में उपलब्ध सबसे उन्नत अर्द्धचालक प्रौद्योगिकी नोड 3 nm और 5 nm (Nanometer) वाले हैं।
- उच्च नैनोमीटर मान वाले अर्द्धचालक ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में लगाए जाते हैं, जबिक कम मान वाले अर्द्धचालकों का उपयोग स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे उपकरणों में किया जाता है।
- चिप बनाने की प्रक्रिया जिटल और बहुत सटीक है, जिसमें आपूर्ति शृंखला में कई अन्य चरण होते हैं जैसे कि कंपनियों द्वारा उपकरणों में उपयोग के लिये नई सिर्किट विकसित करने हेतु चिप-डिजाइनिंग, चिप्स के लिये सॉफ्टवेयर डिजाइन करना और केंद्रीय बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के माध्यम से उनका पेटेंट कराना।

🗷 इसके अंतर्गत चिप-निर्माण मशीन बनाना शामिल है; फैब या कारखाने, ATMP स्थापित करना।

#### महत्त्व:

 सेमीकंडक्टर्स स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में जुड़े उपकरणों तक लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के थंबनेल के आकार के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। वे उपकरणों को संगणकीय शक्ति देने में मदद करते हैं।

#### वैश्विक परिदृश्य:

- ♦ चिप बनाने वाला उद्योग अत्यधिक केंद्रित है, जिसमें बड़े अभिकर्त्ता ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं। वास्तव में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (TSMC) द्वारा ताइवान में 5nm चिप्स का 90% बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।
- इसलिये वैश्विक चिप की कमी, ताइवान पर अमेरिका-चीन तनाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति शृंखला अवरोधों ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को नए सिरे से चिप बनाने के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये प्रेरित किया है।
- वैश्विक अर्द्धचालक उद्योग का मुल्य वर्तमान में 500-600 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्तमान में लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मुल्य के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कि पुर्ति करता है।

## भारतीय परिदृश्य:

- भारत वर्तमान में सभी चिप्स का आयात करता है और वर्ष 2025 तक बाजार के 24 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। हालाँकि सेमीकंडक्टर चिप के घरेलू निर्माण के लिये भारत ने हाल ही में कई पहल शुरू की हैं:
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'अर्द्धचालक और प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र' के विकास का समर्थन करने के लिये 76,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।
  - 🗷 भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और अर्द्धचालकों के निर्माण के लिये इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं अर्द्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS) भी शुरू की है।
  - वर्ष 2021 में MeitY ने सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कम-से-कम 20 घरेलू कंपनियों का पोषण करने और उन्हें अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हासिल करने की सुविधा के लिये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना भी शुरू की।
- भारत में अर्द्धचालकों की अपनी खपत वर्ष 2026 तक 80 अरब डॉलर और वर्ष 2030 तक 10 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

# मोटे अनाजों को बढ़ावा

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिये खरीफ उपज की खरीद पर चर्चा के लिये एक बैठक आयोजित की गई।

- भारत सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहन देने पर विचार किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने गेहूँ और धान की खेती को प्रभावित किया है।
- खरीफ फसल बाजार से मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य दोगुना हुआ, राशन में मोटे अनाज की अधिक संभावना नजर आ रही है।

### मोटे अनाजः

- परिचय:  $\supset$ 
  - मोटे अनाज पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाए जाते हैं।
    - 🗷 कृषि-जलवायु क्षेत्र, फसलों और किस्मों की एक निश्चित श्रेणी के लिये उपयुक्त प्रमुख जलवायु के संदर्भ में भूमि की एक इकाई है।
  - → ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, फिंगर (Finger) बाजरा और अन्य कुटकी (Small Millets) जैसे कोदो (Kodo), फॉक्सटेल (Foxtail) , प्रोसो (Proso) और बार्नयार्ड (Barnyard) एक साथ मोटे अनाज कहलाते हैं।
    - ज्वार, बाजरा, मक्का और छोटे बाजरा (बार्नयार्ड बाजरा, प्रोसो बाजरा, कोदो बाजरा और फॉक्सटेल बाजरा) को पोषक-अनाज भी कहा जाता है।

#### महत्त्व:

- मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर सामग्री के लिये जाने जाते हैं और इसमें सूखा सिहष्णु, प्रकाश-असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन आदि जैसी विशेषताएँ विद्यमान होती हैं।
  - ये फसलें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में और एक आशाजनक निर्यात योग्य वस्तु के रूप में भी अच्छी संभावनाएँ प्रदान करती हैं।
- 💠 मानव उपभोग के लिये भोजन, पशु और मुर्गीयों के लिये चारा और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिये सूखा प्रवण क्षेत्रों में उनकी खेती, ईंधन और औद्योगिक उपयोग के रूप में इनका उपयोग सामान्य है।
  - 🗷 उनका पौष्टिक मूल्य कुपोषण से निपटने के लिये एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में कार्य करता है।

- ♦ यह अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में रोजगार-सृजन में सहायता करता है, जहाँ अन्य वैकल्पिक फसलें सीमित हैं और इन फसलों का उपयोग आकस्मिक फसल के रूप में किया जाता है।
- मोटे अनाज उत्पादक राज्य:
  - कर्नाटक, राजस्थान, पुद्दचेरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि।
- मोटे अनाज के उपयोगः
  - चारा:
    - 🙎 कुछ उत्तरी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्वार और बाजरा की खेती मुख्य रूप से चारे के उद्देश्य से की जाती है।
  - औद्योगिक उत्पाद:
    - 🗷 चारा: माल्टिंग, उच्च फ्रुक्टोज सिरप, स्टार्च, गुड, बेकरी आदि में उपयोग किया जाता है।
    - 🗷 बाजरा: शराब बनाने/माल्टिंग, स्टार्च, बेकरी, पोल्ट्री और पशु आहार में प्रयुक्त।
    - 🗷 मक्का: शराब बनाने, स्टार्च, बेकरी, मुर्गी पालन और पशु चारा, जैव-ईंधन में उपयोग किया जाता है।
  - चारा/फीड का स्रोत (Source of Feed):
    - 🗷 पशुओं के लिये मोटे अनाज और पोल्ट्री फीड की मांग बढ़ रही है।
    - 😕 भारत में चारा की आवश्यकताएँ सामान्य रूप से बेकार अनाज से पूरी की जाती हैं और विशेष रूप से मोटे अनाज से बनाई जाती हैं।
    - 💢 पोल्ट्री फीड में मक्का आवश्यक कार्बोहाइड्रेट स्रोत है।

# शहरी रोज़गार गारंटी

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी रोजगार को बढ़ावा देने हेत् प्रमुख योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है।

### योजना का परिचय:

- उद्देश्य:
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का रोज़गार प्रदान करना।
  - ♦ सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिये 800 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- लक्षित जनसंख्या: 18 से 60 आयु वर्ग के लोग योजना के लिये पात्र हैं।

- रोजगार के अवसर:
  - ♦ जल संरक्षण: खानियों की बावड़ी में नवीनीकरण कार्य योजना के जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत आता है।
  - अभिसरण: लोगों को अन्य केंद्र या राज्य स्तर की योजनाओं में नियोजित किया जा सकता है, जिनके पास पहले से ही एक भौतिक घटक है और जिसके लिये श्रम कार्य की आवश्यकता होती है।
  - अन्य कार्यों में शामिल हैं:
    - 🗷 पर्यावरण संरक्षण जैसे- सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण और पार्कों का रखरखाव।
    - स्वच्छता और सफाई संबंधी कार्य जैसे ठोस कचरा प्रबंधन।
    - 🗷 विरासत संरक्षण और सुरक्षा/बाड़ लगाना/चारदीवारी/ नगरीय निकायों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा आदि से संबंधित कार्य।
- अन्य राज्यों की शहरी रोजगार गारंटी योजनाएँ:
  - केरल:
    - 🙎 वर्ष 2010 में शुरू की गई अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना (AUEGS) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को एक वित्तीय वर्ष में 100 के वेतन रोजगार की गारंटी देकर बढाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से काम करते हैं।
  - हिमाचल प्रदेश:
    - 🗷 मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना 2020 में शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिये एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 120 दिनों की गारंटी मज़दूरी रोज़गार प्रदान करने के लिये शरू की गई थी।
  - झारखंड:
    - 🗷 मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020 में झारखंड राज्य में आजीविका सुरक्षा बढाने के लिये एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोज़गार की गारंटी प्रदान करके शुरू की गई थी।

# प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ (Natural Rubber-NR) की कीमत 16 महीने के निचले स्तर पर पहुँचने के कारण किसानों और विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।

#### कीमतों में तेज़ गिरावट का कारण:

- निम्न मांग और अन्य कारक: इसके अंतर्गत चीन की कमज़ोर मांग और उच्च मुद्रास्फीति के साथ यूरोपीय ऊर्जा संकट जैसे कारण शामिल हैं।
- जबिक चीन में निरंतर शून्य कोविड रणनीति, जो प्राकृतिक रबड़ की वैश्विक मात्रा का लगभग 42% खपत करती है, उद्योग को महंगा पडा है।
- अन्य देशों से आयात: घरेलु टायर उद्योग में आइवरी कोस्ट से ब्लॉक रबड़ और सुदूर पूर्व से मिश्रित रबड़ की पर्याप्त आपूर्ति होती है।
  - प्राकृतिक रबड की कुल खपत के 73.1% हिस्से का उपयोग ऑटो-टायर निर्माण क्षेत्र में होता है।

#### गिरती कीमत का किसानो पर प्रभाव:

- फसल स्थानांतरण: कीमतों में गिरावट का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महसूस किया जाता है, जहाँ ज्यादातर लोग पूरी तरह से रबड़ की खेती पर निर्भर हैं, इसलिये वे अन्य फसलों के उत्पादन की तरफ रूख कर सकते हैं।
  - यह रबड हिस्सेदारी के विखंडन का कारण भी बन सकता है।
- लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रभाव: चूँकि अधिकांश उत्पादन छोटे और मध्यम उद्यमों में होता है, गिरती कीमत उन्हें अनिश्चित भविष्य की ओर ले जा सकती है और अस्थायी रूप से उत्पादन बंद करने के लिये मजबूर कर सकती है।
- केरल में डर का वातावरण: राज्य का योगदान कुल उत्पादन में लगभग 75% है, क्योंकि स्थानीय अर्थव्यवस्था रबड़ उत्पादन पर निर्भर करती है, इसलिये गिरती कीमत केरल के गाँवों में बडी दहशत पैदा कर सकती है।

# प्राकृतिक रबड़:

- वाणिज्यिक रोपण फसल: रबड़ हेविया ब्रासिलिएन्सिस नामक पेड़ के लेटेक्स से बनाया जाता है। रबड को बड़े पैमाने पर रणनीतिक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में माना जाता है और इसे रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं औद्योगिक विकास के लिये विश्व स्तर पर विशेष दर्जा दिया गया है।
- विकास हेतु आवश्यक स्थिति: यह भूमध्यरेखीय फसल है लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है।
  - 💠 तापमान: नम और आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर।
  - 💠 वर्षा: 200 सेमी से अधिक।
  - मृदा का प्रकारः समृद्ध जलोढ़ मृदा।
  - इस रोपण फसल के लिये कुशल श्रम की सस्ती और पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता है।

- विश्व स्तर पर प्रमुख उत्पादक: थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन और भारत।
- प्रमुख उपभोक्ता: चीन, भारत, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया।

## भारत में रबड़ उत्पादन की स्थिति:

- उत्पादन:
  - अंग्रेज़ों ने भारत में पहला रबड बागान वर्ष 1902 में केरल में पेरियार नदी के तट पर स्थापित किया था।
  - 💠 भारत वर्तमान में उच्चतम उत्पादकता के साथ इस प्राकृतिक सामग्री का पाँचवाँ सबसे बडा उत्पादक है।
  - ♦ वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान रबड़ का उत्पादन 8.4% बढ़कर 7,75,000 टन हो गया।
    - 🗷 यह विश्व स्तर पर रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बना हुआ है।
    - 🗷 भारत की कुल प्राकृतिक रबड़ खपत का लगभग 40% वर्तमान में आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
  - शीर्ष रबड़ उत्पादक राज्य: केरल > तिमलनाड़ > कर्नाटक।
- सरकार की पहलें:
  - रबड़ प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम और रबड़ ग्रुप प्लांटिंग स्कीम, सरकार के नेतृत्व वाली पहल के प्रमुख उदाहरण हैं।
  - रबड़ के बागानों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
  - 💠 वाणिज्य विभाग ने राष्ट्रीय रबड नीति मार्च 2019 में पेश की।
    - 🗷 नीति में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन क्षेत्र और संपूर्ण रबड़ उद्योग मूल्य शृंखला का समर्थन करने के लिये कई प्रावधान शामिल हैं।
  - यह देश में रबड़ उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिये रबड क्षेत्र में गठित टास्क फोर्स द्वारा पहचानी गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर आधारित है।
  - अवधि के ढाँचे (Medium Term Framework-MTF) में प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के सतत् और समावेशी विकास योजना को लागू करके रबड़ बोर्ड के माध्यम से उत्पादकों के कल्याण के लिये प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का समर्थन करने हेत् विकासात्मक एवं अनुसंधान गतिविधियों को निष्पादित किया जाता है।

## रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया:

इसका मुख्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासन के  $\supset$ अंतर्गत केरल के कोट्टायम में अवस्थित है।

- रबड़ बोर्ड संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता और प्रोत्साहित करके देश में रबड उद्योग के विकास का कार्य करता है।
- रबड़ अनुसंधान संस्थान, रबड़ बोर्ड के अधीन है।

# विंडफॉल टैक्स

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2022 में घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स /अप्रत्याशित कर लगाए जाने को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह तदर्थ (अचानक बनाया या लिया गया) कदम नहीं है. बल्कि उद्योग के साथ पूर्ण परामर्श के बाद उठाया गया है।

भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी सहित कई देशों ने पहले ही ऊर्जा कंपनियों के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) लगा दिया है या ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं।

## विंडफॉल टैक्स:

- परिचय:
  - 💠 विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित बढ़े मुनाफे पर लगाईं गई उच्च कर दर है। उदाहरण के लिये रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप ऊर्जा मूल्य-वृद्धि।
  - ये ऐसे लाभ हैं जिन्हें फर्म द्वारा किसी सक्रिय निवेश रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
  - अप्रत्याशित लाभ को "बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ" के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - सरकारें आमतौर पर इस तरह के मुनाफे पर कर की सामान्य दरों के ऊपर पूर्वव्यापी रूप से एकमुश्त कर लगाती हैं, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है।
  - ♦ एक क्षेत्र जहाँ इस तरह के करों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है, वह है तेल बाजार, जहाँ कीमतों में उतार-चढाव से उद्योग को अस्थिर या अनिश्चित लाभ होता है।

#### औचित्य:

अप्रत्याशित लाभ के पुनर्वितरण सहित कई कारणों से दुनिया भर की सरकारों द्वारा विंडफॉल टैक्स को पेश किया गया है, जब उपभोक्ता वस्तुओं की उच्च कीमतों से उत्पादकों को लाभ होता है, साथ ही सरकार को भी सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण हेतु राजस्व की प्राप्ति होती है।

### देशों द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाने का कारण:

- पिछले वर्ष के अंत से और चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों में तेल, गैस एवं कोयले की कीमतों में तेज वृद्धि देखी गई है, हालाँकि हाल ही में इनमें कमी आई है।
- यह वृद्धि कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुई है, जिसमें कोविड-19 का सामना करने हेतु आर्थिक सुधार के दौरान ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन जैसे कारक शामिल है, जो युक्रेन-रूस युद्ध के कारण और अधिक बढ़ गया है।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप महामारी से उबरने और आपूर्ति के मुद्दों ने ऊर्जा की मांग को बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक कीमतें बढ़ गईं।
- बढती कीमतों का अर्थ ऊर्जा कंपनियों के लिये भारी और रिकॉर्ड 0 मुनाफा था, जिसका कारण बड़ी एवं छोटी अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू बिलों हेतु बढ़े गैस और बिजली के बिल थे।
- यह कर ऐसे समय में लगाया गया है जब रिफाइनरों ने यूरोप जैसे 0 घाटे में फँसे देशों को ईंधन निर्यात बढाकर बडा लाभ कमाया है, जिसने अब रूस से तेल आयात का बहिष्कार किया है।
- राष्ट्र (United Nations-UN) के प्रमुख ने सभी सरकारों से इन अत्यधिक मुनाफे पर कर लगाने का आग्रह किया "और इस कठिन समय में सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिये धन का उपयोग करने को कहा।"
- अप्रत्याशित करों को लागू करने के आह्वान को IMF जैसे संगठनों 0 में भी समर्थन मिला, जिसने इस प्रकार के करों को आरोपित करने के विषय/तरीकों पर एक परामर्श-पत्र जारी किया।

# विंडफॉल टैक्स से संबंधित मुद्दे:

- बाजार में अनिश्चितताः
  - कर व्यवस्था में निश्चितता और स्थिरता होने पर कंपनियाँ किसी क्षेत्र में निवेश करने में विश्वास रखती हैं।
  - चॅंिक अप्रत्याशित कर पूर्वव्यापी रूप में लगाए जाते हैं और प्राय: अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होते हैं. ये भविष्य के करों के बारे में बाज़ार में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं।
- प्रकृति में लोकलुभावनः
  - 💠 ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कर अल्पावधि में लोकलुभावन और राजनीतिक रूप से उपयुक्त होते हैं।
- भविष्य के निवेश में कमी:
  - 💠 एक अस्थायी अप्रत्याशित लाभ कर का परिचय भविष्य के निवेश को कम करता है क्योंकि संभावित निवेशक निवेश निर्णय लेते समय संभावित करों की संभावना का आकलन करेंगे।

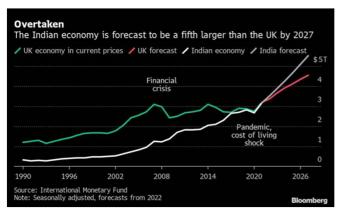
- यदि कीमतों में तीव्र वृद्धि से एकतरफा लाभ में वृद्धि होती है, तो इसे वास्तविक रूप में अप्रत्याशित कहा जा सकता है, लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि ये ऐसे लाभ हैं जिसे कंपनियों ने अंतिम उपयोगकर्त्ता को अंतिम उत्पाद प्रदान करने के क्रम में जोखिम लेने वाले उद्योगों के लिये एक प्रस्कार के रूप में अर्जित किया है।
- यह परिभाषित नहीं है कि यह कर किस पर लगाया जाना चाहिये, उच्च-मूल्य वाली बिक्री या छोटी कंपनियों के व्यापार के लिये जिम्मेदार बड़ी कंपनियाँ, यह सवाल उठाती हैं कि क्या एक निश्चित सीमा से नीचे के राजस्व या लाभ वाले उत्पादकों को छूट दी जानी चाहिये अथवा नहीं।

# भारत बना विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है।

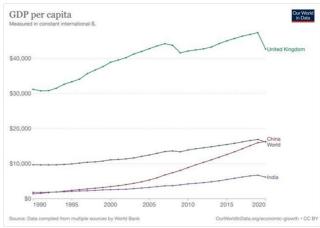
अनिश्चितताओं से युक्त विश्व में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 6-6.5% की वृद्धि करते के साथ ही भारत वर्ष 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिये तैयार है।



# प्रमुख बिंदु

- नया मील का पत्थर:
  - दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक को पीछे छोड़ना, विशेष रूप से दो शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाली अर्थव्यवस्था, वास्तव में मील का पत्थर है।

- 🗅 अर्थव्यवस्था का आकार:
  - मार्च, 2022 की तिमाही में 'सांकेतिक/नॉमिनल कैश टर्म' में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जबिक यूनाइटेड किंगडम की 816 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- 🔾 यूनाइटेड किंगडम के साथ तुलना:
  - जनसंख्या का आकार:
    - प्र वर्ष 2022 तक भारत की जनसंख्या 1.41 बिलियन है जबिक यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या 68.5 मिलियन है।
- ⊃ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद:
  - प्रित व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आय स्तरों की अधिक यथार्थवादी तुलना प्रदान करता है क्योंकि यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करता है।
  - भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम बनी हुई है, वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 190 देशों में से 122वें स्थान पर है।



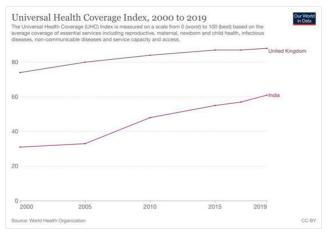
#### 🗅 गरीबी:

- कम प्रति व्यक्ति आय अक्सर गरीबी के उच्च स्तर की ओर संकेत करती है।
- 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन में चरम गरीबी की हिस्सेदारी भारत की तुलना में काफी अधिक थी।
  - हालाँकि भारत ने गरीबी पर अंकुश लगाने में काफी प्रगति की है, फिर भी सापेक्ष स्थिति उलट गई है।

#### 🔾 स्वास्थ्य:

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) सूचकांक को प्रजनन,
 मात्र, नवजात शिश् और बाल स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों, गैर-

- संचारी रोगों तथा सेवा क्षमता एवं पहुँच सहित आवश्यक सेवाओं के औसत कवरेज के आधार पर 0 (सबसे खराब) से 100 (सर्वश्रेष्ठ) के पैमाने पर मापा जाता है।
- जबिक तेज आर्थिक विकास और वर्ष 2005 से स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार की नीति ने भारत के लिये एक अलग सुधार किया है, इसके बावजूद अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।



- ⊃ मानव विकास सूचकांक (HDI):
  - उच्च सकल घरेलू उत्पाद और तेज आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य बेहतर मानव विकास मानकों का होना है।
  - HDI (2019) के अनुसार यूके का स्कोर 0.932 और भारत का स्कोर 0.645 है जो तुलनात्मक रूप से यूके से काफी पीछे हैं।
    - अपने धर्मिनरपेक्ष सुधार के बावजूद भारत को अभी भी ब्रिटेन की वर्ष 1980 की स्थिति को प्राप्त करने में एक दशक लग सकता है।
- 🗅 वर्तमान परिदृश्य:
  - नाटकीय बदलाव पिछले 25 वर्षों में भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ पिछले 12 महीनों में पाउंड के मूल्य में गिरावट देखी गई है।
    - वैश्विक भू-राजनीति में सही नीतिगत परिप्रेक्ष्य और पुनर्सरेखण से भी भारत के अनुमानों में उर्ध्मुखी संशोधन (Upward Revision) हो सकता है।

# यूएस स्टार्ट-अप सेतु

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र में रूपांतरण और कौशल संवर्द्धन कार्यक्रम में यूएस स्टार्टअप सेतु सहायक उद्यमियों का शुभारंभ किया।

## स्टार्टअप सेतुः

- 🗅 परिचय:
  - SETU या परिवर्तन और कौशल में सहायक उद्यमी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार की पहल है।
  - यह पहल भारत में स्टार्ट-अप को संयुक्त राज्य अमेरिका-आधारित निवेशकों और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के अभिकर्त्ताओं को वित्त पोषण, बाजार पहुँच और व्यावसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श एवं सहायता के साथ जोड़ेगी।

#### 🗅 महत्त्व:

- भारत में उद्यमिता और सन राइजिंग स्टार्टअप में निवेश करने के इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के मध्य भौगोलिक बाधाओं को कम करना।
- स्टार्टअप इंडिया पहल मेंटरिशप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन और ग्रोथ (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience, and Growth MAARG) कार्यक्रम के तहत मेंटरिशप पोर्टल के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन किया जाएगा, जो भारत में स्टार्टअप्स के लिये सिंगल-स्टॉप समाधान खोजकर्त्ता है।
  - पोर्टल को इस विचार के साथ विकसित किया गया है कि यह देश के हर कोने से एक संरक्षक से जुड़ने के लिये पहुँच योग्य हो।

#### आवश्यकताः

- यह अनुमान है कि लगभग 90% स्टार्ट-अप और आधे से अधिक अच्छी तरह से वित्त पोषित स्टार्टअप अपने शुरुआती दिनों में विफल हो जाते हैं। व्यवसाय को संभालने में अनुभव की कमी एक प्रमुख समस्या है तथा संस्थापकों को निर्णय लेने और नैतिक समर्थन के लिये सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
- जैसा कि भारत एक अग्रणी स्टार्ट-अप गंतव्य बन गया है, सही समय पर उचित मार्गदर्शन सर्वोपिर है।
- इसके अलावा, भारत सरकार एक स्टार्टअप की यात्रा में प्रोत्साहित कर राष्ट्र के विकास में योगदान के लिये दिग्गजों, अनुभवी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के लोगों को आमंत्रित करती है।

# सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

## चर्चा में क्यों?

हाल की रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का डिजिटल रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) चालू वित्त वर्ष में थोक व्यवसायों के साथ शुरू हो सकता है।

RBI ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जो इसे CBDC लॉन्च करने में सक्षम करेगा।

## सेंट्ल बैंक डिजिटल करेंसी ( CBDC )

- ⊃ परिचय:
  - CBDC कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है।
  - यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ वन टू वन विनिमय योग्य है।
  - फिएट मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा है जो किसी वस्तु की कीमत जैसे सोने या चाँदी की कीमत पर नहीं आँकी जाती है।
  - ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या CBDC का लेन-देन किया जा सकता है।
  - हालाँकि CBDCs की अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी, यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो संपत्तियों से अलग है जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं और न ही 'कानूनी निवदा' है।
- ⊃ उद्देश्य:
  - इसका मुख्य उद्देश्य जोखिम का शमन और वास्तविक मुद्रा के प्रबंधन, पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, परिवहन, बीमा एवं रसद से जुड़े लागत को कम करना है।
  - यह धन हस्तांतरण के साधन के रूप क्रिप्टोकरेंसी से लोगों को दूर भी रखेगा।
- 🗅 वैश्विक प्रवृति:
  - बहामा अपनी राष्ट्रव्यापी CBDC सैंड डॉलर लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था है।
  - नाइजीरिया एक और देश है जिसने वर्ष 2020 में ईनायरा (eNaira) शुरू किया है।
  - चीन अप्रैल 2020 में डिजिटल मुद्रा e-CNY का संचालन करने वाली दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
  - कोरिया, स्वीडन, जमैका और यूक्रेन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू कर दिया है और कई और जल्द ही इसका अनुसरण कर सकते हैं।

CBDC के लाभ और चुनौतियाँ:

- ⊃ लाभ:
  - परंपरा और नवोन्मेष का संयोजन:
    - CBDC मुद्रा प्रबंधन लागत को कम करके धीरे-धीरे आभासी मुद्रा की ओर एक सांस्कृतिक बदलाव ला सकता है।

- CBDC की परिकल्पना दोनों पक्षों के सर्वश्रेष्ठ को साथ लाने के लिये की गई है:
- 💠 जहाँ क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल रूपों की सुविधा एवं सुरक्षा
- पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का विनियमित, आरक्षित-समर्थित धन परिसंचरण शामिल है।
- 💠 सीमा-पार आसानी से भुगतान:
  - प्टBDC एक विश्वसनीय संप्रभु समर्थित घरेलू भुगतान और निपटान प्रणाली को आंशिक रूप से कागजी मुद्रा को प्रतिस्थापित करने के लिये एक आसान साधन प्रदान कर सकता है।
  - इसका उपयोग सीमा-पार भुगतान (Cross-Border Payments) के लिये भी किया जा सकता है; यह सीमा-पार भुगतानों के निपटान के लिये कोरेस्पोंडेंट बैंकों के महंगे नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।
- वित्तीय समावेशन:
  - बेहतर कर एवं नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु असंगठित अर्थव्यवस्था को संगठित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाने के लिये कई अन्य वित्तीय गतिविधियों के संबंध में भी CBDC के बढ़ते उपयोग की तलाश की जा सकती है।
  - यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

# विदेशों में निवेश करने हेतु नए मानदंड

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने नए मानदंडों का निर्धारण किया है जिसके अंतर्गत घरेलू निगमों के लिये विदेशों में निवेश करना आसान हो गया, जबिक ऋण न चुकाने एवं जाँच एजेंसियों का सामना करने वालों के लिये विदेशी संस्थाओं में निवेश करना कठिन हो गया।

## प्रमुख बिंदु

- RBI द्वारा प्रशासित:
  - ♦ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित विदेशी निवेश नियम और विनियम, भारतीय रिज्ञर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रशासित होंगे तथा विदेशी निवेश के साथ-साथ भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण एवं हस्तांतरण से संबंधित सभी मौजुदा मानदंडों को शामिल करेंगे।
- 🔾 नो गो सेक्टर:
  - िकसी भी व्यक्ति के लिये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)
     अनिवार्य होगा, जिसका बैंक खाता गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप

- में वर्गीकृत है या किसी बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है या वित्तीय सेवा नियामक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जाँच की जा रही है।
- इसके अलावा, िकसी भी भारतीय निवासी को उन विदेशी संस्थाओं में निवेश करने की अनुमित नहीं दी जाएगी जो केंद्रीय बैंक की विशिष्ट स्वीकृति के बिना अचल संपित्त व्यवसाय, किसी भी रूप में जुआ और भारतीय रुपए से जुड़े वित्तीय उत्पादों से संबंधित हैं।
- ⇒ 60 दिन की समय सीमा:
  - हालाँकि यदि ऋणदाता या संबंधित नियामक संस्था या जाँच एजेंसी आवेदन प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर NOC प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो यह माना जा सकता है कि उन्हें प्रस्तावित लेनदेन पर कोई आपत्ति नहीं है।

#### 🗅 महत्त्व:

- विदेशी निवेश के लिये संशोधित नियामक ढाँचा विदेशी निवेश हेतु मौजूदा ढाँचे के सरलीकरण का प्रावधान करता है और इसे वर्तमान व्यापार तथा आर्थिक गतिशीलता के साथ जोड़ा जोड़ता है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में स्पष्टता लाई गई है तथा "विभिन्न विदेशी निवेश संबंधी लेनदेन जो पहले अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत थे, अब स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होंगे, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।

# ऑनलाइन मार्केटप्लेस एक्वा बाज़ार

# चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की नौवीं आम सभा की बैठक के दौरान मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर, एक्वा बाजार लॉन्च किया।

# मतस्य सेतु ऐपः

- परिचय:
  - इस ऐप को 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय मीठाजल एक्वाकल्चर अनुसंधान संस्थान' (ICAR-CIFA) भुवनेश्वर द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के माध्यम से 'राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड' (NFDB) द्वारा विकसित किया गया है।
- 🕽 विशेषताएँ:
  - इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी पंजीकृत विक्रेता अपनी इनपुट सामग्री को सूचीबद्ध कर सकता है।

- सूचीबद्ध वस्तुओं को ऐप उपयोगकर्त्ता की भौगोलिक निकटता
   के आधार पर बाजार में प्रदर्शित किया जाएगा।
  - लिस्टिंग को अग्रलिखित प्रमुख श्रेणियों जैसे मछली के बीज, इनपुट सामग्री, सेवाएँ, रोजगार और टेबल फिश आदि में वर्गीकृत किया गया है; ।
  - प्रत्येक लिस्टिंग में विक्रेता के संपर्क विवरण के साथ उत्पाद, मूल्य, उपलब्ध मात्रा, आपूर्ति क्षेत्र आदि के बारे में विस्तृत जानकारी होगी।
- जरूरतमंद किसान/हितधारक विक्रेता से संपर्क कर अपनी खरीद को पुरा कर सकते हैं।
- ऐप उपयोगकर्ताओं के लिये सूचीबद्ध वस्तुओं का बाजार में प्रदर्शन उनकी भौगोलिक समीपता के आधार पर किया जाएगा। सूचीबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में किया गया है; मछली के बीज, इनपुट सामग्री, सेवाएँ, रोजगार और टेबल मछली।
- इच्छुक मछली खरीदार किसानों से संपर्क करेंगे और अपनी कीमतें बताएँगे।

#### 🗅 महत्त्व:

- ऑनलाइन मार्केटप्लेस मछली किसानों और हितधारकों को मछली के बीज, चारा, दवाएँ इत्यादि जैसी जरूरतें खरीदने में मदद करेगा और मछली पालन के लिये आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ किसान भी बिक्री के लिये टेबल-साइज मछली को सूचीबद्ध कर सकते हैं।
  - मार्केटप्लेस का उद्देश्य एक्वाकल्चर सेक्टर के सभी हितधारकों को जोडना है।
  - सही जगह और सही समय के अनुसार उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण जानकारी देश में एक्वाकल्चर की सफलता और विकास के लिये बेहद आवश्यक है।
- यह निश्चित रूप से किसानों को मछली की खरीद करने वाले खरीदारों या खरीदार एजेंटों से अधिक व्यावसायिक पूछताछ प्राप्त करने में मदद करेगा, बाजार की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और किसानों की उपज की बेहतर कीमत वसूली का मार्ग प्रशस्त करेगा।

# पहल को शुरू करने की आवश्यकताः

- कभी-कभी मछली पालकों को महत्त्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण इनपुट जैसे छोटी मछलियाँ, चारा, खाद्य सामग्री, उर्वरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एडिटिव्स, दवाएँ आदि प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - इन आदानों को प्राप्त करने में किसी भी तरह की देरी से उनके मत्स्य पालन संचालन की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।

- कभी-कभी किसान खेत निर्माण, किराये की सेवाएँ, कटाई के लिये जनशक्ति आदि जैसी सेवाओं की भी तलाश करते हैं।
  - इसी तरह निश्चित समय पर मछली पालकों को अपनी उपज को बाजार में बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या वे अपनी उत्पादित मछली की खरीद के लिये सीमित संख्या में खरीदारों/एजेंटों पर निर्भर होते हैं।

## राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

- यह वर्ष 2006 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासिनक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
  - अब यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत
     काम करता है।
- इसका उद्देश्य देश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना तथा एक एकीकृत एवं समग्र तरीके से मत्स्य विकास का समन्वय करना है।
- 🔾 मुख्यालयः तेलंगाना, हैदराबाद।

# तिलपिया जलीय कृषि परियोजनाः

#### मत्स्यपालन

## चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) से प्रेरित होकर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने इजरायली प्रौद्योगिकी के साथ तिलिपया जलीय कृषि परियोजना को समर्थन दिया है।

 प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।

## प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना की घोषणा सितंबर 2020 में तकनीकी रूप से उन्नत मछली पकड़ने के जहाजों, पारंपरिक मछुआरों हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों, नावों और जालों के अधिग्रहण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी।
- इसमें लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों की अवधि में निर्यात आय को दोगुना करके 1,00,000 करोड़ रुपए और मत्स्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 55 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।

कोविड-19 महामारी के दौरान इस क्षेत्र द्वारा सामना किये गए विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत ने अप्रैल से फरवरी 2021-22 तक 7,165 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समुद्री उत्पादों का सर्वकालिक उच्च निर्यात हासिल किया है।

## एक्वाकल्चर ( Aquaculture ):

- परिचय:
  - जलीय कृषि/एक्वाकल्चर शब्द प्रमुख तौर पर किसी भी वाणिज्यिक, मनोरंजक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिये नियंत्रित जलीय वातावरण में जलीय जीवों की खेती को संदर्भित करता है।
  - पौधों और जानवरों का प्रजनन, पालन और कटाई सभी प्रकार के जल वातावरण में होती है जिसमें तालाब, निदयाँ, झीलें, महासागर तथा भूमि पर मानव निर्मित "बंद" प्रणालियाँ शामिल हैं।
- 🗅 उद्देश्य:
  - मानव उपभोग हेतु खाद्य उत्पादन;
  - संकटग्रस्त और संकटापन्न प्रजातियों की आबादी का पुनर्स्थापना;
  - 💠 आवास बहाली;
  - मछिलयों की आबादी बहाल करना;
  - 💠 मछली का उत्पादन; तथा
  - चिडियाघरों और एक्वैरियम के लिये मछली पालन।

## तिलपिया



- तिलिपिया, जिसे जलीय चिकन भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारित मछली खाद्य पदार्थों में से एक बन गया है।
- तिलिपया का पालन दुनिया के कई हिस्सों में व्यावसायिक रूप से लोकप्रिय है और इसकी त्विरित वृद्धि एवं कम रखरखाव के कारण इसे जलीय चिकन घोषित किया गया था।

तिलिपिया विभिन्न प्रकार के जलीय कृषि वातावरणों के प्रति सिहष्णु है, इसकी खेती लवणीय जल में और तालाब या बंद की प्रणालियों में भी की जा सकती है।

#### भारत में मतस्य पालन की स्थिति:

- 🗅 परिचय:
  - मत्स्य पालन समुद्री, तटीय और अंतर्देशीय क्षेत्रों में जलीय जीवों विकास है।
  - समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन, जलीय कृषि के साथ, दुनिया भर में लाखों लोगों को फसल, प्रसंस्करण, विपणन तथा वितरण से भोजन, पोषण एवं आय का स्रोत प्रदान करते हैं।
  - कई लोगों के लिये यह उनकी पारंपिरक सांस्कृतिक पहचान का
     भी हिस्सा है।
  - वैश्विक मत्स्य संसाधनों की स्थिरता के लिये सबसे बड़े खतरों
     में से एक अवैध, असूचित और अनियमित रूप से मछली
     पकड़ना है।

#### महत्त्व:

- मत्स्य पालन प्राथिमक उत्पादक क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है।
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 7.56% हिस्सा है और देश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 1.24% और कृषि GVA में 7.28% से अधिक का योगदान देता है।
- भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है क्योंिक यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है।
- यह क्षेत्र देश के आर्थिक और समग्र विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे "सनराइज सेक्टर" भी कहा जाता है, यह समान और समावेशी विकास के माध्यम से अपार क्षमता वाला क्षेत्र है।
- इस क्षेत्र को 5 मिलियन लोगों को रोज्जगार प्रदान करने और देश के 28 मिलियन मछुआरा समुदाय के लिये आजीविका को बनाए रखने के लिये एक शक्तिशाली कारक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तीन बड़े परिवर्तन देखे
   गए हैं:
  - अंतर्देशीय जलीय कृषि का विकास, विशेष रूप से मीठे पानी की जलीय कृषि।
  - 🗷 मत्स्य पालन का मशीनीकरण।
  - 🗷 खारे पानी के झींगा के जलीय कृषि की सफल शुरुआत।

#### 🗅 चुनौतियाँ:

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, वैश्विक समुद्री मत्स्य उत्पादन के लगभग 90% क्षमता का या तो पूरी तरह या क्षमता से अधिक दोहन हो चुका है जिसकी पुन:प्राप्ति जैविक रूप से संभव नहीं है।
- जल निकायों में प्लास्टिक और अन्य अपिशष्ट जैसे हानिकारक पदार्थों का निर्वहन जो जलीय जीवन के लिये विनाशकारी परिणाम पैदा करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन।

## मत्स्य पालन के लिये सरकार की पहल:

- मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष
- 🗅 नीली क्रांति
- ⇒ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का विस्तार
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- समुद्री शैवाल पार्क।

# भारत में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म

### चर्चा में क्यों?

भारत ने डिजिटल समाज बनने के लिये कई प्रयास किये हैं जिसमें सरकार की मदद से एक बड़े पैमाने पर नागरिकों के लिये एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना शामिल है।

### सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचनाः

- परिचय:
  - यह डिजिटल समाधानों को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण, अर्थात सहयोगी, वाणिज्य और शासन के लिए आवश्यक बुनियादी कार्यों को सक्षम करता है।
- 🗅 भारतीय पहल:
  - भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) व्यक्तियों, बाजारों और सरकार के बीच बातचीत की गति को बढ़ाने के लिये सरलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे हैं।
    - वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत के साथ, भुगतान, भिवष्य निधि, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रॉसिंग टोल, और भूमि रिकॉर्ड की जाँच सभी को आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और इंडिया स्टैक पर निर्मित मॉड्यूलर अनुप्रयोगों के साथ बदल दिया गया है।
- परिसिमन:
  - आपस में जुड़ा नहीं:
    - मौजूदा विभिन्न डिजिटल अवसंरचनाएँ एक डिजाइन के रूप में परस्पर जुड़ी नहीं हैं।

- अंतर-संचालनीय नहीं:
  - तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता है ताकि उन्हें संवादी और अंतर-संचालनीय बनाया जा सके।
- 💠 अक्षम:
  - आज सूचना कई प्रणालियों में फैलती है और वे ज्यादातर सीमित निजी डेटाबेस पर भरोसा करती हैं जो इसे और अधिक जटिल बना देता है, जैसे-जैसे नेटवर्क बढ़ता है, यह लागत बढ़ाता है और अक्षमता पैदा करता है।

# अन्य कुशल डिजिटल प्रणालियाँ

#### वेब 3.0 :

- 그 परिचय:
  - वेब 3.0 एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जिसे ब्लॉकचेन तकनीक पर चलाया जाता है, जो उपयोग में आने वाले संस्करणों, वेब 1.0 और वेब 2.0 से भिन्न होगा।
    - चेब 1.0 में इंटरनेट पर ज्यादातर स्थिर वेब पेज थे जहाँ उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर जाते थे और फिर स्थैतिक सूचना को पढ़ते और इंटरैक्ट करते थे। वेब 0 में उपयोगकर्ता मुख्य रू प से एक सोशल मीडिया प्रकार की बातचीत सामग्री बना सकते हैं।
  - वेब 3 में उपयोगकर्त्ताओं के पास प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन में स्वामित्व हिस्सेदारी होगी जो तकनीकी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करते हैं।

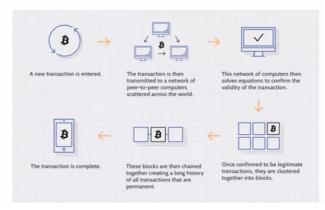
#### महत्त्व:

- वेब 3.0 समावेशी टोकन आधारित अर्थशास्त्र, पारदर्शिता और विकेंद्रीकरण को शामिल करते हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक नया संस्करण स्थापित करता है।
- यह न केवल क्रिप्टोकरेंसी बल्कि एनएफटी या फंजिबल टोकन भी है, जो भौतिक संपत्ति या डिजिटल ट्विन्स का प्रतिनिधित्त्व करता है।
  - एक उपयोगकर्त्ता वितिरत टोकन का उपयोग करके सभी पारिस्थितिक तंत्र लाभों तक पहुँच सकता है जहाँ वे स्वामित्व, टैक्स हिस्ट्री और भुगतान साधनों का प्रमाण दिखा सकते हैं।
  - ब्लॉकचेन रिकॉर्ड वास्तिवक समय में नियामकों द्वारा दृश्यमान, संकलित और ऑडिट किये जा सकते हैं.

#### ब्लॉकचेन:

- परिचय:
  - ब्लॉकचेन एक वितरित डेटाबेस या लेजर है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स के बीच साझा किया जाता है।

- एक डेटाबेस के रूप में एक ब्लॉकचेन डिजिटल प्रारूप में इलेक्टॉनिक रूप से जानकारी संग्रहीत करता है।
- ब्लॉकचेन को क्रिप्टोकुरेंसी सिस्टम में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये जाना जाता है जैसे कि बिटकॉइन लेनदेन का एक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिये।
- एक ब्लॉकचेन का नवाचार यह है कि यह डेटा के रिकॉर्ड की निष्ठा और सुरक्षा की गारंटी देता है और एक विश्वसनीय तृतीय पक्ष की आवश्यकता के बिना विश्वास उत्पन्न करता है।



### 🗅 वैश्विक स्वीकृति:

- एस्टोनिया दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी, आम जनता को दी जाने वाली सभी ई-गवर्नेंस सेवाओं को सत्यापित और संसाधित करने के लिये ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रही है।
- चीन ने क्लाउड में ब्लॉकचेन तकनीक को सुव्यवस्थित दर पर तैनात करने के लिये बीएसएन (ब्लॉकचेन -आधारित सर्विस नेटवर्क) लॉन्च किया।
- ब्रिटेन सेंटर फॉर डिजिटल बिल्ट ब्रिटेन द्वारा निर्मित वातावरण में डिजिटल ट्विन्स के मालिकों और डेवलपर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन प्रोग्राम (NDTp) चला रहा है।
- ब्राजील सरकार ने हाल ही में भाग लेने वाले संस्थानों को शासन और तकनीकी प्रणाली में लाने के लिए ब्राजीलियाई ब्लॉकचेन नेटवर्क लॉन्च किया है जो जनता के लिये समाधान में ब्लॉकचेन अपनाने की सुविधा प्रदान करता है।

#### 🗅 अनुप्रयोगः

- वं अच्छी तरह से स्थापित विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) प्लेटफॉर्म हैं जो ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्भर हैं।
- इन मंचो की बहु-देशीय उपस्थित और उपयोग है, साथ ही ये किसी विशेष नियामक दायरे में नहीं आते हैं।

- DeFi उपयोगकर्त्ताओं को एल्गोरिथम द्वारा निर्धारित दरों पर अल्पकालिक आधार पर क्रिप्टोकरेंसी उधार लेने और उधार देने की अनुमति देता है।
- DeFi उपयोगकर्त्ताओं को टोकन के साथ पुरस्कृत किया जाता है जो शासन के अधिकार प्रदान करते हैं, जो प्रोटोकॉल बोर्ड की सीटों के समान होते हैं।

#### ⊃ उदाहरण:

ब्लॉकचेन प्रदाता सोलाना ने हार्डवेयर और सुरक्षा के साथ प्रोटोटाइप स्मार्टफोन लॉन्च किया जो क्रिप्टो वॉलेट, वेब 3.0 और NFTs में रुचि रखने वाले लोगों के लिये विकेंद्रीकृत ऐप का समर्थन कर सकता है।

# विकसित देश का लक्ष्य

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पंच प्रण को वर्ष 2047 तक (जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे) पूरा करने का लक्ष्य रखा है,

- भारत को अगले 25 वर्षों में एक विकसित देश बनाने का पहला संकल्प है।
- वर्ष 2047 के लिये शेष प्रतिज्ञाएँ हैं दासता के निशान मिटाना, अपनी विरासत पर गर्व करना, विविधता में एकता सुनिश्चित करना और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना।

### विकसित देश:

- एक विकसित देश औद्योगीकृत होता है, जिसमें जीवन की उच्च गुणवत्ता, विकसित अर्थव्यवस्था और कम औद्योगिक राष्ट्रों के सापेक्ष उन्नत तकनीकी अवसंरचना होती है।
- जबिक विकासशील देश वे हैं जो औद्योगीकरण की प्रक्रिया में हैं या पूर्व-औद्योगिक और लगभग पूरी तरह से कृषि प्रधान हैं।
- आर्थिक विकास की मात्रा के मूल्यांकन के लिये सबसे आम मानदंड हैं:
  - ♦ सकल घरेलू उत्पाद (GDP):
    - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।
    - उच्च सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति अर्जित आय की राशि) वाले देशों को विकसित माना जाता है।
  - तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र का प्रभुत्त्व:
    - जिन देशों में तृतीयक (मनोरंजन, वित्तीय और खुदरा विक्रेताओं जैसी सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियाँ) और

उद्योग के चतुर्थ क्षेत्र (ज्ञान आधारित गतिविधियाँ जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, साथ ही परामर्श सेवाएँ और शिक्षा) का प्रभुत्त्व होता है उन्हें विकसित के रूप में वर्णित किया गया है।

- उत्तर-औद्योगिक अर्थव्यवस्था :
  - इसके अलावा, विकसित देशों में आम तौर पर अधिक उन्तत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, जिसका अर्थ है कि सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक धन प्रदान करता है।
- मानव विकास सूचकांक:
  - प्र अन्य मानदंड बुनियादी ढाँचे के मापन, जीवन स्तर के सामान्य मानक और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) हैं।
- चूँिक एचडीआई जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के सूचकांकों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा किसी देश में प्रति व्यक्ति शुद्ध संपत्ति या वस्तुओं की सापेक्ष गुणवत्ता जैसे कारकों को ध्यान में नहीं रखता है।
- यही कारण है कि कुछ सबसे उन्नत देश जिनमें जी7 सदस्य (कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपीय संघ) और अन्य शामिल हैं, एचडीआई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तथा स्विट्जरलैंड जैसे देश एचडीआई में उच्च रैंक पर हैं।

## विकसित देश की परिभाषा:

- 🗅 विकसित देश की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और विश्व आर्थिक मंच जैसी एजेंसियाँ विकसित और विकासशील देशों को वर्गीकृत करने के लिये अपने संकेतकों का उपयोग करती हैं।
- उदाहरण के लिये, संयुक्त राष्ट्र देशों को निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है।
  - यह वर्गीकरण किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) पर आधारित है।

    - 🗷 निम्न मध्य-आय: \$ 4,255 तक प्रति व्यक्ति GNI
    - प्र ऊपरी-मध्य-आय: \$ 13.205 प्रति व्यक्ति GNI
    - उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था: \$ 13,205 से ऊपर प्रति
       व्यक्ति GNI

# संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण का विरोध:

 संयुक्त राष्ट्र का वर्गीकरण बहुत सटीक नहीं है क्योंिक यह सीिमत विश्लेषणात्मक मूल्य पर केंद्रित है। जिसके कारण केवल शीर्ष तीन

- देशों अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे को विकसित देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- जबिक, लगभग 31 विकसित देश हैं, और शेष 17 (संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं) को छोड़कर विकासशील देशों के रूप में नामित हैं।
- चीन के मामले में, देश की प्रति व्यक्ति आय सोमालिया की तुलना में नॉर्वे के करीब है।
  - चीन की प्रति व्यक्ति आय सोमालिया की तुलना में 26 गुना है जबिक नॉर्वे की चीन की तुलना में लगभग सात गुना है, लेकिन फिर भी, इसे एक विकासशील देश का टैग मिला है।
- दूसरी ओर, यूक्रेन जैसा देश, जिसकी प्रति व्यक्ति जीएनआई \$4,120 (चीन का एक तिहाई) है, एक विकसित राष्ट्र के बजाय (संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नामित है।

# आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने आतिथ्य/हॉस्पिटैलिटी और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमों के लिये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) में वृद्धि को मंज़ूरी दी क्योंकि महामारी ने इन क्षेत्रों को बाधित कर दिया था।

सरकार ने इन क्षेत्रों के लिये 50,000 करोड़ रुपए की राशि में 4.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है जो 31 मार्च, 2023 तक वैध रहेगा।

## आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

- 🗅 परिचय:
  - ECLGS को वर्ष 2020 में कोविड-19 संकट के दौरान केंद्र के आत्मिनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
  - इसका उद्देश्य देशव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों का समर्थन करना था।
  - नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLI) - बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को 100% गारंटी प्रदान की जाती है।
  - क्रेडिट उत्पाद जिसके लिये योजना के तहत गारंटी प्रदान की जाएगी, उसका नाम 'गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (GECL)' रखा जाएगा।

#### ECLGS 1.0:

- MSME, व्यावसायिक उद्यमों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये व्यक्तिगत ऋणों को 29 फरवरी, 2020 तक उनके बकाया ऋण के 20% की सीमा तक पूरी तरह से गारंटीकृत और संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना।
- 25 करोड़ रुपए तक के बकाया और 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले MSME इसके पात्र थे।
  - □ हालाँकि नवंबर 2020 में ECLGS 2.0 में संशोधन के
    बाद टर्नओवर सीमा को हटा दिया गया था।

#### ECLGS 2.0:

- संशोधित संस्करण कामथ सिमित द्वारा पहचाने गए 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों में संस्थाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है, जिन पर 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक का ऋण बकाया है।
- योजना में उधारकर्त्ता खातों को 29 फरवरी, 2020 तक देय 30 दिनों से कम या उसके बराबर होना अनिवार्य है अर्थात, उन्हें 29 फरवरी, 2020 तक किसी भी उधारदाता द्वारा SMA-1, SMA-2 या NPA के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिये था।
  - SMA विशेष उल्लेख खाते होते हैं, जो उन शुरुआती दबाव का संकेत देते हैं, जिसमें कर्जदार ऋण चुकाने में डिफ़ॉल्ट करता है।
- SMA-0 खातों में 1-30 दिनों के लिये आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान अतिदेय हैं, जबिक SMA-1 और SMA-2 खातों में क्रमश: 31-60 दिनों और 61-90 दिनों के लिये भुगतान अतिदेय हैं।
- संशोधित योजना में ECLGS 1.0 में चार साल से पाँच वर्ष के रीपेमेंट विंडो का भी प्रावधान किया गया था।

#### ECLGS 3.0:

- इसमें 29 फरवरी, 2020 तक सभी ऋणदाता संस्थानों में कुल बकाया ऋण का 40% तक का विस्तार शामिल है।
- ECLGS 3.0 के तहत दिये गए ऋणों की अवधि 6 वर्ष होगी, जिसमें 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।
- यह आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश एवं खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को शामिल करता है, जिसकी अवधि 29 फरवरी, 2020 तक थी।
  - इसमें कुल बकाया 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं और अतिदेय, यदि कोई हो तो 60 दिनों या उससे कम की अविध के लिये था।

- ⇒ ECLGS 4.0:
  - अस्पतालों, निर्संग होम, क्लीनिकों, मेडिकल कॉलेजों को ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिये 5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 2 करोड़ रुपए तक के ऋण को कवर करने की 100 प्रतिशत गारंटी।

### नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड:

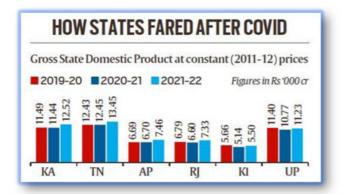
- NCGTC एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसे वर्ष 2014 में वित्तीय सेवा मंत्रालय के वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया था, जो भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में कई क्रेडिट गारंटी फंड के लिये एक आम ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करती है।
  - क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम उधारदाताओं के उधार जोखिम को साझा करने हेतु डिजाइन किये गए हैं और बदले में संभावित उधारकर्ताओं के लिये वित्त तक पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं।

# सकल राज्य घरेलू उत्पाद

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े जारी किये हैं।

- 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अर्थव्यवस्थाओं ने अपने पूर्व-कोविड स्तरों को पार कर लिया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सात रिकॉर्ड दोहरे अंकों की विकास दर दर्ज की गई है।
- इसमें गुजरात और महाराष्ट्र सिहत 11 राज्यों की विकास दर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये उपलब्ध नहीं थी।



### प्रमुख निष्कर्षः

 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के आकार में वर्ष 2020-21 के दौरान नगण्य वृद्धि दर्ज की गई थी, जब सरकार ने कोविड -19 के प्रकोप को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था।

- ये 19 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड, तिमलनाडु, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और पुदुचेरी हैं।
- इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं (GSDP) ने वर्ष 2021-22 में पुन:प्राप्ति की और अपने पूर्व-कोविड (2019-20) स्तरों को पार कर लिया।
  - वर्ष 2021-22 में केरल और उत्तर प्रदेश एकमात्र अपवाद हैं,
     जिनके GSDP पूर्व-कोविड स्तरों से नीचे दर्ज किये गए हैं।
  - आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 11.43 प्रतिशत जबिक पुदुचेरी में सबसे कम 3.31% की वृद्धि दर्ज की गई।
  - आंध्र प्रदेश के अलावा पाँच अन्य राज्यों और एक केंद्रशासित
     प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की:

¤ राजस्थान:11.04%

बिहार: 10.98%

д तेलंगानाः 10.88%

ओडिशा: 10.19%

मध्य प्रदेश: 10.12%

दिल्ली: 10.23%

- कुछ राज्यों के GSDP में तेज उछाल आधार प्रभाव के कारण है;
   जो महामारी के बाद की आर्थिक सुधार को दर्शांती है।
  - वर्ष 2021-22 में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21
     में 6.6% संकुचन के मुकाबले 8.7% पर विस्तारित हुआ।

## सकल राज्य घरेलू उत्पाद

- ⊃ परिचय:
  - सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) एक निश्चित अविध (आमतौर पर एक वर्ष और बिना दोहराव के) के दौरान राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का मौद्रिक उपाय है।
- महत्त्व:
  - राज्य के आर्थिक विकास को मापने के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) या राज्य की आय सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक है।
    - समय के साथ अर्थव्यवस्था के ये अनुमान आर्थिक विकास के स्तरों में परिवर्तन की सीमा और दिशा को प्रकट करते हैं।

- राज्य घरेलू उत्पाद को प्राथिमक क्षेत्र, माध्यिमक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जैसे तीन व्यापक क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत किया गया है और इसे राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धित के अनुसार आर्थिक गतिविधिवार संकलित किया जाता है।
- वर्ष 2015 में NSO ने आधार वर्ष 2011-12 (पूर्व आधार वर्ष 2004-05 था) के साथ राष्ट्रीय खातों के आँकड़ों की नई शृंखला की शुरुआत की।

# यूरिया में आत्मनिर्भरता

#### चर्चा में क्यों ?

भारत अगले चार वर्षों के भीतर अर्थात् वर्ष 2025 तक लिक्विड नैनो यूरिया के रूप में ज्ञात स्थानीय रूप से विकसित संस्करण के उत्पादन का विस्तार करके आयातित यूरिया पर अपनी निर्भरता समाप्त करने की उम्मीद कर रहा है।

## लिक्विड नैनो यूरिया:

- यह एक नैनोकण के रूप में यूरिया है। यह पारंपिरक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्त्व (लिक्विड) है।
  - यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है जो पौधों के लिये एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्त्व है।
- नैनो यूरिया को पारंपिरक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपिरक यूरिया की न्यूनतम खपत को 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
  - इसकी 500 मिली.की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम/लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्त्व प्रदान करेगा।
- यह स्वदेशी यूरिया है, जिसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिये पेश किया गया था।
- प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया
   (LNU) संयंत्र का उद्घाटन किया है।

## यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकताः

आपूर्ति शृंखला में कमी को पूरा करने के लिये भारत दशकों से यूरिया का आयात कर रहा है। भारत, यूरिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक होने के कारण, इसकी मांग यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमत को प्रभावित करती है।

- भारत यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) का दिनया का सबसे बडा खरीदार है।
- DAP, यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है।
- किसान आमतौर पर इस उर्वरक को बुवाई से ठीक पहले या शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस (P) की मात्रा अधिक होती है जो जड़ के विकास को प्रेरित करता है।
- आपूर्ति बाधित होने के कारण इस वर्ष 2022 में वैश्विक उर्वरक कीमतों में तेज वृद्धि से यूरिया और DAP प्रभावित हुए हैं।
- कृषि हमारी लगभग 70% आबादी का मुख्य आधार है, आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी या उर्वरकों जैसे महत्त्वपूर्ण इनपुट की कीमत में वृद्धि का हमारे ग्रामीण क्षेत्र के समग्र आर्थिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।
- यह संभावना है कि निकट भविष्य में यूरिया की मांग में कमी नहीं आने वाली है, इसलिये यूरिया के आयात पर हमेशा निर्भर उचित निर्णय साबित नहीं होगा।
- इस संबंध में वर्ष 2016 में सार्वजिनक क्षेत्र में कई ब्राउनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय एक सार्थक कदम था।
- यूरिया में आत्मिनर्भरता से सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

## संबंधित सरकारी पहल:

- नैनो यूरिया उत्पादन:
  - आठ नए नैनो यूरिया संयंत्र, जिनकी केंद्र द्वारा निगरानी की जा रही है, नवंबर 2025 तक उत्पादन शुरू कर देंगे।
  - ये कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम सिहत कई राज्यों में स्थित हैं।
- 🗅 नीम कोटेड यूरिया (Neem Coated Urea- NCU)
  - उर्वरक विभाग (DoF) ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिये शत-प्रतिशत यूरिया का उत्पादन 'नीम कोटेड यूरिया' (NCU) के रूप में करना अनिवार्य कर दिया है। ताकि मिट्टी की सेहत में सुधार हो, पौधों की सुरक्षा करने वाले रसायनों का उपयोग कम हो।
- 🗅 नई यूरिया नीति 2015:
  - नीति के उद्देश्य हैं-
    - स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना।
    - 🗷 यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
    - 🗷 भारत सरकार पर सब्सिडी के भार को युक्तिसंगत बनाना।

- नई निवेश नीति, 2012:
  - ♦ सरकार ने जनवरी 2013 में नई निवेश नीति (New Investment Policy- NIP), 2012 की घोषणा की जिसे वर्ष 2014 में यूरिया क्षेत्र में नए निवेश की सुविधा तथा भारत को यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये संशोधित किया गया।
- सिटी कम्पोस्ट के संवर्द्धन पर नीतिः
  - भारत सरकार ने सिटी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढाने के लिये 1500 रुपए की बाज़ार विकास सहायता (Market Development Assistance) प्रदान करने हेत् वर्ष 2016 में उर्वरक विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी कम्पोस्ट को बढावा देने की नीति को मंज़री दी।
- उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष पौद्योगिकी का उपयोगः
  - ♦ उर्वरक विभाग ने भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और परमाणु खनिज निदेशालय (AMD) के सहयोग से इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा "रॉक फॉस्फेट का रिफ्लेक्सेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करके संसाधन मानचित्रण" पर तीन साल का पायलट अध्ययन शुरू किया।

- पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना:
  - इसे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से लागु किया गया है।
  - ♦ NBS के तहत, वार्षिक आधार पर तय की गई सिब्सिडी की एक निश्चित राशि सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर इसकी पोषक सामग्री के आधार पर प्रदान की जाती है।

## प्रधानमंत्री जन धन योजना के आठ वर्ष

### चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जो कि वित्तीय समावेशन के लिये एक राष्ट्रीय मिशन है, ने अपने कार्यान्वयन के आठ वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं।

PMIDY के तहत 46.25 करोड से अधिक लाभार्थियों ने PMJDY की शुरुआत से 1,73,954 करोड़ रुपए की राशि जमा की है।



#### प्रधानमंत्री जन धन योजना ( PMJDY ):

- परिचय:
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिये राष्ट्रीय मिशन है।
  - यह वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन की सुलभ तरीके से पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - PMJDY जन-केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारिशला रही है। चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), कोविड-19 वित्तीय सहायता, PM-KISAN, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बढ़ी हुई मजदूरी जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर हो, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है जिसे PMJDY ने लगभग पूरा कर लिया है।
- ⊃ उद्देश्य:
  - एक किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - 💠 कम लागत और व्यापक पहुँच के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- 🗅 योजना के मूल सिद्धांत:
  - बेंक रहित वयस्कों तक बेंक सुविधाओं की पहुँच: न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ मूल बचत बेंक जमा (BSBD) खाता खोलना, केवाईसी में छूट, ई-केवाईसी, कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और शुन्य शुल्क।
  - असुरक्षित को सुरक्षित करना: 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ, व्यापारिक स्थानों पर नकद निकासी और भगतान के लिये स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
  - गैर-वित्त पोषित को वित्त पोषण: अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे सूक्ष्म बीमा, खपत के लिये ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण।

### वित्तीय समावेशनः

- वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने का प्रयास है। इसे 'समावेशी वित्तपोषण' भी कहा जाता है
- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में वित्तीय समावेशन विकास प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। आजादी के बाद से सरकारों, नियामक संस्थानों और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों ने देश में वित्तीय समावेशन तंत्र को मजबूत करने में मदद की है।
- बैंक खाते तक पहुँच प्राप्त करना व्यापक वित्तीय समावेशन की दिशा में पहला कदम है क्योंकि एक लेनदेन खाता लोगों को पैसे जमा करने, भुगतान करने और धन प्राप्त करने की अनुमित देता है। एक लेनदेन खाता अन्य वित्तीय सेवाओं के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

#### भारत में वित्तीय समावेशन बढावा देने वाली पहलें:

- 🗅 प्रधानमंत्री जन धन योजना
- डिजिटल पहचान (आधार)
- ⊃ वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCFE)
- ⊃ वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना
- 😊 ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार
- 🗅 डिजिटल भुगतान का प्रचार

## योजना के प्रमुख छह स्तंभ:

- बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच: शाखा और बैंकिंग काॅरेस्पोंडेंट्स।
- ओवरड्राफ्ट सुविधा: रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाते। प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000/- रुपए।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम: बचत को बढ़ावा देना, ATM का उपयोग, ऋण के लिये तैयार करना, बीमा और पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग हेतु बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग करना।
- क्रेडिट गारंटी फण्ड का निर्माण: बैंकों को चूक के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करना।
- बीमा: 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते पर 1,00,000 रुपए तक का दुर्घटना कवर और 30,000 रुपए का जीवन कवर।
- असंगठित क्षेत्र के लिये पेंशन योजना।

# क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में विभिन्न सुधारों पर चर्चा के लिये वित्त मंत्री और बैंक प्रमुखों के बीच बैठक हुई है।।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( RRBs ):

- 그 परिचय:
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।
  - RRB वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
  - RRB ग्रामीण समस्याओं से पिरिचित होने के साथ सहकारी विशेषताओं और वाणिज्यिक बैंक की व्यावसायिक एवं वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता का विस्तार करतें हैं।
  - वर्ष 1990 के दशक में सुधारों के बाद सरकार ने वर्ष 2005-06
     में समेकन कार्यक्रम शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप RRB

की संख्या वर्ष 2005 में 196 से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 43 हो गई और इन 43 RRBs में से 30 ने शुद्ध लाभ प्रदान किये।

- 🗅 कार्य:
  - बैंक के बुनियादी कार्यों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:
    - प्राहकों की बचत को सुरक्षा प्रदान करने के लिये,
    - ऋण और पैसे की आपूर्ति बढ़ाने के लिये,
    - वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिये,
    - 🗷 जनता की बचत जुटाने के लिये,
    - अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिये तािक समाज के हर वर्ग तक पहुँच सके,
    - सभी ग्राहकों को उनकी आय के स्तर की परवाह किये बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिये,
    - समाज के हर तबके को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके सामाजिक समानता लाना।

## RRBs से संबंधित चुनौतियाँ:

- बढ़ती लागत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के संचालन की बढ़ती लागत।
  - सरकार चाहती है कि वे अपनी कमाई बढ़ाने की दिशा में काम करें।
- सीमित गितविधियाँ: कई शाखाओं के पास पर्याप्त व्यवसाय नहीं है,
   जिसके कारण उन्हें घाटा हो रहा है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में वे मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी सरकारी योजनाओं की पेशकश करते हैं।
- सीमित इंटरनेट बैंकिंग: वर्तमान में केवल 19 RRBs के पास इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएँ हैं और 37 के पास मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस हैं।
  - मौजूदा नियम केवल उन्हीं RRBs को इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश करने की अनुमित देते हैं जो न्यूनतम वैधानिक पूंजी जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) 10% से अधिक बनाए रखते हैं।

## सरकार के सुझाव:

सरकार ने RRBs को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को ऋण देने के माध्यम से अपने साख आधार का विस्तार करने सिहत डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने के लिये कहा है तािक वे अधिंक रूप से सशक्त हो सकें।

- सरकार ने प्रायोजक बैंकों से RRBs को और मज़बूत करने, महामारी के बाद आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिये समयबद्ध तरीके से एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया।
  - साथ ही RRB पर एक कार्यशाला आयोजित करने और परस्पर सर्वोत्तम उपायों को साझा करने का सुझाव दिया।

# वित्तीय समावेशन सूचकांकः आरबीआई

#### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक) जारी किया है।

## प्रमुख बिंदु

- भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक का स्कोर पिछले वर्ष 2021
   में9 से बढ़कर 56.4 हो गया है।
- इसके सभी उप-सूचकांकों (वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता ) में सुधार देखा गया है।

### वित्तीय समावेशन सूचकांक

- 그 परिचय:
  - ♦ वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है।
  - इसे RBI द्वारा वर्ष 2021 में बिना किसी 'आधार वर्ष' के विकसित किया गया था और प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है।
- ⊃ लक्ष्य:
  - देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिये एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण करना।
  - यह सूचकांक सेवाओं की पहुँच, उपलब्धता एवं उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता मापने में आसानी के लिये अनुक्रियाशील है, जिसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं।
- ⊃ मापदंड:
  - यह सूचकांक 0 और 100 के बीच की एकल संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है, जहाँ 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
  - इसमें तीन व्यापक पैरामीटर (भार कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)
     अर्थात् एक्सेस (35%), उपयोग (45%) और गुणवत्ता

(20%) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनकी गणना कुछ संकेतकों के आधार पर की जाती है।

## वित्तीय समावेशन सूचकांक का महत्त्वः

- समावेशन का आकलन:
  - यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है और आंतरिक नीति निर्माण में उपयोग के लिये वित्तीय सेवाओं का आकलन प्रस्तुत करता है।
- विकास संकेतक:
  - इसका उपयोग प्रत्यक्ष विकास संकेतकों में एक समग्र उपाय के रूप में किया जा सकता है।
- G20 संकेतकों को पूरा करता है:
  - यह G20 वित्तीय समावेशन संकेतक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
  - G20 संकेतक राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं की स्थिति का आकलन करते हैं।
- शोधकर्त्ताओं के लिये महत्त्वपूर्णः
  - यह शोधकर्त्ताओं को वित्तीय समावेशन और अन्य व्यापक आर्थिक चरों के प्रभाव का अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करता है।

#### वित्तीय समावेशनः

- वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने का प्रयास है। इसे 'समावेशी वित्तपोषण' भी कहा जाता है
- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में वित्तीय समावेशन विकास प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। आजादी के बाद से सरकारों, नियामक संस्थानों और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों ने देश में वित्तीय समावेशन तंत्र को मजबूत करने में मदद की है।
- बैंक खाते तक पहुँच प्राप्त करना व्यापक वित्तीय समावेशन की दिशा में पहला कदम है क्योंकि एक लेनदेन खाता लोगों को पैसे जमा करने, भुगतान करने और धन प्राप्त करने की अनुमित देता है। एक लेनदेन खाता अन्य वित्तीय सेवाओं के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

### भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ावा देने वाली पहलें:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- 🕽 डिजिटल पहचान (आधार)
- वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय केंद्र (NCFE)
- ⇒ वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFL) परियोजना

- ⊃ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार
- डिजिटल भुगतान का प्रचार

## उद्यम पोर्टल

#### चर्चा में क्यों?

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के अनुसार, लगभग एक करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) ने 25 महीनों के भीतर उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

#### उद्यम पोर्टल:

- 🗅 परिचय:
  - 💠 इसे 1 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया गया था।
  - यह MSMEs के पंजीकरण के लिये स्थापित एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
  - इसके अलावा, यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।
    - GSTN एक अनूठा और जिटल IT उद्यम है जो करदाताओं, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के मध्य संचार और वार्ता के लिये एक नेटवर्क स्थापित करता है।
  - यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिये किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और यह MSME के लिये व्यवसाय को सुगम बनाने की दिशा में एक कदम है।
- 🗅 महत्त्व:
  - MSMEs के लिये MSME मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने और बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से ऋण के लिये उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक हैं।
    - साथ ही एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार मुजन में योगदान करते हैं।
- 그 नई पहल:
  - उद्यम डेटा साझा करने के लिये MSME मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - इसके अलावा उद्यम पंजीकरण के लिये डिजी लॉकर सुविधा को भी जोड़ा जाएगा।

#### **MSME**

- 그 परिचय:
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

- भारत में इस क्षेत्र ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और इसके निर्यात में योगदान के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।
- इस क्षेत्र ने विशेष रूप से भारत के अर्द्ध -शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के संबंध में भी बहुत योगदान दिया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम।
  - उपकरणों में निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर उद्यमों को वर्गीकृत किया गया है।
- संबंधित पहल:
  - पारंपिक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI)
  - नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE):
  - एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम

# भारत में गन्ना और चीनी उद्योग हेतु एफआरपी

### चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मौसम 2022-23 (अक्तूबर-सितंबर) के लिये गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।

- चीनी की 10.25 प्रतिशत रिकवरी के लिय प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये 3.05 रुपये/ क्विंटल का प्रीमियम मिलेगा और रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिये 3.05 रुपये प्रति/ क्विंटल की दर से उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में कमी होगी।
- ⊃ रिकवरी दर गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा है और गन्ने से प्राप्त चीनी की मात्रा जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक कीमत बाजार में मिलती है।

#### गन्ने की खेती:

- तापमान : उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच।
- ⊃ वर्षाः लगभग ७५-१०० सेमी.।
- मिट्टी का प्रकार: गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी।

- 🗅 शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र>उत्तर प्रदेश> कर्नाटक
- इसे बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिये अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है।
- इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और राब का मुख्य स्रोत है।
- चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहलें हैं- चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना (SEFASU) और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन योजना।

### गन्ने का मूल्य निर्धारणः

- गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार (संघीय सरकार) और राज्य सरकारों
   द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- 🗅 केंद्र सरकार : उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)
  - केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्यों की घोषणा करती है जो कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा घोषित किये जाते हैं।
  - FRP, गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर बनी रंगराजन सिमित की रिपोर्ट पर आधारित है।
- राज्य सरकार: राज्य परामर्श मृल्य (SAP)
  - प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा SAP की घोषणा की जाती है।
  - ♦ SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।

## भारत में गन्ना क्षेत्र की स्थिति:

- 🗅 🛮 सबसे बड़ा उत्पादक:
  - 💠 भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है।
    - भारत ने चालू चीनी सीजन 2021-22 में चीनी उत्पादन के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है।
  - न्यूनतम मूल्य, गन्ने की गारंटीकृत बिक्री और चीनी के सार्वजनिक वितरण सिंहत उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों ने भारत को सबसे बड़ा उत्पादक बनने में सहायता की है
  - हालाँकि वर्षा की कमी, भूजल स्तर में गिरावट, गन्ना किसानों को भुगतान में देरी, अन्य फसलों की तुलना में कम शुद्ध आय (किसान के लिये), श्रम की कमी और श्रम की बढ़ती लागत, इसके बाद कोविड -19 महामारी जैसे कारक समग्र रूप से चीनी क्षेत्र के लिये चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं।

- 🗅 दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक:
  - 💠 ब्राज़ील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
  - भारत ने घरेलू खपत के लिये अपनी आवश्यकता को पूरा करने के अलावा चीनी का निर्यात भी किया है जिससे राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायता मिली है।
  - चालू चीनी सीजन 2021-22 में अगस्त 2022 तक लगभग 100 LMT चीनी का निर्यात किया गया है, जिसके 112 LMT तक पहुँचने की संभावना है।
- आत्मिनिर्भर बननाः
  - इससे पहले चीनी मिलें राजस्व उत्पन्न करने के लिये मुख्य रूप से चीनी के विक्रय पर निर्भर थीं। किसी भी मौसम में अधिशेष उत्पादन उनकी तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे किसानों का गन्ना मुल्य बकाया हो जाता है।
  - हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग ने आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली है।
    - वर्ष 2013-14 में तेल विपणन कंपिनयों (OMCs) को इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों को लगभग 49,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
    - प्र चालू चीनी सीजन 2021-22 में चीनी मिलों द्वारा OMCs को इथेनॉल की बिक्री से अब तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है;
  - केंद्र सरकार द्वारा किये गए उपायों और FRP में वृद्धि ने किसानों को गन्ने की खेती के लिये प्रोत्साहित किया है और चीनी के घरेलू निर्माण के लिये चीनी कारखानों के निरंतर संचालन की सुविधा प्रदान की है।

## इथेनॉल संयंत्र

### चर्चा में क्यों ?

विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 पर, भारत सरकार ने हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी में दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की।

यह इथेनॉल संयंत्र अतिरिक्त आय और हिरत ईंधन पैदा करने के साथ-साथ दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

## विश्व जैव ईंधन दिवस

- 🗅 परिचय:
  - यह प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है।
  - यह पारंपिरक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर-जीवाश्म ईंधन के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।

#### 🔾 पृष्ठिभृमि:

- 💠 यहदिवस सर रुडोल्फ डीज़ल के सम्मान में मनाया जाता है।
  - वह डीजल इंजन के आविष्कारक थे और उन्होंने सबसे पहले जीवाश्म ईंधन की जगह वनस्पित तेल की संभावना की भविष्यवाणी की थी।

#### इथेनॉल संयंत्र के बारे में जानकारी:

- यह 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करने के लिये लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे (पराली) का उपयोग करके भारत के वेस्ट टू वेल्थ के प्रयासों को बढ़ावा देगा।
  - यह संयंत्र धान के भूसे के अलावा मक्का और गन्ने के कचरे का
     भी उपयोग एथनॉल के उत्पादन के लिये करेगा।
- यह पिरयोजना संयंत्र संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और चावल के भूसे की कटाई, हैंडलिंग, भंडारण आदि के लिए आपूर्ति शृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा।
- 🔾 इस परियोजना में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा।
  - चावल की भूसी को जलाने में कमी के माध्यम से परियोजना प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में योगदान देगी जो देश की सड़कों पर सालाना लगभग 63,000 कारों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के बराबर है।

#### डथेनॉल:

- परिचय:
  - यह प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है, जो प्रकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है।
  - यह घरेलू रूप से उत्पादित वैकल्पिक ईंधन है जो आमतौर पर मकई से बनाया जाता है। यह सेल्यूलोसिक फीडस्टॉक्स जैसे कि फसल अवशेष और लकड़ी से भी बनाया जाता है।
- ईंधन के रूप में इथेनॉल:
  - आंतरिक दहन इंजनों के लिये ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग या तो अकेले या अन्य ईंधन के साथ मिश्रित रूप में किया जाता है, जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा इसके संभावित पर्यावरणीय और दीर्घकालिक आर्थिक लाभों के कारण इस पर अधिक ध्यान दिया गया है।
  - इथेनॉल को शुद्ध इथेनॉल (E100) तक किसी भी सांद्रता में पेट्रोल के साथ जोड़ा जा सकता है
    - प्रेट्रोलियम ईंधन की खपत को कम करने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को कम करने के लिये निर्जल इथेनॉल (जल के बिना इथेनॉल) को अलग-अलग मात्रा में पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

#### जैव ईंधन के संबंध में भारत की अन्य पहलें:

- इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP):
  - इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और किसानों की आय को बढाना है।
  - सम्मिश्रण लक्ष्य: भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (जिसे E20 भी कहा जाता है) के लक्ष्य को वर्ष 2030 से परिवर्तित कर वर्ष 2025 तक कर दिया है।
  - भारत ने पहले ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे देश का इथेनॉल उत्पादन बढकर 400 करोड लीटर हो गया है।
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018:
  - यह वर्ष 2030 तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करता है।
- ई-100 पायलट प्रोजेक्ट:
  - ♦ टीवीएस अपाचे जैसे दोपहिया वाहनों को E80 या शुद्ध इथेनॉल (E100) पर चलने के लिये डिजाइन किया गया है।
- प्रधानमंत्री जी-वन योजना. 2019:
  - 💠 इस योजना का उद्देश्य 2जी इथेनॉल क्षेत्र में वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- प्रयुक्त खाद्य तेल (RUCO) का पुन: उपयोग:
  - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने यह पहल शुरू की है जो इस्तेमाल किये खाद्य तेल को बायोडीजल के रूप में संगृहीत और रूपांतरित करने में भी सक्षम बनाएगा।

## जाली नोटों में गिरावट

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि बैंकिंग प्रणाली में जाली मुद्रा का मूल्य वर्ष 2016-17 के 43.47 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2021-22 में लगभग 8.26 करोड़ रुपए हो गया।

## जाली मुद्राः

- जालसाज द्वारा अपने लाभ के लिये अवैध रूप से जाली मुद्रा का निर्माण करना एक प्रकार की जालसाज़ी है, जालसाज़ी के तहत किसी वस्तु की प्रतिकृति तैयार की जाती है ताकि जालसाज़ी की घटना को अंजाम दिया जा सके।
- मुद्रा की नकल करने के लिये आवश्यक उच्च स्तर के तकनीकी कौशल के कारण, जालसाज़ी को अन्य कृत्यों से अलग किया जाता

- है और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ए के तहत अलग अपराध के रूप में माना जाता है।
- जालसाजी सबसे पुराने तरीकों में से एक है जिसका उपयोग जालसाज़ों द्वारा लंबे समय से लोंगों को धोखा देने के लिये किया जाता रहा हैं।

#### जालसाजी से खतराः

- आर्थिक आतंकवाद:
  - ♦ FICN (नकली भारतीय करेंसी नोट) भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने के लिये बाहरी स्रोतों द्वारा प्रचालित "आर्थिक आतंकवाद" के रूप में देखा जा सकता है।
  - आर्थिक आतंकवाद राज्य या गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था में पर्दे के पीछे होने वाले हेरफेर को संदर्भित करता है।
  - FICN का प्रचलन भारत की अर्थव्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न करता है, जबिक इससे होने वाले लाभ का उपयोग भारत को लक्षित गुप्त आपराधिक गतिविधियों को निधि देने के लिये किया जाता है।
- मुद्रास्फीति:
  - 💠 बडी मात्रा में जाली मुद्रा के प्रचलन से बाज़ार में मुद्रा की मात्रा बढ जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढती
  - मांग में वृद्धि होने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी हो जाती है, फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ जाती है।
  - ♦ इससे मुद्रा का अवमृल्यन/मृल्यहास होता है।
- क्षति की गैर-प्रतिपूर्ति:
  - ♦ बैंकों की गैर-प्रतिपूर्ति नीति समस्या तब उत्पन्न करती है, जब बैंक जाली नोटों को अस्वीकार कर देते हैं और नुकसान की प्रतिपूर्ति नहीं करते हैं।
  - दैनिक नकद लेन-देन में शामिल फर्मों को अर्थव्यवस्था में FICN की घुसपैठ के कारण लंबे समय में भारी नुकसान का सामना करना पडता है।
- जन विश्वास में कमी: 0
  - ♦ जाली मुद्रा के अन्य प्रभावों में जनता के विश्वास में कमी, उत्पादों की कालाबाजारी, उत्पादों का अवैध स्टॉकिंग आदि शामिल हैं।

## जाली मुद्रा को नियंत्रित करने के उपाय:

- विमुद्रीकरण:
  - 8 नवंबर, 2016 को अवैध लेन-देन के लिये उच्च मूल्य के नोटों के उपयोग को हतोत्साहित करने और जालसाजी पर अंकुश

- लगाने हेतु मुद्रा प्रणाली से 500 एवं 1,000 रुपए के नोट परिचालन से वापस ले लिये गए थे।
- विमुद्रीकरण से तात्पर्य लीगल टेंडर के रूप में जारी मुद्रा इकाई
   को वापस लेने की प्रक्रिया है।
- द्वि-लुमिनसेंट सुरक्षा स्याही:
  - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक द्वि-लुमिनसेंट सुरक्षा स्याही विकसित की है जो नोटों में दो अलग-अलग स्रोतों द्वारा प्रकाशित होने पर लाल एवं हरे रंगों को प्रदर्शित करती है।
- э टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (TFFC) सेल:
  - आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा के मामलों की जाँच के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के तहत एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (TFFC) सेल का गठन किया गया है।
- ⇒ FICN समन्वय समूह:
  - जाली नोटों के प्रचलन की समस्या का मुकाबला करने के लिये केंद्र /राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया/सूचना साझा करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा FICN समन्वय समूह (FCORD) का गठन किया गया है।
- जाली नोटों की समस्या से निपटने को भारत-बांग्लादेश के बीच समझौता जापन:
  - नकली नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने तथा उनका मुकाबला करने के लिये भारत तथा बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन (एमओय्) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - साथ ही नई निगरानी तकनीक का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत किया गया है।

# गिफ्ट सिटी और बुलियन एक्सचेंज

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के गिफ्ट (GIFT) सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी।

- इमारत को प्रतिष्ठित संरचना के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया है, जो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में GIFT-IFSC की बढ़ती प्रमुखता और विस्तार को दर्शाता है।
- उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX), GIFT-IFSC में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, NSE IFSC-SGX कनेक्ट भी लॉन्च किया।

#### बुलियन एक्सचेंजः

- 🗅 बुलियन:
  - बुलियन उच्च शुद्धता के सोने और चाँदी को संदर्भित करता है जिसे अक्सर बार, सिल्लियाँ या सिक्कों के रूप में रखा जाता है।
  - बुलियन को कभी-कभी कानूनी निविदा माना जा सकता है और इसे अक्सर केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार के रूप में रखा जाता है या संस्थागत निवेशकों द्वारा रखा जाता है।
  - सरकार ने अगस्त 2020 में बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद (BDR) के बारे में अधिसूचित किया था जिसमें वित्तीय उत्पाद के रूप में बुलियन और वित्तीय सेवाओं के रूप में संबंधित सेवाएँ शामिल थीं।
- 🔾 बुलियन एक्सचेंज:
  - बुलियन एक्सचेंज एक ऐसा बाजार है जिसके माध्यम से खरीदार और विक्रेता सोने और चाँदी के साथ-साथ संबंधित डेरिवेटिव का व्यापार करते हैं।
  - लंदन बुलियन मार्केट के साथ दुनिया भर में विभिन्न बुलियन मार्केट हैं, जिन्हें सोने और चाँदी के लिये प्राथमिक वैश्विक बाजार टेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है।

## इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ( IIBX ):

- 🗅 परिचय:
  - भारत में ज्वैलर्स द्वारा सोने के आयात को आसान बनाने के लिये पहली बार केंद्रीय बजट वर्ष 2020 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) की घोषणा की गई थी।
  - यह एक ऐसा मंच है जो न केवल ज्वैलर्स को एक्सचेंज में व्यापार करने के लिये नामांकित करता है, बिल्क सोने और चाँदी के भंडारण के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा भी स्थापित करता है।
  - IIBX भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जिम्मेदार और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा।
    - IFSCA को IIBX के माध्यम से सीधे सोने का आयात करने के लिये भारत में पात्र योग्य जौहरियों को अधिसूचित करने का कार्य सौंपा गया है।

#### 🕽 महत्त्व:

- यह भारत को वैश्विक सर्राफा बाजार (Bullion Market) में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने तथा अखंडता और गुणवत्ता के साथ वैश्विक मूल्य शृंखला हेतु सशक्त बनाएगा।
- IIBX भारत को एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में वैश्विक बुलियन कीमतों को प्रभावित करने की दिशा में सक्षम बनाएगा तथा यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी फिर से लागू करता है।

#### गिफ्ट सिटी:

- गिफ्ट (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
- इसमें एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) शामिल है जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) है।
- जिप्पट सिटी (Gujarat International Finance Tec-City) को न केवल भारत बिल्क विश्व के लिये वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकिल्पत किया गया है।
  - IFSCA भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिये एकीकृत नियामक है।
- शहर में सामाजिक बुनियादी ढाँचे में स्कूल, चिकित्सा सुविधाएँ, प्रस्तावित अस्पताल, इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब शामिल हैं। साथ ही इसमें एकीकृत सुनियोजित आवासीय परियोजनाएँ भी शामिल हैं जो गिफ्ट सिटी को वास्तव में "वॉक टू वर्क" शहर बनाती हैं।

### एनएसई-आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट:

- यह गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (SGX) में एनएसई की सहायक कंपनी के बीच एक अवसंरचना है।
- कनेक्ट के तहत सिंगापुर एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा दिये गए निफ्टी डेरिवेटिव पर सभी ऑर्डर एनएसई-आईएफएससी ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मैच किये जाएंगे।
- भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के ब्रोकर-डीलरों से कनेक्ट के माध्यम से ट्रेडिंग डेरिवेटिव हेतु बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है।
- यह GIFT-IFSC में व्युत्पन्न बाजाारों में तरलता को मजबूती तथा वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के साथ ही अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को आकर्षित करेगा।

### अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण:

- ⊃ स्थापनाः
  - IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी।
    - प्र इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है।
- 🗅 कार्य:
  - इसके अंतर्गत IFSC में ऐसी सभी वित्तीय सेवाओं, उत्पादों
     और संस्थाओं को विनियमित किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय क्षेत्र

के नियामकों द्वारा IFSCs के लिये पहले ही अनुमित दी जा चुकी है। प्राधिकरण ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, सेवाओं को भी विनियमित करेगा जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये जा सकते हैं। यह केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की भी सिफारिश कर सकता है जिन्हें IFSC में अनुमित दी जा सकती है।

#### 🔾 शक्तियाँ:

- अधिनियम के तहत संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक (भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, IRDAI तथा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण आदि) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ प्राधिकरण द्वारा IFSC में वित्तीय रूप से नियमन के अनुसार पूरी तरह से प्रयोग की जाएंगी।
- प्राधिकरण की प्रक्रियाएँ:
  - प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली अन्य प्रक्रियाएँ वित्तीय उत्पादों, सेवाओं या संस्थानों पर लागू भारत की संसद के संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार शासित होंगी।
- 🗅 केंद्र सरकार द्वारा अनुदान:
  - केंद्र सरकार को इस संबंध में संसद द्वारा कानून के उचित विनियोजन के बाद प्राधिकरण को इस तरह के धन को अनुदान के रूप में देना होगा क्योंकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिये इसके उपयोग को समझती है।
- विदेशी मुद्रा में लेन-देन:
- IFSCs के जिरये विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाओं का लेन-देन प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

# निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES) पहल के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिये राज्यों को 206 करोड़ रुपए जारी किये हैं।

TIES के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 27 निर्यात बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी गई है।

### निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना ( TIES ):

- 그 परिचय:
  - केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017 में निर्यात योजना (TIES) के लिये व्यापार बुनियादी ढाँचा शुरू किया।
    - वर्ष 2015 में निर्यात और विकास के लिये बुनियादी ढाँचा तैयार करने तथा सहायता (ASIDE) योजना से राज्यों के अलग होने के बाद राज्य सरकारें लगातार निर्यात बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु केंद्र से समर्थन का अनुरोध कर रही थीं।

#### 🔾 उद्देश्य:

निर्यात की वृद्धि के लिये उपयुक्त बुनियादी ढाँचे के निर्माण में
 केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना।

#### कार्य क्षेत्र:

- इस योजना का लाभ राज्यों द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण निर्यात लिंकेज जैसे- सीमा बाजार, भूमि, सीमा शुल्क केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्द्धन केंद्र, निर्यात वेयरहाउसिंग तथा पैकेजिंग, SEZ एवं बंदरगाहों/हवाई अड्डे, कार्गो टर्मिनल के साथ बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये लिया जा सकता है।
- वित्तीय सहायता की सीमा:
  - बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये केंद्र सरकार की सहायता अनुदान सहायता के रूप में होगी, आमतौर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना में यह कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगी।
    - उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख संघ शासित प्रदेशों सहित) यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है।
- उन परियोजनाओं की नकारात्मक सूची जिन पर इस योजना के तहत
   विचार नहीं किया जाएगा:
  - ऐसी परियोजनाएँ जो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT जैसी क्षेत्र
     विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।
  - सामान्य बुनियादी ढाँचा पिरयोजनाएँ जैसे राजमार्ग, बिजली आदि।
  - सामान्य बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएँ जैसे राजमार्ग, बिजली आदि।
  - ऐसी परियोजनाएँ जहाँ अत्यधिक निर्यात लिंकेज स्थापित नहीं किया जा सकता है।



## जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का शत-प्रतिशत लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसमें सभी बर्थ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित हो रहे थे।

#### लैंडलॉर्ड बंदरगाहः

- इस मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय और एक लैंडलॉर्ड के रूप में कार्य करता है, जबिक निजी कंपनियाँ बंदरगाह का संचालन करती हैं जिसमें मुख्य रूप से कार्गो-हैंडलिंग गतिविधियाँ शामिल हैं।
- इस मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह का स्वामित्व अपने पास रखता है, जबिक बुनियादी ढाँचे को निजी फर्मों को पट्टे पर दे दिया जाता है, जो स्वयं उस बंदरगाह को अधिरचना प्रदान करते हैं और उसे बनाए रखते हैं तथा कार्गों के संचालन के लिये अपने स्वयं के उपकरण स्थापित करते हैं।
- बदले में लैंडलॉर्ड बंदरगाह को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता रहता है।

#### सर्विस पोर्ट मॉडल:

- सर्विस पोर्ट मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह की गतिविधियों का प्रशासन और संचालन करता है।
- बंदरगाह संचालन में नौवहन सेवाएँ, गोदाम सुविधाएँ, क्रेन और कुशल कर्मचारी/मजदूर उपलब्ध कराना शामिल है। बुनियादी ढाँचे का निर्माण, अधिरचना और कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बंदरगाह प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है।
- यदि पत्तन बंदरगाह जनिहत में कार्य करता है तो भी बंदरगाह का पूर्ण स्वामित्व राज्य या सरकार के पास रहता है।

- ज्यादातर मामलों में सर्विस पोर्ट मॉडल अक्षमता के कारण नुकसान पर चलते हैं। चूँिक बंदरगाह राज्य से संबंधित है और बंदरगाह प्राधिकरण के पास इसका संचालन नियंत्रण है,इसलिये श्रिमिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNP):
- 🗅 परिचय:
  - यह नवी मुंबई में स्थित है, जो भारत में प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, साथ ही भारत के प्रमुख बंदरगाहों में कुल कंटेनरीकृत कार्गों वॉल्यूम का लगभग 50% है।
  - इसे वर्ष 1989 में अधिकृत िकया गया था और इसके संचालन के तीन दशकों में JNP थोक कार्गो टिर्मिनल (Bulk-Cargo Terminal) से देश का प्रमुख कंटेनर बंदरगाह बन गया है।
- संक्षिप्त अवलोकनः
  - यह देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों (लॉयड्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार) में 26वें स्थान पर है।
  - अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ JNP सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है, उपयोगकर्ता के अनुकूल वातावरण, साथ ही रेल और सड़क मार्ग से भीतरी इलाकों तक उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है।
  - यह वर्तमान में 9000 बीस-फुट समकक्ष इकाइयों (Twenty-Foot Equivalent Units TEU) क्षमता वाले जहाजों को संभाल रहा है और यह उन्नयन के साथ 12200 TEU क्षमता वाले जहाजों को भी संभाल सकता है।

## भारतः शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्त्ता

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य पर जारी विश्व रिपोर्ट' के अनुसार, भारत को वर्ष 2021 में प्रेषण (Remittance) द्वारा 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं।

### रिपोर्ट के बारे में:

- परिचय:
  - यह स्वास्थ्य और प्रवास की वैश्विक समीक्षा की पेशकश करने वाली पहली रिपोर्ट है और दुनिया भर में शरणार्थियों एवं प्रवासियों को उनकी ज़रूरतों के लिये संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने हेतु तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आह्वान करती है।

- परिणामः
  - प्रवासन:
    - प्र रिपोर्ट के अनुसार, 'विश्व स्तर पर प्रत्येक आठ में से लगभग एक व्यक्ति प्रवासी है (कुल 1 अरब प्रवासी हैं)।
    - 1990 से 2020 तक:
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या 153 मिलियन से बढ़कर
     281 मिलियन हो गई है।
- लगभग 48% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी महिलाएँ हैं और लगभग 36 मिलियन बच्चे हैं।
  - वर्ष 2020 तक यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद थी, इसके बाद उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चिमी एशिया का स्थान है।
  - वर्ष 2021 की पहली छमाही के दौरान नए मान्यता प्राप्त शरणार्थियों में से आधे से अधिक पाँच देशों से थे:
  - मध्य अफ्रीकी गणराज्य
  - 💠 दक्षिण सूडान
  - 💠 सीरियाई अरब गणराज्य
  - अफग़ानिस्तान
  - नाइजीरिया
- ⊃ प्रेषण:
  - वर्ष 2021 में शीर्ष पाँच प्रेषण प्राप्तकर्त्ता (अमेरिकी डॉलर में) निम्न और मध्यम आय वाले देश थे:
    - 💢 भारत: ८३ अरब
  - वर्ष 2021 में भारत के प्रेषण में 4.8% की वृद्धि हुई। (वर्ष 2020 में प्रेषण 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर था)।
    - चीन: 53 अरब डॉलर
    - मेक्सिको: 53 अरब डॉलर
    - फिलीपींस: 36 अरब डॉलर
    - 🙎 मिस्र: 33 अरब डॉलर
  - सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के हिस्से के रूप में वर्ष 2021
     में शीर्ष पाँच प्रेषण प्राप्तकर्त्ता छोटी अर्थव्यवस्थाएँ थीं:
    - 🗷 टोंगा: 44%
    - ⊭ लेबनान: 35%
    - 🛘 किर्गिजस्तान: 30%
    - ≖ ताजिकिस्तान: 28%
    - होंडरास: 27%
  - यूरोप और मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और उप-सहारा अफ्रीका व अधिकांश अन्य क्षेत्रों में म5-10% की वृद्धि दर्ज करते हुए प्रेषण में तीव्र सुधार हुआ है।
  - लेकिन चीन को छोड़कर पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 1.4%
     की धीमी गित से वृद्धि हुई।

#### प्रेषण:

- प्रेषित धन या रेमिटेंस का आशय प्रवासियों द्वारा मूल देश में मित्रों और रिश्तेदारों को किये गए वित्तीय या अन्य तरह के हस्तांतरण से है।
- यह मूलत: दो मुख्य घटकों का योग है- निवासी और अनिवासी परिवारों के बीच नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण और कर्मचारियों का मुआवजा, जो उन श्रमिकों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिये दूसरे देश में काम करते हैं।
- प्रेषण, प्राप्तकर्त्ता देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं, लेकिन यह ऐसे देशों को उन पर अधिक निर्भर भी बना सकता है।
  - यह अक्सर प्रत्यक्ष निवेश और आधिकारिक विकास सहायता की राशि से अधिक होता है।
- प्रेषण परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी जरूरतों को पुरा करने में मदद करते हैं।
- भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्तकर्त्ता है।
  - प्रेषण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है और चालू खाते के घाटे को पूरा करने में मदद करता है।

# निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण मॉडल

### चर्चा में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत निर्माण-पिरचालन-हस्तांतरण (Build-Operate-Transfer) मॉडल का उपयोग करके निजी साझेदारों को कम-से-कम दो राजमार्ग उन्नयन पिरयोजनाओं की पेशकश करने की योजना बनाई है।

### निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण ( BOT ) मॉडल:

- परिचय:
  - BOT मॉडल के तहत एक निजी साझेदार को निर्दिष्ट अविध (20 या 30 वर्ष की रियायत अविध) के लिये एक परियोजना के वित्तीयन, निर्माण और संचालन के लिये रियायत दी जाती है, जिसमें निजी साझेदार उपयोगकर्त्ता शुल्क या सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों से टोल के माध्यम से निवेश की भरपाई करता है और इस प्रकार एक निश्चित मात्रा में वित्तीय जोखिम उठाता है।
  - BOT एक निजी-सार्वजनिक भागीदारी (Public Private Partnership) मॉडल है जिसके अंतर्गत निजी साझेदार पर अनुबंधित अवधि के दौरान ढाँचागत

- परियोजना के डिजाइन, निर्माण एवं परिचालन की पूरी जिम्मेदारी होती है।
- निजी क्षेत्र के भागीदार को परियोजना के लिये वित्तीयन के साथ ही इसके निर्माण और रखखाव की जिम्मेदारी लेनी होती है।
- सरकार ने रियायत अवधि के दौरान पूर्व के प्रति 10 वर्ष की जगह अब प्रति 5 वर्ष पर परियोजना की राजस्व क्षमता का आकलन करने का निर्णय लिया है।
  - इसका अर्थ होगा कि निजी कंपनी के लिये राजस्व की निश्चितता सुनिश्चित करने हेतु रियायत अविध (या अविध जब तक सड़क डेवलपर्स टोल एकत्र कर सकते हैं) को अनुबंध अविध पूर्ण होने से पूर्व बढ़ाया जा सकेगा।

#### कार्य प्रक्रियाः

- निर्माण:
  - इसके अंतर्गत निजी कंपनी (या संघ) सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा परियोजना में निवेश करने के लिये सरकार से सहमत होने पर परियोजना के निर्माण के लिये वित्तपोषण करती है।
- परिचालन:
  - इसके अंतर्गत निजी साझेदार एक सहमत रियायत अविध के लिये सुविधा का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करता है तथा शुल्क या टोल के माध्यम से अपने निवेश की वसूली करता है।
- ♦ हस्तांतरण:
  - इसके अंतर्गत रियायती अविध के बाद कंपनी सरकार या संबंधित राज्य प्राधिकरण को सुविधा के स्वामित्व और संचालन का हस्तांतरण करती है।

## BOT मॉडल का महत्त्व और चुनौतियाँ:

- 🤈 लाभ:
  - परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिये वित्त जुटाने और सर्वोत्तम प्रबंधन कौशल का उपयोग करने में सरकार को निजी क्षेत्र का लाभ मिलता है।
  - निजी भागीदारी भी सर्वोत्तम उपकरणों का उपयोग करके दक्षता
     और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।
  - BOT उद्यमों को प्रदर्शन-आधारित अनुबंधों और निर्गत-उन्मुख लक्ष्यों के माध्यम से दक्षता में सुधार करने के लिये तंत्र और प्रोत्त्साहन प्रदान करता है।
  - परियोजनाएँ पूरी तरह से प्रतिस्पर्द्धी बोली की स्थिति में संचालित की जाती हैं और इस प्रकार न्यूनतम संभव लागत पर पूरी की जाती हैं।
  - परियोजना के जोखिम निजी क्षेत्र द्वारा साझा किये जाते हैं।

- 🗅 चुनौतियाँ:
  - वित्तपोषण के इक्विटी हिस्से में लाभ का घटक निहित है, जो ऋण लागत से अधिक होता है। यह वह कीमत है जो निजी क्षेत्र को जोखिम से निपटने के लिये चुकाई जाती है।
  - BOT वित्तपोषण समझौते को तैयार करने और समाप्त करने में काफी समय एवं अग्रिम खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें कई संस्थाएँ शामिल होती हैं और इसके लिये अपेक्षाकृत जटिल कानूनी तथा संस्थागत ढाँचे की आवश्यकता होती है। ऐसें में छोटी परियोजनाओं के लिये BOT उपयुक्त नहीं है।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संस्थागत क्षमता विकसित करने में समय लग सकता है कि BOT के पूर्ण लाभ प्राप्त हों, जैसे कि पारदर्शी और निष्पक्ष बोली और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का विकास तथा प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के दौरान संभावित विवादों का समाधान।

## PPP के कुछ अन्य मॉडल:

- ⇒ इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC):
  - इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग कार्य के लिये बोलियाँ आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM):
  - भारत में नया HAM BOT-एन्युइटी और EPC मॉडल का मिश्रण है। डिजाइन के अनुसार, सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से पहले पाँच वर्षों में परियोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष भुगतान सृजित परिसंपत्तियों और विकासकर्त्ता के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
- ⊃ बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO):
  - इस मॉडल में नविनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी पार्टी के पास रहेगा।
  - पारस्परिक रूप से नियमों और शर्तों पर सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदार परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की 'खरीद' करने पर सहमति बनाई जाती है।
- 🗅 बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT):
  - BOOT के इस प्रकार में समय पर बातचीत के बाद परियोजना को सरकार या निजी ऑपरेटर को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
  - BOOT मॉडल का उपयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिये किया जाता है।

- 🤉 बिल्ड-ओन-लीज-ट्रांसफर (BOLT):
  - इस मॉडल में सरकार निजी साझेदार को सार्वजनिक हित की सुविधाओं के निर्माण हेतु कुछ रियायतें देती है, साथ ही इसके डिजाइन, स्वामित्त्व, सार्वजनिक क्षेत्र के पट्टे का अधिकार भी देती है।
- 🤉 डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट (DBFO):
  - इस मॉडल में अनुबंधित अविध के लिये पिरयोजना के डिजाइन, उसके विनिर्माण, वित्त और पिरचालन का उत्तरदायित्त्व निजी साझीदार पर होता है।
- ⊃ लीज-डेवलप-ऑपरेट (LDO):
  - इस प्रकार के निवेश मॉडल में या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधा का स्वामित्व बरकरार रहता है और निजी प्रमोटर के साथ लीज समझौते के रूप में भुगतान प्राप्त किया जाता है। इसका पालन अधिकतर एयरपोर्ट सुविधाओं के विकास में किया जाता है।

# आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिये 'अस्थिर प्रभावों' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

- चीन ने सभी क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन को प्रभावी ढंग से पूर्ण प्रतिबंध लगाकर अवैध घोषित कर दिया है, जबिक अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अनुमित दी है। क्रिप्टो की वर्तमान स्थिति:
- ⊃ फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी रखना अभी भी अवैध नहीं है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश दिया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लगाया गया था।
- सेंट्रल बैंक वर्ष 2013 से ही लोगों को वर्चुअल करेंसी के इस्तेमाल के प्रति आगाह कर रहा है।
- अप्रैल 2018 में आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं को आभासी मुद्राओं में काम करने या किसी व्यक्ति या संस्था को उनके साथ व्यवहार करने या उन्हें निपटाने में सुविधा प्रदान करने के लिये सेवाएँ प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया था। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश को रह कर दिया था।

- इसके बाद मई 2021 में केंद्रीय बैंक ने अपनी विनियमित संस्थाओं को सलाह दी कि वे अपने ग्राहक को जानें (KYC), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 आदि के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के मानक दायित्व और विदेशी प्रेषण के विनियमन के लिये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) मानदंडों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप, ऐसी विनिमयन प्रक्रियाओं को ग्राहकों के लिये जारी रखें।
- केंद्रीय बजट 2022-2023 में आने वाले वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा पेश करने का भी प्रस्ताव है।

## आरबीआई की चिंताएँ:

- 🗅 नॉन-फिएट मुद्रा:
  - क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा नहीं है क्योंिक हर आधुनिक मुद्रा को केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा जारी करने की आवश्यकता होती है।
- काल्पनिक और अस्थिर:
  - फिएट मुद्राओं का मूल्य मौद्रिक नीति और कानूनी निविदा के रूप में उनकी स्थिति से संबंधित होता है, हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से उच्च रिटर्न के अनुमानों और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है, जो स्थिर नहीं होता है, इसलिये किसी देश की स्थिरता पर इसका मौद्रिक एवं राजकोषीय रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

#### क्रिप्टोकरेंसी:

- 🔾 परिचय:
  - क्रिप्टोकरेंसी, जिसे कभी-कभी क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक ऐसा रूप है जो डिजिटल या वस्तुत: मीजूद है और लेन-देन को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है।
  - क्रिप्टोकरेंसी में मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह लेन-देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिये विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है।
    - इसका संचालन एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा होता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।
- लाभ:
  - तीव्र एवं किफायती लेन-देन: क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन के लिये बैंक या किसी अन्य मध्यस्थ की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, अत: इस माध्यम से बहुत ही कम खर्च में लेन-देन किया जा सकता है।

- निवंश गंतव्य: क्रिप्टोकरेंसी की आपूर्ति सीमित है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत तेज़ी से बढ़ी है।
  - इसके कारण क्रिप्टोकरेंसी एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बन सकता है।
- मुद्रास्फीति रोधी मुद्रा (Anti-Inflationary Currency): क्रिप्टोकरेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफी हद तक बढ़ती प्रक्षेपवक्र पर बनी हुई हैं। इस परिदृश्य में लोग इसे खर्च करने की तुलना में अधिक क्रिप्टोकरेंसी रखते हैं।
  - 🗷 इससे मुद्रा पर अपस्फीतिकारी प्रभाव पड़ेगा।

## क्रिप्टोकरेंसी संबंधी चुनौतियाँ:

- विज्ञापन की अत्यधिका: क्रिप्टो बाजार को त्विरत लाभ कमाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। इसके कारण लोगों को इस बाजार में सट्टा लगाने हेतु लुभाने के लिये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विज्ञापनों की लगातार वृद्धि हो रही है।
  - हालाँिक चिंता का कारण यह है कि "अित-वादा" और "गैर-पारदर्शी विज्ञापन" के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने के प्रयास किया जा रहा है।
- प्रतिकूल उपयोगिताः अनियमित क्रिप्टो बाजार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण का साधन बन सकते हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिरता: बिटकॉइन 40,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 65,000 अमेरिकी डॉलर (जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
  - यह मई 2021 में गिर गया और पूरे जून माह में 30,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे रहा।
- मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता हेतु जोखिम: इस अनियमित परिसंपत्ति वर्ग में भारतीय खुदरा निवेशकों के निवेश जोखिम की सीमा मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिम है।
  - क्रिप्टो एक्सचेंजों के एक समूह के अनुसार, करोड़ों भारतीयों ने क्रिप्टो संपत्ति में 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।
- शेयर बाजार के मुद्दे: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है कि क्रिप्टो मुद्राओं के "समाशोधन और निपटान" पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है और यह प्रतिपक्ष गारंटी की पेशकश नहीं कर सकता जैसा कि शेयरों के लिये किया जा रहा है।
  - इसके अलावा क्या क्रिप्टोकरेंसी एक मुद्रा, वस्तु या सुरक्षा है,
     इसे परिभाषित नहीं किया गया है।

# संकटग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये एक शब्दावली

#### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़कर चार दशक के शीर्ष स्तर पर पहुँच गई। सरकार की ओर से जारी आँकड़ों के अनुसार, जून 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले की तलना में 9.1 फीसदी बढ़ गई।

- कई अमेरिकी पर्यवेक्षकों ने यह तर्क दिया है कि यील्ड कर्व कि स्थिति में अमेरिकी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिये सॉफ्ट-लैंडिंग हासिल करने में सक्षम नहीं होगा।
- रिवर्स करेंसी वॉर की शुरुआत का पूर्वानुमान भी लगाया गया है।
   बॉण्ड यील्ड व्युत्क्रमण (Bond Yield Inversion)
- 🔾 बॉण्डः
  - बॉण्ड: यह धन उधार लेने का एक साधन है। किसी देश की सरकार या एक कंपनी द्वारा धन का सृजन करने के लिये बॉण्ड जारी किया जा सकता है।
  - बॉण्ड यील्ड बॉण्ड के कूपन (ब्याज़) भुगतान से निवेशक को प्राप्त लाभ है।
  - आमतौर पर सरकारी बॉण्ड यील्ड अर्थव्यवस्था में जोखिम-मुक्त
     ब्याज़ दर को समझने का एक अच्छा तरीका है।
- 🔾 यील्ड कर्वः
  - यील्ड कर्व अलग-अलग समयाविध में बॉण्ड (समान क्रेडिट रेटिंग के साथ) से यील्ड का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है।
  - दूसरे शब्दों में यदि कोई अमेरिकी सरकार के अलग-अलग अविध के बॉण्ड लेता है और उन्हें उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली यील्ड के अनुसार प्रबंध करता है, तो उसे यील्ड कर्व मिलेगा।
- 🔾 बॉण्ड यील्ड व्युत्क्रमणः
  - सामान्य परिस्थितयों में:
    - किसी भी अर्थव्यवस्था में ऊपर की ओर झुकी हुई यील्ड कर्व होगी।
  - जैसे ही कोई लंबी अविध के लिये उधार देता है या लंबी अविध के बॉण्ड खरीदता है तो उसे अधिक प्रतिफल मिलता है।
  - यदि कोई लंबी अविध के लिये पैसे की साझेदारी कर रहा है, तो रिटर्न अधिक मिलेगा।
    - जब निवेशक अर्थव्यवस्था के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं तो वे लंबी अविध के बॉण्ड से पैसा निकालते हैं और इसे शेयर बाजारों जैसे अल्पकालिक जोखिम वाले परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं।

- बॉण्ड बाज़ार में लंबी अविध के बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं और उनकी यील्ड (प्रभावी ब्याज़ दर) बढ़ जाती है।
- ऐसा इसलिये होता है क्योंिक बॉण्ड की कीमतें और बॉण्ड यील्ड विपरीत रूप से संबंधित हैं।
- संदिग्ध परिस्थितियाँ:
  - हालाँकि जब निवेशकों को संदेह होता है कि अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही है, तो वे अल्पकालिक जोखिम वाली संपत्तियों (जैसे शेयर बाजार) से पैसा निकालते हैं और उन्हें लंबी अविध के बॉण्ड में निवेश करतें हैं।
  - इससे लंबी अविध के बॉण्ड की कीमतें बढ़ती हैं और उनका प्रतिलाभ गिरता है।

#### सॉफ्ट लैंडिंग:

- अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही कठोर मौद्रिक प्रक्रिया में न केवल मुद्रा आपूर्ति को कम करना शामिल है बल्कि पैसे की लागत (यानी ब्याज दर) में वृद्धि करना भी शामिल है।
  - अमेरिकी फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये
     ऐसा कर रहा है।
- जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी के बिना अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो इसे सॉफ्ट-लैंडिंग कहा जाता है यानी किसी को नुकसान नहीं होता है।
  - लेकिन जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाई मंदी लाती है, तो इसे हार्ड-लैंडिंग कहा जाता है।

#### रिवर्स करेंसी वॉर:

- अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आक्रामक रूप से ब्याज दरें बढ़ाने की कार्रवाई का एक दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका में निवेश करने के लिये अधिक-से-अधिक निवेशक आकर्षित हो रहे हैं।
  - इसने बदले में डॉलर को अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में मज्ञबूत बना दिया है क्योंिक येन, यूरो, युआन आदि की तुलना में डॉलर की अधिक मांग है।
- डॉलर के मुकाबले अन्य देशों की स्थानीय मुद्रा की सापेक्ष कमजोरी
   उनके निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती है।
  - उदाहरण के लिये चीनी या भारतीय निर्यातक को अधिक बढ़ावा मिलता है।
  - अतीत में अमेरिका ने अन्य देशों पर अपनी मुद्रा में हेरफेर करने (डॉलर के मुकाबले इसे कमज़ोर रखने) का आरोप लगाया है ताकि वे अमेरिका के खिलाफ व्यापार अधिशेष का लाभ उठा सकें।
  - 💠 इसे करेंसी वॉर या मुद्रा युद्ध कहा जाता है।

## यूरो-डॉलर समानता

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूरो और अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग समान हो गई है, इसका अर्थ है कि एक अमेरिकी डॉलर से विदेशी मुद्रा बाजार में एक यूरो खरीदा जा सकता है।

वर्ष की शुरुआत के बाद से यूरो में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 12% की गिरावट आई है और आगे भी इसमें गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है।

#### मुद्रा विनिमय दरः

- बाजार अर्थव्यवस्था में किसी भी मुद्रा की कीमत आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है।
  - विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति केंद्रीय बैंक नीति, आयात एवं विदेशी परिसंपत्ति की स्थानीय मांग जैसे विभिन्न कारकों से निर्धारित होती है।
  - दूसरी ओर किसी देश की मुद्रा की मांग, केंद्रीय बैंक नीति, निर्यात एवं घरेलू पिरसंपत्ति की विदेशी मांग जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है।

## यूरो के मूल्य में गिरावट के प्रमुख कारक:

- यू.एस. फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीतियों में विचलन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो के महत्त्वपूर्ण मूल्यहास के पीछे प्राथमिक कारण है।
- जून 2022 में अमेरिका में मुद्रास्फीति चार दशक के उच्च स्तर 9.1% पर पहुँच गई है, जबिक यूरोजोन में मुद्रास्फीति उसी महीने के दौरान अपने उच्चतम स्तर 8.6% पर पहुँच गई है।
  - अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने अमेरिकी मुद्रा आपूर्ति वृद्धि को धीमा करने के लिये इस वर्ष ब्याज़ दरों में वृद्धि करके बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया दी है।
  - ECB नीति को सख्त करने में बहुत कम आक्रामक रहा है, हालाँकि कुछ यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति की दर 22% जितनी अधिक है।
    - यह यूरो के मूल्य को डॉलर के मुकाबले फिसलने करने का कारण बना है क्योंिक मुद्रा कम-से-कम डॉलर की आपूर्ति के मुकाबले बाजार में यूरो की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है।
- यूक्रेन पर रूस का आक्रमण और रूस के खिलाफ आगामी कार्रवाइयों के मद्देनजर ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता से यूरो का मूल्य प्रभावित हुआ है।
  - यूरोप को अब सीमित ऊर्जा आपूर्ति को आयात करने के लिये अधिक यूरो खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसने बदले में यू.एस. डॉलर के मुकाबले यूरो के मुल्य पर प्रतिकृल प्रभाव डाला है।

# भारत नवाचार सूचकांक 2021: नीति आयोग

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति (National Institution for Transforming India-NITI) आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, 2021 जारी की गई, जिसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

- यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के ढाँचे को रेखांकित करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे पर प्रकाश डालता है।
- इसमें अब संकेतकों की संख्या 36 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020
   में) से बढ़कर 66 (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में) हो गई है।

## भारत नवाचार सूचकांकः

- 그 परिचय:
  - यह देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास हेतु व्यापक उपकरण है।
  - यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने के लिये उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करता है।
- शामिल संस्थाएँ:
  - 💠 प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान के साथ नीति आयोग।
- ⊃ प्रयुक्त संकेतक:
  - सूचकांक में 7 स्तंभ हैं, जिनमें से पाँच 'सक्षम' स्तंभ इनपुट को मापते हैं और दो 'प्रदर्शन' स्तंभ आउटपुट को मापते हैं।
  - सर्वेक्षण में जिन संकेतकों का उपयोग किया जाता है उनमें शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता आदि जैसे मानदंड शामिल हैं:
    - पीएचडी छात्रों की संख्या और ज्ञान-गहन रोजगार।
    - इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नामांकन तथा अत्यधिक कुशल पेशेवरों की संख्या।
    - अनुसंधान और विकास गतिविधियों (R&D) में निवेश एवं दायर पेटेंट तथा ट्रेडमार्क आवेदनों की संख्या।
    - इंटरनेट सब्सक्राइबर।
    - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह, कारोबारी माहौल और सुरक्षा एवं कानुनी प्रावधान।



## रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- 🗅 श्रेणियाँ:
  - इनोवेशन इंडेक्स को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है- प्रमुख राज्य,
     केंद्रशासित प्रदेश और पहाड़ी एवं उत्तर-पूर्व के राज्य।
- 🗅 प्रमुख राज्य:
  - शीर्ष राज्य: कर्नाटक 18.05 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा और उसके बाद तेलंगाना तथा हरियाणा का स्थान रहा।
    - कर्नाटक की सफलता का श्रेय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में उसके उच्च स्तरीय प्रदर्शन और बड़ी संख्या में उद्यम पूंजी सौदों को दिया जा सकता है।
  - खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य: बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने सूचकांक में सबसे कम स्कोर किया, जिसने उन्हें "प्रमुख राज्यों" की श्रेणी में सबसे नीचे रखा।
    - 🗷 छत्तीसगढ़ को 10.97 अंक के साथ अंतिम स्थान मिला है।
- ⊃ पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्य:
  - इस श्रेणी में मिणपुर सबसे आगे है जिसके बाद उत्तराखंड और मेघालय का स्थान है।
    - 🗷 नगालैंड अंतिम (10वें) स्थान पर रहा।
- केंद्रशासित प्रदेश/छोटे राज्य:
  - चंडीगढ़ 27.88 अंक के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला प्रदेश रहा है, जिसके बाद दिल्ली, अंडमान और निकोबार का स्थान है।
    - 🗷 लद्दाख अंतिम (१वें) स्थान पर रहा।
- ⊃ चुनौतियाँ:
  - औसतन देश ने ज्ञान कार्यकर्त्ता स्तंभ (Knowledge Worker Pillar) में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, जितना मानव पूंजी स्तंभ (Human Capital Pillar) में किया है।

- मानव पूंजी पर होने वाला खर्च देश में उस ज्ञान का आधार बनाने
   में असमर्थ रहा है।
- नवोन्मेष विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित समस्याओं और मिसिंग मिडल के कारण विषम है।
  - मिसिंग मिडल हजारों लोगों को रोजगार देने के लिये बहुत सारे छोटे, अनौपचारिक उद्यम और बहुत कम बड़े, औपचारिक उद्यम हैं।

#### सिफारिश:

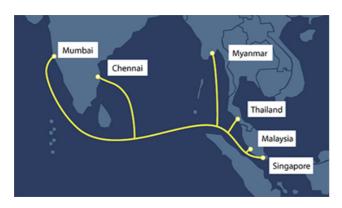
- GDERD (अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय) में काफी सुधार की आवश्यकता है, जो भारत में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएग।
  - GDERD बढ़ने से अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है तथा उद्योग की माँग और देश अपनी शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से जो उत्पादन करता है, उसके बीच की खाई को कम करता है।
  - GDERD पर कम खर्च करने वाले देश लंबे समय में अपनी मानव पूंजी को बनाए रखने में विफल रहते हैं और नवाचार करने की क्षमता मानव पूंजी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है; सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में भारत का GDERD लगभग 0.7% था।
- निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास में तेज़ी लाने की जरूरत है, सार्वजनिक व्यय कुछ हद तक उत्पादक है; एक बार जब विकास एक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करता है, तो यह वांछनीय है कि अनुसंधान एवं विकास को ज्यादातर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाए।

# एमआईएसटी पनडुब्बी केबल प्रणाली

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) की मंज़ूरी के लिये MIST (म्याँमार/ मलेशिया-भारत-सिंगापुर ट्राँजिट) पनडुब्बी केबल प्रणाली की सिफारिश की।

यह मुंबई में स्थापित होने वाला 17वाँ ऐसा ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम होगा जिसके वर्ष 2023 में सेवा हेतु उपलब्ध होने की उम्मीद है।



### म्याँमार/मलेशिया-भारत-सिंगापुर ट्राँज़िट ( MIST ):

- MIST अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल संचार नेटवर्क है, जो भारत को म्याँमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे अन्य एशियाई देशों के साथ जोडने के लिये समुद्र के नीचे स्थापित किया जाता है।
- यह चेन्नई से होते हुए मुंबई से सिंगापुर को जोड़ने वाली समुद्र के नीचे 8,100 किमी. लंबा ट्रांसनेशनल फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम है।
- 그 यह केबल प्रणाली मुंबई में वर्सीवा बीच पर समाप्त हो जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री केबल प्रणाली के तहत कुल लंबाई में से 523.50 किलोमीटर तिमलनाडु के तटीय क्षेत्र में लगभग 12 समुद्री मील और महाराष्ट्र की CRZ सीमा में 202.06 किलोमीटर केबल बिछाई जाएगी।

#### परियोजना का महत्त्वः

- MIST केबल सिस्टम एशिया में सुरक्षित, विश्वसनीय, मजबूत और सस्ती दूरसंचार सुविधाएँ प्रदान करेगा।
- यह भारत और अन्य एशियाई देशों जैसे- म्यॉँमार, थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर के बीच दूरसंचार संपर्क को बढ़ावा देगा।
- यह वैश्विक संचार के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पिरयोजना है और इसका मुंबई के तटीय पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।
- चेन्नई तट पर अंतर्राष्ट्रीय केबल लैंडिंग की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इससे विभिन्न हितधारकों के परस्पर संघर्ष में भी कमी आएगी।

### आगामी परियोजनाएँ :

- रिलायंस जियो इंफोकॉम इंडिया-एशिया एक्सप्रेस (IAX), भारत को मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड से जोड़ती है।
- भारत-यूरोप एक्सप्रेस (IEX) सऊदी अरब और ग्रीस के माध्यम से भारत को इटली से जोड़ती है।
- दूरसंचार प्रदाताओं के संघ के स्वामित्व वाली SeaMeWe-6
  परियोजना भारत, बांग्लादेश, मालदीव के माध्यम से सिंगापुर को
  फ्राँस से जोड़ेगी।

 अफ्रीका-2 केबल कई अफ्रीकी देशों द्वारा भारत को यूनाइटेड किंगडम से जोडेगी।

## डिजिटल बैंक

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक 'डिजिटल बैंक: ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया' (Digital Banks: A Proposal for Licensing & Regulatory Regime for India) है।

 इसने डिजिटल बैंको के लिये एक लाइसेंसिंग व नियामक ढाँचा स्थापित करने का सुझाव दिया है।

#### रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- हाल के वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
   और इंडिया स्टैक द्वारा उत्प्रेरित वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में तीव्र प्रगति की है।
- हालाँकि ऋण तक पहुँच एक नीतिगत चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से देश के 63 मिलियन MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिये।
- वित्तीय समावेशन को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जिसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया है।
  - ♦ UPI ने अक्तूबर 2021 में 7.7 ट्रिलियन रुपए के 4.2 बिलियन से अधिक लेन-देन दर्ज किये हैं।
- FI ने पीएम-िकसान जैसे एप, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और पीएम-स्विनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सूक्ष्म ऋण सुविधाओं का विस्तार किया।
- भारत अपने स्वयं के 'खुले बैंकिंग ढाँचे' को संचालित करने के करीब है।
- डिजिटल बैंकिंग नियामक और नीति के लिये एक ढाँचा का निर्माण भारत को फिनटेक में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के साथ-साथ कई सार्वजनिक नीतिगत चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्रदान करेगा।

### सिफारिशें:

- लाइसेंस प्राप्त ग्राहकों की मात्रा/मूल्य और इसी तरह के अन्य उदाहरणों के संदर्भ में एक प्रतिबंधित डिजिटल बैंक लाइसेंस जारी करने पर रोक लगे।
- भारतीय रिजार्व बैंक द्वारा अधिनियमित एक नियामक सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क में लाइसेंसधारकों की सूची।
- प्रमुख, विवेकपूर्ण और तकनीकी जोखिम प्रबंधन सहित नियामक सैंडबॉक्स में लाइसेंसधारी के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर 'पूर्ण पैमाने' वाला डिजिटल बैंक लाइसेंस जारी करना।

#### डिजिटल बैंक और इसकी आवश्यकता:

- डिजिटल बैंक:
  - इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित किया जाएगा और अपनी बैलेंस शीट के साथ इसका कानूनी अस्तित्व होगा।
  - यह केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) से अलग होगा, जो कि कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और फिनटेक नवाचारों को आगे बढाने के लिये स्थापित किये जा रहे हैं।
    - DBU विशेष निश्चित बिंदु व्यापार इकाई या डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को किसी भी समय स्वयं सेवा मोड में डिजिटल रूप से सुविधा प्रदान करने के लिये कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचनाओं का हब है।
  - डिजिटल बैंक मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के समान विवेकपूर्ण और तरलता मानदंडों के अधीन होंगे।

#### आवश्यकताः

- 🗅 क्रेडिट गैप:
  - भुगतान के मोर्चे पर भारत ने जो सफलता देखी है, उसे अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों की ऋण जरूरतों को पूरा करने में दोहराया जाना बाकी है।
  - क्रेडिट गैप से पता चलता है कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रभावी ढंग से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना साथ ही वंचितों को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाने की जरूरत है।
- डिजिटल चैनलों पर रिलायंस:
  - डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने वाले बैंक और फिनटेक व्यवसाय मुख्य रूप से डिजिटल चैनलों पर भरोसा करते हैं, जिनमें मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के सापेक्ष उच्च दक्षता वाले तंत्र होते हैं।
  - यह संरचनात्मक विशेषता उन्हें एक संभावित प्रभावी चैनल बनाती है जिसके माध्यम से नीति निर्माता कम बैंकिंग वाले छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और खुदरा उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने जैसे सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
- ⊃ नियो-बैंक मॉडल चुनौतियों का सामना:
  - मौजूदा साझेदारी-आधारित नियो-बैंक मॉडल राजस्व सृजन और
     व्यवहार्यता जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हैं।
    - नियो-बैंक के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है, लेकिन बैंक लाइसेंस प्राप्त सेवाएँ प्रदान करने के लिये बैंक भागीदारों पर भरोसा करते हैं।

उनके पास सीमित राजस्व क्षमता, पूंजी की उच्च लागत और केवल भागीदार बैंकों के उत्पादों की पेशकश है।

## जैव अर्थव्यवस्था

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, 2022 जारी की है।

- रिपोर्ट जारी करने के दौरान सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र (BIG-NER) के लिये एक विशेष बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल की शुरूआत की और बायोटेक समाधान विकसित करने हेतु उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 25 स्टार्टअप और उद्यमियों के लिये 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
- BIRAC जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी (धारा 8, अनुसूची B) सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

## रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के वर्ष 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की संभावना है।
- वर्ष 2021 में देश की जैव अर्थव्यवस्था 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि वर्ष 2020 के2 बिलियन अमेरीकी डॉलर से 14.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रही है।
- वर्ष 2021 में हर दिन औसतन कम-से-कम तीन बायोटेक स्टार्टअप शामिल किये गए (वर्ष 2021 में कुल 1,128 बायोटेक स्टार्टअप स्थापित किये गए) और उद्योग ने अनुसंधान एवं विकास खर्च में 1 बिलियन अमेरीकी डॉलर को पार कर लिया।
- भारत के पास अमेरिका के बाहर अमेरिकी खाद्य एवं औषिध प्रशासन(USFDA) द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।
- 🗅 टीकाकरण
  - भारत ने प्रतिदिन कोविड-19 टीकों की लगभग 4 मिलियन टीके दिये(वर्ष 2021 में दी गई कुल 1.45 बिलियन टीके)।
- 🗅 कोविड-19
  - देश ने वर्ष 2021 में हर दिन 1.3 मिलियन कोविड -19 परीक्षण किये (कुल 506.7 मिलियन परीक्षण)।

### जैव अर्थव्यवस्था ( Bioeconomy ):

- 그 परिचय:
  - संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार,
     जैव अर्थव्यवस्था को जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग और

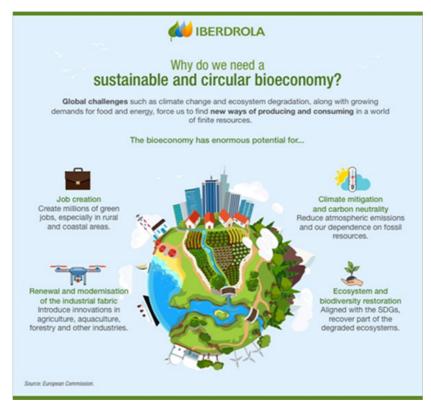
संरक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सूचना, उत्पाद, प्रक्रियाएँ प्रदान करना शामिल है ताकि स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सभी आर्थिक क्षेत्रों को जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाओं और सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

- 🗅 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  - यूरोपीय संघ (EU) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा नए उत्पादों तथा बाजार को विकसित करने के लिये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अपनाए गए ढाँचे के बाद 21वीं सदी के पहले दशक में जैव अर्थव्यवस्था शब्द लोकप्रिय हो गया।
- 🕽 उदाहरण:
  - खाद्य प्रणालियाँ जैव-अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित हैं। इन प्रणालियों में शामिल हैं:
    - 🗷 संधारणीय कृषि
    - संधारणीय मत्स्य

- 🙎 वानिकी और जलकृषि
- खाद्य और चारा निर्माण
- 💠 जैव आधारित उत्पाद:
  - बायोप्लास्टिक्स
  - बायोडिग्रेडेबल कपड़े

#### चक्रीय जैव अर्थव्यवस्थाः

- जैव-अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सतत् विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था के पुनः उपयोग,मरम्मत और पुनर्चक्रण का सिद्धांत जैव-अर्थव्यवस्था का मूलभूत हिस्सा है।
- पुन: उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण के माध्यम से अपिशष्ट की कुल मात्रा और उसके प्रभाव को कम किया जाता है। यह ऊर्जा की भी बचत करता है तथा वायु व जल प्रदूषण को कम करता है, इस प्रकार पर्यावरण, जलवायु एवं जैवविविधता की क्षित को रोकने में मदद करता है।



### जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित भारतीय पहलें:

- 🔾 बायोफार्मा के लिये:
  - नेशनल बायोफार्मा मिशन, 'इनोवेट इंडिया' 2017, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) का 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बायोफार्मा में उद्यमशीलता और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिये उद्योग एवं शिक्षा जगत को एक साथ लाना है।

- स्टार्टअप को बढावा देने के लिये:
  - विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पूरे भारत में 35 बायो इन्क्यूबेटर स्थापित किये गए हैं।
  - DBT और BIRAC द्वारा मिशन इनोवेशन के तहत पहला इंटरनेशनल इन्क्यूबेटर- क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इन्क्यूबेटर स्थापित किया गया है।
  - 23 भाग लेने वाले यूरोपीय संघ के देशों के स्टार्टअप संभावित रूप से भारत में आ सकते हैं और इनक्यूबेट कर सकते हैं, इसी तरह इस इनक्यूबेटर से स्टार्टअप वैश्विक अवसरों तक पहुँच की सुविधा के लिये भागीदार देशों में जा सकते हैं। विभाग 4 बायो-क्लस्टर (NCR, कल्याणी, बंगलूरू और पुणे) का समर्थन कर रहा है।
- जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन: जैव संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच वर्ष 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव-संसाधन एवं सतत् विकास संस्थान द्वारा 'जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन' शुरू किया गया था।

# पूर्वोत्तर क्षेत्र को कृषि निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देने की रणनीति

#### चर्चा में क्यों?

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (APEDA) ने पूर्वोत्तर (NE) राज्यों में उगाए जाने वाले कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक रणनीति तैयार की है।

- APEDA का लक्ष्य निर्यातकों के लिये सीधे उत्पादक समूहों तथा प्रोसेसरों से उत्पादों को प्राप्त करने के लिये असम में एक प्लेटफॉर्म का सजन करना है।
- यह प्लेटफॉर्म असम के उत्पादकों तथा प्रोसेसरों एवं देश के अन्य हिस्सों से निर्यातकों को जोड़ेगा जो असम सिहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में निर्यात पॉकेट के आधार को विस्तारित करेगा

### कृषि निर्यात में NER का महत्त्व:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंिक यह चीन तथा भूटान, म्यॉॅंमार, नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है जो इसे पड़ोसी देशों एवं साथ में विदेशी गंतव्य स्थानों को कृषि ऊपज के निर्यात के लिये संभावित हब बनाता है।
  - पिछले छह वर्षों में कृषि उत्पादों के निर्यात में 85.34% की वृद्धि देखी गई क्योंकि यह वर्ष 2016-17 में 2.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 17.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

- निर्यात का प्रमुख गंतव्य बांग्लादेश, भूटान, मध्य-पूर्व, यूके और यरोप रहा है।
- असम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अन्य राज्यों में अनुकूल जलवायु
   स्थिति है तथा लगभग सभी कृषि एवं बागवानी फसलों को उगाने के
   लिये मृदा मौजूद है।
- NER कई खराब होने वाली वस्तुओं, जैसे-केला, अनानास, संतरा और टमाटर के मामले में भारी बिक्री योग्य अधिशेष पैदा करता है।

# ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने OALP बिड राउंड-VIII लॉन्च किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बोली के लिये 10 ब्लॉकों की पेशकश की गई है।

#### ओपन एकरेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम ( OALP ):

- ⇒ मार्च 2016 में पूर्ववर्ती न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) के स्थान पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) को मंज़ूरी दी गई थी तथा जून 2017 में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के साथ-साथ नेशनल डेटा रिपोजिटरी (NDR) को भारत में अन्वेषण और उत्पादन (E&P) गतिविधियों में तेजी लाने के लिये प्रमुख संचालक के रूप में लॉन्च किया गया था।
- OALP के तहत कंपनियों को उन क्षेत्रों के अन्वेषण की अनुमित है, जिनमें वे तेल और गैस का पता लगाना चाहती हैं।
- कंपिनयाँ वर्ष भर किसी भी क्षेत्र के अन्वेषण हेतु अपनी रुचि को प्रकट कर सकती हैं लेकिन ऐसी सुविधा वर्ष में तीन बार दी जाती है। इसके बाद मांगे गए क्षेत्रों की बोली लगाने की पेशकश की जाती है।
- यह पूर्व नीति से अलग है, इस नीति में जहाँ एक तरफ सरकार ने क्षेत्रों की पहचान की सुविधा दी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बोली लगाने की पेशकश की।

## हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी ( HELP ):

- परिचय:
  - हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP) रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर आधारित है।
  - नई नीति सरल नियमों, कर विराम, मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता का वादा करती है तथा वर्ष 2022-23 तक तेल एवं गैस उत्पादन को दोगुना करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है।

#### ⇒ HELP के कार्य:

- यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग:
  - HELP एक समान लाइसेंसिंग प्रणाली प्रदान करती है जो तेल, गैस और कोल बेड मीथेन जैसे सभी हाइड्रोकार्बन को कवर करेगी।
- NLEP के तहत विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिये अलग-अलग लाइसेंस जारी किये गए थे।
- इससे अतिरिक्त लागत आती है, क्योंिक एक निश्चित प्रकार का अन्वेषण करते समय किसी अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाने पर अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- राजस्व बँटवारा मॉडल:
  - मELP एक राजस्व बँटवारा मॉडल प्रदान करता है, सरकार को तेल और गैस आदि की बिक्री से सकल राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होगा तथा खर्च की गई लागत से कोई सरोकार नहीं होगा।
- NELP लाभ बँटवारा मॉडल था जहाँ लागत की वसूली के बाद सरकार और ठेकेदार के बीच मुनाफे को साझा किया जाता है।
- NELP के तहत सरकार के लिये निजी प्रतिभागियों के लागत विवरण की जाँच करना आवश्यक हो गया और इसके कारण देरी और विवाद उत्पन्न हुए।
- मृल्य निर्धारण:
  - म HELP के पास मार्केटिंग और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता है।
- HELP से पहले, अनुबंध सोना चढ़ाने (महंगी और अनावश्यक सुविधाओं का समावेश) की संभावना के साथ उत्पादन साझा करने पर आधारित थे और 'लाभ में हेरफेर' करके सरकार को नुकसान पहुँचाते थे।
- अनुबंधों की जटिलता को कम करने के लिये इसे राजस्व बँटवारे में बदल दिया गया।
  - नई प्रणाली के तहत रॉयल्टी दरों की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली शुरू की गई थी।
- इस प्रणाली के तहत रॉयल्टी दरें उथले जल (जहाँ अन्वेषण की लागत और जोखिम कम है), गहरे जल (जहाँ लागत और जोखिम अधिक है) से अति-गहरे जल वाले क्षेत्रों में घट जाएगी।

# अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 100वाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया।

 भारत ने "सहकारिता के माध्यम से आत्मिनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण" विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया।

## अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस:

- 🔾 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः
  - 16 दिसंबर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया था।
  - इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहकारी सिमितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उनके विस्तार और लाभप्रदता को बढ़ावा दे।
  - यह अवसर संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दों से निपटने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी आंदोलन और अन्य कारकों के बीच गठबंधन को बढ़ाने एवं विस्तारित करने के लिये सहकारी आंदोलन के योगदान पर प्रकाश डालता है।

#### 🗅 महत्त्व:

- इसका उद्देश्य सहकारी सिमितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आंदोलन के मूल्यों को आगे बढ़ाना है:
  - अंतर्राष्ट्रीय एकता
  - आर्थिक दक्षता
  - समानता
  - д वैश्विक शांति
- 2022 की थीम:

## सहकारी समितियाँ:

- 🗅 परिचय:
  - सहकारिताएँ जन-केंद्रित उद्यम हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये किया जाता है।
  - सहकारिता लोगों को लोकतांत्रिक और समान तरीके से एक साथ लाती है। सदस्य चाहे ग्राहक हों, कर्मचारी हों, उपयोगकर्ता हों या निवासी हों, सहकारी सिमितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से 'एक सदस्य, एक वोट' नियम द्वारा किया जाता है।
    - उद्यम में किये गए पूंजी निवेश की परवाह किये बिना सदस्यों को समान मतदान अधिकार प्राप्त है।
- भारतीय परिप्रेक्ष्यः
  - वर्तमान में भारत में 90 प्रतिशत गाँवों को कवर करने वाली 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ ये ग्रामीण

और शहरी दोनों क्षेत्रों में समावेशी विकास के उद्देश्य से सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण संस्थान हैं।

- भारत में सहकारिता आंदोलन की सफलता की कुछ जानी मानी कहानियों में शामिल हैं:
  - 🛘 आनंद मिल्क युनियन लिमिटेड (AMUL)
  - भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO)
  - 🗷 कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (KRIBHCO)
  - 🗷 राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)

#### संबंधित सरकारी पहल:

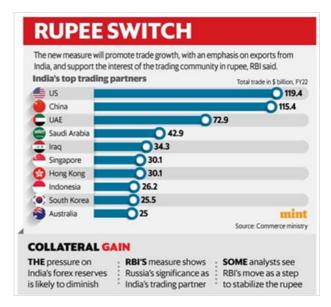
- सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के क्रम में केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके गठन के बाद से मंत्रालय नई सहकारिता नीति और योजनाओं के मसौदे पर काम कर रहा है।
- सहकारिता क्षेत्र में देश के किसान, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं सशक्तीकरण के लिये पर्याप्त संभावनाएँ हैं।
- हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण को स्वीकृति देकर सहकारिता क्षेत्र को मज़बूत बनाने का अहम निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य PACS की दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता के साथ संचालन कर उनकी विश्वसनीयता को बढ़ान, PACS के कामकाज में विविधता लाना और कई गितिविधियों/सेवाओं के संचालन में सहायता देना है।

# RBI ने रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दी

## चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तत्काल प्रभाव से रुपए (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिये एक तंत्र स्थापित किया है।

- हालाँकि ऐसे लेन-देन के लिये डीलर के रूप में कार्य करने वाले अधिकृत बैंकों को इसका उपयोग कर इसे सुविधाजनक बनाने के लिये नियामक से पूर्वानुमित लेनी होगी।
- RBI द्वारा प्रस्तावित संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत कवर किये गए क्रॉस-बॉर्डर निर्यात और आयात को भारतीय रुपए में डिनॉमिनेट और इनवॉइस किया जा सकता है. हालॉॅंकि RBI ने निर्धारित किया है कि दोनों व्यापार भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार के अनुसार निर्धारित की जाएगी



#### रुपया भुगतान तंत्र:

- भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमित दी गई है (एक खाता जो एक अधिकृत बैंक दूसरे बैंक की ओर से रखता है)।
  - इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातक भारतीय रुपए में भुगतान करेंगे जो विदेशी विक्रेता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिये चालान भागीदार देश के अधिकृत बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा।
  - तंत्र का उपयोग करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के अधिकृत बैंक के नामित विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा शेष राशि से भारतीय रुपए में निर्यात का भुगतान किया जाएगा।
- भारतीय निर्यातक उपर्युक्त रुपए भुगतान तंत्र के माध्यम से विदेशी आयातकों से भारतीय रुपए में निर्यात के लिये अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
  - निर्यात के लिये अग्रिम भुगतान की ऐसी किसी भी प्राप्ति की अनुमित देने से पहले भारतीय बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन खातों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग पहले से ही निष्पादित निर्यात आदेशों/पाइपलाइन में निर्यात भुगतान से उत्पन्न भुगतान दायित्वों के लिये किया जाता है।
  - विशेष वोस्ट्रो अकाउंट में शेष राशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जा सकता है: परियोजनाओं और निवेशों के लिये भुगतान, निर्यात/आयात अग्रिम प्रवाह प्रबंधन, सरकारी प्रतिभृतियों में निवेश आदि।

## मौजूदा तंत्रः

यदि कोई कंपनी निर्यात या आयात करती है, तो लेन-देन (नेपाल और भूटान जैसे देशों को छोड़कर) हमेशा एक विदेशी मुद्रा में होता है।

- इसिलये आयात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है (मुख्य रूप से डॉलर में और इसमें पाउंड, यूरो, येन आदि मुद्राएँ भी शामिल हो सकती हैं)।
- निर्यात के मामले में भारतीय कंपनी को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाता है और कंपनी उस विदेशी मुद्रा को रुपए में परिवर्तित कर देती है क्योंकि उसे ज्यादातर मामलों में अपनी ज़रूरतों के लिये रुपए की आवश्यकता होती है।

## मौजूदा तंत्र के लाभ:

- ⊃ विकास को बढ़ावा:
  - यह वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा और भारतीय रुपए के प्रति
     वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करेगा।
- ⊃ स्वीकृत देशों के साथ व्यापार:
  - जब से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, भुगतान की समस्या के कारण रूस के साथ व्यापार लगभग ठप है।
    - प्रिणामस्वरूप रूस के साथ भुगतान संबंधी मुद्दे को हल करना आसान हो गया है।
- विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव:
  - इस कदम से विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी कम होगा, विशेष रूप से यूरो-रुपया सममूल्यता को देखते हुए।
- 🔾 रुपए की गिरावट पर नियंत्रण:
  - इस तंत्र का उद्देश्य रुपए में लगातार गिरावट के दौरान व्यापार प्रवाह हेतु रुपए में निपटान को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा की मांग को कम करना है।

# भारत का रक्षा निर्यात

## चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2021-22 के लिये भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ रुपए अनुमानित था जो अब तक का सबसे अधिक है।

 अमेरिका एक प्रमुख खरीदार था साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र भी शामिल थे।

## प्रमुख बिंदु

- निजी क्षेत्र का निर्यात में 70% हिस्सा था, जबिक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्म बाकी के लिये जिम्मेदार थी।
  - पहले निजी क्षेत्र का 90% हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का हिस्सा बढ़ गया।
- जबिक हाल के वर्षों में अमेरिका से भारत का रक्षा आयात काफी बढ़ गया है, भारतीय कंपिन तेज़ी से अमेरिकी रक्षा कंपिनयों की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रही हैं।

#### भारत का रक्षा निर्यात:

- रक्षा उत्पादन में आत्मिनर्भरता प्राप्त करने के लिये रक्षा निर्यात सरकार के अभियान का प्रमुख स्तंभ है।
- 30 से अधिक भारतीय रक्षा कंपनियों ने इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्राँस, नेपाल, मॉरीशस, श्रीलंका, इजरायल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन जैसे देशों को हथियारों और उपकरणों का निर्यात किया है।
- निर्यात में व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली, इंजीनियरिंग यांत्रिक उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स सूट, रेडियो सिस्टम तथा रडार सिस्टम शामिल हैं।
- हालाँिक भारत का रक्षा निर्यात अभी भी अपेक्षित सीमा तक नहीं पहुँच पाया है।
  - स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 2015-2019 के लिये प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में भारत को 23वें स्थान पर रखा।
  - भारत अभी भी वैश्विक हथियारों का केवल 0.17% हिस्सा ही निर्यात करता है।
- भारत के रक्षा निर्यात में निराशाजनक प्रदर्शन का कारण यह है कि
   भारत के रक्षा मंत्रालय के पास अब तक निर्यात के लिये कोई
   समर्पित एजेंसी नहीं है।
- भारत ने 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।

## रक्षा क्षेत्र से संबंधित पहल:

- रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति 2020 (DPEPP 2020):
  - DPEPP 2020 को आत्मिनर्भरता और निर्यात के लिये देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर एक केंद्रित संरचित एवं महत्त्वपूर्ण रूप से बल प्रदान करने के लिये व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- आत्मिनर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में बहुआयामी कदम:
  - निजी उद्योग को सशक्त बनाने के लिये फोकस के साथ प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं।
  - डीपीपी 2016 भारतीय आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) नामक एक नई श्रेणी के साथ सामने आया है।
  - यदि कोई भारतीय कंपनी भारतीय आईडीडीएम का विकल्प चुनती है तो उसे अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता दी जाती है।

- रणनीतिक साझेदारी:
  - एक रणनीतिक साझेदारी मॉडल भारतीय कंपनियों को विदेशी ओईएम के साथ सहयोग और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने तथा भारत के निर्माण और भारत में परियोजनाओं को बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है।
  - 💠 कामकाज में पारंपरिक पनडुब्बियों के लिये पहला आरएफपी।
- सकारात्मक स्वदेशीकरणः
  - पहली बार सरकार किसी वस्तु के आयात पर खुद पर प्रतिबंध लगा रही है, सरकार स्वदेशी उद्योग को सशक्त बनाना चाहती है।
  - 4 101 वस्तुओं तथा 108 वस्तुओं की दो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ हैं जिसकी रेंज प्लेटफार्मों से लेकर हथियार प्रणालियों तक तथा सेंसर से लेकर अधिकतम वस्तुओं तक हैं।

# लघु बचत योजनाएँ

#### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने मुद्रास्फीति के ऊँचे स्तर के कारण वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही के लिये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate- NSC) और सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund-PPF) सहित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है।

## लघु बचत योजनाएँ/उपकरणः

- 그 परिचय:
  - ये भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं और इसमें 12 उपकरण/
     प्रपत्र (Instrument) शामिल हैं।
  - इसमें जमाकर्त्ताओं को उनके धन पर सुनिश्चित ब्याज मिलता
     है।
  - सभी लघु बचत प्रपत्रों से संग्रहीत राशि को राष्ट्रीय लघु बचत
     कोष (NSSF) में जमा किया जाता है।
  - कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी घाटे में वृद्धि की वजह से उधार की उच्च आवश्यकता को पूरा करने के लिये छोटी बचतें सरकारी घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं।
- वर्गीकरण: लघु बचत उपकरणों को तीन प्रमुख भागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - डाक जमा: इसमें बचत खाता, आवर्ती जमा, अलग-अलग परिपक्वता की साविध जमा और मासिक आय योजना शामिल है।

- ♦ बचत प्रमाणपत्र: राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP)।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजिनक भविष्य निधि (PPF) और विरिष्ठ नागिरक बचत योजना (SCSS)।
- 🔾 दरों का निर्धारण:
  - छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर निर्धारित किया जाता है जो कि समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉण्डों में संचलन के अनुरूप होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दरों की समीक्षा की जाती है।
  - लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ सिमिति (2010)
     ने छोटी बचत योजनाओं के लिये बाजार संबद्ध ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था।

# विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी

#### चर्चा में क्यों?

विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से लगातार धन की निकासी कर रहे हैं। जून 2022 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगभग 50,203 हजार करोड़ रुपए के शेयर बेचे जो मार्च 2020 (जब देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी) से अब तक निकासी का सबसे उच्च स्तर है।

## विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकः

- परिचय:
  - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो अपनी घरेलू सीमा के बाहर के बाजारों में निवेश करते हैं।
    - म्प FPI के उदाहरणों में स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (ADR), और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (GDR) शामिल हैं।
  - FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसे भुगतान संतुलन (BOP) पर दर्शाया जाता है
    - भगतान संतुलन (Balance Of Payment-BoP) का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है, जो एक निश्चित अविध के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है।
  - वे आमतौर पर सिक्रय शेयरधारक नहीं होते हैं और उन कंपिनयों
     पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं जिनके शेयर उनके पास हैं।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वर्ष 2014
   के पूर्ववर्ती FPI विनियमों की जगह नया FPI विनियम,
   2019 लागू किया।
- FPI को अक्सर "हॉट मनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एफपीआई अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिये यह FDI की तुलना में अधिक जोखिम भरा है।
- ⇒ FPI का महत्त्व:
  - अंतर्राष्ट्रीय ऋण तक पहुँच:
    - निवेशक विदेशों में ऋण की बढ़ी हुई राशि तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे निवेशक अधिक लाभ और अपने इक्विटी निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
  - यह घरेलू पूंजी बाजारों की तरलता को बढ़ाता है:
    - जैसे-जैसे बाजार में तरलता बढ़ती जाती हैं, बाजार अधिक गहन और व्यापक होते जाते हैं, फलस्वरूप अधिक व्यापक श्रेणी के निवेशों को वित्तपोषित किया जा सकता है।
    - म नतीजतन निवेशक यह जानकर विश्वास के साथ निवेश कर सकते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो वे अपने पोर्टफोलियो का शीघ्र प्रबंधन कर सकते हैं या अपनी वित्तीय प्रतिभृतियों को बेच सकते हैं।
  - यह इिक्वटी बाजारों के विकास को बढावा देता है:
    - वित्तपोषण के लिये बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा बेहतर प्रदर्शन, संभावनाओं और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करती है।
    - जैसे-जैसे बाजार की तरलता और कार्यक्षमता विकसित होती है, इक्विटी की कीमतें निवेशकों के लिये उचित व प्रासंगिक बन जाती हैं, अंतत: ये बाजार की दक्षता को बढ़ावा देती हैं।

#### भारत में FPI:

- एफपीआई भारतीय बाजार में सबसे बड़े गैर-प्रवर्तक शेयरधारक हैं और उनके निवेश निर्णयों का शेयर की कीमतों व बाजार की समग्र दिशा पर भारी असर पड़ता है।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपिनयों में FPI (मूल्य के संदर्भ में) की होल्डिंग 31 मार्च, 2022 को99 लाख करोड़ रुपए थी, जो अक्तूबर 2021 से निरंतर बिकवाली के कारण 31 दिसंबर, 2021 के 53.80 लाख करोड़ रुपए से 3.36% की कम थी।
- एफपीआई की निजी बैंकों, टेक कंपनियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बडी कंपनियों में हिस्सेदारी है।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) से उपलब्ध ऑंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में मई 2022 तक57 लाख करोड़ रुपए के FPI निवेश का एक बड़ा हिस्सा है, इसके बाद मॉरीशस में 5.24 लाख करोड़ रुपए, सिंगापुर में 4.25 लाख करोड़ रुपए और लक्जमबर्ग में 3.58 लाख करोड़ रुपए है।

# वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो

#### चर्चा में क्यों?

कैबिनेट नियुक्ति सिमिति (ACC) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की स्थापना के लिये एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया है।

नए ढाँचे का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया गया था।

## वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरोः

- 그 परिचय:
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपिनयों के प्रमुखों का चयन करेगा।
- FSIB के पास दिशा-निर्देश जारी करने और राज्य द्वारा संचालित गैर-जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के महाप्रबंधकों तथा निदेशकों का चयन करने का स्पष्ट अधिदेश होगा।
  - FSIB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये सिफारिशें करने वाली एकल इकाई होगी।
- वित्तीय सेवा विभाग पहले राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 (संशोधित) में आवश्यक संशोधन करेगा।
- FSIB के अध्यक्ष: ACC ने FSIB के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में दो साल के लिये भानु प्रताप शर्मा की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है। वह BBB के पूर्व अध्यक्ष भी हैं।

## सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ( PSB ):

- यह एक ऐसा बैंक है जिसमें सरकार के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा होता है।
  - उदाहरण के लिये भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 60% है।

### वित्तीय संस्थान ( FI ):

 एक वित्तीय संस्थान वित्तीय और मौद्रिक लेन-देन से संबंधित कंपनी
 के लिये एक अंब्रेला टर्म है, जिसमें ऋण, जमा और/या निवेश शामिल हैं।

- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFI) विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता हैं।
- उदाहरण:
  - प्राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NBFID)
  - भारतीय निर्यात-आयात बेंक (EXIM Bank)
  - 🗷 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
  - चेशनल हाउसिंग बैंक (NHB)
  - 🗷 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

### बैंक बोर्ड ब्यूरो ( BBB ):

- 🗅 पृष्ठभूमि:
  - देश के बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिये वर्ष 2014 में पी.जे. नायक की सिफारिशों के आधार पर बैंक बोर्ड ब्युरो (BBB) का गठन किया गया था।
- 🥽 गठन:
  - सरकार ने वर्ष 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks- PSBs) और वित्तीय संस्थाओं (Financial Institution- FI) के निदेशक मंडल (पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष) की नियुक्ति हेतु सिफारिशें करने के लिये BBB के गठन को मंजूरी दी।
    - BBB एक एक स्वायत्त संस्तुतिकर्त्ता संस्था के रूप में
      कार्य करती है।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित बैंक बोर्ड
     ब्युरो एक सार्वजनिक प्राधिकरण था।
  - वित्त मंत्रालय के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।

#### 🗅 कार्य:

- सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के लिये किम्यों की सिफारिश करने के अलावा ब्यूरों को सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपिनयों में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु किम्यों की सिफारिश करने का काम भी सौंपा गया था।
- इसे सभी PSB के निदेशक मंडल के साथ जुड़ने का काम भी सौंपा गया था ताकि उनके वृद्धि और विकास के लिये उपयुक्त रणनीति तैयार की जा सके।

#### 🗅 चुनौतियाँ:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सामान्य बीमा कंपनियों के निदेशकों का चयन करने के लिये BBB की शक्ति को रद्द कर दिया था और सरकार ने BBB द्वारा चुने गए तत्कालीन सेवारत निदेशकों की सभी नियुक्तियों को रद्द करके पहले ही फैसले को लागू कर दिया था।

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में फैसला सुनाया कि BBB राज्य द्वारा संचालित सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन नहीं कर सकता क्योंकि यह एक सक्षम निकाय नहीं था।
  - न्यू इंडिया एश्योरेंस, देश का सबसे बड़ा सामान्य बीमाकर्ता है, लगभग 100 दिनों से नियमित रूप से CMD के बिना काम कर रहा है।
  - 🛘 कृषि बीमा कंपनी में CMD का पद भी खाली हो गया।

## राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021

#### चर्चा में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किये गए।

इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) रैंकिंग जारी की गई, जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) रिपोर्ट, 2020 पर आधारित है।

#### राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग:

- 🗅 परिचय:
  - भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल में नवाचार को बढ़ावा देने और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने के लिये देश में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतिरक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है।
  - यह अभ्यास देश में स्टार्टअप के लिये कारोबारी माहौल को आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ⊃ उद्देश्य:
  - स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिये राज्यों/केंद्रशासित
     प्रदेशों द्वारा की गई प्रगित को सामने लाने में मदद करना।
  - प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों
     को सिक्रय रूप से काम करने के लिये प्रेरित करना।
  - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अच्छे अभ्यासों की पहचान करना,
     सीखने और दोहराने के लिये सुविधा प्रदान करना।
- वर्गीकरण: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है,
  - सर्वश्रेष्ठ कलाकार
  - शीर्ष प्रदर्शक
  - 💠 नेता

- आकांक्षी नेता
- उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र।

रैंकिंग 2021 के बारे:

- 🗅 🏻 7 व्यापक सुधार क्षेत्र:
  - प्रतिभागियों का मूल्यांकन 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों में किया गया,
     जिसमें 26 कार्य बिंदु शामिल थे।
    - संस्थागत सहयोग
    - 🗷 नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
    - 🗷 बाजार तक पहुँच
    - इनक्युबेशन सहयोग
    - वित्तीय सहयोग
    - प्र सक्षमकर्ताओं के क्षमता निर्माण के लिये मेंटरशिप सहयोग।
- 🗅 परिणाम:
  - गुजरात और कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्त्ता के रूप में उभरे हैं।
    - केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है।
  - केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना ने राज्यों की श्रेणी में शीर्ष कलाकार का पुरस्कार जीता।
    - केंद्रशासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जम्मू और कश्मीर शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता के रूप में दिखाई दिया।



#### संबंधित पहल:

- 🔾 डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क
- फिशरीज़ स्टार्टअप ग्रैंड
- 🔾 स्टार्टअप इंडिया फंड
- 🔾 स्टार्टअप्स के लिये नीतिगत सुधार
- 🗅 स्टार्ट-अप सेल

- 🔾 राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद
- आत्मिनभर भारत उदय-अटल न्यू इंडिया चैलेंज
- ⊃ एआईएम-आईसीआरईएसटी

# उद्यम और सेवा केंद्रों का विकास विधेयक

### चर्चा में क्यों?

सरकार की योजना संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास (DESH) विधेयक को पेश करने की है।

#### DESH विधेयकः

- यह वर्ष 2005 के मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कानून में बदलाव करेगा, जिसका उद्देश्य SEZ में रुचि को पुनर्जीवित करना और अधिक समावेशी आर्थिक केंद्रों को विकसित करना है।
- SEZ को नया रूप दिया जाएगा और विकास केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा तथा ये उन कई कानूनों से मुक्त होंगे जो वर्तमान में उन्हें प्रतिबंधित करते हैं। ये हब घरेलू टैरिफ क्षेत्र एवं SEZ की दोहरी भूमिका निभाते हुए निर्यात-उन्मुख व घरेलू निवेश दोनों की सुविधा प्रदान करेंगे।
- सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर समतुल्य लेवी (Equalisation Levy) लगा सकती है तािक करों को बाहर की इकाइयों द्वारा प्रदान किये गए करों के बराबर लाया जा सके।

## वर्तमान SEZ अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता:

- WTO की विवाद समाधान सिमित ने निर्णय दिया है कि SEZ योजना सिहत भारत की निर्यात-संबंधित योजनाएँ, WTO के नियमों के साथ असंगत थीं क्योंिक वे सीधे कर लाभ को निर्यात से जोडती थीं।
- देशों को सीधे निर्यात सिब्सिडी देने की अनुमित नहीं है क्योंिक यह
   बाजार की कीमतों को विकृत कर सकता है।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर की शुरुआत और कर छूट को हटाने के लिये
   एक सनसेट क्लॉज के बाद SEZ में गिरावट शुरू हो गई।
  - SEZ इकाइयों को पहले पाँच वर्षों के लिये निर्यात आय पर 100% आयकर छूट प्रदान की जाती है, फिर अगले पाँच वर्षों के लिये 50% आयकर छूट, और उसके बाद पाँच वर्षों के लिये 50% निर्यात लाभ मिलता है।

## अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस

#### चर्चा में क्यों?

हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है, इसका आयोजन विश्व भर में MSME के महत्त्व को उजागर करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये किया जाता है।

इससे पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सस्टेनेबल (जेड-जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट) प्रमाणन योजना शुरू की गई है।

## प्रमुख बिंदु

- 🕽 इतिहास:
  - अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया।
  - मई 2017 में 'एनहेनसिंग नेशनल केपेसिटीज फॉर अनलेशिंग फुल पोटेंशियल्स ऑफ एमएसएमई इन अचीविंग द एसडीजीज इन डेवलिंग कंट्रीज' (Enhancing National Capacities for Unleashing Full Potentials of MSMEs in Achieving the SDGs in Developing Countries') नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया।
  - इसे संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कोष (United Nations Peace and Development Fund) के सतत् विकास उप-निधि के लिये 2030 एजेंडा द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- वर्ष 2022 के लिये थीम: 'लचीलापन और पुनर्निर्माण: सतत् विकास के लिये एमएसएमई' (Resilience and Rebuilding: MSMEs for Sustainable Development)।
  - थीम मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डालती है कि किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम एक आवश्यक घटक हैं।
- 🗅 उद्देश्य:
  - विश्व MSME दिवस 2022 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में MSMEs की क्षमता और उनकी भूमिका को मान्यता प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य विश्व आर्थिक विकास और सतत् विकास में MSMEs के योगदान के बारे में सार्वजिनक जागरूकता बढाना भी है।

#### 🗅 महत्व:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, औपचारिक और अनौपचारिक सभी फर्मों में MSMEs की भागीदारी 90% से अधिक है तथा कुल रोजगार में औसतन 70% एवं सकल घरेलू उत्पाद में 50% हिस्सेदारी है। देश की अर्थव्यवस्था में इतने महत्त्वपूर्ण योगदान के साथ MSMEs रोजगार- सृजन, नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि के लिये आवश्यक हैं।
- हालाँिक रोजगार सृजन में एक प्रमुख भूमिका होने के बावजूद दुनिया भर में MSMEs को सरकारों और प्रशासन से समर्थन की कमी के अलावा काम करने की स्थिति, उत्पादकता तथा अनौपचारिकता में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- विश्व MSME दिवस ऐसे उद्यमों के क्षमता विस्तार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु इसका उपयोग बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।

## सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम:

- 🗅 परिचय:
  - सूक्ष्म-लघु और मध्यम आकार के उद्यम ऐसे संगठन हैं जो आमतौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार नहीं देते हैं, हालाँकि वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र दो-तिहाई से अधिक रोजगार सजन करने के लिये जिम्मेदार हैं।

Revised MSME Classification			
Composite Criteria: Investment and Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment < Rs 1 cr and Turnover < Rs 5 cr	Investment < Rs 10 cr and Turnover < Rs 50 cr	Investment < Rs 20 cr and Turnover < Rs 100 cr

- 🗅 भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME की भूमिका:
  - वे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गित प्रदान करते हैं, देश
     के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30% का
     योगदान देते हैं।
  - निर्यात के संदर्भ में वे आपूर्ति शृंखला का एक अभिन्न अंग हैं और कुल निर्यात में लगभग 48% का योगदान करते हैं।
  - MSME रोज़गार सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार देते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि MSME ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आधे से अधिक MSME ग्रामीण भारत में कार्यरत हैं।

#### MSME क्षेत्र से संबंधित पहलें:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, ग्राम एवं जूट उद्योगों सिहत MSME क्षेत्र के वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत MSME क्षेत्र की कल्पना करता है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को वर्ष 2006 में MSME को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये अधिसूचित किया गया था।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपिरक उद्योगों के उत्थान के लिये निधि की योजना (SFURTI): इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपिरक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाजार पिरदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- ⇒ नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढावा देती है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी एमएसएमई को उनकी वैधता की अविध के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील साविध ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSME को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP): इसका उद्देश्य MSME की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढाना है।
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सिंब्सडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS): इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सिंब्सडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।

- CHAMPIONS पोर्टल: इसका उद्देश्य भारतीय MSME को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
- MSME समाधान: यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: यह नया पोर्टल देश में MSME की संख्या पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है।
- एमएसएमई संबंध: यह एक सार्वजिनक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजिनक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSME से सार्वजिनक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये शुरू किया गया था।

# पार्टिसिपेटरी नोट्स

#### चर्चा में क्यों?

पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के माध्यम से मई के अंत, 2022 तक भारतीय पूंजी बाजार में निवेश घटकर 86,706 करोड़ रुपए रह गया है।

- हालाँकि अनुमानतः आने वाली 1-2 तिमाहियों में विदेशी निवेशक अपना बिकवाली का रुख बदलेंगे और देश के शेयरों में वापसी करेंगे।
- पी-नोट निवेश में गिरावट के अनुरूप विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के अंतर्गत परिसंपत्तियाँ मई, 2022 के अंत में 50.74 ट्रिलियन रुपए (जो अप्रैल, 2022 के अंत में थी) से 5% घटकर 48.23 ट्रिलियन रुपए हो गईं।
  - FPI द्वारा इक्विटी से शुद्ध निकासी का यह लगातार आठवाँ महीना था।

### पार्टिसिपेटरी नोट्सः

- पी-नोट्स विदेशी निवेशकों को पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा जारी किये गए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ODI) हैं जो सीधे खुद को पंजीकृत किये बिना भारतीय शेयर बाजारों का हिस्सा बनना चाहते हैं।
  - पी-नोट्स में भारतीय स्टॉक उनकी अंतर्निहित संपत्ति के रूप में होते हैं।
  - FPI अनिवासी हैं जो भारतीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, सरकारी बॉण्ड, कॉरपोरेट बॉण्ड आदि में निवेश करते हैं।
- हालाँिक पी-नोट धारकों के लिये सरल पंजीकरण आवश्यकताएँ हैं, उन्हें भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (SEBI) की उचित त्वरित प्रक्रिया से गुजरना होगा।

#### पी-नोट्स में कमी के कारण:

- मुद्रास्फीति के स्तर में अनिश्चितता:
  - मुद्रास्फीति के स्तर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed's)
     की कार्रवाइयों को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।.
  - पी-नोट्स में गिरावट का श्रेय यूएस फेड द्वारा मौद्रिक नीति को कड़ा करने के कारण को दिया जा रहा है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये दरों में बढ़ोतरी कर रहा है।
    - प्रिटेन और यूरोजोन सिहत अन्य केंद्रीय बैंक भी इसका अनुसरण कर रहे हैं।
- ⊃ मुद्रा/करेंसी में सुधार:
  - करेंसी की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है।
    - एक सुधार एक मूल्य प्रतिक्षेप है जिसे प्रत्येक प्रवृत्ति आवेग के बाद देखा जा सकता है। सुधार होने के बाद, मूल्य अपनी प्रवृत्ति पर वापस आ जाता है। वर्तमान समय में उपकरणों की अधिक बिक्री या अधिक खरीद के कारण मुद्रा बाजार में सुधार होता है।
    - इस कमी का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी और डेबिट पोर्टफोलियो में बाजार सुधार को लेकर है।

# भुगतान विज़न 2025: आरबीआई

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तीव्र, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से "भुगतान विजन 2025" (Payment Vision 2025) प्रस्तुत किया गया है।

## प्रमुख बिंदु

## भुगतान विज़न 2025:

- भुगतान विज्ञन 2025 के बारे में:
  - भुगतान विज्ञन 2025 को आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिये बोर्ड के मार्गदर्शन से तैयार किया गया है।
  - 💠 यह भुगतान विज्ञन 2019-21 की पहल पर आधारित है।
  - भुगतान विज्ञन 2025 दस्तावेज को समग्रता, समावेश, नवाचार, संस्थागतकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के पाँच प्रमुख लक्ष्य पदों पर प्रस्तुत किया गया है।
- 🔾 थीम: ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम (4E)।

#### 🗅 उद्देश्य:

- किसी भी समय और कहीं भी सुविधा के साथ सुलभ भुगतान विकल्पों के साथ उपयोगकर्त्ताओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भगतान प्रणाली को उन्नत करने में सहायक।
- क्लोज्ड सिस्टम PPIs सिहत प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (Prepaid Payment Instruments- PPIs) के लिये डिजिटल भुगतान अवसंरचना तथा लेन-देन और पुनरीक्षण दिशा-निर्देशों की जियोटैगिंग को सक्षम करने के लिये।
- भुगतान पारिस्थितिको तंत्र में सभी महत्त्वपूर्ण बिचौलियों को विनियमित करना तथा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग उत्पादों के क्रेडिट घटकों को यूपीआई से जोड़ना।
- एक राष्ट्र एक ग्रिड समाशोधन और निपटान पिरप्रेक्ष्य सिहत चेक ट्रंगकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System-CTS) में वृद्धि लाने के लिये तथा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन व्यापारी भुगतान को संसाधित करने हेतु एक भुगतान प्रणाली निर्मित करना।
- ♦ भुगतान क्षेत्र में बिगटेक (BigTechs) और फिनटेक (FinTechs) का विनियमन।
- बुक नाउ पे लेटर (Book Now Pay Later-BNPL) विधियों की जाँच और BNPL से जुड़े भुगतानों पर उचित दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना।
- 🔾 प्राप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्य:
  - चेक-आधारित भुगतानों की मात्रा कुल खुदरा भुगतान के
     0.25% से कम होनी चाहिये।
  - 💠 डिजिटल भुगतान लेन-देन की संख्या को तीन गुना करना।
  - UPI 50% की औसत वार्षिक वृद्धि और IMPS/NEFT
     20% की वृद्धि दर्ज करे।
  - भुगतान लेन-देन टर्नओवर को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बढ़ाकर 8% करना।
  - ♦ PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) पर डेबिट कार्ड लेनदेन में 20% की वृद्धि।
  - मूल्य के संदर्भ में क्रेडिट कार्ड से आगे निकलने के लिये डेबिट कार्ड का उपयोग।
  - PPI लेनदेन में 150% की वृद्धि।
  - कार्ड स्वीकार करने का बुनियादी ढाँचा 250 लाख तक बढ़ाया जाएगा।
  - मोबाइल आधारित लेनदेन के लिये पंजीकृत ग्राहक आधार में 50% CAGR की वृद्धि।

 GDP के प्रतिशत के रूप में कैश इन सर्कुलेशन (CIC) में कमी।

## सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना

#### चर्चा में क्यों?

भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से 2022-23 के लिये सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) किश्तों में जारी करेगी।

SGB में निवेश कोविड-प्रभावित वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा क्योंकि निवेशकों ने 2020-21 और 2021-22 के साथ इक्विटी बाजारों में अस्थिरता के बीच सुरक्षित विकल्पों की तलाश की, जो नवंबर 2015 में योजना की स्थापना के बाद से बॉण्ड की कुल बिक्री का लगभग 75% हिस्सा था।

#### सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजनाः

- 🗅 शुरुआत:
  - सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से (जिसका उपयोग स्वर्ण की खरीद के लिये किया जाता है) को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से नवंबर, 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond) योजना की शुरुआत की थी।
- निर्गमन:
  - गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड सरकारी प्रतिभूति (GS) अधिनियम, 2006
     के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किये जाते हैं।
  - ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।
  - बॉण्ड की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों (जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिये या तो सीधे अथवा एजेंटों के माध्यम से की जाती है।
- पात्रताः इन बॉण्डों की बिक्री निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), न्यासों/ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों तक ही सीमित है।
- ⊃ विशेषताएँ:
  - विमोचन मूल्यः गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड की कीमत इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (India Bullion and Jewellers Association- IBJA) द्वारा १९९१ शुद्धता वाले सोने (24 कैरट) के लिये प्रकाशित मूल्य पर आधारित होती है।

- निवंश सीमा: गोल्ड बॉण्ड एक ग्राम यूनिट के गुणकों में खरीदे जा सकते हैं जिसमें विभिन्न निवंशकों के लिये एक निश्चित सीमा निर्धारित होती है।
  - म् खुदरा (व्यक्तिगत) तथा हिंदू अविभाजित परिवारों (Hindu Undivided Families- HUFs) के लिये खरीद की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम है। ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये प्रति वित्त वर्ष 20 किलोग्राम की अधिकतम सीमा लागू होती है।
  - संयुक्त धारिता के मामले में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होती है।
  - 🗷 न्यूनतम स्वीकार्य निवेश सीमा 1 ग्राम सोना है।
- अविध: इन बॉण्डों की पिरपक्वता अविध 8 वर्ष होती है तथा 5 वर्ष के बाद इस निवेश से बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध होता है।
- ब्याज दर: निवंशकों को प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर लागू होती है, जो छह माह पर देय होती है।
  - गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर/टैक्स आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार अदा करना होगा।

#### **)** लाभ:

- ऋण के लिये बॉण्ड का उपयोग संपार्श्विक (जमानत या गारंटी)
   के रूप में किया जा सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है।
  - विमोचन (Redemption) का तात्पर्य एक जारीकर्त्ता द्वारा परिपक्वता पर या उससे पहले बॉण्ड की पुनर्खरीद के कार्य से है।
  - पूंजीगत लाभ (Capital Gain) स्टॉक, बॉण्ड या अचल संपत्ति जैसी संपत्ति की बिक्री पर अर्जित लाभ है। यह तब प्राप्त होता है जब किसी संपत्ति का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो जाता है।
- SGB में निवेश के नुकसान:
  - यह भौतिक स्वर्ण (जिसे तुरंत बेचा जा सकता है) के विपरीत
     एक दीर्घकालिक निवेश है।
  - सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं लेकिन इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, इसलिये परिपक्वता से पहले बाहर निकलना मुश्किल होगा।

## PACS का डिजिटलीकरण

#### चर्चा में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies-PACS) के डिजिटलीकरण की मंज़्री दी।

2,516 करोड़ रुपए की लागत से PACS का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे लगभग 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। प्रत्येक प्राथमिक कृषि ऋण सिमिति को अपनी क्षमता को उन्नत करने के लिये लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे और यहाँ तक कि पुराने लेखा रिकॉर्ड को भी डिजिटल किया जाएगा और क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा।

#### पहल का महत्त्वः

- PACS के कम्प्यूटरीकरण से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता में वृद्धि होगी एवं बहुउद्देशीय PACS के लेखांकन में भी सुविधा होगी।
- यह PACS को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ब्याज सहायता योजना (ISS), फसल बीमा योजना (PMFBY) और उर्वरक एवं बीज के आदानों जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक नोडल केंद्र बनने में भी मदद करेगा।
- इस पहल से प्रत्येक केंद्र में लगभग 10 नौकिरयों के अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी और इसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में PACS की संख्या को बढ़ाकर 3 लाख करना है।

## प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ:

- 🗅 परिचय:
  - PACS जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिये अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं।
  - यह जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर काम करती हैं।
  - पहली प्राथमिक कृषि ऋण सिमिति (PACS) का गठन वर्ष 1904 में किया गया था।
  - सहकारी बैंकिंग प्रणाली के आधार पर कार्यरत PACS ग्रामीण क्षेत्र को लघु अविध और मध्यम अविध के ऋण के प्रमुख खुदरा बिक्री केंद्रों का गठन करती हैं।
- ⊃ उद्देश्य:
  - ऋण लेने और सदस्यों की आवश्यक गतिविधियों का समर्थन करने के उद्देश्य से पूंजी जुटाना।

- सदस्यों की बचत की आदत में सुधार लाने के उद्देश्य से जमा राशि एकत्र करना।
- सदस्यों को उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं की आपूर्ति करना।
- सदस्यों के लिये पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति एवं विकास की व्यवस्था करना।
- सदस्यों के लिये पशुधन की उन्नत नस्लों की आपूर्ति एवं उनके विकास की व्यवस्था करना।
- आवश्यक आदानों और सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से विभिन्न आय-सुजन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

#### PACS का महत्त्वः

- ये बहुआयामी संगठन हैं जो बैंकिंग, साइट पर आपूर्ति, विपणन, उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- ये वित्त प्रदान करने के लिये मिनी-बैंकों के साथ-साथ कृषि इनपुट और उपभोक्ता सामान प्रदान करने हेतु काउंटर के रूप में कार्य करते हैं।
- ये सिमितियाँ किसानों को अपने खाद्यान्नों के संरक्षण और भंडारण हेतु भंडारण सेवाएँ भी प्रदान करती हैं।
- ⇒ देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिये गए किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card- KCC) ऋणों में PACS का 41% (3.01 करोड़ किसान) हिस्सा है तथा PACS के माध्यम से इन KCC ऋणों में से 95% (2.95 करोड़ किसान) छोटे और सीमांत किसानों के हैं।

## सहकारी बैंक

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मामलों और सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय संघ (NAFCUB) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया है, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिये आवश्यक सुधारों पर जोर दिया गया है।

NAFCUB देश में शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड का एक शीर्ष स्तर का निकाय है। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण की गित को बढ़ावा देना और क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है।

## सहकारी बैंक:

- परिचय:
  - यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिये सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना

शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है।

- ये सहकारी ऋण सिमितियाँ हैं जहाँ एक समुदाय समूह के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी सिमिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी सिमिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।
- सहकारी बैंक निम्न द्वारा शासित होते हैं:
  - д बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
  - 🗷 बैंकिंग कानून (सहकारी समिति) अधिनियम, 1955
- वे प्रमुख रूप से शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभाजित हैं।

#### विशेषताएँ:

- ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएँ: सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं।
- लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण: इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। सदस्यों के पास आमतौर पर "एक व्यक्ति, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत के अनुसार समान मतदान अधिकार होते हैं।
- लाभ आवंटन: वार्षिक लाभ, लाभ या अधिशेष का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर आरक्षित करने के लिये आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी और वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है।
- वित्तीय समावेशन: उन्होंने बैंक रहित ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं।
- ⇒ शहरी सहकारी बैंक (UCB):
  - शहरी सहकारी बैंक (UCB) शब्द औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संदर्भित करता है।
  - शहरी सहकारी बैंक (UCB), प्राथमिक कृषि ऋण सिमितियाँ (PACS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (LAB) स्थानीय क्षेत्रों में काम करते हैं इसिलये इन्हें अलग-अलग बैंक माना जा सकता है।
  - वर्ष 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये
     धन उधार देने की अनुमित थी।
  - पारंपिरक रूप से UCBs का कार्य छोटे समुदायों, क्षेत्र के कार्य समूहों तक केंद्रित थे और इनका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों

को धन उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। आज उनके संचालन का दायरा काफी व्यापक हो गया है।

## ज़मानती बॉण्ड

### चर्चा में क्यों?

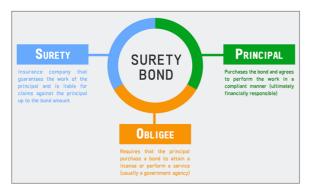
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) को सामान्य बीमाकर्ताओं के परामर्श से जमानती बॉण्ड पर एक मॉडल उत्पाद विकसित करने के लिये कहा है।

- ⇒ कई चुनौतीपूर्ण मुद्दों ने बीमाकर्त्ताओं के साथ जमानती बॉण्ड को पूरी तरह से गैर-स्टार्टर बना दिया है और IRDAI को प्रस्तावित किया गया है कि इसे एक मॉडल उत्पाद तैयार करना चाहिये।
- भारतीय अनुबंध अधिनियम के साथ-साथ दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) में परिवर्तन के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया ताकि डिफाल्ट के मामले में उनके लिये उपलब्ध सबूतों के संदर्भ में जमानती बॉण्ड बैंक गारंटी के समान स्तर पर हों, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

#### ज़मानती बॉण्डः

- परिचय:
  - किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिये एक लिखित समझौते के रूप में एक जमानती बॉण्ड को अपने सरल रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
  - यह एक अद्वितीयक प्रकार का बीमा है क्योंिक इसमें तीन-पक्षीय समझौता शामिल है। एक जमानत समझौते में तीन पक्ष होते हैं:
    - मुख्य पक्ष- वह पक्ष जो बॉण्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है।
    - जमानत पक्ष- दायित्व की गारंटी देने वाली बीमा कंपनी या जमानत कंपनी का प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो जमानत पक्ष निरंतर नुकसान के लिये संविदात्मक रूप से उत्तरदायी है।
  - ओिब्लगी- जिस पार्टी की आवश्यकता होती है वह प्राय: जमानती बॉण्ड से लाभ प्राप्त करता है। अधिकांश जमानती बॉण्ड के लिये 'ओिब्लगी' एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है।
  - बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को जमानती
     बॉण्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना शुरू कर रही है।

- ⊃ उद्देश्य:
  - जमानती बॉण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह आपूर्तिकर्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके विकल्पों में विविधता लाने व बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में कार्य करता है।
- लाभ:
  - जमानती बॉण्ड लाभार्थी को उन कृत्यों या घटनाओं से बचाता
     है जो मुख्य पक्ष को अंतर्निहित दायित्वों से वंचित करते हैं।
  - वे निर्माण या सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपक्रमों तक विभिन्न दायित्वों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं।



### ज़मानती बॉण्ड से संबंधित मुद्देः

- एक नई अवधारणा के रूप में जमानती बॉण्ड काफी जोखिम भरा हो सकता है और भारत में बीमा कंपनियों को अभी तक ऐसे व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन में विशेषज्ञता हासिल नहीं हुई है।
- इसके अलावा मूल्य निर्धारण, डिफॉल्टिंग ठेकेदारों के विरुद्ध उपलब्ध सहायता और पुनर्बीमा विकल्पों पर कोई स्पष्टता नहीं है।
  - ये काफी महत्त्वपूर्ण विषय हैं और जमानत से संबंधित विशेषज्ञता एवं क्षमताओं के निर्माण में बाधा डाल सकते हैं तथा अंतत: बीमाकर्त्ताओं को इस व्यवसाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।

### अवसंरचना परियोजनाओं को किस प्रकार बढ़ावा देगा?

- ज्ञमानती अनुबंधों के लिये नियम बनाने के कदम से बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र को अधिक तरलता और वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- यह बड़े, मध्यम एवं छोटे ठेकेदारों के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।
- जमानती बीमा व्यवसाय, निर्माण परियोजनाओं के लिये बैंक गारंटी के विकल्प को विकसित करने में सहायता करेगा।
  - यह कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग को सक्षम करेगा और निर्माण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक की आवश्यकता को कम करेगा।

- जोखिम संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बीमाकर्त्ता वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे।
  - इसलिये यह जोखिम पहलुओं पर समझौता किये बिना बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में तरलता लाने में सहायता करेगा।

# आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21

### चर्चा में क्यों?

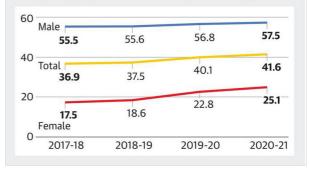
हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा 2020-21 के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जारी किया गया।

### PLFS के मुख्य बिंदु :

- ⊃ बेरोजगारी दर:
  - इससे पता चलता है कि बेरोजगारी दर वर्ष 2020-21 में गिरकर
     4.2% हो गई, जबिक वर्ष 2019-20 में यह दर 4.8% थी।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में 3.3% तथा शहरी क्षेत्रों में 6.7% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):
  - जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात् काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिये उपलब्ध) में व्यक्तियों का प्रतिशत पिछले वर्ष के 40.1% से बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान 41.6% हो गया।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):
  - 💠 यह पिछले वर्ष के 38.2% से बढ़कर 39.8% हो गया।
- 🔾 प्रवासन दर:
  - प्रवासन दर 28.9% है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रवास दर क्रमश: 48% और 47.8% थी।

# Looking for work | The labour force

participation rate (LFPR) has continued to improve further in 2020-21, according to the latest Periodic Labour Force Survey. The graph shows LFPR over years across genders



### अन्य प्रमुख बिंदु

- बेरोजगारी दर: बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- श्रम बल: करेंट वीकली स्टेटस (CWS) के अनुसार, श्रम बल का आशय सर्वेक्षण की तारीख से पहले एक सप्ताह में औसत नियोजित या बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या से है।
- CWS दृष्टिकोण: शहरी बेरोज्ञगारी PLFS, CWS के दृष्टिकोण पर आधारित है।
  - CWS के तहत एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है
     यदि उसने सप्ताह के दौरान किसी भी दिन एक घंटे के लिये भी
     काम नहीं किया, लेकिन इस अवधि के दौरान किसी भी दिन
     कम-से-कम एक घंटे के लिये काम की मांग की या काम
     उपलब्ध था।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

### आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ( PLFS ):

- अधिक नियत समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की शुरुआत की।
- ⊃ PLFS के मुख्य उद्देश्य हैं:
  - 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात् श्रमिक-जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना।
  - प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति
     (पीएस+एसएस) और CWS दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

# विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2022

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रबंधन विकास संस्थान (IMD) द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी किया गया।

- आईएमडी स्विट्रज्ञलैंड में स्थित एक स्विस फाउंडेशन है, जो अपने कॅरियर के प्रत्येक चरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिये समर्पित है।
- भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, जिसमें भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुँच गया है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है।

WHO STANDS WHERE		
2022	Country	2021
1 <	Denmark	<b>3</b>
2 <	Switzerland	0 1
3 <	Singapore	<b>5</b>
4 <	Sweden	<b>O</b> 2
5 <	Hong Kong	7
6 <	Netherlands	<b>O</b> 4
7 <	Taiwan, China	8
8 <	Finland	C 11
9 <	Norway	<b>6</b>
10 <	US	C 10
37 <	India	C 43
Source: IMD's World Competitiveness Index		

# विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2022:

- 🔾 परिचय:
  - आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक (WCY) पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई, यह एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्द्धा पर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है।
  - यह देशों का विश्लेषण और रैंक करता है कि वे दीर्घकालिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिये अपनी दक्षताओं का प्रबंधन कैसे करते हैं।
- कारक: यह चार कारकों (334 प्रतिस्पर्द्धात्मकता मानदंड) की जाँच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मापता है:
  - अार्थिक प्रदर्शन
  - सरकारी दक्षता
  - 💠 व्यापार दक्षता
  - 💠 आधारभूत संरचना

### सूचकांक की मुख्य विशेषताएँ:

- शीर्ष वैश्विक प्रदर्शक:
  - यूरोप: डेनमार्क पिछले साल के तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुँच गया है, जबिक स्विट्रजलैंड शीर्ष रैंकिंग से दूसरे स्थान पर खिसक गया है और सिंगापुर पाँचवें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है।

- एशिया: शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ सिंगापुर (3वीं), हॉन्गकॉन्ग (5वीं), ताइवान (7वीं), चीन (17वीं) और ऑस्ट्रेलिया (19वीं) हैं।
- अन्यः एकत्र किये गए डेटा की सीमित विश्वसनीयता के कारण इस वर्ष के संस्करण में रूस और यूक्रेन दोनों का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

#### भारत का प्रदर्शन:

- चार मानकों पर प्रदर्शन:
  - आर्थिक प्रदर्शन: यह वर्ष 2021ं के 37वें से सुधरकर वर्ष 2022 में 28वें स्थान पर पहुँच गया है।
  - सरकारी दक्षता: यह वर्ष 2021 के 46वें से वर्ष 2022 में 45वें स्थान पर पहुँच गया।
  - व्यावसायिक दक्षता: इसमें वर्ष 2021 के 32वें स्थान से वर्ष 2022 में 23वें स्थान पर एक बड़ा सुधार देखा गया।
  - आधारभूत संरचना: दूसरी ओर आधारभूत संरचना में पूर्व वर्ष के 49 वें स्थान में कोई बदलाव नहीं आया।
- भारत के अच्छे प्रदर्शन के कारण:
  - 🗷 वर्ष 2021 में पूर्वव्यापी करों के संदर्भ में प्रमुख सुधार।
  - ड्रोन, अंतरिक्ष और भू-स्थानिक मानचित्रण सहित कई क्षेत्रों का पुनः विनियमन।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में उल्लेखनीय स्थार।
  - भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये वैश्विक आंदोलन में एक प्रेरक शक्ति के रूप में तथा COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक नेट-जीरो की भारत की प्रतिबद्धता भी रैंकिंग में पर्यावरण से संबंधित प्रौद्योगिकियों में अपनी ताकत के अनुरूप है।
- भारत के समक्ष चुनौतियाँ:
  - भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें व्यापार व्यवधानों और ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन, महामारी के बाद उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बनाए रखना, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन, परिसंपत्ति मुद्रीकरण एवं बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये संसाधन जुटाना शामिल है।

#### भारत की शक्ति:

व्यापार के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्ष पाँच आकर्षक कारक हैं- एक कुशल कार्यबल, लागत प्रतिस्पर्द्धा, अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, उच्च शैक्षिक स्तर और खुला एवं सकारात्मक दृष्टिकोण।

# भारत द्वारा अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मका बढ़ाने हेतु हाल ही में उठाए गए कदम:

- विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की ओर: भारत ने विनिर्माण क्षमता में लचीलापन सुनिश्चित करने हेतु सराहनीय प्रयास किये हैं जैसे-आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल जो घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं तथा विनिर्माण केंद्रों में भारी निवेश के उद्देश्य से ही शुरू की गई हैं।
  - सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive Scheme-PLI)) योजना शुरू की है।
- तकनीकी उन्नित: बढ़ती प्रतिस्पर्द्धात्मक के लिये तकनीकी प्रगित की सुविधा हेतु भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) ने 6G तकनीक पर छह टास्क फोर्स का गठन किया है।
  - विदेश मंत्रालय अपने नए उभरते और सामिरक प्रौद्योगिकी (एनईएसटी) प्रभाग के माध्यम से प्रौद्योगिकी शासन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की सिक्रय भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहा है।
    - यह नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों के लिये मंत्रालय के भीतर नोडल डिवीजन के रूप में कार्य करता है तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी भागीदारों के सहयोग से सहायता करता है।

# क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ना

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमित देने का प्रस्ताव रखा है।

- क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा पूर्व-निर्धारित क्रेडिट सीमा के साथ जारी किया गया एक वित्तीय साधन है, जो कैशलेस लेन-देन में मदद करता है। यह कार्डधारकों को (अर्जित ऋण के आधार पर) व्यापारी से ली गई वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान हेतु सक्षम बनाता है।
- इसका उद्देश्य उपयोगकर्त्ताओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना और डिजिटल भुगतान के दायरे को बढ़ाना है।

### एकीकृत भुगतान प्रणाली ( UPI ):

- परिचय:
  - यह तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) का एक उन्नत संस्करण
     है- कैशलेस भुगतान को तेज, और आसान बनाने के लिये
     चौबीसों घंटे धन हस्तांतरण सेवा।

- UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन (भाग लेने वाला कोई भी बैंक) में कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक प्लेटफार्म में विलय करने की शक्ति प्रदान करती है।
- UPI वर्तमान में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), RuPay आदि सिहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) संचालित प्रणालियों में सबसे बडा है।
- ⇒ UPI के साथ क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता:
  - UPI समय के साथ भारत में भुगतान का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है, जिसमें 26 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता और पाँच करोड़ व्यापारी शामिल हैं।
  - मई 2022 में इंटरफेस के माध्यम से 10.4 लाख करोड़ रुपए के लगभग 594 करोड़ लेन-देन को संसाधित किया गया था।
  - वर्तमान में यूपीआई उपयोगकर्ताओं के डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत/चालू खातों को जोड़कर लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है।

#### कदम का महत्त्वः

- 🔾 भुगतान के लिये अतिरिक्त विकल्प:
  - इस व्यवस्था से ग्राहकों को भुगतान के लिये एक अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है जिससे सुविधा में वृद्धि होगी।
- 🔾 क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढेगा:
  - इससे क्रेडिट कार्ड की पहुँच और उपयोग में बढ़ोत्तरी होगी।
  - UPI को व्यापक रूप से अपनाने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अनुमान है कि भारत में क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ जाएगा।
- UPI पर क्रेडिट बनाने का विकल्प:
  - यह भारत में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई द्वारा क्रेडिट बनाने की राह खोलता है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों में स्लाइस (Slice), यूनी (Uni), वन (One) आदि जैसे कई स्टार्टअप उभरे हैं।
- मर्चेंट साइट्स पर मजबूत लेन-देन:
  - इससे मर्चेंट साइट्स पर अधिक लेन-देन और स्वीकृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।.
  - जो लोग आमतौर पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पसंद करते हैं ताकि लंबी पे-बैक अविध या क्रेडिट-कार्ड बकाया पर ऋण प्राप्त किया जा सके, या जो खरीदारी के समय अपनी बचत को छूना नहीं चाहते हैं, वे यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं।

- 🔾 कुल खर्च में बढ़ोत्तरी:
  - इस कदम से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कुल खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से खर्च औसत खर्च के दोगुने से भी अधिक है। अधिक खर्च आमतौर पर अर्थव्यवस्था के लिये एक बल गुणक है।
- 🗅 वित्तीय लेन-देन के औसत टिकट आकार को बढ़ावा:
  - ♦ डिजिटल लेन-देन में तेजी लाने के अलावा, इस उपाय से वित्तीय लेन-देन के औसत आकार के भी प्रभावित होने की उम्मीद है।
    - वर्तमान में प्रति लेन-देन औसत टिकट का आकार (Average Ticket Size) 1,600 रुपए है, जबिक क्रेडिट कार्ड में यह 4,000 रुपए है।
  - इसलिये विश्लेषकों का दावा है नए विकास के साथ यूपीआई विनिमय का आकार लगभग 3,000 रुपए से 4,000 रुपए तक जाने की संभावना है।

### चुनौतियाँ:

- यह स्पष्ट नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किये गए यूपीआई विनिमय पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' कैसे लागू होगा।
  - MDR एक शुल्क है जो एक व्यापारी को उसके जारीकर्ता बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिये लिया जाता है।
- जनवरी 2020 से प्रभावी एक मानदंड के अनुसार, UPI और RuPay शून्य-MDR को आकर्षित करते हैं, जिसका अर्थ है कि इन लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।
- यूपीआई पर ज़ीरो-एमडीआर लागू होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे अन्य कार्ड नेटवर्क अभी तक क्रेडिट कार्ड के लिये यूपीआई में शामिल नहीं हुए हैं।

# ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने देश के तेजी से बढ़ते डिजिटल ई-कॉमर्स स्पेस को "लोकतांत्रिक" करने के उद्देश्य से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ( Open Network for Digital Commerce-ONDC) का पायलट चरण शुरू किया है, जिसमें वर्तमान में दो अमेरिकी मुख्यालय वाली फर्मों - अमेजॅन और वॉलमार्ट का वर्चस्व है।

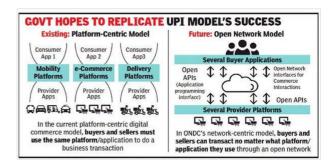
#### ONDC के बारे में:

- परिचय:
  - ONDC वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है और इसे एक प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से एक खुले नेटवर्क की ओर ले जाना है।
    - MONDC के तहत, यह परिकल्पना की गई है कि एक भाग लेने वाली ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये-अमेजॅन) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये, फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है।
    - वर्तमान में, खरीदारों और विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले लेनदेन के लिये एक ही ऐप पर होना चाहिये। उदाहरण के लिये, किसी खरीदार को अमेजॅन पर किसी विक्रेता से उत्पाद खरीदने के लिये अमेजॅन पर जाना होगा।
  - यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो उद्योगों में स्थानीय डिजिटल कॉमर्स स्टोर को किसी भी नेटवर्क-सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोजने और संलग्न करने में सक्षम बनाने के लिये एक नेटवर्क की पेशकश करेगा।
    - खुले नेटवर्क की अवधारणा खुदरा क्षेत्र से परे, थोक, गितशीलता, खाद्य वितरण, रसद, यात्रा, शहरी सेवाओं आदि सिहत किसी भी डिजिटल वाणिज्य डोमेन तक फैली हुई है।
  - यह न तो एक एग्रीगेटर एप्लीकेशन है और न ही एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, और सभी मौजूदा डिजिटल कॉमर्स एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म स्वेच्छा से अपनाने और ONDC नेटवर्क का हिस्सा बनने का विकल्प चुन सकते हैं।
  - ONDC का उद्देश्य किसी भी विशिष्ट प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र, खुले विनिर्देशों और खुले नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करके, ओपन-सोर्स पद्धति पर विकसित नेटवर्क को बढ़ावा देना है।
  - ONDC का कार्यान्वयन, जिसके एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) की तर्ज पर होने की उम्मीद है, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा रखे गए विभिन्न परिचालन पहलुओं को एक ही स्तर पर ला सकता है।
  - ओपन-सोर्स तकनीक पर आधारित नेटवर्क के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने की परियोजना को भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है।
    - आपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जिसमें सोर्स कोड होता है जो आसानी से सुलभ होता है और जिसे किसी के द्वारा संशोधित या

बढ़ाया जा सकता है। ओपन सोर्स एक्सेस किसी एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं को टूटे हुए लिंक को ठीक करने, डिजाइन को बढ़ाने या मूल कोड में सुधार करने की अनुमति देता है।

#### लाभ:

- ONDC कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन और ऑर्डर पूर्ति जैसे कार्यों का मानकीकरण करेगा, जिससे छोटे व्यवसायों के लिये नेटवर्क पर खोजे जाने योग्य और व्यवसाय का संचालन करना सरल और आसान हो जाएगा।
- 🗅 संभावित मुद्दे:
  - विशेषज्ञों ने ग्राहक सेवा और भुगतान एकीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ साइन अप करने के लिये पर्याप्त संख्या में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्राप्त करने जैसे संभावित संभावित मुद्दों की ओर इशारा किया है।



#### महत्त्व:

- ONDC पर खरीदार और विक्रेता इस तथ्य के बावजूद लेनदेन कर सकते हैं कि वे एक विशिष्ट ई-कॉमर्स पोर्टल से जुड़े हुए हैं।
- यह छोटे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - हालाँकि यदि यह अनिवार्य किया जाता है तो यह बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये समस्यायुक्त हो सकता है, क्योंकि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने संचालन के इन क्षेत्रों हेतु अपनी प्रक्रियाएँ और प्रौद्योगिकी स्थापित कर रखे हैं।
- ONDC से संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज करने, संचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशन को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिये मूल्य बढ़ाने की अपेक्षा है।
- यह मंच समान अवसर भागीदारी की परिकल्पना करता है और उपभोक्ताओं के लिये ई-कॉमर्स को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की अपेक्षा रखता है क्योंकि वे संभावित रूप से किसी भी संगत एप्लीकेशन/प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा की खोज कर सकते हैं, जिससे उनकी पसंद की स्वतंत्रता बढ़ जाती है।

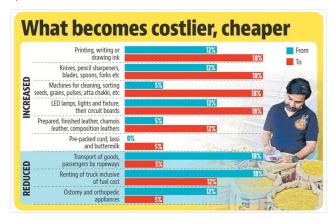
- यह किसी भी मूल्यवर्ग के लेनदेन को सक्षम करेगा, इस प्रकार ONDC को वास्तव में 'लोकतांत्रिक वाणिज्य हेतु खुला नेटवर्क' बना देगा।
- अगले पाँच वर्षों में ONDC नेटवर्क पर 90 करोड़ उपयोगकर्त्ताओं और 12 लाख विक्रेताओं को जोड़ने की अपेक्षा करता है, जिससे 730 करोड अतिरिक्त खरीदारी हो सकेगी।



# वस्तु और सेवा कर परिषद

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद की 47वीं बैठक में अधिकारियों ने दर संरचना को सरल बनाने के लिये बड़े पैमाने पर कई उपभोग वस्तुओं की छूट को समाप्त करते हुए कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिये दरों में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी।



### GST परिषदः

- 그 पृष्ठभूमि:
  - 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वॉं संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई।

- इसके बाद 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टि की जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी।
- 그 परिचय:
  - ♦ GST परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
  - इसे राष्ट्रपित द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1)
     के अनुसार स्थापित किया गया था।
- 🗅 सदस्य:
  - परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
  - प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
- 🗅 कार्यः
  - ऐ परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार, "GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिये है, जैसे- वस्तुओं और सेवाओं पर GST, मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है"।
  - यह GST के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
    - उदाहरण के लिये मंत्रियों के एक पैनल की अंतिरम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया है।
- 🕽 हाल के घटनाक्रम:
  - मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह पहली बैठक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
  - न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को GST पर कानून बनाने की "एक साथ" शक्ति देता है तथा परिषद की सिफारिशें "संघ एवं राज्यों को शामिल करने वाली वार्ता का परिणाम है"।
    - केरल और तिमलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इसका स्वागत किया, जो मानते हैं कि राज्य अपने अनुकूल सिफारिशों को स्वीकार करने में अधिक लचीले हो सकते हैं।

### जीएसटी का महत्त्वः

- एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण: यह भारत के लिये एक एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद करेगा। यह विदेशी निवेश और "मेक इन इंडिया" अभियान को भी बढ़ावा देगा।
- कराधान को सुव्यवस्थित करनाः केंद्र और राज्यों तथा केंद्रशासित राज्यों के बीच कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों में सामंजस्य स्थापित होगा।

- कर अनुपालन में वृद्धि: अनुपालन के लिये बेहतर वातावरण बनेगा क्योंकि सभी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल किये जाएंगे, इनपुट क्रेडिट को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक स्तर पर कागज रहित लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- कर चोरी को हतोत्साहित करना: समान SGST और IGST दरें पड़ोसी राज्यों के बीच तथा अंतर-राज्यीय बिक्री के बीच दर मध्यस्थता को समाप्त करके चोरी के लिये प्रोत्साहन को कम करेंगी।
- निश्चितता लाना: करदाताओं के पंजीकरण के लिये सामान्य प्रक्रियाएँ, करों की वापसी, कर रिटर्न के समान प्रारूप, सामान्य कर आधार, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली कराधान प्रणाली को अधिक निश्चितता प्रदान करेगी।
- भ्रष्टाचार में कमी: आईटी के अधिक उपयोग से करदाता और कर प्रशासन के बीच मानवीय संपर्क कम होगा, जो भ्रष्टाचार को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
- माध्यिमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना: यह निर्यात और विनिर्माण गितिविधि को बढ़ावा देगा, अधिक रोजगार पैदा करेगा और इस प्रकार लाभकारी रोजगार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा जिससे वास्तविक आर्थिक विकास होगा।

# रबर उद्योग

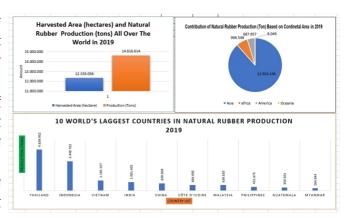
### चर्चा में क्यों ?

ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (AIRIA) के अनुसार, 2 अरब डॉलर के गैर-टायर रबर क्षेत्र ने वर्ष 2025 तक अपने निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

- वैश्विक बाज़ार में रबर उत्पादों की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 212 बिलियन डॉलर की है, जिसके वर्ष 2025 तक बढ़ने की उम्मीद है।
- सरकार को यह सुनिश्चित काना चाहिये कि मुक्त व्यापार समझौता (FTA) की शर्तों के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (MSME) को अंतर्राष्ट्रीयकरण का लाभ प्राप्त हो।
- चूँिक MSME भारत की अर्थव्यवस्था और वाणिज्य के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है, इसलिये विदेशी बाजारों में व्यापार करते समय MSME को जिन विशेष चिंताओं, मांगों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें दूर करने के लिये भारत को FTA प्रावधानों को शामिल करना चाहिये।

### ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ( AIRIA ):

अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ (AIRIA) उद्योग के हितों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्यों के साथ रबर उद्योग एवं व्यापार संबंधी सुविधा प्रदान करने वाला एक गैर-लाभकारी निकाय है।



### रबर की प्रमुख विशेषताएँ:

- 🗅 परिचय:
  - प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, जो एक कार्बनिक यौगिक है।
  - रबर एक सुसंगत लोचदार ठोस पदार्थ है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रो में पाए जाने वाले पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जिसमें हेवेया ब्रासीलिएन्सिस सबसे महत्त्वपूर्ण है।
  - रबर के पेड़ों के रोपण के बाद लगभग 32 वर्षों तक ये आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।
- 🕽 स्रोत:
  - प्राकृतिक रबर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, सबसे आम पारा रबर का पेड़ (हेवेया ब्रासीलिएन्सिस) है। यह अपने पूर्ण विकास के साथ कई वर्षों तक लेटेक्स उत्पन्न करता है।
  - लैंडोल्फिया (Landolphia) वर्ग की लताओं से कांगो रबर का उत्पादन होता है। इन लताओं को खेतों में नहीं उगाया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप कांगो में जंगली पौधों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ।
  - सिंहपर्णी दूध में भी लेटेक्स मौजूद होता है जिसका उपयोग रबर के उत्पादन के लिये किया जा सकता है।
- 🔾 रबर के पेड़ के लिये अनुकूल वातावरण:
  - 💠 मृदाः
    - ये पेड़ अच्छी जल-निकास प्रणाली वाले और मौसम के अनुकूल मृदा में विकास करते हैं।
    - प्र इन पेड़ों की वृद्धि के लिये लैटेराइट, जलोढ़, तलछटी और गैर-लैटेराइट लाल मिट्टी सबसे अच्छी होती है।
  - वर्षा और तापमान:
    - वर्ष में कम-से-कम 100 वर्षा वाले दिनों के साथ समान रूप से वितरित वर्षा और लगभग 20 से 34°C की तापमान सीमा हेविया रबर के पेड़ के विकास के लिये अनुकूल स्थितियाँ प्रदान करते हैं।

- सर्वोत्तम परिणामों के लिये लगभग 80% आर्द्रता, 2000 घंटे की धूप और तेज हवाओं की अनुपस्थिति भी आवश्यक है।
- 🕽 उपयोगः
  - रबर का उपयोग पेंसिल के निशान मिटाने से लेकर टायर, ट्यूब और बड़ी संख्या में औद्योगिक उत्पादों के निर्माण तक विभिन्न उद्देश्यों के लिये किया जाता है।
- विदार प्रतिरोधी (Tear Resistance) होने के साथ-साथ इसकी उच्च तन्यता क्षमता व कंपन प्रतिरोधी गुणों के कारण सिंथेटिक रबर के स्थान पर प्राकृतिक रबर को प्राथमिकता दी जाती है।
  - यह गुण निर्माण और ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिये इसे और महत्त्वपूर्ण बनाता है।
  - देशों में ऑटोमोबाइल बाजार की वृद्धि से प्राकृतिक रबर उत्पादन की मांग बढ़ने का अनुमन लगाया जा रहा है।
  - लेटेक्स उत्पादों, जैसे- कैथेटर, दस्ताने और बेल्ट की मांग में वृद्धि भी एक ऐसा कारक है जो रबर बाजार के विकास को बढावा दे सकता है।
- उत्पादन और वितरण:
  - वर्ष 2019 के खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (FAOStat) के अनुसार, थाईलैंड दुनिया में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और चीन का स्थान है।

### भारत में रबर उत्पादन की वर्तमान स्थिति:

- FAOStat 2019 के अनुसार, भारत दुनिया में रबर का चौथा सबसे बडा उत्पादक और उपभोक्ता है
- 🗅 खपतः
  - रबर की अधिकांश खपत परिवहन क्षेत्र में होती है, इसके बाद फुटवियर उद्योग का स्थान आता है।
- निर्यात:
  - वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान भारत से निर्यात किये जाने वाले प्राकृतिक रबर की मात्रा 12 हजार मीट्रिक टन से अधिक थी।
  - भारत से प्राकृतिक रबर का आयात करने वाले प्रमुख देशों में जर्मनी, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली शामिल हैं।
  - निर्यात उत्पादों में ऑटोमोटिव टायर और ट्यूब, जूते, चिकित्सा सामान, कोट और एप्रन शामिल हैं।
- 🕽 वितरण:
  - भारत में पहला रबर बागान वर्ष 1895 में केरल की पहाड़ी ढलानों पर स्थापित किया गया था।

- हालाँकि वाणिज्यिक पैमाने पर रबर की खेती वर्ष 1902 में शुरू की गई थी।
- केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है।
  - प्रमुख क्षेत्र: इस राज्य के कोट्टायम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझीकोड सभी जिले रबर का उत्पादन करते हैं।
- तिमलनाडुः
  - नीलिगिरि, मदुरै, कन्याकुमारी, कोयंबटूर और सलेम तिमलनाडु के मुख्य रबर उत्पादक जिले हैं।
- कर्नाटक:
  - 🗷 चिकमंगलूर और कोडागु मुख्य उत्पादक जिले हैं।
- त्रिपुरा, असम, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि कुछ अन्य रबर उत्पादक राज्य हैं।

# PFMS का एकल नोडल एजेंसी (SNA) डैशबोर्ड

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के एकल नोडल एजेंसी (NSA) डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।

- इसे वित्त मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM)
   समारोह के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।
- वित्त मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिये 6 से 12
   जून 2022 तक 'आइकॉनिक वीक' समारोह मना रहा है।
- इसके अतिरिक्त, मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में व्यय विभाग के लिये प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किये गए थे।

### मिशन कर्मयोगीः

- भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना।
- कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिये व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में व्यापक सुधार।

### SNA डैशबोर्डः

- परिचय:
  - यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिये धन जारी करने,
     वितरित करने और निगरानी करने के तरीके के संबंध में 2021
     में शुरू किया गया एक बड़ा सुधार है।

- इस संशोधित प्रक्रिया जिसे अब SNA मॉडल के रूप में संदर्भित किया जाता है, के लिये प्रत्येक राज्य को प्रत्येक योजना हेतु एक SNA की पहचान करने और उसे नामित करने की आवश्यकता होती है।
- किसी विशेष योजना में उस राज्य के लिये सभी निधियाँ अब इस बैंक खाते में जमा की जाती हैं, इसमें शामिल अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गए सभी व्यय इस खाते से प्रभावित होते हैं।

#### महत्त्व:

- निधियों का आवंटन:
  - SNA मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि CSS के लिये राज्यों को निधियों का आवंटन समय पर और विभिन्न शर्तों को पूरा करने के बाद किया जाए।
- अधिक दक्षता लाना:
  - प्र इस मॉडल के प्रभावी कार्यान्वयन से CSS निधि के उपयोग, निधियों की ट्रैकिंग, व्यावहारिक और राज्यों को निधियों को समय पर जारी करने में अधिक दक्षता प्राप्त हुई है; अंतत: सभी सरकार के उचित नकद प्रबंधन में योगदान दे रहे हैं।

#### आवश्यकताः

- SNA मॉडल के हितधारकों को योजनाओं के संचालन में आवश्यक प्रतिक्रिया और निगरानी उपकरण देने के लिये।
- डैशबोर्ड में मंत्रालयों द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी की गई विज्ञप्ति, राज्य के कोषागारों द्वारा SNA खातों में जारी की गई आगे की रिलीज, एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किये गए व्यय, बैंकों द्वारा SNA खातों में भुगतान किये गए ब्याज आदि को सुगम, सूचनात्मक व आकर्षक ग्राफिक्स में दर्शाया गया है।

### सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली:

- परिचय:
  - PFMS, जिसे पहले 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम' (CPSMS) के नाम से जाना जाता था, एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक (CGA) के कार्यालय द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है।
  - PFMS को शुरुआत में 2009 के दौरान योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी राशि को ट्रैक करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय रिपोर्टिंग करना था।

- इसके बाद वर्ष 2013 में योजना और गैर-योजनागत दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे भुगतान को कवर करने के लिये इसका दायरा बढ़ाया गया था।
  - वर्ष 2017 में सरकार ने योजना और गैर-योजना व्यय के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया।

#### 🗅 उद्देश्य:

- एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान सह लेखा नेटवर्क की स्थापना करके भारत सरकार के लिये एक ठोस सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना।
- 🗅 कवरेज:
  - वर्तमान में PFMS कवरेज के दायरे में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के साथ-साथ वित्त आयोग अनुदान सिंहत अन्य व्यय शामिल हैं।
  - PFMS भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में विभिन्न हितधारकों को एक वास्तविक समय पर, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली व एक प्रभावी निर्णय सहायता प्रणाली प्रदान करता है।
  - PFMS को देश में कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

# न्यूनतम समर्थन मूल्य

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंज़ूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि दरें उत्पादन की औसत लागत का कम-से-कम 1.5 गुना होंगी।

14 खरीफ फसलों की दरों में 4% से 8% तक की बढ़ोतरी की गई है।

### खरीफ सीजनः

- इस सीजन में फसलें जून से जुलाई माह तक बोई जाती हैं और कटाई सितंबर-अक्तूबर माह के बीच की जाती है।
- फसलें: इसके तहत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूँग, उड़द, कपास, जूट, मूँगफली और सोयाबीन आदि शामिल हैं।
- राज्यः असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तिमलनाडु, केरल और महाराष्ट्र।

### न्यूनतम समर्थन मूल्यः

- 그 परिचय:
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ गुना अधिक होती है।

- 'न्यूनतम समर्थन मूल्य'- िकसी भी फसल के लिये वह 'न्यूनतम मूल्य' है, जिसे सरकार िकसानों के लिये लाभकारी मानती है और इसलिये इसके माध्यम से िकसानों का 'समर्थन' करती है।
- ⇒ MSP के तहत फसलें:
  - 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
    - मृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) कृषि एवं
       किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
  - अधिदिष्ट फसलों में 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और दो अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
  - इसके अलावा लाही और नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) का निर्धारण क्रमश: सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) के आधार पर किया जाता है।
- MSP की सिफारिश संबंधी कारक:
  - किसी भी फसल के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करते समय 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' द्वारा कृषि लागत समेत विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है।
  - यह फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति, बाजार मूल्य प्रवृत्तियों (घरेलू व वैश्विक), उपभोक्ताओं के निहितार्थ (मुद्रास्फीति), पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग) और कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों जैसे कारकों पर भी विचार करता है।
- 🔾 तीन प्रकार की उत्पादन लागत:
  - CACP द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिये तीन प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है।
  - - इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किये गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है।
  - - इसके तहत 'A2' के साथ-साथ अवैतिनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है।
  - - यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंिक इसके अंतर्गत 'A2+FL' में किसान की स्वामित्त्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।

  - जबिक 'C2' लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिये कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित MSP कम-से-कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।
- केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय सिमिति (CCEA) MSP के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है।
- MSP की आवश्यकता:
  - वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में लगातार दो सूखे (Droughts) कि घटनाओं के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा।
  - विमुद्रीकरण (Demonetisation) और 'वस्तु एवं सेवा कर' ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी, पंगु बना दिया है।
  - वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोविड महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिये परिदृश्य विकट बना हुआ है।
  - डीजल, बिजली एवं उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया ही है।

### भारत में MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएँ:

- सीमितता: 23 फसलों के लिये MSP की आधिकारिक घोषणा के विपरीत केवल दो- चावल और गेहूँ की खरीद की जाती है क्योंकि इन्हीं दोनों खाद्यान्नों का वितरण NFSA के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशत: तदर्थ व महत्त्वहीन ही है।
- अप्रभावी रूप से लागू: शांता कुमार सिमित ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हो सका, जिसका अर्थ यह है कि देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित रहे हैं।
- खरीद मूल्य के रूप में: मौजूदा MSP व्यवस्था का घरेलू बाजार की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य NFSA की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिससे इसका अस्तित्व न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय एक खरीद मूल्य के रूप में है।

- गेहूँ और धान की प्रमुखता वाली कृषि: चावल और गेहूँ के पक्ष में अधिक झुकी MSP प्रणाली इन फसलों के अति-उत्पादन की ओर ले जाती है तथा किसानों को अन्य फसलों एवं बागवानी उत्पादों की खेती के लिये हतोत्साहित करती है, जबिक उनकी मांग अधिक है तथा वे किसानों की आय में वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं।
- मध्यस्थ-आश्रित व्यवस्था: MSP-आधारित खरीद प्रणाली मध्यस्थों/बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और APMC अधिकारियों पर निर्भर है, जिसे छोटे किसान अपनी पहुँच के लिये कठिन व जटिल पाते हैं।

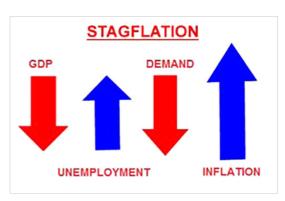
# स्टैगफ्लेशन

### चर्चा में क्यों ?

विश्व भर के केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने के लिये नीतियाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका सिहत कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को मंदी को ट्रिगर किये बिना नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में स्टैगफ्लेशन की संभावना है।

### स्टैगफ्लेशन:

- ⊃ परिचय:
  - स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता की विशेषता वाली स्थिति।
    - स्टैगफ्लेशन शब्द नवंबर 1965 में यूनाइटेड किंगडम में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद इयान मैकलेओड द्वारा गढ़ा गया था।
  - इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में विर्णित किया जाता है जहाँ विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोजगारी का स्तर लगातार ऊँचा रहता है, फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर एक ही समय में उच्च रहता है।
  - 💠 यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिये खतरनाक होती है।
    - आमतौर पर कम विकास की स्थिति में केंद्रीय बैंक और सरकारें मांग पैदा करने के लिये उच्च सार्वजनिक खर्च एवं कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं।
    - ये उपाय भी कीमतों को बढ़ाते हैं और मुद्रास्फीति का कारण बनते हैं। इसिलये इन उपकरणों को तब नहीं अपनाया जा सकता है जब मुद्रास्फीति पहले से ही उच्च स्तर पर हो, जिससे कम वृद्धि-उच्च मुद्रास्फीति के जाल से बाहर निकलना मृश्किल हो जाता है।



- 🗅 स्टैगफ्लेशन का मुद्दा:
  - वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत और मध्य में जब ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन), जो कि एक कार्टेल की तरह काम करता है, ने आपूर्ति में कटौती करने का फैसला किया और दुनिया भर में तेल की कीमतों में बढोतरी की।
  - एक ओर तेल की कीमतों में वृद्धि ने उन अधिकांश पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादक क्षमता को बाधित कर दिया, जो तेल पर बहुत अधिक निर्भर थीं, इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। दूसरी ओर तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही वस्तुएँ अधिक महंगी हो गईं।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 1974 में तेल की कीमतों में लगभग 70% की वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में भी वृद्धि देखी गई।

### स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में नवीनतम चिंताएँ:

- 🔈 कोविड-19 और उसके बाद के वित्तीय एवं मौद्रिक उपाय:
  - कोविड-19 महामारी के प्रकोप और वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लगाए गए प्रतिबंध दुनिया भर में पहली बड़ी आर्थिक मंदी का कारण बने, परिणामस्वरूप अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तरलता में पर्याप्त वृद्धि सहित मंदी को दूर करने के लिये किये गए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों ने मुद्रास्फीति में तीव्र उछाल को बढावा दिया है।
- 🗅 रूस-यूक्रेन की स्थिति और मास्को पर प्रतिबंध:
  - फेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड केंद्रीय बैंकों में से हैं जिन्होंने बढ़ती कीमतों को कम करने के लिये ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया है, रूस द्वारा अपने दक्षिणी पड़ोसी देश पर आक्रमण और मॉस्को पर परिणामी पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने परिस्थितियों को और भी जटिल बना दिया है।

- आपूर्ति कारक:
  - संघर्ष के कारण तेल और गैस से लेकर खाद्यान्न, खाद्य तेल एवं उर्वरक तक सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से अधिकारियों को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जो अब मांग आधारित नहीं है (इसलिये इसे साख/ ऋण को विनियमित करके नियंत्रित किया जा सकता है) और लगभग पूरी तरह से आपूर्ति कारकों पर निर्भर है जिन्हें प्रबंधित करना कहीं अधिक कठिन है।

# कोर सेक्टर आउटपुट

### चर्चा में क्यों ?

भारत के आठ कोर उद्योग ने मार्च 2022 में 4.9% की तुलना में अप्रैल में 8.4% की मज़बूत वृद्धि दर्ज की है।

- आठ कोर उद्योग में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
- आठ कोर उद्योग अपने भारांक के घटते क्रम में हैं: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

### आठ कोर उद्योग सूचकांक:

- 🗅 परिचय:
  - आठ कोर उद्योग सूचकांक (ICI) उत्पादन मात्रा सूचकांक को संदर्भित करता है
  - यह चयनित आठ कोर उद्योगों में उत्पादन के संयुक्त और
     व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
  - आठ कोर उद्योगों का वर्तमान भारांक (अप्रैल 2021) नीचे दिया गया है:
    - प्रेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (28.04%), बिजली (19.85%), स्टील (17.92%), कोयला उत्पादन (10.33%), कच्चा तेल (8.98%), प्राकृतिक गैस उत्पादन (6.88%), सीमेंट उत्पादन (5.37%), उर्वरक उत्पादन (2.63%)।
  - ICI को आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA), उद्योग और आंतरिक व्यापार संबर्द्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है।
- महत्त्व:
  - ICI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ द्वारा आईआईपी जारी करने से पहले 'कोर' प्रकृति के उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन पर अग्रिम संकेत प्रदान करता है।

 आठ प्रमुख उद्योगों से सामान्य आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावित होने की संभावना है।

### औद्योगिक उत्पादन सूचकांकः

- 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित समय अविध में विकास दर को प्रदर्शित करता है।
- इसका संकलन तथा प्रकाशन मासिक आधार पर 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय', 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' द्वारा किया जाता है।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत िकये गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है जिनमें शामिल है:
  - व्यापक क्षेत्र (Broad sectors)- खनन, विनिर्माण और विद्युत।
  - उपयोग आधारित क्षेत्र (Use-based Sectors)-मूलभूत वस्तुएँ, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
- ⇒ IIP के आकलन के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।

### औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का महत्त्वः

- इसका उपयोग नीति-निर्माण के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- IIP, त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमानों की गणना के लिये अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

# बैड बैंक

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL), भारतीय ऋण समाधान कंपनी (IDRCL) के साथ मिलकर बैंकों के बैड लोन के पहले सेट का समाधान करने का प्रयास करेगी।

- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों की बैलेंसशीट की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, उनका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात वित्त वर्ष 2018 में 11.2% से घटकर वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 6.9% हो गया है।
- ⇒ IDRCL एक सेवा कंपनी/पिरचालन इकाई है जो पिरसंपित्त का प्रबंधन करती है और बाजार के पेशेवरों तथा विशेषज्ञों को इसमें शामिल करती है। सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक (PSB) एवं सार्वजिनक वित्तीय संस्थानों के पास अधिकतम 49% हिस्सेदारी होती है और शेष हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होती है।

सरकार पहले ही NARCL द्वारा जारी की जाने वाली सुरक्षा रसीदों (SR) के लिये 30,600 करोड़ रुपए की संप्रभु गारंटी की घोषणा कर चुकी है, जो बैंकों से 2 लाख करोड़ रुपए के गैर-निष्पादित ऋण की खरीदारी करेगी।

### गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ( NPA ):

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है, जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भगतान बकाया होता है।
- अधिकतर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अविध के लिये न किया गया हो।
- सकल गैर-निष्पादित पिरसंपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जिन्हें वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा चुकाया नहीं गया है।
- शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ वह राशि है जो सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से 'प्रोविज्ञन अमाउंट' की कटौती के बाद प्राप्त होती है।

#### बैड बैंक:

- बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति
   (NPA), या बैड लोन खरीदने के लिये स्थापित किया गया है।
- बैड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों को उनकी बैलेंसशीट से बैड लोन को समाप्त कर बोझ को कम करना है और उन्हें बिना किसी बाधा के ग्राहकों को फिर से उधार देना है।
- बैंक से बैड लोन की खरीद के बाद बैड बैंक NPA को पुनर्गठित करने और उन निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं।
- बैड बैंक अपने परिचालन में लाभ कमा सकता है यदि वह वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये भुगतान की तुलना में अधिक कीमत पर ऋण का प्रबंधन करता है।
- हालॉंकि आमतौर पर एक बैड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, इसका उद्देश्य बैंकों पर बोझ को कम करना, तनावग्रस्त संपत्तियों का रख-रखाव करना और उन्हें अधिक सक्रिय रूप से उधार देना है।

### बैड बैंक के लाभ और हानि:

- ⊃ लाभ:
  - ♦ एकल अनन्य इकाई (Single Exclusive Entity):
    - यह एक ही अनन्य इकाई के तहत बैंकों के सभी बैड लोन को समेकित करने में मदद कर सकता है।
    - बैड बैंक के विचार को अतीत में अमेरिका, जर्मनी, जापान और अन्य देशों में आजमाया गया है।

- 2008 के वित्तीय संकट के बाद यू.एस. ट्रेज़री द्वारा कार्यान्वित संकटग्रस्त संपत्ति कार्यक्रम, जिसे TRP के रूप में भी जाना जाता है, को एक बैड बैंक के विचार के अंतर्गत तैयार किया गया था।
- मुक्त पूंजी उपयोग की स्वतंत्रता:
  - मं संकटग्रस्त बैंकों के बही-खाते से डूबे हुए ऋणों को समाप्त कर बैड बैंक 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मुक्त पूंजी की मदद कर सकता है, जिन्हें इन फॅंसे हुए ऋणों के प्रावधानों के रूप में बैंकों द्वारा बंद कर दिया गया है।
  - इससे बैंकों को अपने ग्राहकों को अधिक ऋण देने के लिये
     मुक्त पूंजी का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी।
- पूंजी बफर में सुधार:
  - यह कार्य बैंक के भंडार को बढ़ाकर नहीं बिल्क बैंकों के पूंजी बफर में सुधार कर बैंक ऋण प्रदान करने में मदद कर सकता है।
  - इस हद तक कि सरकार द्वारा स्थापित एक नया बैड बैंक पूंजी को मुक्त करके बैंकों के पूंजी बफर में सुधार कर सकता है, यह अधिक आत्मविश्वास के साथ फिर से उधार देने में बैंकों की मदद कर सकता है।

#### हानि:

- सरकार की एक ईकाई से दूसरी इकाई में संपत्ति का हस्तांतरण:
  - सरकार द्वारा समर्थित बैड बैंक केवल सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों जो सरकार के स्वामित्व में हैं, के हाथों से बैड एसेट्स को एक बैड बैंक में स्थानांतिरत कर देगा, जिस पर फिर से सरकार का स्वामित्व होगा।
  - यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सरकार की एक ईकाई से दूसरी ईकाई में संपत्ति के हस्तांतरण से इन अशोध्य ऋणों का सफल समाधान हो जाएगा, जब इन संस्थाओं के सामने प्रोत्साहन का सेट अनिवार्य रूप से समान है।
  - स्वामित्व की प्रकृतिः
    - निजी बैंकों के विपरीत, जो उन व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं जिनके पास उन्हें अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिये मजबूत वित्तीय स्थिति है, सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन नौकरशाहों द्वारा किया जाता है, जो अक्सर इन उधारदाताओं की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिये समान प्रतिबद्धता नहीं रखते हैं।
    - उस हद तक कि एक बैड बैंक के माध्यम से बैंकों को बाहर निकालने से वास्तव में बैड लोन संकट की मूल समस्या का समाधान नहीं होता है।

- नैतिकताः
  - जिन वाणिज्यिक बैंकों को एक बैड बैंक द्वारा गारंटी दी जाती है, उनके द्वारा अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने की बहुत कम संभावना होती है
  - आखिरकार एक बैड बैंक द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा जाल इन बैंकों को लापरवाही से उधार देने के और अधिक कारण देता है तथा इस प्रकार यह बैड लोन संकट को और बढा देता है।

### नियोबैंक

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नियोबैंक बिजनेस मॉडल पर कड़ी नजर रख रहा है, जहाँ फिनटेक एक पारंपरिक बैंक के नेटवर्क से संबंधित हो जाते हैं और ग्राहक उन्मुख बैंकिंग सेवा प्रदाता बन जाते हैं।

चिंता की बात यह है कि डिजिटल मॉडल व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और ग्राहकों के मामले में अंतर्निहित बैंक से बड़ा हो सकता है। यद्यपि नियोबैंक ग्राहक अंतर्निहित बैंक के खाताधारक बने रहते हैं, तो इन उपयोगकर्ताओं के लिये उपलब्ध एकमात्र चैनल फिनटेक के स्वामित्व वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

### नियोबैंक:

- नियोबैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय, नियोबैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- नियोबैंक वित्तीय संस्थान हैं जो ग्राहकों को पारंपिरक बैंकों का एक सस्ता विकल्प देते हैं।
- वे पिरचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएँ
   प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ
   उठाते हैं।
- नियोबैंक ने 'चैलेंजर बैंक' के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने पारंपरिक बैंकों के जटिल बुनियादी ढाँचे और 'क्लाइंट ऑनबोर्डिंग' प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
- भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस प्राप्त सेवाएँ प्रदान करने के लिये बैंक भागीदारों पर निर्भर हैं।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि RBI ने अभी तक बैंकों को 100%
     डिजिटल करने की अनुमित नहीं दी है।
  - RBI बैंकों की भौतिक उपस्थिति को प्राथमिकता देने के प्रति दृढ़ है और उसने डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के लिये कुछ भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में भी बात की है।

 रेजरपेएक्स, जुिपटर, नियो, ओपन आदि भारत के शीर्ष नियोबैंक के उदाहरण हैं।

### नियोबैंक के विभिन्न ऑपरेटिंग मॉडल:

- गैर-लाइसेंस प्राप्त फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) फर्में, पारंपरिक बैंकों के साथ मिलकर एक मोबाइल/वेब प्लेटफॉर्म और अपने सहयोगी बैंकों के उत्पादों के चारों ओर एक आवरण बनाए रखती हैं।
- 🗅 पारंपरिक बैंक जो डिजिटल पहल कर रहे हैं।
- लाइसेंस प्राप्त नियोबैंक (आमतौर पर उन देशों में डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के साथ जो इसे अनुमित देते हैं)।

#### पारंपरिक बैंकों और नियोबैंक के बीच अंतर:

- फंडिंग और ग्राहकों का भरोसा: नियोबैंक की तुलना में पारंपिरक बैंकों के कई फायदे हैं, जैसे कि फंडिंग और सबसे महत्त्वपूर्ण ग्राहकों का भरोसा।
  - हालाँकि विरासत प्रणालियाँ उनका महत्त्व कम कर रही हैं और उन्हें तकनीक-प्रेमी पीढ़ी की बढ़ती जरूरतों के अनुकूल होना मुश्किल लगता है।
- नवाचार: नियोबैंक के पास पारंपिरक बैंकों को उखाड़ फेंकने के लिये धन या ग्राहक आधार नहीं है, जबिक उनके पास नवाचार है।
  - वे पारंपिरक बैंकों की तुलना में अपने ग्राहकों को अधिक तेज़ी से सेवा देने के लिये सुविधाओं को लॉन्च कर सकते हैं और साझेदारी विकसित कर सकते हैं।
- पारंपिरक बैंकों द्वारा कम सेवा: नियोबैंक खुदरा ग्राहकों, छोटे और मध्यम व्यवसायों कि आवश्यकता को पूरा करता है, आमतौर पर कार्य पारंपिरक बैंकों द्वारा कम किये जाते हैं।
  - वे अभिनव उत्पादों को पेश कर और बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करके खुद को अलग करने के लिये मोबाइल-फर्स्ट मॉडल का लाभ उठाते हैं।
- उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेशक: वे ऐसे बैंकों के लिये बाजार के अवसरों पर गहरी नजर रख रहे हैं और उनमें अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं।
- स्मार्टफोन का प्रभाव: वर्ष 2020 तक भारत में स्मार्टफोन प्रवेश दर 54% थी, जो वर्ष 2040 तक 96% तक बढ़ने का अनुमान है।
  - भले ही 80% आबादी की कम-से-कम एक बैंक खाते तक पहुँच है, लेकिन वित्तीय समावेशन के स्तर में अभी तक सुधार नहीं हुआ है।

#### नियोबैंक के लाभ:

कम लागत: कम नियम और क्रेडिट जोखिम की अनुपस्थित नियोबैंक को अपनी लागत कम रखने की अनुमित देते हैं। बिना मासिक रखरखाव शुल्क के उत्पाद आमतौर पर सस्ते होते हैं।

- सुविधा: ये बैंक ग्राहकों को एक एप के माध्यम से अधिकांश (यदि सभी नहीं) बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- गित: नियोबैंक ग्राहकों को त्विरत खाता खोलने और अनुरोधों को तेज़ी से संसाधित करने की अनुमित देता है। वे ऋण की पेशकश करते हैं, ऋण के मूल्यांकन के लिये नवीन रणनीतियों में अधिक समय लेने वाली आवेदन प्रक्रियाओं को सीमित करते हैं।
- पारदर्शिता: नियोबैंक पारदर्शी हैं तथा ग्राहकों पर लगाए गए किसी शुल्क और दंड की रीयल-टाइम सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
- गहरी अंतर्दृष्टि: अधिकांश नियोबैंक अत्यधिक उन्नत इंटरफेस के साथ डैशबोर्ड समाधान प्रदान करते हैं और भुगतान, भुगतान योग्य और प्राप्य, बैंक स्टेटमेंट जैसी सेवाओं को अधिक सुलभ तरीके से प्रदान करते हैं।

# लिक्विड नैनो यूरिया

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया (LNU) संयंत्र का उद्घाटन किया।

यह स्वदेशी यूरिया है, जिसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिये पेश किया गया था।

### भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ( IFFCO )

- 🗅 परिचय:
  - यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी सिमितियों में से एक है
     जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी सिमितियों के पास है।
  - वर्ष 1967 में केवल 57 सहकारी सिमितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी, वर्तमान में यह 36,000 से अधिक भारतीय सहकारी सिमितियों का एक समूह है, जिसमें उर्वरकों के निर्माण और बिक्री संबंधी मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त सामान्य बीमा से लेकर ग्रामीण दूरसंचार तक विविध व्यावसायिक हित निहित हैं।
- 🔾 उद्देश्य:
  - भारतीय किसानों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ, विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट और सेवाओं की समय पर आपूर्ति के माध्यम से समृद्ध होने और उनके कल्याण के लिये अन्य गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना।

### लिक्विड नैनो यूरिया:

- 그 परिचय:
  - 💠 यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के

परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्त्व (तरल) है।

- यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिये एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्त्व है।
- नैनो यूरिया को पारंपिरक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपिरक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
  - इसकी 500 मिली.की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम/ लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/ बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्त्व प्रदान करेगा।

#### 🗅 निर्माण:

- इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (कलोल, गुजरात) में आत्मिनर्भर भारत अभियान और आत्मिनर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है।
  - भारत अपनी यूरिया की जरूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर है।
- ⊃ उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य पारंपिरक यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना तथा मिट्टी, पानी व वायु प्रदूषण को कम करना है।
- 🗅 महत्त्व:
  - पौधों के पोषण में सुधार:
    - मैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिये प्रभावी और कुशल पाया गया है। यह बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन बढ़ाने में भी सक्षम है।
    - यह मृदा में यूरिया अनुप्रयोग के अतिरिक्त उपयोग को कम करके संतुलित पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा देगा, साथ ही फसलों को मज़बूत एवं स्वस्थ बनाएगा और उन्हें लॉजिंग प्रभाव से बचाएगा।
  - लॉजिंग प्रभाव से फसल के तने जमीन की तरफ झुक जाते है, जिससे फसलों की कटाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उपज में नाटकीय रूप से कमी आ सकती है।
  - पर्यावरण में सुधार:
    - भूमिगत जल की गुणवत्ता और सतत् विकास पर भी इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग में कमी लागा।
  - कसानों की आय में वृद्धिः
    - यह किसानों का पॉकेट फ्रेंडली है और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर होगा। इससे लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग की लागत में भी काफी कमी आएगी।

# महाराष्ट्र पुनः शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य

### चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र पाँच साल बाद एक बार फिर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उत्पादन में इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है।

- वर्ष 2021-22 के लिये महाराष्ट्र द्वारा चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन है।
- वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी 105 लाख टन है।

### महाराष्ट्र में चीनी के भारी उत्पादन का कारण:

- जल की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति:
  - गन्ना एक जल गहन फसल है जिसे एक बड़ी जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है और महाराष्ट्र के किसान इसे वर्षा, जलाशयों, नहरों के नेटवर्क तथा भूजल से उचित रूप से प्राप्त कर रहे हैं।
  - दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान वर्ष 2019 से महाराष्ट्र में पर्याप्त वर्षा जल प्राप्त हो रहा है।
  - पर्याप्त वर्षा के कारण भूजल जलभृत और अन्य जलाशय जल से भर गए। जल के ये स्रोत कृषि उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- गन्ना उत्पादन की कम रिपोर्टिंगः
  - महाराष्ट्र राज्य में गन्ने के वास्तिवक उत्पादन से संबंधित आँकड़े बिल्कुल सटीक नहीं थे।
  - इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रशासन ने गन्ना उत्पादन के दर्ज आँकडों में सुधार करने का प्रयास किया।
    - प्र इसके परिणामस्वरूप अंततः गन्ना उत्पादन का रकबा 11.42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.4 लाख हेक्टेयर हो गया।
    - इस प्रकार महाराष्ट्र ने वर्ष 2021-22 में गन्ने के रकबे में वृद्धि का लाभ उठाया।

# भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आँकड़े तक पहुँच गई है।

एक यूनिकॉर्न का अर्थ कम-से-कम 7,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले स्टार्टअप से है। इन यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 330 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।  भारतीय यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, यूके और कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है।

### यूनिकॉर्न:

- 그 परिचय:
  - एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
  - यह अन्य उत्पादों/सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिये समर्पित नई संस्थाओं की उपिस्थिति को दर्शाता है।
  - ♦ फिनटेक, एडटेक, बिजनेस-टू-बिजनेस (B-2-B) कंपिनयाँ आदि इसकी कई श्रेणियाँ हैं।

#### 🕽 विशेषताएँ:

- विभाजनकारी नवाचार: अधिकतर सभी यूनिकॉर्न उस क्षेत्र में नवाचार लाए हैं जिससे वे संबंधित हैं, उदाहरण के लिये 'उबर' ने आवागमन के स्वरुप को बदल दिया है।
- तकनीक संचालित: यह व्यापार मॉडल नवीनतम तकनीकी नवाचारों और प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है।
- उपभोक्ता-केंद्रित: इनका लक्ष्य उपभोक्ताओं के लिये कार्यों को सरल बनाना और उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बनना है।
- वहनीयता : उत्पादों को वहनीय बनाना इन स्टार्टअप्स की एक प्रमुख विशेषता है।
- निजी स्वामित्व: अधिकांश यूनिकॉर्न निजी स्वामित्व वाले होते हैं, जब एक स्थापित कंपनी इसमें निवेश करती है तो उनका मूल्यांकन और बढ़ जाता है।
- सॉफ्टवेयर आधारित: एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि यूनिकॉर्न के 87% उत्पाद सॉफ्टवेयर हैं, 7% हार्डवेयर हैं और बाकी 6% अन्य उत्पाद एवं सेवाएँ हैं।

### भारत में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की स्थिति:

- 그 स्थिति:
  - भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है।
  - वर्ष 2021 में 44 भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिससे यूनिकॉर्न की कुल संख्या 83 हो गई है, जिनमें से अधिकॉॅंश सेवा क्षेत्र में हैं।
  - भारत ने कई रणनीतिक और सशर्त कारणों से यूनिकॉर्न में इतनी तेज़ी से वृद्धि देखी है।
- विकास का चालकः
  - सरकारी सहायता:
    - भारत सरकार मूल्य शृंखला में विघटनकारी नवप्रवर्तकों के साथ काम करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के

- लिये उनके नवाचारों का उपयोग करने के महत्त्व को समझ रही है।
- पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर 5 श्रेणियों में 10 लाख रुपए के स्टार्टअप को पुरस्कृत करने के लिये एक बड़ी प्रतिस्पर्द्धा का आयोजन किया है।
- डिजिटल सेवाओं को अपनाना:
  - महामारी के दौरान स्टार्टअप और नए जमाने के उपक्रमों को ग्राहकों के लिये तकनीकी केंद्रित व्यवसाय बनाने में मदद करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल सेवाओं को अपनाने में तेजी देखी गई।
- ऑनलाइन सेवाएँ और वर्क फ्रॉम होम संस्कृति:
  - कई भारतीय खाद्य वितरण और एडु-टेक से लेकर ई-किराने तक सेवा प्रदाता ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
  - वर्क फ्रॉम होम संस्कृति ने स्टार्टअप्स के उपयोगकर्ता आधार की संख्या बढ़ाने में मदद की और उनकी व्यवसाय विस्तार योजनाओं में तेजी लाकर निवेशकों को आकर्षित किया।
- डिजिटल भुगतान:
  - इंडिजिटल भुगतान की वृद्धि एक और पहलू है जिसने यूनिकॉर्न को सबसे अधिक सहायता दी।
- प्रमुख सार्वजिनक निगमों से खरीद:
  - कई स्टार्टअप प्रमुख सार्वजनिक निगमों से खरीद के परिणामस्वरूप यूनिकॉर्न बन जाते हैं जो आंतरिक विकास में निवेश करने के बजाय अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लियेअधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं।

### 🗅 संबद्ध चुनौतियाँ:

- निवेश बढ़ाना स्टार्टअप की सफलता सुनिश्चित नहीं करता: कोविड-19 संकट के बीच जब केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में तरलता जारी की है, तो पैसा जुटाना कोई कठिन काम नहीं है।
  - स्टार्टअप्स में निवेश किये जा रहे अरबों डॉलर दूरगामी परिणामों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं, न कि राजस्व के माध्यम से मृल्य सुजन।
  - साथ ही इस तरह के निवेशों के साथ इन स्टार्टअप्स के गतिमान रहने की उच्च दर की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसे मुनाफे से सुनिश्चित किया जा सकता है।
- अंतिरक्ष क्षेत्र में भारत अभी भी एक सीमांत खिलाड़ी: फिनटेक
   और ई-कॉमर्स क्षेत्र में भारत के स्टार्टअप असाधारण रूप से

- अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र अभी भी स्टार्टअप के लिये एक बाहरी क्षेत्र बना हुआ है।
- वर्तमान में वैश्विक अंतिरक्ष अर्थव्यवस्था 440 बिलियन डॉलर की हो चुकी है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम है।
- यह परिदृश्य इस तथ्य के बावजूद है कि भारत एंड-टू-एंड क्षमता के साथ उपग्रह निर्माण, संवर्द्धित प्रक्षेपण यान के विकास और अंतर-ग्रहीय मिशनों को तैनात करने के मामले में एक अग्रणी अंतरिक्ष-अन्वेषी देश है।
  - अंतिरक्षि क्षेत्र में स्वतंत्र निजी भागीदारी की कमी के कारणों में एक ऐसे ढाँचे का अभाव प्रमुख है जो कानूनों के संबंध में पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करे।
- भारतीय निवेशक जोखिम लेने को तैयार नहीं: भारत के स्टार्टअप क्षेत्र के बड़े निवेशक विदेशों से हैं, जैसे जापान का सॉफ्टबैंक, चीन का अलीबाबा और अमेरिका का सिकोइया (Sequoia)।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि भारत में एक महत्त्वपूर्ण उद्यम पूंजी उद्योग का अभाव है जो जोखिम लेने को तैयार हो।
  - देश के स्थापित कारोबारी समूह का जुड़ाव प्राय: पारंपरिक व्यवसायों से रहा है।

### संबंधित सरकारी पहल:

- स्टार्टअप इनोवेशन चुनौतियाँ: यह किसी भी स्टार्टअप के लिये अपने नेटवर्किंग और फंड जुटाने के प्रयासों का लाभ उठाने का एक शानदार तरीका है।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारः यह उन उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने और पुरस्कृत करने का प्रयास करता है जो नवाचार एवं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिशीलता में योगदान दे रहे हैं।
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर राज्यों की रैंकिंग: यह एक विकसित मूल्यांकन उपकरण है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समर्थन से अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- SCO स्टार्टअप फोरम: पहली बार शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्टअप फोरम को सामूहिक रूप से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और सुधार के लिये अक्तूबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
- प्रारंभ (Prarambh): 'प्रारंभ' शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्ट अप और युवांओं को नए विचारों, नवाचारों और आविष्कारो हेतु एक साथ आने के लिये मंच प्रदान करना है।

# वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट: ILO

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट पर ILO मॉनिटर का नौवाँ संस्करण जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही के दौरान महत्त्वपूर्ण लाभ के बाद वर्ष 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम के घंटों की संख्या में गिरावट आई है, जो कोविड-19 से पहले रोजगार की स्थिति से 3.8 प्रतिशत कम है।

- इसका मुख्य कारण हाल ही में चीन में लॉकडाउन, यूक्रेन एवं रूस के बीच संघर्ष और खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में वैश्विक वृद्धि है।
- रिपोर्ट इस संदर्भ में वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है कि देश कैसे अनियमित श्रम बाजार में सुधार कर रहे हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता, बढ़ती मुद्रास्फीति और सख्त कोविड-19 रोकथाम उपायों की निरंतरता जैसे कारकों से बाधित हुआ है।

### रिपोर्ट के अन्य निष्कर्ष:

- 🗅 वैश्विक:
  - कार्याविध में कमी:
    - भारत और निम्न-मध्यम-आय वाले देशों ने वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में कार्यावधि गिरावट में लैंगिक अंतर का अनुभव किया।
    - हालाँकि भारत में महिलाओं के काम के घंटों का प्रारंभिक स्तर बेहद कम था, भारत में महिलाओं द्वारा किये गए कार्य के घंटों में कमी का निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के समग्र प्रदर्शन पर मामुली प्रभाव पड़ा है।
    - इसके विपरीत भारत में पुरुषों द्वारा कार्य करने के घंटों में कमी का समग्र प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
  - विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर:
    - म विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच महत्त्वपूर्ण व बढ़ती असमानता बनी हुई है।
    - जहाँ उच्च आय वाले देशों में काम के घंटों में सुधार देखा गया, वहीं निम्न और निम्न-मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में संकट-पूर्व आधार रेखा की तुलना में वर्ष की पहली तिमाही में 3.6 एवं 5.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
  - कार्यस्थल बंद होने की प्रवृत्तिः
    - वर्ष 2021 के अंत और वर्ष 2022 की शुरुआत में संक्षिप्त उछाल के बाद वर्तमान में कार्यस्थल बंद होने की प्रवृत्ति में गिरावट आई है।

- जबिक अधिकांश श्रमिक किसी-न-किसी प्रकार के कार्यस्थल प्रतिबंध वाले देशों में रहते हैं, लेकिन प्रतिबंध का सबसे गंभीर रूप (आवश्यक कार्यस्थलों को छोड़कर सभी के लिये अर्थव्यवस्था-व्यापी आवश्यक बंद) अब लगभग समाप्त हो गया है।
- हाल ही में सख्ती के साथ कार्यस्थलों को बंद करने में यह कटौती यूरोप और मध्य एशिया में विशेष रूप से स्पष्ट की गई थी, जहाँ वर्तमान में 70% श्रमिकों को या तो केवल अनुशंसित बंद का सामना करना पड़ता है या बिल्कुल भी नहीं।
- रोजगार पुन: प्राप्ति प्रवृत्तियों में विचलन:
  - काम के घंटों में समग्र विचलन के अनुरूप वर्ष 2021 के अंत तक अधिकांश उच्च-आय वाले देशों में रोजगार के स्तर में सुधार हुआ था, जबिक अधिकांश मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में घाटे की प्रवृत्ति बनी रही।
  - वर्ष 2019 की अंतिम तिमाही से रोजगार-से-जनसंख्या अनुपात में अंतर वर्ष 2021 के अंत तक समाप्त हो गया था।
- 💠 श्रम आय की अब तक पुन: प्राप्ति नहीं हुई है:
  - वर्ष 2021 में पाँच में से तीन श्रमिक उन देशों में रहते थे जहाँ औसत वार्षिक श्रम आय अभी तक वर्ष 2019 की चौथी तिमाही के अपने स्तर तक नहीं पहुँच पाई थी।
  - निम्न, निम्न-मध्यम और उच्च-मध्यम आय वाले देशों
     (चीन को छोड़कर) में श्रमिकों को वर्ष 2021 में क्रमशः
     -1.6%, -2.7% और -3.7% की दर से कम श्रम आय भुगतान पर कार्य करना पड़ा।
- अनौपचारिक रोजगार अधिक प्रभावित हुआ, विशेष रूप से महिलाओं के मामले में लेकिन औपचारिक रोजगार की तुलना में विपरीत स्थिति विद्यमान है:
  - उदाहरण के लिये औपचारिक रोजगार से विस्थापित श्रमिक आजीविका चलाने के लिये अनौपचारिक रोजगार का सहारा लेते हैं, जबिक जो पहले से ही अनौपचारिक रोजगार में हैं, वे वहीं पर बने रहते हैं।
  - इस कारण से आर्थिक मंदी के दौरान अनौपचारिक रोजगार में औपचारिक रोजगार की तुलना में कम परिवर्तन देखा गया।

#### 🗅 भारत:

- महामारी से पहले रोजगार में संलग्न हर 100 महिलाओं में से महामारी की इस पूरी अवधि के दौरान औसतन 12.3 महिलाओं ने अपना रोजगार खो दिया।
- 💠 इसके विपरीत प्रत्येक 100 पुरुषों पर यह आँकड़ा 7.5 है।

- इसलिये ऐसा लगता है कि महामारी ने देश में रोजगार भागीदारी
   में पहले से ही व्याप्त लैंगिक असंतुलन को बढ़ा दिया है।
- भारत में महिला रोजगार में कमी आई है, विशेष रूप से कोविड 19 महामारी के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में।

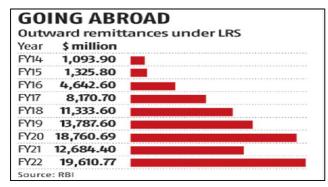
# बहिर्वाह प्रेषण प्रवृत्ति

### चर्चा में क्यों?

आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत कुल बहिर्वाह प्रेषण, मार्च 2022 में 12.684 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मार्च 2022 के अंत तक 19.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया था।

मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी भारतीयों द्वारा देश से बाहर ले जाए जाने वाले अमेरिकी डॉलर और यूरो सहित विदेशी मुद्रा में 54.60% की वृद्धि हुई है।

### प्रेषण:



- प्रेषण से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तु के रूप में अपने मृल समुदाय/परिवार को भेजी जाने वाली आय से है।
- यह मूल रूप से दो मुख्य घटकों का योग है- निवासी और अनिवासी पिरवारों के मध्य नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण तथा कर्मचारियों का मुआवजा, यह उन श्रमिकों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिये दूसरे देश में काम करते हैं।
- प्रेषण प्राप्तकर्त्ता देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता करते हैं, लेकिन यह ऐसे देशों को प्रेषण अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भर भी बना सकता है।

### बहिर्वाह प्रेषण:

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अनुसार, बहिर्वाह प्रेषण का आशय किसी भी वास्तविक उद्देश्य से भारत से किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर एक लाभार्थी (नेपाल और भूटान को छोड़कर) को विदेशी मुद्रा के रूप में धन का हस्तांतरण करना है।

### बहिर्वाह प्रेषण प्रवृत्तिः

- 🗅 कुल बहिर्वाह प्रेषण:
  - कुल बहिर्वाह प्रेषण वित्त वर्ष 2022 में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर था क्योंकि इसने कोविड-19 व्यवधान में कमी के कारण पिछले वर्ष के कमजोर प्रदर्शन की तुलना में मजबूत वापसी की।
  - इस वापसी को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और विदेशी शिक्षा पर भारतीयों
     के अधिक खर्च किये जाने की वजह से समर्थन मिला।
- बहिर्वाह प्रेषण के भागः
  - अंतर्राष्ट्रीय यात्रा: वित्त वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में तेज़ी आई, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने यात्रा पर 6.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया, जो कि वित्त वर्ष 2021 में यात्रा पर किये गए खर्च के दोगुने से अधिक है।
    - हालाँकि वित्त वर्ष 2020 में भी भारतीयों द्वारा यात्रा पर किया गया खर्च लगभग 6.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - विदेशी शिक्षा: विदेशी शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण खंड है जिसने वित्त वर्ष 2022 में समुचित विकास देखा है क्योंिक भारतीयों ने वर्ष में 5.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रेषण किया है।
    - प्र इसमें वित्त वर्ष 2021 से 35% की वृद्धि देखी गई है, जब भारतीयों ने 3.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण किया था।
    - वित्त वर्ष 2020 में विदेशी शिक्षा के लिये प्रेषण लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - उपहार: भारतीयों ने वित्त वर्ष 2022 में उपहार के रूप में 2.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण किया, जो वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 47.28% अधिक है।
    - वित्त वर्ष 2020 में भारतीयों ने LRS योजना के तहत उपहार के रूप में लगभग 1.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे।

### विदेशी इक्विटी और ऋण में निवेश:

- भारतीयों द्वारा विदेशी इक्विटी और ऋण में निवेश भी वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर 746.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबिक पिछले वर्ष यह 471.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। उदारीकृत प्रेषण योजना:
- यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्त्वावधान में फरवरी 2004 में प्रारंभ की गई थी।
- वर्तमान समय में LRS के तहत सभी निवासी व्यक्तियों जिसमें नाबालिग भी शामिल हैं, को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेन-देन या दोनों के संयोजन के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) तक 2,50,000 डॉलर तक की छूट दी जाती है।

- यह योजना किसी कॉर्पोरेट, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) एवं ट्रस्ट आदि के लिये उपलब्ध नहीं है।
- LRS के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से प्रेषित अथवा उनके माध्यम से खरीदे गए विदेशी मुद्रा की कुल राशि 2,50,000 डॉलर की निर्धारित संचयी (Cumulative) सीमा के भीतर होनी चाहिये।

### चालू और पूंजी खाता विनिमय:

- चालू खाता विनिमय: एक निवासी द्वारा किये गए सभी लेन-देन जो भारत के बाहर आकस्मिक देनदारियों सिहत उसकी संपत्ति या देनदारियों को परिवर्तित नहीं करते हैं, चालू खाता विनिमय कहलाते हैं।
  - उदाहरणः विदेश व्यापार के संबंध में भुगतान, विदेश यात्रा के संबंध में खर्च, शिक्षा आदि।
- पूंजी खाता विनिमय: इसमें वे लेन-देन शामिल हैं जो भारत के निवासी द्वारा किये जाते हैं जिसमें भारत के बाहर उसकी संपत्ति या देनदारियाँ परिवर्तित हो जाती हैं (या तो बढ़ जाती है या घट जाती है)।
  - उदाहरण: विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि।

# NDB की 7वीं वार्षिक बैठक

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के लिये भारत की गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की।

- बैठक में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राज्यपाल और बांग्लादेश एवं संयुक्त अरब अमीरात (नए सदस्य) भी शामिल हुए।
- इस वार्षिक बैठक का विषय "NDB: अधिकतम विकास प्रभाव (NDB: Optimising Development Impact)" था।

### बैठक की मुख्य विशेषताएँ:

- वित्त मंत्री ने बहुपक्षवाद के महत्त्व एवं आर्थिक सुधार के लिये
   वैश्विक सहयोग की भावना को रेखांकित किया।
- इस संबंध में वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि NDB ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिये खुद को एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

- इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही है और इसके 8.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।
  - 💠 यह भारत की दृढ़ता और त्वरित सुधार को दर्शाता है।
- वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत चालू वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में उच्च विकास दर हासिल करना जारी रखेगा।

### न्यू डेवलपमेंट बैंक:

- परिचय:
  - यह वर्ष 2014 में ब्राजील के 'फोर्टालेजा' में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ कोरिया) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
  - इसका गठन ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिये बुनियादी अवसंरचना व सतत् विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया था।
  - 💠 इसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में स्थित है।
  - वर्ष 2018 में 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सिक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिये एक मजबूत आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था।
- ⊃ उद्देश्य:
  - सदस्य देशों के विकास को बढावा देना।
  - 💠 आर्थिक विकास का समर्थन करना।
  - प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन की सुविधा
     प्रदान करना।
  - विकासशील देशों के बीच ज्ञान साझाकरण मंच का निर्माण करना।

# क्रिप्टोकरेंसी के कारण 'डॉलरीकरण'

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संसदीय पैनल को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी अर्थव्यवस्था के हिस्से का "डॉलरीकरण" कर सकती है जो भारत के संप्रभु हित के खिलाफ होगा।

### डॉलरीकरण:

डॉलरीकरण मुद्रा प्रतिस्थापन का रूप है, जहाँ डॉलर का उपयोग किसी देश की स्थानीय मुद्रा के अतिरिक्त या उसके स्थान पर किया जाता है।

- यद्यपि कई अर्थव्यवस्थाएँ काफी हद तक डॉलरीकृत हैं फिर भी केवल लाइबेरिया और पनामा जैसे टैक्स हेवन देशों को सही अर्थों में 'डॉलरीकृत' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- वास्तव में दो-तिहाई डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इसे जारी करता है, के बाहर रखे जाते हैं।
  - बोलीविया जैसे देश जो अति मुद्रास्फीति के शिकार हुए हैं, का भी डॉलरीकरण हो गया है, यहाँ 80% से अधिक मुद्रा का उपयोग डॉलर के रूप में किया जा रहा है।

#### डी-डॉलरीकरण:

- यह वैश्विक बाजारों में डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिये संदर्भित है। यह अमेरिकी डॉलर को मुद्रा के रूप में प्रतिस्थापित करने की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्न हेतु किया जाता है:
  - व्यापारिक तेल और/या अन्य वस्तुएँ
  - विदेशी मुद्रा भंडार हेतु अमेरिकी डॉलर ख़रीदना
  - द्विपक्षीय व्यापार समझौते
  - डॉलर मूल्यवर्ग की संपत्ति
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की प्रभुत्वशाली भूमिका अमेरिका को अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर असंगत प्रभाव रखने का अवसर देती है। अमेरिका लंबे समय से अपने विदेश नीति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रतिबंधों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है।
  - डी-डॉलरीकरण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों को भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाने की भावना से प्रेरित है, जहाँ एक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

### डॉलरीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

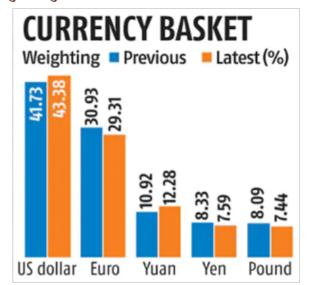
- अपनी मौजूदा मुद्रास्फीति की समस्याओं के बावजूद भारत काफी हद तक डॉलरीकरण से बहुत दूर है।
  - हालाँकि कुछ शोध पत्रों के अनुसार, भारतीय निर्यात-आयात
     (EXIM) लेन-देन में डॉलर का दबदबा है।
- भारतीय आयात और निर्यात दोनों ही गतिविधियाँ लगभग 86%
   डॉलर में ही की जाती हैं।
- भारत, अमेरिका को 15% निर्यात और वहाँ से केवल 5% ही आयात करता है।
  - यह दर्शाता है कि विदेशों में डॉलर की लोकप्रियता के भय से कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिये अपनी मुद्राओं का उपयोग करते हैं।

# विशेष आहरण अधिकार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार मुद्रा टोकरी में युआन के भारांक को बढ़ा दिया, जिससे उत्साहित होकर चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने वित्तीय बाजारों को और अधिक उदार बनाने का संकल्प लिया।

### प्रमुख बिंदु



- IMF ने वर्ष 2016 में चीनी मुद्रा के टोकरी में शामिल होने के बाद से SDR मूल्यांकन की अपनी पहली नियमित समीक्षा में युआन का भारांक 10.92% से बढ़ाकर 12.28% कर दिया है।
- अमेरिकी डॉलर का भारांक 41.73% से बढ़कर 43.38% हो गया, जबिक यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड में गिरावट आई।
- समीक्षा के बाद मुद्राओं के भारांक की रैंकिंग समान है, साथ ही युआन तीसरे स्थान पर बना हुआ है।
- अप्रैल के अंत से युआन के तेज़ी से मूल्यह्रास के बीच यह पिरवर्तन आया क्योंिक यह कोविद-प्रेरित लॉकडाउन और पूंजी बहिर्वाह तथा अमेरिका के साथ अपनी व्यापक मौद्रिक नीति विचलन के कारण घरेलू विकास के धीमा होने की दोहरी मार का सामना कर रहा है।

### विशेष आहरण अधिकार:

- 🗅 परिचय:
  - SDR न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा। बल्कि, यह आईएमएफ के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के एवज में एसडीआर का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

- SDR आईएमएफ और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है।
- SDR की मुद्रा कीमत का निर्धारण यूएस डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाजार विनिमय दर, मुद्राओं की एक SDR बास्केट पर आधारित होता है।
- ♦ मुद्राओं की SDR बास्केट में युएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग एवं चीनी रॅन्मिन्बी (वर्ष 2016 में शामिल) हैं।
- ♦ SDR मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन (अवकाश को छोडकर या जिस दिन IMF व्यावसायिक गतिविधियों के लिये बंद हो) होता है एवं मुल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कोटा (Quotas) को SDRs में इंगित किया गया है।
- किसी देश का कोटा ( आईएमएफ में योगदान की गई राशि) SDR में अंकित होता है।
  - सदस्य देशों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित होता है।
  - ♦ IMF अपने सदस्यों को उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य SDR आवंटित करता है।
- IMF में भारत का कोटा.
  - 💠 वर्ष 2016 में IMF में कोटा और प्रशासन संबंधी सुधार हुए।
  - ♦ इसके अनुसार, भारत का मतदान अधिकार 0.3% बढकर 2.3% से 2.6% हो गया है और चीन का मतदान अधिकार 2.2% बढकर 3.8% से 6% हो गया है।
  - वर्तमान में भारत के पास IMF में विशेष आहरण अधिकार कोटा का 2.75% और वोट 2.63% है।
  - भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में IMF में स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति और रिज़र्व ट्रेंच के अलावा अन्य विशेष आहरण अधिकार भी शामिल है।

### अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष:

- परिचय:
  - ♦ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बैंक के साथ IMF की स्थापना युद्ध से तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये की गई थी।
    - IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, यह उन 190देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। भारत ने 27 दिसंबर, 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की।
  - IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, यह विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों (तथा उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।

- वर्ष 2012 में एक कोष के जनादेश के अंतर्गत वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करने के लिये इसको अद्यतित किया
- IMF की रिपोर्ट:
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।

# भारतीय प्रतिस्पर्ब्स आयोग ( CCI )

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) के 13वें वार्षिक दिवस समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और CCI के लिये एक उन्नत वेबसाइट का शुभारंभ भी किया।

### भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग ( CCI ):

- परिचय:
  - भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिये उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया
  - राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP Act). 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- संरंचना:
  - 💠 प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियक्त किया जाता है।
  - ♦ आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देने के साथ-साथ अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक होते हैं।
- सदस्यों की पात्रता: 0
  - 💠 इसके अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिये ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जो सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ-साथ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो या जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा

कार्य, प्रबंधन, उद्योग, लोक कार्य या प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों में कम-से-कम पंद्रह वर्ष का विशेष ज्ञान एवं वृत्तिक अनुभव हो और केंद्र सरकार की राय में आयोग के लिये उपयोगी हो।

### प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम. 2002:

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था और प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा इसे संशोधित किया गया। यह आधुनिक प्रतिस्पर्द्धा विधानों के दर्शन का अनुसरण करता है।
  - 💠 यह अधिनियम प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी करारों और उद्यमों द्वारा अपनी प्रधान स्थिति के दुरुपयोग का प्रतिषेध करता है तथा समुच्चयों [अर्जन, नियंत्रण, 'विलय एवं अधिग्रहण' (M&A)] का विनियमन करता है, क्योंकि इनकी वजह से भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या इसकी संभावना बनी रहती है।
  - 💠 संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग और प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (Competition Appellate Tribunal- COMPAT) की स्थापना की गई।
  - वर्ष 2017 में सरकार ने प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) से प्रतिस्थापित कर दिया।

### CCI की भूमिका और कार्य:

- प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकृल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- किसी विधान के तहत स्थापित किसी सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ के लिये प्रतिस्पर्द्धा संबंधी विषयों पर परामर्श देना एवं प्रतिस्पर्द्धा की भावना को संपोषित करना, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना एवं प्रतिस्पर्द्धा के विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- उपभोक्ता कल्याण: उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिये बाजारों को सक्षम बनाना।
- अर्थव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी विकास एवं वृद्धि के लिये देश की आर्थिक गतिविधियों हेतु निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्द्धा नीतियों को लागू करना।

प्रतिस्पर्द्धा के पक्ष-समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढाना और सभी हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के लाभों को लेकर सूचना का प्रसार करना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा की संस्कृति का विकास तथा संपोषण किया जा सके।

# प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

### चर्चा में क्यों?

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम (PMEGP) को वित्त वर्ष 2026 तक पाँच साल के लिये विस्तार की मंज़ूरी दे दी है।

PMEGP को अब 13,554.42 करोड रुपए के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल के लिये 15वें वित्त आयोग अवधि तक जारी रखने की मंज़ुरी दी गई है।

#### PMEGP योजनाः

- शुरुआत:
  - भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सजन कार्यक्रम (PMEGP) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत को मंज़ूरी दी।
  - यह उद्यमियों को कारखाने या इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति देता है।

#### 0 प्रशासन:

- ♦ यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- 'केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय' के तहत संचालित इस योजना का क्रियान्वयन 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) द्वारा किया जाता है।
- विशेषताएँ:
  - पात्रताः
    - 🗷 कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
    - 🗷 इस कार्यक्रम के तहत केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिये सहायता प्रदान की जाती है।
    - 🗷 इसके साथ ही ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्हें किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न मिल रहा हो, 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860' के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादक कोऑपरेटिव सोसायटी और चैरिटेबल ट्रस्ट आदि इसके तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

- 💠 परियोजना / यूनिट की अधिकतम स्वीकार्य लागत:
  - विनिर्माण क्षेत्र: 50 लाख रुपए
  - 🗷 सेवा क्षेत्र: 20 लाख रुपए
- सरकारी सिंब्सडी:
  - प्रामीण क्षेत्र: सामान्य वर्ग के लिये 25% और विशेष श्रेणी के लिये 35%, जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यक, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से अक्षम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आकांक्षी व सीमावर्ती जिले के लाभार्थी शामिल हैं।
  - शहरी क्षेत्र: सामान्य श्रेणी के लिये 15% और विशेष श्रेणी के लिये 25%।
- बेंकों की भूमिका: संबंधित राज्य टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाते हैं।

#### 🗅 बदलाव:

- योजना के लिये ग्रामोद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव किया गया है।
- पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, जबिक नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा।

#### महत्त्व:

- यह योजना पाँच वित्तीय वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिये स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
- यह गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके देश भर में बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा प्रदान करती है।
- 2008-09 में इसकी स्थापना के बाद से लगभग 7.8 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 19,995 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ अनुमानित 64 लाख व्यक्तियों के लिये स्थायी रोजगार पैदा करने में सहायता मिली है। सहायता प्राप्त इकाइयों में से लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 50% इकाइयाँ अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति और महिला श्रेणियों के स्वामित्व में हैं।

# विश्व दुग्ध दिवस

### चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।

### प्रमुख बिंदु

- 그 परिचय:
  - 💠 विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि

- संगठन (FAO) द्वारा एक वैश्विक आहार के रूप में दूध के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये स्थापित किया गया।
- इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करना है।

#### 🕽 थीम:

- इस वर्ष की थीम जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और जलवायु परिवर्तन पर डेयरी क्षेत्र के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिये पहले से चलाए जा रहे कार्योंक्रमों को बढ़ावा देना है।
- इस मंच का उपयोग करते हुए डेयरी नेट ज़ीरो के प्रति संदेश
   और कार्रवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

#### ⊃ विशेषताएँ:

- ♦ विश्व दुग्ध दिवस डेयरी क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण योगदान के निम्नलिखित विषयों पर चर्चा को प्रोत्साहित है:
  - 🗷 अच्छा भोजन, स्वास्थ्य और पोषण।
  - किसानों की अपने समुदायों, जमीनों और अपने पशुधन पर निर्भरता।
  - 🙎 डेयरी क्षेत्र में स्थिरता।
  - डेयरी क्षेत्र कैसे आर्थिक विकास और आजीविका में योगदान करता है।

### भारतीय डेयरी क्षेत्र:

- भारत 22% वैश्विक दुग्ध उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का नंबर आता है।
- देश में दूध उत्पादन लगभग 6.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2020-21 में 209.96 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जो वर्ष 2014 में 146.31 मिलियन टन था।
  - शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (14.9%), राजस्थान (14.6%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.6%) और आंध्र प्रदेश (7.0%)।

# पहला लैवेंडर महोत्सव

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया।

लैवेंडर की खेती ने जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों में लगभग 5,000 किसानों और युवा उद्यमियों के लिये रोजगार पैदा किया है। 200 एकड़ में इसकी खेती करने वाले 1,000 से अधिक किसान परिवार इसमें शामिल हैं।

#### लैवेंडर क्रांति:

- 🗅 परिचयः
  - बेंगनी या लैवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी।
  - जम्मू-कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लैवेंडर की खेती की जाती है।
  - पहली बार में किसानों को खेती के लिये मुफ्त में लैवेंडर के पौधे दिये गए, जबिक जिन किसानों ने पहले लैवेंडर की खेती की थी, उन्हें 5-6 रुपए प्रति पौधा दिया गया था।

#### लक्ष्यः

 आयातित सुगंधित तेलों की बजाय घरेलू किस्मों को बढ़ावा देकर घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करना।

#### 🗅 उत्पाद:

- मुख्य उत्पाद लैवेंडर तेल है जो कम-से-कम 10,000 रुपए प्रति लीटर बिकता है।
- लैवेंडर का जल जो लैवेंडर के तेल से अलग होता है, का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिये किया जाता है।
- हाइड्रोसोल जो कि फूलों से आसवन के बाद बनता है, साबुन
   और रूम फ्रेशनर बनाने के लिये उपयोग किया जाता है।

#### 🗅 महत्त्व:

- यह 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने की सरकार की नीति
   के अनुरूप है।
- यह उभरते किसानों, कृषि उद्यमियों को आजीविका के साधन प्रदान करने में मदद करेगा और स्टार्टअप इंडिया अभियान एवं क्षेत्र में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देगा।
  - 500 से अधिक युवाओं ने बैंगनी क्रांति का लाभ उठाया था और अपनी आय में कई गुना वृद्धि की।

#### अरोमा मिशन:

#### 🗅 परिचय:

- इत्र उद्योग और ग्रामीण रोजगार के विकास को बढ़ावा देने के लिये कृषि, प्रसंस्करण और उत्पाद विकास के क्षेत्रों में वांछित हस्तक्षेप के माध्यम से सुगंध क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिये CSIR द्वारा अरोमा मिशन की परिकल्पना की गई है।
- यह मिशन ऐसे आवश्यक तेलों के लिये सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देगा, जिनकी अरोमा (इत्र) उद्योग में काफी अधिक मांग है।

- यह मिशन भारतीय किसानों और अरोमा (सुगंध) उद्योग को 'मेन्थॉलिक मिंट' जैसे कुछ अन्य आवश्यक तेलों के उत्पादन व निर्यात में वैश्विक प्रतिनिधि बनने में मदद करेगा।
- इसका उद्देश्य उच्च लाभ, बंजर भूमि के उपयोग और जंगली एवं पालतू जानवरों से फसलों की रक्षा करके किसानों को समृद्ध बनाना है।
- ⇒ अरोमा मिशन चरण- I एवं चरण II:
  - पहले चरण के दौरान CSIR ने 6000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करने में मदद की और देश भर के 46 आकांक्षी जिलों को कवर किया। इसके अलावा 44,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया।
  - फरवरी 2021 में CSIR ने अरोमा मिशन का दूसरा चरण शुरू किया जिसमें 45,000 से अधिक कुशल मानव संसाधनों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिससे देश भर में 75,000 से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा।
- 🗅 🛮 नोडल एजेंसी:
- सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान (CSIR-CIMAP), लखनऊ इसकी नोडल एजेंसी है।
- संभावित परिणाम:
  - लगभग 5500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुगंधित नकदी फसलों की कैप्टिव खेती के तहत लाना, विशेष रूप से पूरे देश में वर्षा सिंचित / निम्नीकृत भूमि को लक्षित करना।
  - पूरे देश में किसानों/उत्पादकों को आसवन और मूल्यवर्द्धन के लिये तकनीकी और ढाँचागत सहायता प्रदान करना।
  - किसानों/उत्पादकों हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये
     प्रभावी बाय-बैक (Buy-Back) तंत्र को सक्षम करना।
  - वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में उनके एकीकरण के लिये आवश्यक तेलों व सुगंध सामग्री का मूल्यवर्नद्ध करना।

# विश्व मधुमक्खी दिवस

### चर्चा में क्यों ?

विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है।

 इससे पहले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की थी।

### विश्व मधुमक्खी दिवसः

- परिचय:
  - यह दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जनसा की जयंती का प्रतीक है।

- एंटोन जनसा स्लोवेनिया में मधुमक्खी पालकों के एक परिवार से हैं, जहाँ मधुमक्खी पालन एक महत्त्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, जिसकी एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है।
  - एंटोन ने यूरोप के पहले मधुमक्खी पालन स्कूल में दाखिला लिया और मधुमक्खी पालक के रूप में पूर्णकालिक काम किया।
- उनकी पुस्तक 'डिस्कशन ऑन बी-कीपिंग' भी जर्मन में प्रकाशित हुई थी।
- 🔾 2022 के लिये थीम:
  - "बी एंगेज्ड: मधुमिक्खियों और मधुमक्खी पालन प्रणालियों की विविधता का जश्न मनाना" (Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees and beekeeping systems)।

### मधुमक्खी पालन का महत्त्वः

- महत्त्वपूर्ण परागणकर्ताः
  - मधुमिक्खयाँ सबसे महत्त्वपूर्ण परागणकों में से हैं, जो खाद्य और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और जैव विविधता सुनिश्चित करती हैं।
- ⊃ जलवायु परिवर्तन के शमन में योगदान:
  - मधुमिक्खियाँ जलवायु परिवर्तन को कम करने और पर्यावरण के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।
  - दीर्घाविध में मधुमिक्खियों का संरक्षण और मधुमक्खी पालन क्षेत्र गरीबी एवं भूख को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही एक स्वस्थ पर्यावरण व जैव विविधता सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।
- 🔾 सतत् कृषि और ग्रामीण रोजगार सृजित करना:
  - सतत् कृषि और ग्रामीण रोजगार सृजित करने की दृष्टि से भी मधुमक्खी पालन महत्त्वपूर्ण है।
  - परागण द्वारा वे कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं, इस प्रकार खेतों
     में विविधता एवं बहुरूपता बनाए रखते हैं।
  - इसके अलावा वे लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और किसानों की आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं।
- किसानों की आय दोगुनी करने के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना:
  - खाद्य और कृषि संगठन के डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2017-18 में भारत शहद उत्पादन (64.9 हजार टन) के मामले में दुनिया में आठवें स्थान पर था, जबिक चीन (551 हजार टन के उत्पादन के साथ) पहले स्थान पर था।
  - इसके अलावा किसानों की आय को दोगुना करने के वर्ष 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मधुमक्खी पालन महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

# इथेनॉल सम्मिश्रण

### चर्चा में क्यों?

भारत में पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण का स्तर 9.99% तक पहुँच गया है।

### इथेनॉल सम्मिश्रणः

- यह प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है, जो प्रकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है।
- इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (EBP): इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और किसानों की आय को बढ़ाना है।
- सम्मिश्रण लक्ष्य: भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (जिसे E20 भी कहा जाता है) के लक्ष्य को वर्ष 2030 से परिवर्तित कर वर्ष 2025 तक कर दिया है।

#### इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्त्वः

- 🔾 पेट्रोलियम पर कम निर्भरता:
  - इथेनॉल को गैसोलीन में मिलाकर यह कार चलाने के लिये आवश्यक पेट्रोल की मात्रा को कम कर सकता है जिससे आयातित महँगे और प्रदूषणकारी पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।
    - आज भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है।
- पैसे की बचत/लागत में कमी:
  - भारत का शुद्ध पेट्रोलियम आयात 2020-21 में 185 मिलियन टन था जिसकी लागत 551 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
  - अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग परिवहन में किया जाता है, अत: E20 कार्यक्रम देश के लिये सालाना 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचा सकता है।
- ⊃ कम प्रदूषण:
  - इथेनॉल कम प्रदूषणकारी ईंधन है और पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समान दक्षता प्रदान करता है।
    - अधिक कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, खाद्यान्न और गन्ने के बढ़ते उत्पादन के कारण अधिशेष, संयंत्र-आधारित स्रोतों से इथेनॉल का उत्पादन करने के लिये प्रौद्योगिकी की उपलब्धता तथा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) के अनुरूप वाहनों को बनाने की व्यवहार्यता रोडमैप में उपयोग किये जाने वाले कुछ सहायक कारक हैं। E20 लक्ष्य "न केवल एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है, बल्कि इसे एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता" के रूप में संदर्भित किया गया है।

# भारतीय रुपए का अवमूल्यन

### चर्चा में क्यों?

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 77.44 के अब तक के सबसे निम्न स्तर पर आ गया है।

# प्रमुख बिंदु

### अवमूल्यन:

- अवमूल्यन के बारे में:
  - मुद्रा का मूल्यह्रास/अवमूल्यन का आशय अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट से है।
  - रुपए के मूल्यह्रास का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का कमज़ोर होना।
    - इसका मतलब है कि रुपया अब पहले की तुलना में कमजोर है।
    - उदाहरण के लिये पहले एक अमेरिकी डॉलर 70 रुपए के बराबर हुआ करता था। अब एक अमेरिकी डॉलर 77 रुपए के बराबर है जिसका अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हुआ है यानी एक डॉलर को खरीदने में अधिक रुपए लगते हैं।
- भारतीय रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव:
  - रुपए में गिरावट भारतीय रिज्ञर्व बैंक के लिये एक दोधारी तलवार (नकारात्मक एवं सकारात्मक) की भाँति होती है।
    - सकारात्मक प्रभाव:
  - सैद्धांतिक रूप से कमजोर रुपए को भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये, लेकिन अनिश्चितता और कमजोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपए के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में परिवर्तित नहीं हो सकती है।
    - नकारात्मक प्रभाव:
  - यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम उत्पन्न करता है और केंद्रीय बैंक के लिये ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना सकता है।
  - भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकता के दो-तिहाई से अधिक की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है।
  - भारत खाद्य तेलों के शीर्ष आयातक देशों में से एक है। एक कमज़ोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को और अधिक बढ़ाएगी तथा उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी।

### मुद्रा का अभिमूल्यन और अवमूल्यनः

लचीली विनिमय दर प्रणाली (Floating Exchange Rate System) में बाजार की ताकतें (मुद्रा की मांग और

- आपूर्ति) मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती हैं।
- मुद्रा अभिमूल्यन: यह किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है।
  - सरकार की नीति, ब्याज दरों, व्यापार संतुलन और व्यापार चक्र सिंहत कई कारणों से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है।
  - मुद्रा अभिमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करता है क्योंकि विदेशों से वस्तुएँ खरीदना सस्ता हो जाता है, जबिक विदेशी व्यापारियों द्वारा देश की वस्तुएँ खरीदना महँगा हो जाता है।

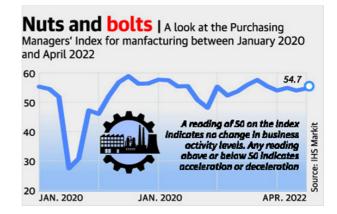
### अवमूल्यन और मूल्यहासः

- यदि प्रशासिनक कार्रवाई से भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट आती है, तो यह अवमूल्यन है।
  - मूल्यह्रास और अवमूल्यन के लिये प्रक्रिया अलग है, प्रभाव के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है।
- भारत वर्ष 1993 तक विनिमय की प्रशासित या निश्चित दर का पालन करता था, जब वह बाजार-निर्धारित प्रक्रिया या अस्थायी विनिमय दर आधारित था।
  - 💠 चीन अभी भी पूर्व नीति का पालन करता है।

# क्रय प्रबंधक सूचकांक

### चर्चा में क्यों?

एसएंडपी वैश्विक भारत विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) के अनुसार, भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने नए ऑर्डर और उत्पादन में मामूली तेजी दर्ज की जो जो मार्च 2022 के 54 से बढ़कर अप्रैल 2022 में 54.7 हो गई।



### सूचकांक की मुख्य विशेषताएँ:

 मार्च में नौ महीने के पहले संकुचन के बाद अप्रैल के आँकड़ों में नए निर्यात मांगों में एक बड़ा बदलाव देखा गया।

- संकुचन, अर्थशास्त्र में व्यापार चक्र के एक चरण को संदर्भित करता है, इस दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जाती है।
- संकुचन की स्थिति आमतौर पर व्यापार चक्र के शीर्ष पर पहुँचने
   के बाद होती है।
- इस बीच वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, रूस-यूक्रेन युद्ध और अधिक परिवहन लागत के कारण मुद्रास्फीति के बढने की संभावना है।
- उत्पादक सामग्री की कीमतों में पाँच महीने में सबसे तेज गित से वृद्धि हुई है, जबिक उत्पाद शुल्क मुद्रास्फीति 12 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई।
- नवीनतम परिणामों के चलते मुद्रास्फीति का गंभीर दबाव देखा गया क्योंकि ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता, वैश्विक इनपुट की कमी और युक्रेन में युद्ध आदि ने खरीद लागत को बढ़ा दिया था।
- रोजगार के संदर्भ में अप्रैल 2022 के दौरान केवल मामूली वृद्धि हुई
   थी।

#### क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI):

- यह एक सर्वेक्षण-आधारित प्रणाली है। क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) के दौरान विभिन्न संगठनों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आउटपुट, नए ऑर्डर, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और रोजगार जैसे महत्त्वपूर्ण संकेतक शामिल होते हैं, साथ ही सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों से इन संकेतकों को रेट करने के लिये भी कहा जाता है।
- PMI का उद्देश्य कंपनी के निर्णयकर्त्ताओ, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान एवं भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
- यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की गणना अलग-अलग करता है,
   फिर एक समग्र सुचकांक भी बनाता है।
- ⊃ PMI को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है।
  - 50 से ऊपर का स्कोर विस्तार, जबिक इससे कम स्कोर संकुचन को दर्शाता है।
  - 50 का स्कोर कोई बदलाव नहीं दर्शाता है।
- यदि पिछले महीने का PMI चालू माह के PMI से अधिक है तो यह इस बात को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था संकृचित हो रही है।
- यह आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है। इसलिये इसे आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा अग्रणी संकेतक माना जाता है।
- PMI को IHS मार्किट द्वारा दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिये संकलित किया गया है।
  - IHS मार्किट दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले प्रमुख उद्योगों और बाजारों के लिये सूचना, विश्लेषण एवं समाधान हेतु एक वैश्विक मंच है।
  - आईएचएस मार्किट एसएंडपी ग्लोबल का हिस्सा है।

- चूँिक औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि पर आधिकारिक आँकड़े बहुत बाद में प्राप्त होते हैं.; PMI पहले चरण में उचित निर्णय लेने में मदद करता है।
- यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) से अलग है, जो अर्थव्यवस्था में गतिविधि के स्तर को भी मापता है।
  - PMI की तुलना में IIP व्यापक औद्योगिक क्षेत्र को कवर करता है।
  - हालाँकि मानक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलना में
     PMI अधिक गतिशील है।

# कृषि, फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक साझेदारी के लिये समझौता

### ज्ञापन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

### समझौता ज्ञापन का उद्देश्य:

- UNDP केंद्र की महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- समझौता ज्ञापन के तहत UNDP संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिये कृषि मंत्रालय का समर्थन करने हेतु प्रणाली में अपने वैश्विक अनुभवों से अर्जित विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।

### PMFBY योजनाः

- परिचय:
  - यह योजना किसानों को फसल की विफलता (खराब होने) की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है।
  - अधिसूचित फसलों हेतु फसल ऋण/िकसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाते में ऋण लेने वाले िकसानों के लिये इस योजना को अनिवार्य बनाया गया है, जबिक अन्य िकसान स्वेच्छा से इस योजना से जुड़ सकते हैं।
- दायरा (Scope): वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक/ बागवानी फसलें, जिनके लिये पिछली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं।

- बीमा किस्त: इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त/ प्रीमियम- खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है।
  - िकसानों के हिस्से की प्रीमियम लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बराबर साझा किया जाता है।
  - हालाँकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा किस्त सब्सिडी का 90% हिस्सा वहन किया जाता है।

#### 🗅 कवरेज:

- इस योजना में प्रतिवर्ष औसतन 5.5 करोड़ से अधिक किसान आवेदन शामिल होते हैं।
- आधार सीडिंग (इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से आधार को लिंक करना) ने किसानों के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है।
- रबी 2019-20 के मौसम में टिड्डी हमले के दौरान राजस्थान राज्य में लगभग 30 करोड़ रुपए का दावा प्रस्तुत किया गया जो एक एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0:
- योजना के अधिक कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 के खरीफ सीजन में PMFBY में आवश्यक सुधार किया गया था।
- इस संशोधित PMFBY को प्राय: PMFBY 2.0 भी कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
  - पूर्णत: स्वैच्छिक: इसके तहत वर्ष 2020 की खरीफ फसल से सभी किसानों के लिये नामांकन 100% स्वैच्छिक है।
  - सीमित केंद्रीय सब्सिडी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत गैर-सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है।
  - राज्यों को अधिक स्वायत्तताः केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को PMFBY को लागू करने के लिये व्यापक छूट प्रदान की है और साथ ही उन्हें इसमें किसी भी अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं का चयन करने का विकल्प भी दिया है।
  - आईसीई गतिविधियों में निवेश: अब इस योजना के तहत बीमा कंपिनयों द्वारा एकत्र किये गए कुल प्रीमियम का 0.5% सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

### PMFBY के तहत तकनीकी का प्रयोग:

- फसल बीमा एपः
  - 💠 यह किसानों को आसान नामांकन की सुविधा प्रदान करता है।
  - किसी भी घटना के घटित होने के 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसान रिपोर्टिंग की सुविधा।
- नवीनतम तकनीकी उपकरण: फसल के नुकसान का आकलन करने के लिये सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लिनैंग का उपयोग किया जाता है।
- PMFBY पोर्टल: भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लिये PMFBY पोर्टल की शुरुआत की गई है।

### किसान क्रेडिट कार्ड योजनाः

- 🗅 परिचय:
  - इसे वर्ष 1998 में किसानों को उनकी खेती के लिये आसान और सरल प्रक्रियाओं के साथ तथा अन्य जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि कृषि आदानों की खरीद, आहरण एवं उनकी उत्पादन जरूरतों हेतु बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त और समय पर नकद ऋण सहायता प्रदान करने हेतु पेश किया गया था।
  - इस योजना को वर्ष 2004 में किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता को संबद्ध और गैर-कृषि गतिविधियों के लिये आगे बढ़ाया गया था।

#### ⊃ उद्देश्य:

- किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रदान किया जाता है:
  - फसलों की खेती के लिये अल्पकालिक ऋण आवश्यकताएँ।
  - 🗷 फसल के बाद का खर्च।
  - किसान परिवार की खपत आवश्यकताएँ हेतु कृषि-ऋण विपणन।
  - कृषि संपत्ति और कृषि से संबंधित गतिविधियों, जैसे-डेयरी पशु, अंतर्देशीय मत्स्य पालन आदि के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी।
  - कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे- पंपसेट, स्प्रेयर, डेयरी पशु आदि के लिये निवेश ऋण की आवश्यकता।
- 🔾 क्रियान्वयन एजेंसी:
  - किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंकों और सहकारी सिमतियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
  - किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक की खरीद और परिवार के लिये घर के निर्माण तथा गांव में कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना के लिये अल्पकालिक ऋण सहायता नहीं दी जाती है।

# UPI123Pay और डिजिसाथी

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के फोन के लिये नई UPI सेवाएँ UPI123Pay शुरू की हैं, साथ ही डिजिटल भुगतान के लिये 24x7 हेल्पलाइन की भी शुरूआत की गई है, जिसे 'डिजीसाथी' कहा गया।

डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी पर उपयोगकर्ताओं को स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा 'डिजीसाथी' की स्थापना की गई है। वर्तमान में यह अंग्रज़ी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

### 'UPI123Pay' क्या है ?

- परिचय:
  - यह उन साधारण फोन पर काम करेगा, जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।
    - अभी तक UPI फीचर ज्यादातर स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध हैं।
  - फीचर फोन के लिये UPI सेवा खुदरा भुगतान पर आरबीआई
     के नियामक सैंडबॉक्स का लाभ उठाएगी।
    - एक नियामक सैंडबॉक्स आमतौर पर नियंत्रित/परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है जिसके लिये नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ नियामक छूट की अनुमति दी जा सकती है।
  - UPI सेवा UPI अनुप्रयोगों में 'ऑन-डिवाइस' वॉलेट तंत्र के माध्यम से डिजिटल लेन-देन को सक्षम करेगी।
  - उपयोगकर्त्ता चार प्रौद्योगिकी विकल्पों के आधार पर कई लेन-देन करने में सक्षम होंगे, जिनमें- आईवीआर (इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस) नंबर, मिस्ड कॉल-आधारित दृष्टिकोण, फीचर फोन में एप की कार्यक्षमता और 'नियर वॉइस' आधारित भुगतान शामिल हैं।
- लाभ:
  - फीचर फोन हेतु नई सेवा व्यक्तियों को स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना दूसरों को सीधे भुगतान करने में सक्षम होगी।
  - उपयोगकर्ताओं द्वारा मित्रों और परिवार को भुगतान किया जा सकता हैं, साथ ही इससे उपयोगिता बिलों का भुगतान कर सकते हैं, अपने वाहनों के फास्ट टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल बिलों का भुगतान कर सकते हैं तथा उपयोगकर्त्ता अपने खाते की शेष राशि को भी चेक कर सकते हैं।

- यह ग्राहकों को स्कैन और भुगतान को छोड़कर लगभग सभी लेन-देन हेतु फीचर फोन का उपयोग करने की अनुमित देगा।
- UPI123Pay अनुमानित 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा और उन्हें सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। यह स्मार्टफोन का उपयोग न करने वाले उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोडने में मददगार साबित होगा।

# बाजार अवसंरचना संस्थान

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के निष्कर्षों के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), देश का सबसे बड़ा इक्विटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज तथा एक व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण बाजार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institution- MII) है।

### भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( SEBI )

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
- ⊃ प्रमुख कार्य:
  - प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
  - प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना।

#### बाजार अवसंरचना संस्थान:

- स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और समाशोधन निगम को सामूहिक रूप से बाजार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institutions) प्रतिभूति के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में स्थापित (2010 में) एक पैनल के अनुसार, 'मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर' शब्द इस पूंजी बाजार की सेवा क्षेत्रक मूलभूत सुविधाओं और प्रणालियों को दर्शाता है।
  - प्रतिभूतियों/पूंजी बाजार का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी/वित्तीय संसाधनों के आवंटन/पुनर्आवंटन को सक्षम बनाना है।
- MIIs अर्थव्यवस्था में धन के इष्टतम उपयोग में मदद करने के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- यह पूंजी आवंटन प्रणाली का केंद्र हैं तथा आर्थिक विकास हेतु अपिरहार्य हैं और किसी भी अन्य बुनियादी ढाँचा संस्थान की तरह समाज पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

### नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का सबसे बडा वित्तीय बाजार है।
- वर्ष 1992 से निगमित 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' एक परिष्कृत, इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में विकसित हुआ है, जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्युम के हिसाब से दुनिया में चौथे स्थान पर है।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत में आधुनिक, पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था।
  - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत में सबसे बड़ा निजी वाइड-एरिया नेटवर्क है।
- निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE)
   का प्रमुख सूचकांक है।
- सूचकांक ब्लू चिप कंपिनयों, सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल भारतीय प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो के व्यवहार को ट्रैक करता है। इसमें NSE में सूचीबद्ध लगभग 1600 कंपिनयों में से 50 शामिल हैं।

### उन्हें महत्त्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

- MIIs भारत में व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण हैं और यह तथ्य सूचीबद्ध कंपिनयों के बाज़ार पूंजीकरण, जुटाई गई पूंजी एवं निवेशक खातों की संख्या तथा डिपॉजिटरी के खाते में रखी गई संपत्ति के मूल्य के मामले में इन संस्थानों की अभूतपूर्व वृद्धि से स्पष्ट है।
- इस तरह एक MII की कोई भी विफलता और भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है जिसके परिणामस्वरूप समग्र आर्थिक गिरावट हो सकती है जो संभावित रूप से प्रतिभूति बाजार तथा देश की सीमाओं से आगे बढ़ सकती है।
- दूरगामी प्रभाव की संभावना को देखते हुए एक MII की विफलता व्यापक बाजार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, शासन और निरीक्षण बिल्कुल महत्त्वपूर्ण हैं तथा इनके लिये उच्चतम मानकों की आवश्यकता है।

# भारत में विशिष्ट संस्थान जो MII के रूप में अर्हता रखते हैं

- स्टॉक एक्सचेंजों में सेबी ने बीएसई, एनएसई, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सिहत सात को सूचीबद्ध किया है।
- दो डिपॉजिटरी हैं प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने और उनके व्यापार तथा हस्तांतरण को सक्षम करने के लिये चार्ज किया जाता है - जिन्हें MII टैग किया जाता है: सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड।

- नियामक 'मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन' सिंहत सात समाशोधन गृहों को भी सूचीबद्ध करता है।
  - क्लियरिंग हाउस, अपने हिस्से के लिये प्रतिभूतियों के व्यापार को मान्य और अंतिम रूप देने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि खरीदार और विक्रेता दोनों अपने दायित्वों का सम्मान करते हैं।

# रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर द्वारा बंगलूरू में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) का उद्घाटन किया गया।

### रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब ( RBIH ):

- परिचय:
  - इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।
  - यह RBI की पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनी है।
- ⊃ उद्देश्य:
  - RBIH का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिये वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुँच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो।
    - यह RBIH की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप है,अर्थात् भारत में वित्तीय क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवाचार लाने हेतु यह वित्तीय समावेशन के अंतर्निहित विषय से युक्त है।
  - हब से प्रोटोटाइप, पेटेंट और जाँच के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और नियामक डोमेन तथा राष्ट्रीय सीमाओं में फैले राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत विचारों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  - इसमें अधिकतम क्षमता वाले स्टार्ट-अप की पहचान करने और उन्हें सलाह देने की योजना थी।
  - विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं की पहचान करने और संभावित समाधानों का पता लगाने के लिये विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और शिक्षाविदों के साथ सहयोग करने की भी उम्मीद है।
  - आरबीआई इनोवेशन हब ने महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों
     के स्थायी समाधान हेतु स्वनारी टेकस्प्रिंट की मेजबानी की।
    - टेकस्प्रिंट का उद्देश्य भारत में महिलाओं के लिये डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है।

### वित्तीय समावेशन हेतु अन्य पहलें:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMIDY)
- ⇒ अटल पेंशन योजना (APY)
- ⊃ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- 🔾 स्टैंडअप इंडिया योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

# MSMEs के लिये RAMP योजना

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने यानी RAMP (Rising and Accelerating MSME Performance) योजना को मंज़ूरी दी है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में होगी।

- यह यू.के सिन्हा सिमिति, के.वी कामथ सिमिति तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक ने MSME क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देने के लिये वर्ष 2019 में यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
- इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी।

### RAMP योजना

- 🗅 परिचय:
  - यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) से जुड़ी कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद दी जा रही है।
- 🗅 उद्देश्य:
  - 💠 बाज़ार और ऋण तक पहुँच में सुधार।
  - केंद्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और शासन को मजबूत करना।
  - केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारियों को बेहतर करना।
  - MSME द्वारा विलंबित भुगतान और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाना।
- 🕽 घटक:
  - RAMP का महत्त्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना (SIP) तैयार करना है जिसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाएगा।

- प्र SIP और RAMP के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु योजना के रूप में प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान करना, विशेष उपलब्धियों एवं परियोजना का निर्धारण तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर-कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, महिला उद्यम आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये आवश्यक बजट पेश करना शामिल है।
- RAMP की समग्र निगरानी और नीति का अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय MSME परिषद द्वारा किया जाएगा।
  - इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सिंहत MSME मंत्रालय के मंत्री शामिल होंगे। इस योजना के तहत MSME मंत्रालय के सिचव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम समिति गठित होगी।

#### निधियनः

इस योजना के लिये कुल परिव्यय 6,062.45 करोड़ रुपए है जिसमें से 3750 करोड़ रुपए विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे तथा शेष 2312.45 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

#### 🗅 कार्यान्वयन रणनीति:

- बाजार पहुँच और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए MSME मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिये भुगतान से जुड़े संकेतकों (Disbursement Linked Indicators- DLIs) से अलग मंत्रालय के बजट में RAMP के माध्यम से वित्त का आवंटन होगा।
- विश्व बैंक से RAMP के लिये प्राप्त निधियों की अदायगी, भुगतान से जुड़े निम्नलिखित संकेतकों को पूरा करने हेतु की जाएगी:
  - 🗷 राष्ट्रीय MSME सुधार एजेंडा को लागू करना।
  - MSME क्षेत्र के लिये केंद्र-राज्य सहयोग को तेज करना।
  - प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना की प्रभावशीलता बढ़ाना (CLCS-TUS)।
  - MSME के लिये प्राप्य वित्तपोषण बाजार को मजबूत बनाना।
  - म् सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (CGTMSE) और "ग्रीनिंग एंड जेंडर" डिलीवरी की प्रभावशीलता बढाना।
  - 🗷 विलंबित भुगतान की घटनाओं को कम करना।

# फिनक्लुवेशन

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank- IPPB) द्वारा फिनक्लुवेशन प्लेटफॉर्म (Fincluvation Platform) को लॉन्च किया गया है, ताकि फिनटेक स्टार्टअप्स के सहयोग से अभिनव उपायों को बढ़ावा दिया जा सके और वंचित तथा सेवाओं तक पहुँच वाली आबादी के बीच वित्तीय समावेशन में तेज़ी लाई जा सके।

फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) शब्द व्यवसायों द्वारा उपयोग किये जाने वाले उन सॉफ्टवेयर और अन्य आधुनिक तकनीकों को संदर्भित करता है जो स्वचालित एवं आयातित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।

### फिनक्लुवेशनः

- फिनक्लुवेशन, भाग लेने वाले स्टार्टअप के साथ समावेशी वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने हेत् IPPB का एक स्थायी मंच होगा।
  - IPPB और डाक विभाग (Department of Post-DoP) सामूहिक रूप से डाकघरों और उनमें कार्यरत्त 4,00,000 से अधिक कर्मचारियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से 430 मिलियन ग्राहकों को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं जो इसे विश्व के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद डाक नेटवर्क का निर्माण करते हैं।
- वित्तीय समावेशन के लिये लिक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप्स समुदाय को प्रोत्साहित करने हेतु एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है।
- स्टार्टअप्स को निम्नलिखित ट्रैक्स के साथ संरेखित समाधान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है:
  - क्रेडिटाइजेशन- लिक्षत ग्राहकों के साथ संयोजित नवोन्मेषी तथा समावेशी क्रेडिट उत्पादों का विकास करना एवं उन्हें डाक नेटवर्क के माध्यम से उनके द्वार तक पहुँचाना।
  - डिजिटाइज्रेशन- डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक सेवाओं के समन्वयन के माध्यम से सुविधा प्रदान करना, उदाहरण के लिये अंत: पारस्परिक बैंकिंग सेवा के रूप में पारंपरिक मनीऑर्डर सेवा उपलब्ध कराना।
  - बाजार आधारित समाधान- बाजार आधारित कोई भी समाधान जो लक्षित ग्राहकों की सेवा करने में आईपीपीबी (IPPB) और/या डाक विभाग से संबंधित किसी अन्य समस्या का समाधान करने में सहायता कर सकती है।
- फिनक्लुवेशन मेंटर स्टार्टअप्स के साथ मिलकर कार्य करेंगे ताकि ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से उत्पादों में बदलाव किया जा सके और आईपीपीबी और डीओपी के ऑपरेटिंग मॉडल के साथ बाजार में प्रवेश की रणनीति बनाई जा सके।

### भारत में फिनक्लुवेशन की आवश्यकता:

- नए अवसरों को बढ़ावा देना: पारंपिरक वितरण नेटवर्कों से जुड़ी वित्तीय सेवाओं के साथ प्रौद्योगिकी का समन्वयन नए प्रकार के व्यवसाय अवसर उपलब्ध करा रही है।
- उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बढ़ानाः प्रौद्योगिकी खरीद के पारंपरिक मॉडल के कारण बैंकों द्वारा उत्पाद निर्माण में अक्सर उपयोगकर्त्ता के अनुभव की कमी देखी जाती है जिससे ग्राहकों की अपेक्षाओं और सेवा वितरण के बीच एक बड़ा अंतर उत्पन्न होता है।
- पारंपिरक प्रौद्योगिकियों की विफलता: उत्पाद निर्माण में स्वामित्व की कमी के कारण पारंपिरक प्रौद्योगिकी फर्म ग्राहकों की सेवा अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहती है। भारतीय नागिरकों की विविध जरूरतें हैं, इसलिये उपयोगकर्त्ताओं के बीच सावधानीपूर्वक विचार करते हुए उत्पाद का डिजाइन और प्रतिरूप तैयार करने की आवश्यकता है।

# सीवीड की खेती

### चर्चा में क्यों?

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार करने हेतु तमिलनाडु में एक सीवीड/समुद्री शैवाल पार्क को स्थापित करेगा।

- तिमलनाडु से सीवीड की खेती के लिये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) हेतु स्थान चुनने के लिये कहा गया है।
- वर्ष 2021 में प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (TIFAC) ने एक सीवीड मिशन शुरू किया था।

### सीवीड

- सीवीड के बारे में :
  - ये शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
  - सीवीड पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फारेस्ट (Kelp Forest) कहा जाता है। ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिये नर्सरी का कार्य करते हैं।
  - सीवीड की अनेक प्रजातियाँ हैं जैसे- ग्रेसिलिरिया एडुलिस, ग्रेसिलिरिया क्रैसा, ग्रेसिलिरिया वेरुकोसा, सरगस्सुम एसपीपी और टर्बिनारिया एसपीपी आदि।
- 🗅 लाभ:
  - पोषण के लिये:
    - सीवीड विटामिन, खिनज और फाइबर का स्रोत होते हैं तथा कई सीवीड स्वादिष्ट भी होते हैं।

- औषधीय उद्देश्य के लिये:
  - कई सीवीड में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल एजेंट विद्यमान होते हैं। उनके ज्ञात औषधीय प्रभाव हजारों वर्षों से विरासत में प्राप्त हुए हैं।
  - कुछ सीवीड में कैंसर से लड़ने वाले शक्तिशाली एजेंट भी पाए जाते हैं अत: शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ये अंतत: लोगों में घातक ट्यूमर और ल्यूकेमिया के उपचार में प्रभावी साबित होंगे।
- अार्थिक विकास के लिये:
  - सीवीड आर्थिक विकास में भी सहायक होते हैं। विनिर्माण में उनके कई उपयोगों में, टूथपेस्ट और फलों की जेली जैसे वाणिज्यिक सामानों में प्रभावी बाध्यकारी एजेंट (पायसीकारक) और कार्बिनिक सौंदर्य प्रसाधन तथा त्वचा देखभाल उत्पादों में लोकप्रिय सॉफ्नर (इमोलियेंट्स) के रूप में उपयोग किया जाता हैं।
- जैव संकेतक:
  - जब कृषि, जलीय कृषि (Aquaculture), उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा समुद्र में प्रवेश करता है, तो यह पोषक तत्वों के असंतुलन का कारण बनता है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन (Algal Bloom) होता है। सीवीड अतिरिक्त पोषक तत्त्वों को अवशोषित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं।
- अायरन सीक्वेस्टर:
  - मं सीवीड प्रकाश संश्लेषण के लिये लौह खिनज पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जब इस खिनज की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है तो सीवीड इसका अवशोषण करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचा लेते हैं। सीवीडों द्वारा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुओं को अवशोषित कर लिया जाता है।
- 💠 ऑक्सीजन और पोषक तत्त्वों का पूर्तिकर्त्ता:
  - सीवीड प्रकाश संश्लेषण और समुद्री जल में मौजूद पोषक तत्त्वों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपने शरीर के हर हिस्से से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये अन्य समुद्री जीवों को भी जैविक पोषक तत्त्वों की आपूर्ति करते हैं।

### उबला चावल

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र द्वारा अधिक उबला चावल/पारबॉइल्ड राइस/उसना चावल (Parboiled Rice) की खरीद पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी जिसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक समान धान खरीद नीति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

### उबला चावल (Parboiled Rice)

- 🔾 उबला चावल के बारे में:
  - ऐपारबॉइल्ड' (Parboil) का शाब्दिक अर्थ है 'आंशिक रूप से उबालकर पकाया गया' (Partly Cooked by Boiling')।
    - इस प्रकार उबला चावल उस चावल को संदर्भित करता है जिसे चावल/धान (Paddy) के मिलिंग चरण (Milling Stage) से पहले आंशिक रूप से उबाला जाता है।
  - चावल को उबालना कोई नई प्रथा नहीं है तथा भारत में प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है।
    - हालाँकि भारतीय खाद्य निगम या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा उबले हुए चावल की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
- 🗅 चावल को उबालने की प्रक्रिया (उदाहरण):
  - केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (Central Food Technological Research Institute-CFTRI), मैसूर, एक ऐसी विधि का उपयोग करता है जिसमें धान को 8 घंटे से अधिक समय तक भिगोने की सामान्य विधि के विपरीत, धान को तीन घंटे के लिये ही गर्म पानी में भिगोया जाता है।
    - इसके बाद चावल को पानी से निकाल दिया जाता है और धान को 20 मिनट के लिये स्टीम कर दिया जाता है। साथ ही धान को CFTRI द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधि में किसी छायादार स्थान में सुखाया जाता है, लेकिन सामान्य विधि में इसे धूप में सुखाया जाता है।
  - धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र (Paddy Processing Research Centre- PPRC), तंजावुर द्वारा एक अन्य विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस (Chromate Soaking Process) के रूप में जाना जाता है।
    - इस विधि में प्रयोग िकया जाने वाले क्रोमेट लवण के आयनों में क्रोमियम और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, गीले चावल से गंध को दूर करने में सहायक होते हैं।
- उबालने के लिये उपयुक्त चावल की किस्में:
  - सामान्यत: चावल की सभी किस्मों को उबले चावल में संसाधित किया जा सकता है, लेकिन मिलिंग के दौरान चावल के टूटने की प्रक्रिया को रोकने हेतु लंबी पतली किस्मों (Slender Varieties) का उपयोग करना उचित होता है।
  - हालाँिक सुगंधित किस्मों को उबालने के लिये प्रयोग नहीं किया
     जाना चाहिये क्योंिक इस इसकी सुगंध कम हो सकती है।